राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

गुरुवार,

01 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अंजू खन्गवाल।

बस्सी तहसील (जयपुर) में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत करवाये गये कार्य

40. **श्रीमती अंजू खन्गवाल** (बस्सी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील बस्सी में वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो प्रत्येक ठेकेदारों द्वारा भरी गई निविदाओं की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील बस्सी में उक्त अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत ठेकेदार को कार्य किस आधार पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा सिंगल फेज एवं हैण्ड पम्प गलत स्थानों पर लगाकर और गलत तरीके से भुगतान उठाया गया है? यदि नहीं, तो भुगतान किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ठेकेदार से वसूली कर उसे ब्लैकलिस्टेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन सवास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी हां। वित्तीय

(डा. जितेन्द्र सिंह)

वर्ष 2010-11 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम' के अन्तर्गत जिला जयपुर की तहसील बस्सी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु विभिन्न कार्यों की कुल 15 निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-11 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम' अन्तर्गत उक्त स्वीकृत कार्यों हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाएं आमंत्रित की जाकर वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में न्यूनतम दरदाता को कार्यादेश दिया गया।

(3) जी नहीं। उक्त कार्यों से संबंधित ठेकेदारों द्वारा सिंगल फेज नलकूप एवं हैण्ड पम्प विभाग द्वारा स्वीकृत स्थानों पर स्थापित किये जाकर विभाग द्वारा नियमानुसार ही भुगतान किया गया है।

(4) जी नहीं। उपरोक्तानुसार कार्य सही रूप से सम्पादित कराये गये हैं। अत: ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन किया था कि जितनी निविदाएं भरी गयी हैं, उनकी प्रति मुझे दी जाए लेकिन उन निविदाओं की प्रति मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सिर्फ ठेकेदारों के...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, क्या मंत्रीजी?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निविदाओं की प्रतियां इतनी बड़ी वज़न थीं लेकिन मैं उपलब्ध करवा दूंगा, मैं अर्ज करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): मैंने सिर्फ 2010-11 की मांगी थी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैंने उसमें सारी डिटेल दे दी है, अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपको उसमें...

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): लेकिन इसमें नाम हैं और सिर्फ नाम से भ्रष्टाचार का पता नहीं चल सकता, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैंने जो डिटेल दी थी आपको, जो आपने मांगी थी, वे सारी डिटेल्स इसमें दे दी हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): मंत्रीजी की तैयारी पूरी नहीं है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): नहीं, नहीं, तैयारी पूरी है, सर।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मुझे 10-11 के, थोड़े से जो मेरे पास नाम हैं, वे इतने बड़े नहीं हैं, उनमें से 3-4 के भी देते तो मैं शायद तैयारी कर सकती थी। मुझे वह उपलब्ध कराई जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इसको पेंडिंग रख दो, साहब।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): इस प्रश्न को स्थगित करें। मेरे पास सारे, आपने जो मुझे जवाब सेकंड दिया है, उसका कोई आधार ही नहीं बनता है। क्योंकि जब मुझे वह प्रति ही नहीं मिली है तो मैं आधार क्या बताऊंगी कि किस आधार पर उनको पेमेंट हुआ है? उनको पेमेंट किस आधार पर किया है, यह मैं कैसे बता सकती हूं, क्योंकि मुझे वह प्रति नहीं मिली है? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारा विवरण इसमें संलग्न है। 15 जो इसमें निविदादाता थे, उनका सारा विवरण इसमें उपलब्ध है। उसके अन्दर कौन एल-1 था, वह भी सारा उपलब्ध है। क्योंकि यह इतना हैवी था, इसमें अगर ये चाहेंगी तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, अध्यक्ष महोदय, उनको कोई क्वैरी करनी हो तो।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): कुल 15 बताये इन्होंने, 15 में से मुझे आप 3 ही दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। हम विधान सभा में आते हैं, सवाल लगाते हैं तो साथ में जो इन्फार्मेशन मांगें, वह तो देनी चाहिए। यह कोई जवाब थोड़े ही हुआ। आप संरक्षित नहीं करेंगे तो कौन करेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। ऐसा है, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि इसमें यह लिखा है, प्रश्न में, कि निविदाओं की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। तो इसकी प्रति आप आज ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दीजिए, शाम तक।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं करवा दूंगा, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा सप्लीमेंटरी आ जाए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सप्लीमेंटरी कैसे पूछेंगे? (व्यवधान) प्रश्न कैसे पूछेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): मेरे पास और भी, मेरा प्रश्न अभी बाकी है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी क्या पूछेंगी? उनको पहले का जवाब ही नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने तो दीजिए। माननीय सदस्या को बोलने तो दीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्या, आप सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री पेमाराम (धोद): स्थगित कर दें, स्थगित कर दें। (व्यवधान) स्थगित कराकर अगली बार..। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): दूसरे प्रश्न का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जब तक वह मिलेगा नहीं, तब तक भ्रष्टाचार का पता नहीं चलेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हां, यह है, यह है प्रश्न। इसलिये इसे स्थगित किया जाए।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): तीसरा प्रश्न भी है। तीसरा प्रश्न है मेरा, तीसरे प्रश्न में जो उसका जवाब है, जी नहीं। कोई भी हैण्ड पम्प गलत स्थान पर नहीं लगाया, गलत तरीके से भुगतान नहीं उठाया है, ''उक्त कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों, द्वारा सिंगल फेज...,'' मतलब उनका बचाव किया गया है पूरी तरह से जबकि मेरे पास इतनी लम्बी फेहरिस्त है। मैंने खुद इंडिविजुअली जाकर खुद वहां पर निरीक्षण किया है, जहां पर गलत-गलत जगह हैण्ड-पम्प लगे हुए हैं और वहां पेमेंट उठाई गई है ठेकेदारों द्वारा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्य, को कोई उसमें आपत्ति हो तो कृपया उसके बारे में मुझे अवगत करायें, मैं एक-एक उसका जवाब दूंगा। उसको वे व्यक्तिश: मुझे बता दें।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): जी, मैं बिलकुल करवा दूंगी। (व्यवधान) मैं बिलकुल करा दूंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन अब हाउस की प्रापर्टी है, पूरा हाउस पूछ सकता है। यह कोई बात हुई। हमारा भी अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, हमारा भी अधिकार है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों की दादागिरी, मैं 2009 से शुरू कर रही हूं, जबकि मैंने 10-11 का विवरण मांगा था, 2009 में एक चिकित्सालय के बाहर हैण्ड पम्प लगा हुआ था। वहां पर केवल मेडिकल स्टोर था, आशीष मेडिकल स्टोर, वहां पर वह प्रभावशाली व्यक्ति था, उसने उस हैण्ड पम्प को नीचे दबा दिया, उस पर चबूतरा बना दिया। उसके बाद फिर कंटिजेंसी से एक और हैण्ड पम्प सैंक्शन हुआ। उसने अपनी करतूत छिपाने के लिये बिलकुल उसके 5 फीट की दूरी पर एक हैण्ड पम्प लगवा दिया। अब आप मुझे यह बताइये कि क्या उसकी रिकवरी निकलेगी? क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में आशीष मेडिकल स्टोर, बस्सी है, उसके सामने एक हैण्ड पम्प लगा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 से वह हैण्ड पम्प ड्राई हो गया। वह पंचायत की भूमि है।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): उसका रिकार्ड भी तो होगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आपकी अनुशंसा पर, माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा पर वहीं उसके खिलाफ एक दूसरा हैण्ड पम्प लगा दिया गया। अब माननीय अध्यक्ष महोदय उस भूमि पर जो पूर्व में...

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): 5 फीट की दूरी पर ड्राई नहीं था? 5 फीट की दूरी पर ड्राई नहीं था? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आप कृपया सुनें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जब वह ड्राई हो गया तो उसके 5 फीट पास में दूसरा हैण्ड पम्प लग ही नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो पूरा आने दीजिए।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): आप कह रहे हो ड्राई हो गया; फिर कह रहे हो, 5 फुट की दूरी पर लग गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कैसे लगेगा? अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए पूरा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं। कृपया या तो आप बोल लीजिए, या मुझे जवाब देने दीजिए। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, एक हैण्ड पम्प ड्राई हो गया, उसके बगल में दूसरा हैण्ड पम्प लग ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को अवसर दीजिए आप। मूल प्रश्नकर्ता को अवसर दीजिए।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अगर वह ड्राई हो गया था तो उसके 2 महीने बाद उसमें पानी 5 फीट पर कैसे आ गया? पहली बात। दूसरी बात यह कि उसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने भी तो अभिशंसा की बताई दूसरा लगाने की।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): कंटिंजेंसी में लगा, वह 500 मीटर दूर लगा जाकर। वह अपने स्थान पर नहीं लगा। और इन्होंने जवाब दिया, जी हां, सही जगह लगे हैं सभी हैण्ड पम्प। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 500 मीटर की दूरी पर लगा है। तो इनका जवाब जो इन्होंने गलत दिया है, जो इन्होंने बचाव किया है अपने अधिकारियों का, वह यहां पर पता चल रहा है। भ्रष्टाचार का यहां पता चल रहा है, बिलकुल क्लीयर।

दूसरा, नारदपुरा में अभी सिर्फ 15 दिन पहले ही, मैंने खुद वहां पर, वहां से मेरे पास फोन आये और सबूत के तौर पर खुद पंचायत के 15 लोगों के हस्ताक्षर जो हुए हैं, मेरे पास हैं, जिन्होंने बताया कि गलत जगह लग रहा है, आप इसे रोकें। इतने लोगों के इस पर हस्ताक्षर हैं। इन्होंने बताया और फिर जब मैंने फोन किया, एक्स.ईएन. फोन स्विच आफ रखता है। या तो उठायेगा नहीं, या स्विच-आफ रखता है। मैंने ठेकेदार से कहा, ठेकेदार ने कहा मुझे ए.ईएन. ने कहा है; ए.ईएन. से मैंने बात की, बोला, मैडम, सही जगह लग रहा है। मैंने फिर भी उसे रुकवा दिया। उसके बाद वह हैंड-पम्प शाम तक रुक गया, उसके बाद वह रात को ड्रिल हो गया। रात को ठेकेदार ड्रिल कर रहा है, आप ठेकेदार को बचा रहे हैं। यह सबूत के तौर पर मैं पेश भी कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: आप जरा इन तथ्यों की जांच करा लें।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): यह बहुत लम्बी फेहरिस्त है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है, आपने एक हैण्ड पम्प एस.सी. बस्ती के लिये स्वीकृत किया और एस.सी. बस्ती के अन्दर वहां के सम्बन्धित सभी सरपंचगण ने चिह्नित करके हैण्ड पम्प वहां उन्होंने अलोकेट किये। जब माननीय सदस्य ने आपत्ति की, उसको रोककर, उसको रोक दिया गया है। अगर अध्यक्ष महोदय

(डा. जितेन्द्र सिंह)

चाहेंगे, क्योंकि एस.सी. बस्ती से रिलेटेड मैटर है, राज्य सरकार, सुनिश्चित कार्यक्रम है कि एस.सी., एस.टी. बस्ती के जो भी हैण्ड पम्प चाहेंगी, विभाग उनको दे देगा, मैं उनको कहता हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी इर्रेगुलरिटी है...।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी प्रश्न पूछना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) श्री राधेश्याम गंगानगर।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी इर्रेगुलरिटी है तो सरकार ठेकेदारों का पक्ष नहीं लेगी, एक-एक की जांच कराएगी। यह अधिकारियों को नहीं बचाएगी।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, एस.सी. की बस्ती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस्सी का है, माननीय सदस्य, खाली बस्सी का है। (व्यवधान) खाली बस्सी क्षेत्र का है। (व्यवधान) खाली बस्सी क्षेत्र का है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): सप्लीमेंटरी क्वेश्चन तो पूछ लेने दें, साहब। (व्यवधान) आप कभी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, अगर एस.सी. का व्यक्ति प्रभावशाली है, वह पैसे वाला है तो वह अपनी मर्जी से वापस लगवा सकता है क्योंकि वह एस.सी. का है और जो गरीब है, वह रह जाएगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): प्रश्न संख्या 41, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इंदिरा गांधी नहर मंत्रीजी।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, अगर सबकी ए.सी.डी. की जांच नहीं होगी तो मैं वेल में धरने पर बैठूंगी। मेरे पास जितनी फेहरिस्त

(श्रीमती अंजू खन्गवाल)

है उसकी ए.सी.डी. जांच होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में जितना पैसा आ रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है जमके।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुनकर मंत्रीजी से निवेदन कर दिया है कि वे तथ्यों की जांच करा लेंगे।

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): वे ए.सी.डी. से जांच करवाएंगे, यह आश्वासन दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते कि किससे जांच करवानी है, क्या करानी है। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): मैं बाध्य तो नहीं कर सकती पर मैं धरने पर तो बैठ सकती हूं। धरने पर बैठ सकती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जांच करवाने तो दीजिए। अगर आपको जांच पर भरोसा नहीं हो तो फिर बाद में देखें। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): मैं आपको बाध्य नहीं कर सकती पर धरने पर बैठ सकती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज चर्चा समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी): आप जब तक मुझे आश्वासन नहीं देंगे मैं वेल में क्वेश्चन आवर के दौरान धरने पर बैठूंगी।

धरना

(माननीय सदस्या, श्रीमती अंजू खन्गवाल द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रीजी आप जवाब दीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष से कोई बात आती है तो सत्ता पक्ष को इसको फीड-बैक के नाते लेना चाहिए। इसमें सरकार हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करती है? एक आपको फीड-बैक मिला है, उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही हो। इसमें क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष, कोई अलग-अलग नहीं है। यह जन भावना आपके सामने आती है, उसमें आप इस प्रकार से टालने की कोशिश करते हैं। ठीक नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमारी एक महिला विधायक धरने पर बैठी हैं, व्यवस्था दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला विधायक धरने पर बैठी हैं, व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्या, श्रीमती अंजू खन्गवाल द्वारा सदन कूप में धरना समाप्त)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राधेश्याम गंगानगर।

इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत हेतु प्राप्त राशि

41. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद फीडर की पंजाब स्थित नहरों की मरम्मत हेतु 952 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है? यदि हां, तो कब? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने मरम्मत हेतु नहरबंदी का निर्णय किया है? यदि हां, तो कब-कब तथा किस-किस प्रकार से नहरबंदी की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नहरबंदी से कपास की फसल लम्बे समय तक नहीं हो पाएगी और बाग़ सूख जाएगा? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2012 में उक्त बजट में से किस-किस नहर के कहां-कहां मरम्मत कार्य करवाये जाएंगे तथा उक्त कार्य कब से प्रारम्भ करवा दिये जाएंगे?

राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां। इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) की री-लाइनिंग के लिए राशि 952.10 करोड़ रुपये एवं सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग के लिए 489.165 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्लानिंग कमीशन द्वारा दी गई है जिनकी छाया प्रतियां परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा री-लाइनिंग हेतु अधिकतम जन-प्रतिनिधियों की सहमति व पंजाब सरकार की मांग अनुसार दिनांक 01.04.2012 से 30.06.2012 तक क्लोजर हेतु सहमति पंजाब सरकार को भेजी है। यह सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि इस अवधि में राजस्थान को पीने हेतु 2000 क्यूसेक्स पानी सरहिन्द फीडर के माध्यम से उपलब्ध करावाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) यह सही है कि नहरबंदी के कारण कपास की फसल की बुआई प्रभावित होगी। अत: नरमे व कपास के स्थान पर ग्वार व दलहनी फसलों की बुआई कर काफी हद तक भरपाई हो सकेगी। यह निर्णय अधिकांश जन-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

प्रतिनिधियों की राय के अनुसार काश्तकारों के दीर्घकालीन हित में ही लिया गया है।

(4) 01 अप्रैल, 2012 से प्रस्तावित बंदी में सरहिन्द फीडर एवं इंदिरा गांधी फीडर की री-लाइनिंग का कार्य पंजाब द्वारा करवाया जाएगा। पंजाब सरकार से निविदाएं आदि समय पर प्राप्त कर री-लाइनिंग का कार्य समय पर करवाने हेतु आग्रह किया गया है। प्रथम वर्ष में बुर्जी 411 से 496 तक का कार्य प्रस्तावित है लेकिन पंजाब द्वारा अभी तक इस कार्य के टेंडर आमंत्रित नहीं किए हैं जिससे वर्ष 2012 में कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना कम है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पर मेरे को बड़ा तरस आ रहा है कि किस तरह का जवाब दिया है आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका सप्लीमेंटरी प्रश्न क्या है? सप्लीमेंटरी पूछें आप। पूरक प्रश्न पूछें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा प्रश्न यह था कि मेरे को जो जवाब दिया है, जवाब ही पूरा गलत है। मैंने जो क्वेश्चन किया है, ''क्या यह सही है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद फीडर की पंजाब स्थित नहरों की मरम्मत हेतु 952 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है? यदि हां, तो कब? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।'' इसका जो जवाब दिया है, वह तो बिलकुल गलत है, वह मेल ही नहीं खाता है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): प्रतियां आपको लगा दीं परिशिष्ट 'अ' और 'ब' पर। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इन्होंने कहा, जी हां, इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) की री-लाइनिंग के लिए राशि 952.10 करोड़ प्राप्त हुई; सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग के लिए 489.165 करोड़ रुपये हमें मिले हैं। प्लानिंग कमीशन द्वारा दी गई। यह जानकारी छाया प्रति, जो प्लानिंग कमीशन है, उसने स्वीकृति दी है, जबकि यहां भारत सरकार के अलावा राजस्थान सरकार का कोई पैसा नहीं लगता। बड़े लम्बे अर्से से राजस्थान के लोग रो रहे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हैं, एक। मैडम वसुन्धराजी ने एक अध्ययन दल बनाया था पिछली बार पानी की कमी रहती थी तो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है या भाषण है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पानी की बड़ी भारी कमी रही। उस समय अध्ययन दल में पूरे गंगानगर के भारतीय जनता पार्टी के लोग ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा प्रश्न तो यह है न जी कि 90 दिन की बंदी नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो आपका सुझाव है। आपका प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 90 दिन की बंदी नहीं लें।

श्री अध्यक्ष: यह तो सुझाव है। प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): प्रश्न यही है कि 90 दिन की बंदी गवर्नमेंट ले रही है, यह मुझे जवाब दिया है कि गवर्नमेंट 90 दिन की बंदी ले रही है। अगर 90 दिन की बंदी गवर्नमेंट ले लेगी तो यह जो आठ-नौ जिले हैं, वे बिलकुल बरबाद हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): प्रश्न तो ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है। प्रश्न बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्यों ले रहे हैं बंदी?

श्री अध्यक्ष: आप बैठो न। अपनी परफोर्मेंस दे रहे हैं, आपकी परफोमेंस ठीक है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बंदी नहीं ली जाए। क्यों ले रहे हैं?

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): बंदी नहीं होगी तो फिर मरम्मत कैसे होगी? 90 दिन की बंदी नहीं होगी तो फिर मरम्मत कैसे होगी?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 90 दिन की नहीं, 40 दिन की हो।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): 90 दिन में ही होगी। (व्यवधान) वहां जाकर हाथ थोड़े ही लगाना पड़ता है। 90 दिन की होगी तब ही नहर की मरम्मत होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 90 दिन की बंदी क्यों ले रहे हैं, यह मैंने सवाल किया है। अब उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मंत्रीजी, यह पूछ रहे हैं कि 90 दिन की बंदी क्यों ले रहे हैं?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मुझे भी जवाब दिला दीजिए। (व्यवधान)...

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रयत्न करके राजस्थान सरकार ने और विशेषकर मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी से बात की, पंजाब के मुख्य मंत्री से बात की और यह मंजूरी करवाई। इस हाउस में कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिसमें नहर की मरम्मत कराने की बात नहीं आई हो। पंजाब सरकार ने हमको यह सूचित किया है कि 90 दिन बिना काम किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए पहले साल 90 दिन की बंदी की बात है और आगे के तीन साल में 60-60 दिन की बंदी की बात है। उस पर भी हमने एक-तरफा निर्णय नहीं किया है। पहले गवर्नमेंट ने लिखा जो संबंधित कलक्टर थे उनको कि आप जल समितियों की मीटिंग बुलाकर इसमें कंसेंसस बनाने की कोशिश करें। वहां 40 दिन की बात आई। उसके बाद माननीय जल संसाधन मंत्रीजी की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर को एक मीटिंग जयपुर में आयोजित की गई। उसमें गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राधेश्यामजी गंगानगर उपस्थित थे; माननीय वीरेन्द्रजी बेनीवाल उसमें उपस्थित थे, माननीय विनोदजी, जो हनुमानगढ़ के माननीय सदस्य हैं; वे उसमें उपस्थित थे; माननीय छोटू सिंहजी भाटी जो बाड़मेर के माननीय सदस्य हैं, वे उसमें उपस्थित थे और कुछ किसान प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे। आदरामजी मेघवाल ने हमको बाद में लिखकर दिया। डाक्टर परम नवदीप भी उपस्थित थीं, दौलतरामजी समेजा भी उपस्थित थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपस्थित थे तो क्या कहा?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं वे। बार-बार खड़े हो जाते हो। जवाब दे रहे हैं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इनसे पूछें कि किस-किस ने सहमति दी है, किन-किन जन प्रतिनिधियों ने सहमति दी है, किन-किन जन प्रतिनिधियों ने सहमति दी है। नम्बर-एक। उन्होंने कहा कि 90 दिन की बंदी के दौरान वहां नरमा-कपास नहीं होगा ग्वार की फसल होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे इलाके में ग्वार की खेती नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 दिन की बंदी नहीं हो। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हमारी जमीन पक्की है। जिस इलाके में नरमा-कपास नहीं हो, ग्वार की फसल नहीं हो, क्या राज्य सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी? यह सदन में मंत्री महोदय बतायें।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): मरम्मत कैसे होगी 90 दिन की बंदी नहीं होगी तो?

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): मेरा प्रश्न यह है, मंत्रीजी बतायें कि बंदी होगी या नहीं? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी एम.एल.ए. ने सहमति नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): जब पंजाब सरकार ने सहमति नहीं दी है तो बंदी कैसे होगी? (व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): जवाब तो देने दीजिए। (व्यवधान)

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा कि पंजाब सरकार ने सहमति नहीं दी है। पंजाब सरकार ने सहमति नहीं दी है तो बंदी कैसे करेंगे? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी जन- प्रतिनिधि ने बंदी के लिए सहमति नहीं दी है। सत्ता पक्ष के एम.एल.ए. भी खड़े हैं और विपक्ष के भी खड़े हैं। सरकार अपनी मनमर्जी से यह चाह रही है कि... (व्यवधान) जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं के खिलाफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, फैसला किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है इलाके में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आपको जवाब नहीं सुनना? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यहां तक कि इलाके में कोई पानी के टांके नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब नहीं सुनना है? मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मंत्रीजी ने जिन-जिन लोगों का नाम लिया है, वे वहां उपस्थित थे। क्या आप इसमें यह सत्य कह रहे हैं कि किसी ने भी 'हां' भरी थी? ये हेमारामजी बैठे हैं, किसी एक भी व्यक्ति ने 'हां' भरी थी क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनेंगे क्या? मैं आगे चलूं फिर? जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मीटिंग में चाय पीने गये थे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात का जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जवाब यह है कि हमने कहा था कि 90 दिन की बंदी बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: जवाब इनका आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहर बनानी भी जरूरी है। आप 40 दिन की बंदी लेकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। इनको आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हो। जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दुग्गल साहब, डाक्टर परम नवदीप... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब देने के लिए खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सदस्यों ने, माननीय दुग्गल साहब ने, डाक्टर परम नवदीप ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): और माननीय दौलतराजजी ने, माननीय पवन दुग्गलजी ने कहा कि 40 दिन बंदी होनी चाहिए। सात सदस्य ने यह कहा कि नहर की मरम्मत होना जरूरी है, अगर 90 दिन हो तो 90 दिन, 84 दिन हो तो 84 दिन। गंगाजलजी मील ने यह कहा, जयदीपजी डूडी ने यह कहा, वीरेन्द्रजी बेनीवाल ने यह कहा, विनोदजी साहब ने यह कहा। सात सदस्यों ने यह कहा कि अगर 90 दिन बंदी देनी है तो जरूरी है। हमने मीटिंग की प्रोसीडिंग्स माननीय सदस्यों को भेजी है, मेरे पास भी है, उसमें आप कोंट्राडिक्ट कर दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अब मैं पूछूं, साहब?

श्री अध्यक्ष: समाप्त हो गयी बात। अंकित नहीं हो। (हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने यह कहा है, इसमें आपने सहमति दी है, वह उन्होंने बता दिया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप तो जबरदस्ती खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। बोलने दीजिये इनको।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के किसानों के और राजस्थान के आमजन के हितों का मामला है। नहर की स्थिति, क्योंकि कई जगह खराब है, हम इस पर पीने के पानी के लिये निर्भर हैं, हम इससे उद्योगों को भी पानी देते हैं और पानी की डिमाण्ड आती जा रही है। 40 दिन की बंदी अगर ली जाती है तो 20 दिन तो उसको सूखने में ही लग जायेंगे। हमको भारत सरकार ने यह कहा है कि 2014 तक इसकी मरम्मत हो जानी चाहिये। अगर 40 दिन की बंदी लेते हैं तो वह आठ साल तक उसका काम चलेगा। और पंजाब गवर्नमेंट को जो कार्य करना है, वह कह रही है कि 90 दिन की बंदी के बिना

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। हमने 90 दिन की सहमति भिजवा दी। उसके बाद भी पंजाब गवर्नमेंट ने उसके टेण्डर फ्लोट नहीं किये हैं। वहां आपकी सरकार है, आप सहयोग करो और करवाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको बोलने की परमिशन नहीं दी, फिर भी आप बोल रहे हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह भाषण का अवसर नहीं है। माननीय सदस्य, आप दूसरे तरीके से भाषण देने के लिये इश्यू को उठा सकते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित ही नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

मनरेगा कार्यों में प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच

42. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नरेगा कार्यक्रम की क्रियान्विति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितने अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिकारियों के द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि की अनियमितताएं की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना मंत्री) (श्री महेन्द्रजीत सिंह): (1) नरेगा कार्यक्रम की क्रियान्विति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताएं पाई गई हैं। पाई गई अनियमितताओं का विवरण निम्नानुसार है:-

- कम्प्यूटर एवं प्रिंटर डी.जी.एस. एंड डी. दर संविदा में अनुमोदित निर्माता कम्पनी/अधिकृत दर संविदाधारक के स्थान पर कम्पनी के डीलर से क्रय।
- क्रय किये गये सामान का निरीक्षण डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा निर्धारित अधिकारी/संस्था द्वारा नहीं किया जाना।
- पर्याप्त समय होने के बावजूद अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण।
- न्यूनतम निविदादाता के द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में सप्लाई करने से इंकार करने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से नेगोशिएशन कर निविदा स्वीकृत करना एवं न्यूनतम निविदादाता की धरोहर राशि जब्त नहीं करना।
- न्यूनतम निविदादाता की दर की अपेक्षा द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की अधिक दरें स्वीकृत करना।

(2) प्रश्नगत अधिकारियों को भविष्य में वित्त संबंधी प्रकरणों में अधिक चौकसी बरतने, क्रय प्रकरणों में अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों पर पूर्णत: निर्भरता के स्थान पर अपने स्वयं के स्तर पर अधिक सावधानी बरतने, वित्त संबंधी प्रकरणों में संदेह होने पर राज्य सरकार से मार्ग-दर्शन लेने, क्रय संबंधी प्रकरणों में जल्दबाजी नहीं करने हेतु हिदायत दी गई।

(3) प्रकरणवार अनियमितताओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, अनियमितता का पता सबसे पहले आपको कब लगा? क्या आयुक्त सामाजिक अंकेक्षण, महालेखाकार नरेगा, नम्बर दो, संयुक्त निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण; नम्बर तीन, आयुक्त नरेगा; और नम्बर चार, मंत्री, पंचायती राज एवं विकास विभाग ने अपनी कुछ जांच के आधार पर इन पांच अधिकारियों को दोषी पाया? जिसमें जिला कलक्टर, डूंगरपुर, श्रीमती आरूषी ए. मलिक, इसने 85 लाख रुपये का तत्कालीन नरेगा से जो खरीदा, उस समय आयुक्त ने अपनी उस फाइंडिंग में लिखा था, यह मैंने सब सूचना-के-अधिकार के तहत ले रखे हैं, इन्हें सस्पेंड करें, परन्तु आज दिन तक नहीं किया।

नम्बर दो, नीरज के. पवन, उसके विरुद्ध नियमानुसार पंचायतों के लिये लैपटाप खरीदने का इसने आदेश दिया, लेकिन फिर बाद में मामला उठने के बाद उसने खरीदना बंद करके जो पौधे खरीदे, एक पौधे की कीमत 9.90 पैसा आई। उसको उसने बैक-आउट किया और 38 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से 51 लाख रुपये के पौधे लिये। तीसरा, जोगाराम, जिला कलक्टर, दौसा ने लगभग एक करोड़ 44 लाख रुपये का सामान बिना किसी तरह की पूर्ति किये हुए खरीदा। सुबीर कुमार ने एक करोड़ 40 लाख 98 हजार रुपये के कम्प्यूटर बिना किसी प्रकार की निविदाओं के खरीदे। श्री नवीन जैन ने भी 89 लाख रुपये के कम्प्यूटर बिना किसी स्वीकृति के खरीदे। आपने अपने सवाल के जवाब में इन सब बातों को माना है।

इसमें आप देखिये कि जो आपकी जांच रिपोर्ट है, जो मैंने सूचना-के-अधिकार के तहत ली है। मैं केवल इसमें कुछ बातें पढ़ता हूं। आज सौभाग्य है, सदन के नेता यहां मौजूद हैं, 25 मार्च, 2010 को यह स्थगन के माध्यम से आया था और आपने उसमें जांच का आश्वासन दिया था। इसमें करौली के मामले में लिखा है, जिस कम्पनी ने न्यूनतम दर पर अपनी असमर्थता जताई 9 रुपये 90 पैसे में, पहले वाले ने, यह कहकर कि मैं यह सप्लाई नहीं कर सकता हूं, उसके स्थान पर 38 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से 51 लाख के पौधे खरीदे और यह जांच रिपोर्ट में आ रहा है कि इसमें से किसी भी पौधे का पता नहीं लगता है कि कहां है। इसमें मंत्री महोदय ने स्वयं ने, मैं धन्यवाद देता हूं, भरत सिंहजी, कि अभी भी इस हिन्दुस्तान में ईमानदारी बची हुई है, कुछ करेक्टर बचा हुआ है, आपको धन्यवाद इस बात के लिये। मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कर रहे हो कि धन्यवाद में उलझ गये? प्रश्न पूछ रहे हो कि धन्यवाद में उलझ गये?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपको यह कह रहा हूं कि... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर किसी एक मंत्री की तारीफ की जाती है तो, साहब, आसन को तो हमें और प्रोत्साहित करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न तो पूछो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने नरेगा से संबंधित अपनी फाइल पर लिखा है कि गम्भीर शिकायतों में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : यह किसने लिखा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह भरत सिंहजी ने लिखा है अपने हाथ से कि कार्यवाही किया जाना उचित है। नरेगा का सर्वोच्च अधिकारी कलक्टर है और सारी खरीद कलक्टर के स्तर पर हुई है। इस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इस जांच के आधार पर प्रमुख शासन सचिव सी एस राजन ने 23.03.2010 को जोगाराम को लिखा है कि ''महानरेगा में कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, शिशु पालना एवं अन्य सामग्री क्रय में की गई अनियमितताओं के क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु। उपरोक्त विषय के अन्तर्गत आपके जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महानरेगा, दौसा के पद पर प्रस्तावित अवधि में जिला परिषद, दौसा के द्वारा महानरेगा योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, शिशु पालना व अन्य सामग्री की जांच में क्रय कार्यवाही की अनियमितता पायी गयी। जांच प्रतिवेदन में अनियमितताओं के लिए आपको उत्तरदायी माना है। जांच की प्रति संलग्न है। अत: जांच प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को सात दिन में पेश करें।'' ऐसे नोटिस सी एस राजन ने पांचों कलक्टर्स को दिये हैं।

इस प्रकरण को मैंने विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से 25.03.2010 को रखा। मुझे आज कहते हुए बड़ा अफसोस है कि आप जिस करेक्टर के आदमी हो और जिस गांधीवादी की बात करते हो, आपने इस हाउस में एश्यारेंस दिया था कि इसकी मैं हाइएस्ट लेवल पर जांच करवाऊंगा। आपने जांच की कमेटी ऐसी बनायी कि तीन करोड़ उन्यासी लाख रुपये का गबन करने वाले पांचों कलक्टर्स को आपने केवल वार्निंग देकर मुक्त कर दिया। यह जांच है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक कांस्टेबल गाड़ी का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चालान बनाते समय यदि सौ रुपया ले ले तो उसको आप नौकरी से निकाल कर उसके बच्चों को महरूम कर सकते हो, पर चूंकि जांच करने वाले आई ए एस, और दण्ड पाने वाले भी आई ए एस, इसके कारण से सारे केस को रफा-दफा कर दिया। अगर आपके मन में ईमान हो और अगर मन में कोई भरोसा हो तो इस देश के लोकतंत्र का...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं धन्यवाद देता हूं, मंत्रीजी ने निर्देश प्रदान किये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पांच करोड़ रुपये का गबन कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): टोंक जिले का विधान सभा में प्रश्न लगा हुआ है। (व्यवधान) इसके साथ ही जवाब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को पहले प्राथमिकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सदन की समिति जांच करे, नहीं तो अध्यक्ष करें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित निदेशक इन तीनों जिलों में गये। सरकार स्वयं आगे होकर इन तीन जिलों में गयी है जिसके कारण से यह बात हमारे सामने आयी। कुछ अनियमितताएं और त्रुटियां हुई हैं और उसी आधार पर आगे इसकी कार्यवाही हुई है। डूंगरपुर से एक शिकायत मिली। जिस कम्पनी को वह आदेश दिया गया, उसके बारे में बाद में जाकर ज्ञात हुआ कि यह आदेश गलत हो गया है। उस आदेश की शंका पर खुद मैसर्स डोबीर इंस्टिट्यूट की शिकायत में आया कि मुझे भुगतान नहीं हो रहा है। उससे एक बात का पता लग गया।

दूसरा करौली जिले का मामला है। वहां पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय बना हुआ है और वह समय-समय पर जिलों व क्षेत्रों में जाकर इस तरह की शिकायतों की जानकारी करता है। जब यह जानकारी में आया तो सी एस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें वित्त सचिव और प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज के द्वारा उच्च

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

स्तरीय जांच हुई। उस जांच में त्रुटिपूर्ण बात सामने आयी है। उसका तमाम अध्ययन करने के बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डी ओ पी सेक्रेटरी ने तमाम कलक्टर्स को हिदायत दी है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह सारी सूचना सूचना-के-अधिकार के कारण से मैं इन सब डाक्यूमेंट्स को ले पाया और हर डाक्यूमेंट में है कि किस तरह से जांच हुई है, किसने जांच की है, उसमें जो दोषी हैं, उन सबका, एक-एक का है। हनुमानगढ़ की है। करौली वाले का तो कमाल ही है कि 38 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से 51 लाख के पौधे खरीद लिये और आपने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया! धन्य हो आप! जहां तीन करोड़ उन्यासी लाख के कम्प्यूटर, आपके निर्देश हैं, निदेशक के नार्म्स के अनुसार ही आप कम्प्यूटर खरीदेंगे। करौली वाले ने तो लैपटाप खरीद लिए। गांव में लैपटाप कौन चलायेगा? जब हल्ला हुआ तो बरी हो गये।

श्री अध्यक्ष: तकनीक आगे बढ़ गयी। तकनीक लैपटाप तक आ गयी और अब उससे छोटा भी आ जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हां, वह भी आ जायेगा। इसमें यह लिखा है कि जिन पंचायतों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो, जिनमें कमरों की व्यवस्था नहीं हो, वहां ये नहीं खरीदे जाएं। ऐसा निर्देशों में है। ये सब इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दे रखे हैं उनको, किस तरीके से खरीदने हैं, किस सिस्टम से खरीदने हैं लेकिन सबने अपने-अपने, नरेगा का पैसा है, उस गरीब का मेहनत का पैसा है जिसको कलक्टर और आप दोनों मिलकर जैसे चाहो, उसे लुटाओ; जैसे चाहो, उसको आप खाओ। प्रश्न के जवाब में जब यह मान लिया कि वे दोषी हैं तो इतने बड़े दोष के लिए क्या इतने बड़े अधिकारियों को वार्निंग देना ही पर्याप्त है? या उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने की कार्यवाही का आपका मन है? बताइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रुपये वसूल करने के आदेश दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। कर्नल सोना रामजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अधिकारी दोषी है और भ्रष्टाचार है तो कार्यवाही होनी चाहिए परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ जन-प्रतिनिधि भी इन्वाल्व हैं, भ्रष्ट हैं और अफसोस है कि कुछ केसेज के अन्दर हम जन-प्रतिनिधियों का भी बचाव करते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा प्रश्न यह है कि बायतू विधान सभा क्षेत्र में एक सिंगूनिया पंचायत है, उसके अन्दर सरपंच है, वह अभी भी जन-प्रतिनिधि ही है। वहां करोड़ों का भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सम्बन्ध कैसे नहीं है, साहब? यह भ्रष्टाचार का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए। कटारिया साहब का जवाब दीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जन लेखा समिति में भी हम जांच रिपोर्ट सरकार को दे देते हैं, कुछ नहीं होता। तो आई ए एस अधिकारियों की समिति द्वारा... (व्यवधान) कुछ नहीं होता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर प्रजातंत्र की प्रणाली को मजबूत करना है तो उसमें कुछ करना होगा, तब दुनिया मानेगी। वरना यह लूट होती रहेगी। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, आप मुझे समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इससे संबंधित प्रश्न नहीं है आपका।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, इससे संबंधित मेरा है। टोंक जिले के अन्दर ...(व्यवधान)... उत्तर दिया गया है। टोंक जिले के अन्दर एक लाख छियासी हजार छह सौ पौधे लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संबंधित था मामला।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को, आपके दल के उप नेता, घनश्यामजी को मैंने निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा):×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं, उप नेता प्रश्न कर रहे हैं। कृपया विराजें आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, भाई। एक मिनट, एक मिनट।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो उठा लेना आप। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न उस बात से सम्बन्धित नहीं है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक प्रश्न उठा था, मंत्री महोदय ने जवाब दिया था, आपने फाइल मंगायी और फाइल मंगाने के बाद में आपके निर्देश के आधार पर यह कार्यवाही हुई थी। इस कार्यवाही के बाद सभी लोगों को, इस कमेटी में सब को दोषी पाया गया।

यह एक मामूली काम नहीं है। केवल सामान्य रूप से मुख्य सचिव महोदय ने सब को वार्निंग देकर छोड़ दिया कि आपकी गलती है, आपने यह काम गलत किया, आपने यह काम गलत किया है, आपको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में आप यह काम नहीं करेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल चेतावनी का मामला नहीं है। इस सारे मामले को या तो सरकार खड़े होकर कहे कि एफ.आई.आर. दर्ज करा रहे हैं, नहीं तो आप सदन की समिति बनाइये और सदन की समिति से इसकी जांच कराइये। यह एक पब्लिक का धन, पैसा न नेताओं को खाने का अधिकार है, ना अधिकारियों को खाने का अधिकार है। यह नरेगा का पैसा गरीब आदमी का पैसा है। कोई कितना बड़ा अफसर हो, उसको भी इसका जवाब देना पड़ेगा और कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, उसको भी जवाब देना पड़ेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जब तक सदन की समिति नहीं बनती इस मामले में या सारे के सारे मामले को एफ.आई.आर. दर्ज करके ए.सी.बी. में नहीं दे देते, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह करना पड़ेगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरे बायतू के अन्दर ...(व्यवधान) एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी गलतियों पर इनको सज़ा मिलने की अपेक्षा इन सब को प्राइम पोस्टिंग दी है इन्होंने। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उसको रोका जा रहा है। (व्यवधान) एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बोलने दो, +++, एक मिनट बैठ तो जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय के ऊपर मुख्य सचिव हो गया। सदन के नेता बैठे हुए हैं ...(व्यवधान) इस राजस्थान में नौकरशाही कितनी हावी है। मंत्री लिखते हैं कि अफसरों पर कार्यवाही होनी चाहिए और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी ...(व्यवधान) छोड़ देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। (व्यवधान) मंत्री लिखते हैं (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, हमारे टोंक जिले में...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर सदस्य हैं, इतने लोग एक साथ बोलेंगे, व्यवधान पैदा करेंगे तो क्या अंकित कराऊंगा मैं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति, कृपया शांति। माननीय विपक्ष की नेता।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आपको पारदर्शी सरकार कहती है। आपके चीफ सैक्रेटरी की कमेटी ने बैठ कर इसके पूरे प्रकरण की जांच की है, जांच करने के बाद ये सब दोषी पाये गये हैं। ये सब फैक्ट्स हैं। वह सब करने के बाद उनको वार्निंग देकर इतने सीरियस मैटर पर खाली लेट-आफ कर दिया जायेगा तो इसका मेसेज पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर क्या जा रहा है? आप बहुत इसके ऊपर ध्यान देते हैं। आप लोग चला-चला कर, जहां भी आपने देखा, आप कहते हो कि हमारा मैसेजिंग सही होना चाहिए, सही तरीके से जनता की ओर यह बात पहुंचनी चाहिए कि जहां किसी ने कोई गलती की है, उसको हम तुरन्त ही पकड़ेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। परन्तु इतनी बड़ी गलती हो, पांच-पांच लोग इन्डाइक्ट हों, पांच-पांच लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, तो मैं समझती हूं कि सदन के नेता को इसके ऊपर तो बहुत बड़े और गम्भीरतापूर्वक गहन विचार करना चाहिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरी प्रेयर है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदन के नेता जवाब दे रहे हैं, विराजिये आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने जो क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब, प्रत्युत्तर पूरा दिया गया। यह कोई जो जांच की गयी है, मैंने, जो आपने कहा, सदन में यह बात कही थी कि हाइएस्ट लेवल पर जांच करवायेंगे। चीफ सैक्रेटरी से जांच करवाने के मायने क्या होते हैं? यही मायने होते हैं, हाइएस्ट लेवल पर उसकी जांच की गयी। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद में ये पाया गया कि प्रकरण में त्रुटि हुई है, प्रोसीजर की त्रुटि हुई है, प्रक्रिया की त्रुटि हुई है, कोई खुला गबन नहीं हुआ है। नम्बर वन। (व्यवधान) सुनिये आप, सुनिये।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, जवाब आने दीजिए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कोई गबन नहीं हुआ है और प्रक्रिया की गलती होने के बाद में उनको हिदायत देकर उनको छोड़ा गया। नम्बर दो।

उसके बाद में विभिन्न स्तरों पर जो ये अनियमितताएं हुई हैं, अनियमितताएं तो हुई हैं, यह तो सदन में स्वीकार किया है, माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, उसके ऊपर अतिरिक्त आयुक्त जो हैं प्रथम, वे उसकी और जांच कर रहे हैं।

जहां तक पांच कलक्टरों के बारे में जो कहा गया है, जो उत्तर अभी दिया गया है, उसमें तमाम बातें स्पष्ट कर दी गयी हैं। यह कोई कलक्टर ने खुद गबन कर लिया हो और वह सिद्ध हो गया हो और सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है तो आप कह सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कैसे बचा सकते हो? ...(व्यवधान) आप नहीं बचा सकते, मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नो। ऐसे नहीं बचा सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये पूरा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्लीयर कैसे कर देंगे आज? (व्यवधान) आज मुख्य मंत्रीजी बरी कर रहे हैं उनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनिये। पूरा जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुनियेगा, माननीय सदस्य जो सांगानेर से आने वाले हैं, जब जांच कर ली गयी चीफ सैक्रेटरी के द्वारा, उसके

(श्री अशोक गहलोत)

बाद में मैं कह रहा हूं यह बात आपको। समझना पड़ेगा आपको। खाली आपके यह जोर से बोलने से, हो-हल्ला करने से काम चलने वला नहीं होता है। आप बात सुनिये पहले। जब मैं यह कह रहा हूं तो सोच-समझकर के कह रहा हूं मैं आपको कि कोई तरह का गबन नहीं पाया गया। जांच पूरी की गयी है। और गबन पाया जाता तो चाहे वह कलक्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई अधिकारी होता, उनके खिलाफ एक्शन होता। यह आप इसका पूरा आन्सर पढ़िये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): विराजिये, मैं बोल रहा हूं, अगर पूरा आन्सर पढ़ेंगे, पढ़ा अभी आपने, उसमें साफ लिखा गया है, अनियमितताएं पाई गई हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह क्या होती है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इर्रेगुलरिटी होती है। यह मुझे समझाना पड़ेगा आपको, इतने सीनियर मेम्बर हैं आप, मुझे समझाने की आवश्यकता है क्या कि इर्रेगुलरिटी में और स्कैण्डल में और करप्शन में क्या फर्क है? मुझे समझाना पड़ेगा आपको? कृपा करके, आप इसको जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।

जो पेमेंट भी हुआ, उसके बाद पेमेंट भी पूरी प्रक्रिया, उसका भौतिक सत्यापन, स्पेसिफिकेशन की जांच करने के बाद भुगतान हुआ है। इसलिए खाली पांच कलक्टर, पांच कलक्टर हम कहने लग जायें, हमारे तत्कालीन मंत्रीजी ने, मान लीजिये, हाउस में कहा कि कलक्टरों की इर्रेगुलरिटी सामने आ रही है, गबन के आरोप लग रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि उनके आरोपों का हम स्पष्टीकरण दें। सदन का अधिकार है मांगने का और सरकार का अधिकार है पूरी जांच करवा कर बताने का। बताने के बाद आप ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं जैसे यह बहुत बड़ा करप्शन हो गया है, स्कैण्डल हो गया करोड़ों रुपये का और सरकार उनको बचा रही है।

मैं अब यह भी कहना चाहूंगा, मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जब यह कहा, पांच साल आप भी राज में रहे हो, कितने आरोप लगे हुए हैं आपके ऊपर, आज तक उनका जवाब आप दे नहीं पाये हो। (व्यवधान) किस मुंह से आप ये बातें बोल रहे हो? आपने खुद ने कितने करप्शन किये हैं, कितने स्कैण्डल हुए हैं (व्यवधान) कितने आरोप लगे हैं...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई स्कैण्डल हुए हैं...(व्यवधान) उनका जवाब आप लोग नहीं दे पाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (इशारे से मना किया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपके मुंह से शोभा नहीं देता यह कि करप्शन की बात आप करो हमारे कलक्टर की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता...(व्यवधान) सदन के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने एक बहुत गम्भीर आरोप लगाया है और डायरेक्टली मुझ पर और मेरी सरकार के ऊपर लगाने की बात कही है। मैं कहती हूं कि इसको तो तुरन्त ही एक्सपंज कर दिया जाय और उनसे माफी मंगवाई जाय कि हाउस के अन्दर इस तरह से आरोप लगावें वो ...(व्यवधान) फिर माथुर आयोग ने पूरी जांच कर ली....(व्यवधान)

सदन कूप में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.57 बजे 12.57 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.57 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, आज सदन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। एक इश्यू को बड़े विस्तार से माननीय सदस्यों ने प्रश्न काल के समय यहां प्रस्तुत किया था, और अध्यक्ष महोदय उम्मीद तो हमें यह थी कि सदन के नेता इन दोषी कलक्टर्स के विरुद्ध कोई गम्भीर कार्यवाही करके सदन को आश्वस्त करेंगे परन्तु आश्चर्य यह है कि ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यदि आप उनको दोषी मानते हैं...(व्यवधान) आप अगर उनको दोषी मानते हैं... (व्यवधान) आप अगर उनको दोषी मानते हो...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कोई दोष ही नहीं है। (व्यवधान) ये नहीं हैं दोषी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप अगर उनको दोषी मानते हैं तो...(व्यवधान) अदालत का दरवाजा आपके लिये खुला हुआ है। (व्यवधान) आप दोषी मानते हैं तो आप कार्यवाही करवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आरोप लगाये...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात नहीं है कि पिछले तीन साल से सैकड़ों...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है जिसमें उन्होंने प्रक्रिया का दोषी माना है...(व्यवधान) फिर भी आप अगर उनको दोषी मानते हैं...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप उनके आरोपों से भागना चाहते हैं...(व्यवधान) बोलना नहीं चाह रहे...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बांसवाड़ा के कलक्टर पर यह आरोप लगा था कि...(व्यवधान) खरीद में पैसे खाये हैं तो आपने 15 दिन के लिये हटा करके...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): माथुर आयोग बनाया और खंगाल-खंगाल कर...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): और आप पर तो खूब आरोप लगे हैं...(व्यवधान) आप पर तो बात-बात पर सदन में खूब आरोप लगे...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस तरीके से आरोप आप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भैरोंसिंह जी शेखावत संसार में नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर भी हम कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप सदन के नेता के लिये कह रही हैं जिसका पूरा दामन स्वच्छ रहा है...(व्यवधान) जिसने स्वच्छ राजनीति की है...(व्यवधान) अशोकजी गहलोत के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा सका..(व्यवधान) मुख्य मंत्री पर आरोप लगाये हैं ...(व्यवधान) आप सदन से माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सदन के नेता को ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन के नेता से जाकर के माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): 4 करोड़ का घोटाला...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): पिछले चुनाव में (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): वह ललित मोदी कहां है? (व्यवधान) वह ललित मोदी कहां है? (व्यवधान) करोड़ों रुपयों की संपत्ति कहां से आयी? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ समझा हूं ...(व्यवधान) अगर किसी मंत्री को ...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं। (व्यवधान)

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्री के ऊपर चीफ सैक्रेटरी भी नहीं होता है। मंत्री के ऊपर चीफ सैक्रेटरी नहीं होता है। अगर इस फाइल पर यही बात कहनी है तो मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 1 मार्च, 2012 को शून्य काल में बोलने हेतु 21 पर्चियां प्राप्त हुईं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जब कोई गलती नहीं है ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.01 बजे 14.01 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(14.01 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

जेठमल बरवड़, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जेठमल बरवड़ के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री जेठमल बरवड़ का जन्म 17 जनवरी, 1927 को नागौर में हुआ। आप हिन्दी तथा अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान रखते थे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री जेठमल बरवड़ दूसरी, तीसरी, पांचवीं से सातवीं विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। श्री बरवड़ दूसरी विधान सभा में नावां तथा तीसरी एवं पांचवीं एवं सातवीं विधान सभा में परबतसर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति तथा खाद्य एवं आपूर्ति, गृह रक्षा दल, नागरिक सुरक्षा व देवस्थान विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति भी रहे।

श्री बरवड़ अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1955 से 1956 तक मकराना नगरपालिका के सदस्य रहे। आप श्री तेजाजी पशु मेला, परबतसर, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति एवं कारागृह सलाहकार समिति, नागौर के सदस्य रहे। श्री बरवड़ लगभग दो वर्ष तक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल कोष समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1980 से 1981 तक राजस्थान भूमि विकास बैंक, नागौर के अध्यक्ष रहे। श्री बरवड़ जिला कांग्रेस कमेटी, नागौर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री जेठमल बरवड़ का दिनांक 27 जनवरी, 2012 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री जेठमल बरवड़ के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिपक्ष के नेता द्वारा सदन पटल पर रखे बयान को रिकार्ड पर लिया जाना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी सदन के अन्दर प्रतिपक्ष के नेता ने आपकी अनुमति से अपनी बात रखी थी। कुछ बातें सदन के पटल पर आ गईं और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
कुछ बातें सदन के शोरगुल से सुनी नहीं गईं और उन्होंने अपना लिखा हुआ वक्तव्य आपकी अनुमति से टेबल कर दिया। मेरी विनती सिर्फ इतनी सी...

श्री अध्यक्ष: अब आप छोड़िए, सारी बात हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उसको रिकार्ड पर ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सारी बात हो चुकी है, सारा मामला निपट गया। दोनों पक्षों ने बैठकर सदन को चलाने की बात कर ली तो इसको क्यों कुरेद रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उसको रिकार्ड पर, मैं तो आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों कुरेद रहे हो इसको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रिकार्ड पर ले लें।

श्री अध्यक्ष: सारी बात जब हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रिकार्ड पर ले लें उसको।

श्री अध्यक्ष: आप स्वयं उपस्थित थे, सारी बात दोनों पक्षों में बैठकर हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रिकार्ड पर तो आ गई न?

श्री अध्यक्ष: उसके बाद नई चीजें कुरेद कर क्यों व्यवधान पैदा करना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी ही है कि वह रिकार्ड पर आ गई न वह बात? अगर रिकार्ड पर आ गई तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: यदि आप नहीं चाहते हैं कि सदन चले,...बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चाहिए क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: बैठिए, आगे का काम चलाने दीजिए, सदन का काम चलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो बैठ जाऊंगा पर रिकार्ड पर आ तो गया न? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अधिसूचना। श्री हेमाराम चौधरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(7)राज-6/1995/24 दिनांक 27.9.2011 जिसके द्वारा प्रशासनिक सेवा के कतिपय परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(7)राज-6/1995/25 दिनांक 27.9.2011 जिसके द्वारा प्रशासनिक सेवा के कतिपय परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(48)राज/2001/पार्ट/26 दिनांक 5.10.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (राजस्व मंडल के अध्यक्ष, सदस्यों की योग्यता एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)राज-6/2004/28 दिनांक 13.10.2011 जिसके द्वारा श्री चन्दन यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव, ग्राम पो. बेरू, तहसील नगर, जिला भरतपुर को नगर जिला भरतपुर हेतु भू-आबंटन सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(24)राज-6/2001/पार्ट/29 दिनांक 9.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सेलाइन क्षेत्र में भू-आबंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(7)राज-6/1995/31 दिनांक 22.11.2011 जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक प्रशासनिक सेवा के कतिपय प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.9(79)राज-6/2011/32 दिनांक 1.12.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आबंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/33 दिनांक 27.12.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

(श्री हेमाराम चौधरी)

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(79)राज-6/2011/1 दिनांक 3.1.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आबंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/4 दिनांक 16.1.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किये गये हैं;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/2006/5 दिनांक 17.1.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.9(22)राज-6/2002/पार्ट/6 दिनांक 2.2.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाघर तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आबंटन, परिवर्तन तथा नियमन) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

याचिका

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

सूरसागर के श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन

1. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करती हूं।

सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सार्वजनिक पार्कों का जीर्णोद्धार

2. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अस्तित्व खोते सार्वजनिक पार्कों के जीर्णोद्धार बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली (अनुपस्थित)। श्री कैलाश चन्द भंसाली, नहीं है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद। श्री शांती धारीवाल।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के मध्य मंत्री के वक्तव्य की औचित्यता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर वाद विवाद में माननीय मंत्रीजी एक वक्ता के रूप में या अभिभाषण के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार के कई प्रश्न हमेशा आए हैं। उनमें अध्यक्षों ने यही निर्णय दिया है कि माननीय मंत्री बहस में हस्तक्षेप कर सकते हैं, बहस में वक्ता के रूप में सम्मिलित नहीं हो सकते इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि पुराने अध्यक्षों की परम्पराओं के अनुसार इनको आप हस्तक्षेप करने के लिए कहें और हस्तक्षेप और वक्ता में अंतर बिलकुल स्पष्ट है। हस्तक्षेप का मतलब है कुछ बातें जो सदन में आ गई हों, उनका स्पष्टीकरण अगर करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन एक वक्ता के रूप में उसमें मंत्री शामिल नहीं हो सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे सुनने के बाद आप तय करना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 290 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 290 में लिखा है, लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकता है; मतलब एक विषय पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहजा फरमायें, सिर्फ एक विषय पर; ऐसा नहीं कि भाषण दे सकता है। कोई ऐसी पाइण्टेड बात हो जिसकी रिप्लाई वह कर सकता है, आपकी अनुमति से कर सकता है। वरना, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा दर्जन अध्यक्षीय फैसले जिसमें मंत्री सदन के अन्दर भाषण नहीं दे सकता, आधा दर्जन से ज्यादा हैं अध्यक्षीय फैसले। इसलिए नई परम्परा काहे को डालें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब कुछ शांति से चल रहा है और यह शांतिजी का नाम अशांतिजी है या अशांति धारीवाल है, फिर अशांति पैदा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप डर रहे हो क्या? इनकी बात से डर रहे हो क्या?

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे भी कोई वक्ता नहीं हूं और जहां तक हस्तक्षेप का सवाल है, चूंकि मैं मंत्रिमण्डल का सदस्य हूं, कई बातें हैं, राठौड़ साहब, आप थोड़ा तसल्ली रखो। कई बातें इस प्रकार की होती हैं जिनका स्पष्टीकरण मान लीजिए या मेरे मानस में कोई इस प्रकार की बात आई है, उस बारे में मैं अपने सुझाव देकर दुरुस्त करवाना चाहता हूं। तो बोलने का अधिकार मुझे है। सवाल यह है कि जो कुछ मैं बोलूंगा, उसको बोलने के बाद ही आप तय कर लेना कि मैं वक्ता के रूप में बोल रहा हूं या हस्तक्षेप के रूप में बोल रहा हूं और जब बोलने लगते हैं तो कुछ न कुछ बात इधर-उधर 19-20 होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ईमानदारी के साथ यह मंशा है कि यह हाउस चले और किसी भी प्रकार का कोई विवाद यहां पर पैदा न हो।

(14.13 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार द्वारा जो जनकल्याणकारी नीतियां चलायी गयी हैं, उनके बारे में जो सरकारी प्रयत्न हो रहे हैं और जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीगण हैं, उनकी सफल क्रियान्विति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं यह समझता हूं, पूरे प्रदेश की जनता उसको अच्छी तरह से जानती है। प्रतिपक्ष के द्वारा इन कार्यों को करवाने के लिए यहां पर वकत-वक्त पर वक्ताओं ने जो बात उठायी, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, कल पहलवान साहब का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि केकड़ी से लेकर वहां तक एक सड़क बनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार से कइयों ने मांग की। (व्यवधान) बिलकुल सही था। आप कभी गलती करते ही नहीं हो। बात भी सही है प्रतिपक्ष के सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मांगा किससे जाय; मांगा उसी से जाय जो दे सकता हो। कांग्रेस सरकार के प्रति आम जनता में यह विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार से कोई चीज मांगी जाय तो यह जन हित में है और उसे दी जाएगी।

इसी के साथ-साथ प्रतिपक्ष के नेताओं ने अपना धर्म निभाते हुए कुछ आलोचनाएं भी कीं। आलोचना करना निश्चित तौर पर उनका कर्तव्य भी बनता है। एक कवि ने कहा है ''जो फल देते हैं औरों को, उन्हीं का यह मुकद्दर है।'' जो फल देते हैं औरत को.... (व्यवधान) औरों को...(व्यवधान) तिवाड़ी साहब जानते हैं, उम्र 68 साल की हो गई। ''जो फल देते हैं औरों को'' ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नगर निगम की महापौर ने जो आपके बारे में कहा कि आपकी जबान फिसल जाती है, वही हो रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ''जो फल देते हैं औरों को, उन्हीं का यह मुकद्दर है और जो सूखे पेड़ होते हैं, उन्हें कभी पत्थर नहीं लगता।''

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं राव साहब का पूरा वक्तव्य सुन नहीं पाया था और न मैंने तिवाड़ी साहब का वक्तव्य सुना, लेकिन दो-चार बातें जो निगाह में आयीं, एक राव साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 153 में राज्यपाल होगा और 159 में राज्यपाल शपथ लेगा। 153 में यह प्रोविजन है कि राज्यपाल एक ही जगह का नहीं, दो जगह का भी हो सकता है। उसमें कहीं मना नहीं है। इस प्रकार के दसों एग्जाम्पल इसी राजस्थान की धरती के हैं। 1991 को ले लें, 1993 को ले लें, 2003 को ले लें, 2007 को ले लें, 2009 को ले लें, चाहे स्वरूप सिंहजी थे; गुजरात के राज्यपाल थे, धनिक लाल मण्डल थे; हरियाणा के राज्यपाल थे, वे भी राजस्थान के कार्यपालक राज्यपाल रहे; कैलाशपति मिश्र थे; गुजरात के थे; राजेश्वर राव थे, वे राज्यपाल उत्तर प्रदेश के थे। किदवई थे, प्रभा रावजी थीं, वगैरह, वगैरह। जो भी दूसरे राज्य के राज्यपाल थे, उन्हें राजस्थान राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था और उन्होंने फुल टाइम वही काम निभाया कि जो एक राज्यपाल निभाता था। कार्यपालक राज्यपाल भी वही काम निपटाएगा जो कि पूरा फुल-फ्लेज्ड राज्यपाल निपटाएगा। उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। यह दूसरी बार था, जब महामहिम ने यहां पर भाषण दिया। लेकिन जब पहली बार भाषण दिया तो किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के संबंध में उठायी गयी शंका जो राव साहब की थी, वह निराधार है। संसदीय परम्पराएं हैं, समय-समय पर आसन के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं की बाबत यह भी साफ-साफ है कि सदन में उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी।

मैं पहले राव साहब से बात कर लूं, फिर आप पर आऊंगा। दूसरी बात राव साहब ने यह उठायी कि सहरियाओं के लिए 72 करोड़ रुपये ईयरमार्क किये गये। 72 करोड़ रुपये ईयरमार्क नहीं किये गये। 72 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था, लेकिन 52 करोड़ रुपया ही स्वीकृत हुआ और उसमें से केवल 25 करोड़ रुपये मंजूर किये। 25 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये और उसमें से 23 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसको आप

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

दुबारा से देख लें, हो सकता है, जो मेरे द्वारा सूचना दी गई है, उसको आप देखकर सही स्थिति पर पहुंच जाएंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): करेक्ट कर देता हूं, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं है, यहीं करेक्ट कर देता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): डिस्टर्ब तो हो जाऊंगा मैं। मैं फिर पक्का हो जाऊंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि इसको बाद में देख लेना।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप फरमा दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरा, मेरा यह निवेदन था, (व्यवधान) जवाब भी नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, वक्तव्य भी नहीं होना चाहिए तो फिर हम काहे के लिए यहां पर विराजमान हैं? फरमा तो दो। हम आप ही का चेहरा कहां तक देखते रहें? (व्यवधान)

जी एस डी पी के बाबत आपने फरमाया। आपने फरमाया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1973-74 में 46.14 परसेंट था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह फिगर 1973-74 का था, लेकिन आज 2004-05 का फिगर आप उठाकर देखेंगे तो यह जनसंख्या 17.15 परसेंट रह गई है। इसको भी देख लें, तसल्ली से देख लें, फिर कभी बात कर लेंगे इस बाबत। ठीक इसी तरीके से पूरे विश्व में विकास के साथ-साथ उद्योग और सर्विसेज के क्षेत्र के मुकाबले में निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर में गिरावट होती है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कही, वह भी आप देखें कि 1988-89 में जो फूडग्रेन, इंक्लूडिंग पल्सेज, फूडग्रेन का प्रोडक्शन था वह 6.35 था, वह राजस्थान में 2011-12 में बढ़कर 9.75 हो गया। आयलसीड का प्रोडक्शन ले लें, आयलसीड का प्रोडक्शन 15.42 था वह बढ़कर 2010-11 में 21.22 हो गया। काटन का ले

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

लें, काटन में गिरावट आयी; काटन में भी आयी और शुगरकेन में भी आयी, लेकिन वह मामूली गिरावट है।

एक बात और कही गयी कि पूरे हिन्दुस्तान में अगर मिनिमम वेजेज हैं वे राजस्थान में कम हैं। यह थोड़ा सा असत्य है। शायद आपने कहा? आपने नहीं कहा तो फिर इन्होंने कहा होगा, तो इनको बोल दूंगा।

नि:शुल्क दवाओं के लिए कहा आपने। आपका बहुत अच्छा सजेशन था। मुझे याद है, मैं शाहपुरा भी गया था और शाहपुरा में भी आपकी बड़ी कृपा थी कि आप वहां पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर आपने वहां पर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह कह चुके हैं कि मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं तो यह व्यवस्था चाहता हूं, आप यह व्यवस्था कर दें, मंत्रीजी भी भाषण दे सकते हैं। मैंने कहा था, हस्तक्षेप कर सकते हैं। परम्पराएं देख लें। मुझे तो ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अभी अन्दर सहमति बनी थी। आप भी तो विराजे थे अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मुख्य सचेतक महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा और आपका एग्रीमेंट यहां खुले में बताऊं तो ठीक नहीं रहेगा। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पूरे राजस्थान की जनता को पता है आपका और इनका क्या एग्रीमेंट है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नि:शुल्क वेक्सिनेशन के लिए आपने बात कही थी कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे जिस प्रकार के वेक्सिनेशन के लिए, प्रिवेंटिव, नोट क्योर; क्योर दवा से होगा, वेक्सिनेशन से प्रिवेंटिव होगा। वह आपका सजेशन वाकई बहुत अच्छा था, मैंने उस बात को चलाया भी है। हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है पूरे देश में, जहां पर कि राजस्थान की सरकार जितने वेक्सिनेशन लगा रही है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उनके अलावा कोई लगाती हो, अलावा एक बिहार के। बिहार में जापानी एन्सीफेलाइटिस, यह एक अवेलेबल है, सिर्फ बिहार में है, बाकी और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। राजस्थान की सरकार निश्चित तौर पर इस बात की कोशिश करेगी कि और भी अगर कोई वेक्सिसीनेशंस मिल सकते हों तो उनको भी लगाने का प्रयत्न करेंगे। अभी भी आप देख लें चाहे तपेदिक का हो, पोलियो का हो, डिप्थीरिया का हो, काली खांसी का हो या आपका हेपेटाइटिस-बी का हो, खसरा का हो, वगैरह, वगैरह। ये सारे वेक्सिनेशंस लगाये जा रहे हैं।

दवाइयों का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 स्टेट में दवाइयां वितरित हो रही हैं लेकिन जिस तरीके से दो अक्टूबर से यहां पर चालू हुई, 2 अक्टूबर, 2011 से इतने कम समय में इतनी दवाइयां चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों और चाहे एस एम एस हास्पिटल हो, जितनी दवाइयां यह राजस्थान की सरकार पहुंचा रही है, यह बहुत क्रेडिटेबल है। आपको ध्यान होगा जिस वक्त आप वहां पर विराजमान थे शाहपुरा में, मैं आपके पास में बैठा हुआ था और मैंने चिल्ला-चिल्ला करके लोगों से यह कहा था, दवाइयों के बाबत अपनी राय दें, अपने सुझाव दें। एक व्यक्ति ने भी, हालांकि दो सौ, चार सौ आदमी मौजूद थे वहां पर लेकिन एक व्यक्ति ने भी दवाइयों के बाबत यह शिकायत नहीं की कि साहब, ये दवाइयां हमें उपलबध नहीं हो पा रही हैं। यह जरूर है कि कोई व्यक्ति 10 तारीख को अगर अस्पताल में गया हो, उस रोज दवा नहीं मिली हो, 12 तारीख को आने वाली हो अस्पताल में, वह दो रोज के लिए यह जरूर कह सकता है कि दो रोज बाद में मुझे मिली। लेकिन जो यहां से भेजी गई हैं और वह वहां पर अवेलेबल नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने, जन कल्याणकारी काम हाथ में लिया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि उसमें आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है।

इसी के साथ-साथ, मैं इस बात पर निवेदन करना चाहता हूं, तिवाड़ी साहब ने कल यह कहा, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपने जो कुछ कहा, ''विदेशों से जो लोग राजस्थान में आएंगे, उनको 90 परसेंट टिकट का पैसा हवाई जहाज का राजस्थान सरकार देगी। खाला जी का राज है, यह कहा आपने, क्यों दे दोगे? ''वे राजस्थान के लोग हैं, वे घूमने आएंगे, अपने ट्रिप पर आएंगे, बिजनेस ट्रिप करेंगे, हनीमून मनाएंगे। आप उनकी टिकट का पैसा दोगे। राजस्थान का पैसा सिर्फ लोक कल्याणकारी कामों में खर्च हो सकता है, किसी भी सरकार को

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

इस प्रकार का पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं है।'' मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, तभी आप इतना कड़वा बोले, वरना आप नहीं बोलते। बहुत होशियार आदमी हो आप, आपको जानकारी होती तो निश्चित तौर पर आप कभी यह बात यहां पर नहीं उठाते। आपको ध्यान हो तो 2001 में पहली बार एन आर आई सम्मेलन राजस्थान में हुआ और उसकी वाहवाही और उसकी प्रसिद्धि और उसके रिजल्ट देखकर ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने यह आदेश दिया था कि इस तरीके का सम्मेलन हमारे पूरे विश्व में जितने भी एन आर आईज हैं, उनके लिए दिल्ली में बुलाया जाए। उन्होंने शुरू किया और बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं है और शुरू ही नहीं किया, उन्होंने कंसेशंस देना भी चालू किये। बाकायदा यह डिपार्टमेंट बैठा, डिपार्टमेंट का गठन किया गया, मिनिस्ट्री आफ ओवरसीज इण्डियन अफेयर्स और उसमें यह कंसेशन दिये गये बाकायदा। जो राजस्थान की सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर अपनी घोषणाएं की, हालांकि अभी इसके आर्डर्स जारी नहीं हुए, न कोई नियम वगैरह बने हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, निश्चित तौर पर जारी होंगे, सब कुछ होगा। जो चीज मुख्य मंत्रीजी यहां बोले, वह की वह चीज केन्द्रीय सरकार लागू कर चुकी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाकायदा उन्होंने 40 का ग्रुप बनाया है कि युवक-युवतियां जो 18 से लेकर 26 वर्ष तक के हैं, उनके 40 के ग्रुप तैयार होंगे, संबंधित हाई कमिश्नर या अम्बेसेडर उनका सलेक्शन करेगा, अगर कोई सोशल आर्गेनाइजेशन उस देश में मौजूद है, सोशल आर्गेनाइजेशन सिफारिश करेगा, उनको सलेक्ट करेगा और सलेक्ट करके यहां पर भेजने का करेगा।

इरादा क्या था, इरादा मौटे तौर पर उनका वही था, जो राजस्थान की सरकार का 2001 में बना था, हमारा इरादा था, जानो अपने राजस्थान को। अपनी मातृ भूमि की संस्कृति और विरासत से सुपरिचित होने के लिए ही यह सब कुछ कार्यक्रम किया गया, युवा वर्ग के अपनी मातृ भूमि से भावनात्मक संबंध अगर कायम होते हैं क्योंकि जो लड़का वहां पर पैदा हुआ है, अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोई लड़का पैदा होता है और पैदा होने के बाद वह 4 साल के बाद क्लासेज में चला जाता है पढ़ने के लिए और लगातार पढ़ता रहता है। पढ़ने से कोई फुर्सत नहीं मिलती, वह कभी हिन्दुस्तान आता नहीं है, ज्यों ही उसकी पढ़ाई खतम होती है, वह नौकरी पर चला जाता है या बिजनेस में लग जाता है। वह कभी आने की कोशिश ही नहीं करता। उसको

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

फुर्सत ही नहीं मिलती कि यहां पर आए, उनको हम इसलिए बुलाना चाहते हैं कि वे यह देखें कि उनके पुरखे इस राजस्थान में क्या-क्या किया करते थे, किस प्रकार की संस्कृति में जीवित रहते थे, क्या धंधा किया करते थे, यहां के किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की मेहमाननवाजी यहां पर है, यहां पर आर्ट एण्ड कल्चर क्या है। इन सब बातों को देखने के लिए यह सब कुछ किया गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो महीने तय किये गये हैं, जनवरी और अक्टूबर; जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किये कि 40 आदमियों का ग्रुप किया, यहां वालों ने जो तय किया, जो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा थी, वह 10 और 14 दिवस के लिए थी, सिर्फ 10 और 14 के लिए थी और बाकी वही कंसेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी कि निवास, यात्रा, बोर्डिंग, बोर्डिंग में वे अपनी टिकट लेंगे, टिकट लेकर 90 प्रतिशत रिइम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से उनको राज्य के अतिथि गृहों में ठहराया जाएगा या आर टी डी सी के होटलों में ठहराया जाएगा। सौ रुपये रोज का भत्ता केन्द्र सरकार दे रही है। फर्क इतना सा आ रहा है, सारा सब कुछ वह का वह है, जो केन्द्र सरकार दे रही है लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा करके सौ रुपये को दो सौ रुपये कर दिया। इसलिए मैं आपको दुरुस्ती के लिए कह रहा हूं कि यह आपकी जानकारी में होता तो आप हाउस को मिस-लीड नहीं करते।

इसके अलावा, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देखिए, कोई भी बात छिपाने से नहीं छुपती। आपको ध्यान होगा, कोका-कोला का निर्माण चालू हुआ पेयजल का, 125 वर्ष पूर्व और उसका फार्मूला लोग तलाश करते रहे, करते रहे, करते रहे लेकिन 125 साल के बाद में आज उसका फार्मूला बाजार में आ गया है। छुपती नहीं है। हमें वह वक्त याद है, जब आप ही की सरकार ने 2004 के एजेंडे में 26 प्रतिशत की भागीदारी एफ डी आई को देने के लिए मोहर लगाई थी और इसी में आप ही के शासन काल में निजी मंडियां खोली गई थीं, मल्टी-नेशनल कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये थे और आज आप एफ डी आई का विरोध करते हो। परमिशन मत देते, जमीन मत देते उनको आप लेकिन एफ डी आई की जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात छेड़ी तो आपने सबसे ज्यादा विरोध किया। मैं आपसे अब भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब कोई विदेशी संगठन हमारी तरफ आंख नहीं उठा सकता। आज की अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक के कठोर पैरामीटर्स से नियंत्रित होती है। वह जमाना

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गया, जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी यहां पर व्यापार करने आई और हम पर ढाई सौ साल राज करके चली गई। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हिन्दुस्तानी की तरफ आंख उठाकर देख ले और हिन्दुस्तान पर कब्जा कर ले।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने महबूब खान की मदर इण्डिया देखी होगी, मदर इण्डिया। किसान अपनी उपज को चार पोटली में बांध कर लाता है, उसमें एक दृश्य है, 4 पोटली में लाकर वह चार ढेर लगा देता है। एक व्यापारी आता है गुण्डों के साथ और आकर के उस किसान की पिटाई करता है, पिटाई करके उन चार ढेरों में 3 ढेर अपने कब्जे में ले लेता है और कब्जे में लेकर एक तरफ बैठ जाता है। ग्राहक आते हैं, ग्राहक आकर के किसान से अपना माल लेते हैं और माल जब उसका खतम हो जाता है, तब व्यापारी अपनी दुकान, उन ढेरों को लगाकर बैठता है और फिर मनमर्जी से पैसा लेता है। अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि जनता किसी भी तरीके से ऐसा होने नहीं देगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात, कई बातें हैं, काले धन की बात, आडवाणी जी ने कहा ...(व्यवधान) राधेश्यामजी अपन मित्र हैं। आडवाणी जी ने 11 फरवरी, 2011 को यह कहा था कि एन.डी.ए. का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसकी विदेश में कोई सम्पति या विदेशी बैंक में किसी प्रकार का कोई पैसा हो और इस प्रकार का शपथ-पत्र हम देंगे। दिया क्या एक भी? एक भी दिया?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने दे दिया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमने सब ने दे दिया और आपसे भी निवेदन है कि आप भी दे दो वरना सी पी एम में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे।

ठीक इसी तरीके से अन्ना हजारे साहब का आंदोलन हुआ। बगैर बुलाये आपने स्वयंसेवक जा ठोके उनके साथ और वे स्वयंसेवक ऐसे ठोकें कि बाद में फिर बेइज्जत होकर के ही उनको विथड्रा करना पड़ा एवं आखिर में उस आजाद मैदान पर उनके साथ कुछ ही लोग रह गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैसला करने के पहले हमें उस बात को भी देख लेना चाहिए, एक रेलवे प्लेटफार्म पर दो अंधे खड़े हुए थे और एक अंधा दूसरे अंधे से पूछ रहा था....

श्री उपाध्यक्ष: मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक अंधा दूसरे अंधे से पूछ रहा था कि फर्स्ट ए.सी. की बोगी निकल जाए और सेकंड ए.सी. की बोगी आये तब तू मुझे बता देना। तो हमें यह समझना चाहिए कि अन्ना हजारे एक व्यक्ति हैं और संसद एक संवैधानिक संस्था है। जिस रोज हम एक व्यक्ति को संवैधानिक संस्था के ऊपर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोकतंत्र का कत्ल भी करेंगे और कत्ल ही नहीं करेंगे बल्कि तानाशाही प्रवृत्तियों को और बढ़ावा देंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये अपना समय ही ले रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में.... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तानाशाही और संविधान को ध्वस्त करने का रिवाज कांग्रेस ने चलाया था। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप कहोगे जो बोलेंगे क्या? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार हमारा है, समय हमारा है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): .... इनको आइना दिखा दिया, इनकी योजनाओं की पोल खुल गई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ....19 महीने तक जेल में रखने का काम कांग्रेस ने इस देश में... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बड़ी मुश्किल से तो आये हो। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अन्ना हजारे की चर्चा वहां संसद में होनी चाहिए, यहां विधान सभा में क्यों हो रही है? (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ..... आप यह क्यों विवाद कर रहे हो? लाइन पर आइये, मतलब की बात कहिये। यह सदन है, यह घर नहीं है, बाजार नहीं है। यह कोई प्रवचन करने का स्थान नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर शक्तिशाली कोई एलीमेंट है तो वह है विश्वास। अगर विश्वास कायम रहता है, सरकार किसी की भी हो,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

विश्वास यह होना चाहिए कि जन उपयोगी काम लेंगे और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): .....एक भी काम नहीं किया आपकी सरकार ने। पोल खुल गई, जनता समझ गई। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...हमको मत बताओ कि लोकतंत्र क्या होता है। हमने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उधर से लिस्ट आती है, उस लिस्ट में नाम लिखाकर आराम से बोलो न। कहां दिक्कत है, यह सदन बढ़िया तरीके से चल रहा है, आप 2-4 लोगों के भरोसे यह सब डिस्टर्बेंस क्यों करते हो बिना बात का? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये यहां पर कौनसा पाठ किसको पढ़ा रहे हैं? डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, ये किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अन्ना जी के आगे झुकते हो और उनके आगे निमंत्रण पत्र भेजते हो, आपके 3-3 मंत्री गिड़गिड़ाते हैं उनके आगे, सोनिया जी उनको बुलाती हैं, प्रधान मंत्री बुलाते हैं और उनसे समझौता करते हैं और आप कह रहे हैं कि अन्ना लोकतांत्रिक नहीं है। (व्यवधान) लोकतांत्रिक नहीं है तो केन्द्र सरकार के 3-3 मंत्री उनको बुलाने क्यों गये? (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ....सुरेश कलमाड़ी और दूसरे मंत्री वहां क्यों बैठे हैं? (व्यवधान) घोटाले होकर भी आप नहीं मान रहे हैं कि आपके मंत्री जेल में हैं। (व्यवधान) आपके मंत्री जेल में बैठे हैं, यह नहीं मान रहे हैं क्या आप? मंत्री जेल में बैठे हैं अरबों रुपयों के घोटाले में। (व्यवधान) यह जवाब है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पहलवान जी, आप अपने समय में उसका जवाब दे देना।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ....वे इस पवित्र सदन के ही सदस्य थे जिस सदन में.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बाबा रामदेव को हवाई जहाज से लेने गये, अन्ना जी को 3-3 मंत्री हाथ जोड़ने गये। (व्यवधान) अगर वे लोकतांत्रिक नहीं हैं, उनका आंदोलन लोकतांत्रिक नहीं है तो क्यों आपने समझौता किया?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और फिर फिजूल में क्यों बहस का समय खराब कर रहे हैं? (व्यवधान) आप तो अपने आपको बहुत सुलझे हुए कहते हैं आप अनावश्यक रूप से वाद-विवाद का, अभिभाषण का..... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप अपना नाम भिजवायें न अपने सचेतक से और फिर आराम से बोलें। टाइम लेकर बोलें न। क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं तो बोलूंगा, टाइम लेकर ही बोलूंगा और आप सुनेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ....हम करिश्मा जारी रखेंगे और दोषों को दूर करने का हरचंद प्रयास करेंगे, जन हित की योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक स्थिरता कायम रखने के लिए किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। राजनीतिक स्थिरता के लिए किसी भी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम आदमी को समझने की आवश्यकता है। आम आदमी का क्या पहनावा है, क्या उसकी भाषा है, किस प्रकार का उसका चाल-चलन है, किस प्रकार की उसकी शिक्षा है, किस प्रकार का उसका जीवन स्तर है, किस तरीके का उसका पहनावा है, यह समझने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया, वह आम आदमी की कठिनाइयों को भी समझेगा और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अगर इस देश में आम आदमी को किसी ने समझा है तो या तो महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने या राजीव गांधी ने या राहुल गांधी ने समझा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा रिकार्ड पर जा रहा है। सारी डिबेट लेकर के आज जायेंगे। (व्यवधान) अब उसको दुरूस्त करेंगे वे, यह समझ में आया। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर प्रवचन दे रहे हैं या अभिभाषण पर बात करेंगे आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राहुल गांधी को राज़ी करने के लिए कह रहे हो, यह समझ में आ गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देंगे, आपको भी देंगे, फिर बाद में आप बोलें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिस व्यक्ति ने आम आदमी को समझ लिया वह इतिहास में अमर हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वाह, राहुल गांधी अमर हो गये। राहुल गांधी अमर हो गये न? हम तो राहुल गांधी का पूछ रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बीच-बीच में क्यों इंटरवीन करते हो? बीच में कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राठौड़ साहब, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आम आदमी को समझ लिया, सरलता से उन्होंने अपने आपको आम आदमी के साथ जोड़ लिया। राहुल गांधी ने कलावती को देखा, उसके घर गये, उसका खाना खाया, उसके यहां टूटी खाट पर सोये और उसके मन को अच्छी तरह से टटोलकर पूछा कि बोलो, आपको क्या तकलीफ है? लेकिन मैं एक बात आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, कहना क्या चाहते हो? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अपने अधिकार के तहत वे जो बोल रहे हैं उसको सुनो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कहना क्या चाहते हो? (व्यवधान) यहां कोई प्रवचन हो रहा है? (व्यवधान) यह प्रवचन किस बात का है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप डिक्टेशन थोड़े दोगे। बोल दो न उनको, यह अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी का रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड वही होगा जो ये बोलेंगे। (व्यवधान) आप तो करो, वह उनसे कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आम आदमी को किसने समझा है? ''मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तू फेंक'' वह कवि था जो आगे जाकर के राष्ट्र-कवि कहलाया। किसने समझा आम आदमी को, वह था राजकपूर जिसने-''मेरा जूता है जापानी, यह पतलून इंग्लिशतानी'' आम आदमी की भाषा समझी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर कोई गुनगुनाता था तो यह गुनगुनाता था, ''काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो'' ।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष से, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सात-आठ आदमी आपके पास बैठे हुए हैं, इनका पीहर यह है, मायका वह है। ये कब इधर आ जाये, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धारीवाल साहब, आपको 35 मिनट हो गये हैं, 35 मिनट हो गये हैं। (व्यवधान) यह जो बोलेंगे, वही रिकार्ड हो रहा है। ना तो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वे अपना पक्ष रख रहे हैं, आप सुनिये। आप अच्छा बोलिये। उसमें क्या बात है? आप अच्छा बोलिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पांच मिनट। फर्क यह है कि कांग्रेस आम आदमी को देखती है और आपने आम आदमी की छवि किसमें देखी... (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ××× (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कांग्रेस आम आदमी को देखकर उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाती है, उसको भरपूर, उसकी झोलियां भरती हैं लेकिन आपने आम आदमी की छवि किसमें देखी, ललित मोदी में। भर दी उसकी झोली। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखिये, भ्रष्टाचार की बात अपन करते हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस में जिस-जिस व्यक्ति के ऊपर, वह चाहे कितने भी बड़े पद पर रहा हो, अगर थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार सोनिया गांधी को दिखा तो उन्होंने उसकी छुट्टी की, उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं रखी लेकिन पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 2.76 लाख करोड़ रुपये में से एक रुपया बरामद नहीं किया और उसको ओपन तो पत्रकारों ने किया था, सोनियाजी ने नहीं किया था, पत्रकारों ने किया था। जब वह फंस गया तो विवशता हो गई थी निकालकर जेल में डालने की। 2.76 लाख करोड़ रुपये इस राष्ट्र का गबन कहां गया? भंवरी देवी के दांत नहर में ढूंढ लिये, पूंछ ढूंढ ली, घड़ी ढूंढ ली, लेकिन 2.76 लाख करोड़ रुपये नहीं ढूंढे गये। वह सी बी आई लाकर खड़ी कर दो और हमें बता दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो सदन का सदस्य नहीं है, उनका

(श्री उपाध्यक्ष)

नाम नहीं लें तो अच्छा रहेगा। जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम कोई भी नहीं ले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये कांग्रेस के लोग, धारीवाल साहब बार-बार राजीव गांधी, सोनियाजी का नाम ले रहे हैं, सोनियाजी सदस्य हैं क्या यहां की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब ये समाप्त करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा बैठिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजीव गांधी ब्रिगेड है। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात सुनो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय धारीवाल साहब, आप भी देख लो, यह कांग्रेस की राजीव गांधी ब्रिगेड है और सारी यह जेल में है। खाली प्रदेशाध्यक्ष है, वह फरार चल रहा है। तो इनके बारे में भी तो कोई सोचो कि कितना भ्रष्टाचार का माल लिया है। यह कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष है, इनके बारे में भी कोई कह दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, आपको मौका मिलेगा बोलने का। आप विराजिये, आपको मौका मिलेगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप कह रहे हैं, हमारी सरकार सही काम कर रही है तो यह पूरी आपकी ब्रिगेड लूट-खसोट में लगी हुई है, इनको तो जेल में डालो। ये सारे सड़ रहे हैं, एक प्रदेशाध्यक्ष फरार है। इनके ऊपर भी कोई विचार करो। (व्यवधान) इनके मुकदमे चल रहे हैं, पूरी फाइल है और आपके दिलीपजी चौधरी, सारे आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में जो कुछ हुआ, उससे तो कर्नाटक का नाम बदलकर ''कर नाटक'' यह कर देना चाहिए।

मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा आखिरी सवाल है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फालतू बात में समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? (व्यवधान) यह सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं। ये फालतू बातों में समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान) आप कमाल कर रहे हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): समय हमारी पार्टी का है, हमारा अधिकार है बोलने का, हमारे टाइम में से बोल रहे हैं। हमारे टाइम में से बोल रहे हैं। आप जबरदस्ती बीच-बीच में खड़े हो रहे हो। आपको क्या एतराज है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बैठिये आप, बैठिये आप। क्या तमाशा बना दिया? क्या तमाशा बना दिया सदन का। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान का नाम कलंकित किया है। (व्यवधान) मंत्रीजी जेल में चले...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी का अपना कोई स्टेटस होता है, कोई मंत्रीजी का सम्मान होता है...(व्यवधान) मंत्री की कोई गरिमा होती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों बोले जा रहे हो? हमारा समय ले रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको दिक्कत क्या है?

श्री करणसिंह (छबड़ा): जसवन्त सिंह जी यादव साहब, आपका तो नम्बर आयेगा, आप खूब बोलना। यादव साहब, आप खूब बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ये हमारे समय में से बोल रहे हैं। (व्यवधान) आधा समय तो आप इसी में खराब कर रहे हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने तो अटलजी की भी नहीं सुनी थी, यह बात सही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आखिरी एक सवाल माननीय तिवाड़ी साहब से पूछना चाहता हूं। द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था और कटारियाजी और तिवाड़ी जी जैसे पांडव टुकर-टुकर, टुकर-टुकर देख रहे थे और ललित मोदी... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को क्या समझ रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बीच-बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हर बार? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या वह चीरहरण दुबारा से करवाना चाहते हो? क्या चीरहरण दुबारा करवाना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह राजस्थान के पवित्र सदन की गरिमा को खराब कर रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह हमारे समय में से बोल रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? हमारे समय में से बोल रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? (व्यवधान) क्या परेशानी है आपको, मेरी समझ में नहीं आती। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मंत्रीजी का चैक-अप करवाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये +++ हो गये हैं +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके उप नेता बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, on an explanation, personal explanation.

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समय में से कटौती नहीं होनी चाहिए इसमें। यह इंटरवेंशन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन यह है कि माननीय शांती धारीवाल ने जो कहा...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले मेरी बात तो सुनो आप, फिर प्रश्न करना आप। पूरी बात तो सुनो मेरी आप। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके व्यक्तित्व को किसी भी तरीके से पांडवों के व्यक्तित्व से कम नहीं समझते हैं। आप हो, कटारिया जी हो, वगैरह-वगैरह। दो-तीन और जोड़ लो। ये राव साहब को भी मैं मानता हूं पर राव साहब तो इनके बदन से तो भीम नहीं लगते लेकिन इनको भीम मान लो आप। (व्यवधान) लेकिन जब इस प्रदेश की जनता का चीरहरण ललित मोदी कर रहे थे, तब आप टुकर-टुकर क्यों देख रहे थे? (व्यवधान) इस बात का जवाब दो आप। इस बात का जवाब दो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है? जो सदन का सदस्य नहीं है, जो सदन का मेम्बर नहीं है, सदस्य नहीं है, उसके बारे में ये क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) क्या कहना चाहते हैं ये?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको एतराज क्या है, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। जो सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो सदन का सदस्य नहीं है और ये बार-बार नाम ले रहे हैं। आपने कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। यह एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ये मंत्रीजी बार-बार नाम ले रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) यह कार्यवाही से निकाला जाये। ये बोलना क्या चाह रहे हैं? कोई मजाक बना रखा है। सरकार सरकार होती है, सरकार का कोई चीरहरण नहीं होता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले ललित मोदी कर रहा था, अब ललित कोठारी कर रहा हैं। आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त कर चुके क्या? समाप्त हो गया क्या? समाप्त हो गया क्या? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये बकवास की बात कर रहे हैं जिससे सदन स्थगित हो जाये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये सरकार के दु:शासन, ये चीरहरण करने वाले हैं जनता का। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इतनी जनकल्याण की योजनाएं जन हित में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कल्पतरू के बारे में भी बोल जाइये, यह जनमंगल के बारे में भी बोल जाइये, नया जयपुर में आपने क्या किया, यह भी बोल जाइये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस गहलोत सरकार के द्वारा जितनी जन कल्याण योजनाएं हाथ में ली गई हैं, जिनके सफल क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य बनाया गया है, मानस बनाया गया है, कृपया उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम आपके सुझावों को निमंत्रण देते हैं, आप आमंत्रित हैं, आप उसमें सुझाव दीजिये। आप अगर सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से आपके सुझावों का सम्मान करेंगे। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपकी पार्टी के लोग, आपके दल के लोग, विधायक दल की बैठक में कितना विश्वास प्रकट किया आपके लोगों ने, सबको पता है। पहले अपने लोगों का विश्वास करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये समाप्त कर रहे हैं। अब आप इनको बोलने दो ना।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अपने लोगों को विश्वास में लो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह तो विधायक दल है, आपके तो मंत्रिमण्डल में क्या होता था, आप क्या बात करोगे? आपके तो मुख्य मंत्रीजी की बैठक में मंत्रीजी जाते नहीं थे। आपकी हालत आपने नहीं देखी? यह विधायक दल की बैठक में जो हुआ, यह हमारा लोकतंत्र है, हमारी अपनी व्यवस्था है। मन की बात कहने का हमारे नेता ने अधिकार दे रखा है कि मन में कोई बात हो तो अन्दर, घर में बैठकर करो। यहां हाउस में हम सब एक हैं, हम कोई भी अलग नहीं हैं। आपकी पार्टी में क्या होता था? मंत्रिमण्डल के लोग मुख्य मंत्रीजी के बुलाने पर भी नहीं जाते थे। (व्यवधान) आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? आप अपनी गिरीबां में झांको, अपनी गिरीबां में झांको। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 150 सी.डी. बनी हुई है आप लोगों की। 150 सी.डी. बनी हुई हैं आपकी पार्टी के लोगों की, कांग्रेस की। (व्यवधान) वे आपकी पोल खोल रही हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं दो लाइन सुनाता हूं, कविता की। यह तो कविता है, +++।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक सौ पचास सीडी हैं आपकी। इसका हमें क्या? एक सौ पचास सी.डी. हैं कांग्रेस की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान की विधान सभा में कविता सुनने आये हैं हम? यह कविता सुनने आये हैं हम? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये समाप्त कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कविता सुनने आये हैं हम? (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पहली बार तो धारीवाल साहब इतना अच्छा बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बेइज्जती इनकी हुई है, जिस बेदर्दी से गृह मंत्री की कुर्सी इनसे हटाई है....(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप इतना समय खराब करते हैं इस सदन का...

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता को ये कविता कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: त्रिवेदीजी, त्रिवेदीजी। समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं, गीता को ये कविता कह रहे हैं राठौड़ साहब।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उपाध्यक्ष महोदय, सदन यह जानना चाहता है कि ललित मोदी का नाम बार-बार आता है तो इधर से बार-बार क्यों उखड़ते हैं ये लोग? तो ऐसा क्या हो गया ललित मोदी में? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन के बाहर के आदमी का नाम नहीं लें, प्रक्रिया है। कृपया आवश्यकत हो तो ही लें, अन्यथा नहीं लें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अपनी ही आग में दिन भर तो जलेगा सूरज और फिर किसी गहरे समंदर में उतर जायेगा। अपनी ही आग में दिन भर तो जलेगा सूरज और फिर किसी गहरे समंदर में उतर जायेगा। आज हम तुम हैं यहां, आज हम तुम हैं यहां, यह गनीमत मानो, किसको मालूम कल कौन किधर जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंहजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को...

श्री उपाध्यक्ष: इसको, लम्बी हो जायेगी चर्चा।

स्पष्टीकरण

घनश्याम तिवाड़ी, श्री, का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, लम्बी नहीं करूंगा। मुझे कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन करना है...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनको तो आगे चलकर लम्बा करना है।

श्री उपाध्यक्ष: जी हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनल इंगित करके कहा और मैं आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप हमने जैसे उन्हें सुना, आप मेरी भी सुनें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कौरव थोड़े ही बताया है, आपको पांडव बताया है +++, क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान) हां, तो यह क्या बात हुई,

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं पांडव के रूप में ही बोलूंगा, जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पांडव के रूप में ही बोलूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सही-सही बात बोल देना आप तो, जो कुछ हुआ न।

श्री उपाध्यक्ष: इन दोनों के बीच में कोई नहीं बोले तो ठीक रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हां। मुझे इंगित करके पूछा माननीय मंत्रीजी ने कि ललित मोदी के बारे में क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ललित मोदीजी के बारे में सबको पता है। ललित मोदी के कारण से कांग्रेस की सेंट्रल सरकार टिकी हुई है। पता नहीं है क्या, ललित मोदीजी कहां रहते हैं? बार-बार मुख्य मंत्री पूछते हैं। पूछो उस शरद पंवार से जाकर, कहां हैं; पूछो प्रफुल्ल पटेल से, कहां हैं; पूछो सी.पी. जोशी से, किसके सहारे से अध्यक्ष बने हैं। (व्यवधान) पूछो संजय दीक्षित से, आज वह क्या कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष: बाहर के जो सदस्य नहीं हैं...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह काल्पनिक बातें आप जो कह रहे हैं न, क्या तथ्य हैं आपके पास इन बातों के?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह आरोप गलत है इनका। आपके पास कोई तथ्य हों सी.पी. जोशी के खिलाफ तो यहां रखिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बता रहा हूं, आप रुको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सी.पी. जोशी की बात मत करिये, यह गलत बात है। (व्यवधान) यह गलत बात है, बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हम आपकी बात कह रहे हैं, माननीय, सी.पी. जोशी ललित मोदी की मदद से नहीं बने हैं। (व्यवधान) गलतफहमी है आपको...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके पास क्या तथ्य हैं ललित मोदी ने...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ आप यहां आरोप नहीं लगा सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं कह रहा हूं आपको...

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंहजी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ललित मोदी की मदद से नहीं बने हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप नेता, माननीय उप नेता, तिवाड़ीजी बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूछिये राजीवजी शुक्ला से, कहां हैं। इसलिए कि अगर वह आ गये हिन्दुस्तान में तो भारत की केन्द्रीय सरकार गिर जायेगी। इसलिए वह रोज तो ट्वीट करते हैं, रोज टेलीफोन पर आते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो बुला लो। आप तो बुला लो। (व्यवधान) हमारी चिंता मत करो। हमारी चिंता मत करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। डा. दिगम्बर सिंह। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो बुला लो उनको, हमारी चिंता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंहजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आपको क्या बोलना है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मफतलाल महनोत के बारे में भी पूछिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ मैं जाने दो न मफतलाल महनोत को।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, बोलिये। कोई बात नहीं, आप बोलिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, करीब पैंतालीस-पचास मिनट का यह अभी जो समय माननीय मंत्री महोदय ने लिया, ऐसा लग रहा था कि आप विधान सभा में....

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंहजी, मैं एक निवेदन करूं आपसे, यह जितने से व्यक्तिगत जो बाहर के आदमियों का नाम लेते हैं, एक तो कृपा करके उसको अवाइड करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं अभिभाषण पर ही बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप एक्सपंज करने की व्यवस्था दे दें, उपाध्यक्ष महोदय। आप आसन पर विराजे हैं, एक्सपंज करने की व्यवस्था दे दें। एक्सपंज करने की व्यवस्था दे दें, आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप डिक्टेशन क्यों देते हैं आसन को हर बार? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह अच्छी बात की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): करा दीजिये न एक्सपंज। आप रोज डिक्टेशन क्यों देते हैं हाउस, आसन को?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन आपका नहीं, मेरा भी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय भाषा में और अभिभाषण के ऊपर ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, संसदीय भाषा थोड़ी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अब यह पचास मिनट का जो समय मंत्री महोदय ने अभी बरबाद किया इस सदन का, ऐसा....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एतराज है। बरबाद कैसे किया? हमने अपनी बात कही है। इसको आप बरबाद करना कैसे कह सकते हैं? हम सुन रहे हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ऐसा लग रहा था जैसे तो कोई हास्य कवि सम्मेलन में हम बैठे हैं यहां पर। विधान सभा के अन्दर इतनी हल्की बातें, सेंसलैस, यूजलैस, नानसेस बातें पूरे पचास मिनट के अन्दर जो इन्होंने रखी, मेरे खयाल से कोई भी काम की बात इन्होंने नहीं की।

(डा. दिगम्बर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से जो गरमाहट इस सदन में पैदा हुई, जो कुछ मैं समझ पाया हूं, मैं भी मानता था कि हमारे सदन के नेता, मुख्य मंत्रीजी तो बहुत गम्भीर आदमी हैं और जिस तरह वे पोज करते हैं कि कभी उनको गुस्सा नहीं आता, बहुत सहनशीलता उनके अन्दर है, परन्तु एक आदमी की लिमिट होती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल के अन्दर जूतमपैजार हुआ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक दल की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान) आप सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बात करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कांग्रेस विधायक दल के बारे में बात मत करो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने दल की चिंता करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपस में झगड़े...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह जो आप विधान सभा के फ्लोर को दुरुपयोग करना चाहते हैं, कांग्रेस विधायक दल की जिम्मेदारी हमारी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने दल की मर्यादाओं को संभाल कर रख लीजिये आप। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ऐसा लगने लगा...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी हर कारगुजारी को जनता देख रही है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो अपना ध्यान रखो, वही ज्यादा ठीक है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हम उजागर करेंगे क्योंकि राज में हो आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जनता में आ जाना न, सामने हो जायेगा फैसला। क्या दिक्कत है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): करा लो अभी चुनाव।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): होगा चुनाव, गलतफहमी भी दूर होगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अभी करा लो, अभी। (व्यवधान) आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, पचास सीटें नहीं आयेंगी आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों वही बात करते हैं जो सदन में गम्भीर चर्चा की बात होती है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): लोकतंत्र का फैसला चंद व्यक्ति नहीं करते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि यही हालत रही तो कांग्रेस की पचास सीट से ज्यादा नहीं आयेंगी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): लोकतंत्र का फैसला जनता करेगी। आप लोग मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हो न, वक्त आने पर पता चल जायेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो कराओ न चुनाव, कराओ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मुख्य सचेतक महोदय, बात सुनो। उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह...(व्यवधान) त्रिवेदी, त्रिवेदी, सुन लो न भाई।

श्री उपाध्यक्ष: त्रिवेदीजी, बैठकर नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सीट पर बैठे-बैठे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय गुलाबजी कटारिया ने अपनी बात सदन के अन्दर रखी प्रश्न काल के समय में, उसमें केवल बात यह थी कि चार अधिकारी जिनके खिलाफ में, पांच अधिकारी जिनके खिलाफ में प्रूव हो चुका है इन्क्वायरी में, उनके खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ, जबकि सदन के नेता ने आश्वासन दिया था इसी सदन के अन्दर कि इनके खिलाफ निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। मैं जहां तक समझ पाया, एक तो कटारियाजी की गलती रही कि उन्होंने भरत सिंहजी की तारीफ कर दी; न तो शांती धारीवाल की तारीफ की और न मुख्य मंत्री महोदय की तारीफ की। इससे भी उनका दिमाग खराब हुआ और पिछले जितने भी कांड हुए, गोपालगढ़ कांड के अन्दर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार ने कलक्टर, एस पी को कुर्बान किया; जलमहल प्रकरण में जुत्शी जैसा ईमानदार अफसर छुपता फिरे और आज अगर पांच कलक्टर्स के खिलाफ यह सरकार हिम्मत करती उनके खिलाफ एक्शन लेने का तो इनको पता था कि पूरी ब्यूरोक्रेसी

(डा. दिगम्बर सिंह)

हमारे फ्रंट पर खड़ी हो जायेगी। पूरी बात तो नहीं कह पाये, परन्तु इस अपच के कारण से आज जितना असंयत जो उनका व्यवहार रहा, मैं समझता हूं, वह कुछ ठीक नहीं था और एक टाइम-पास सरकार की भूमिका, जैसे कबड्डी में टाइम-पास करते हैं, लास्ट में करते हैं कि टाइम पास करना है, तो टाइम पास सरकार की भूमिका यह सरकार निभा रही है। इन्होंने आज इस...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बैठे-बैठे क्यों बोलते हैं?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप काहे को इतना परेशान हो रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): खड़े होकर बोलो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आज मुझे इस बात की खुशी भी है क्योंकि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने बहुत तारीफ की है कि हमारे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इतना जोरदार था, इतनी उन्होंने गाथाएं सुनाईं, पर जहां तक मैं समझता हूं, एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति होने के नाते, यह राज्यपाल महोदय की मजबूरी थी कि ऐसे थोथे, झूठ के पुलिंदे को पढ़ना उनको यहां पड़ा। अगर वे संवैधानिक रूप से बंधे हुए नहीं होते तो मेरे खयाल से इसको रखकर कह देते कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय, मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता और न ये गंदी बातें इसमें जो लिखी हैं, अर्थहीन बातें, वह मैं जनता के सामने पेश करना चाहता हूं। आपका संगठन और...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपका जो टाइम था, आप जब यहां मंत्री विराज रहे थे...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपके सत्ता और संगठन, आप विराजो मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मतलब की बात करो न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह जो भी वातावरण हुआ, उसके बाद जिस तरह का वातावरण बना, दोनों तरफ के नेताओं ने मिलकर के एक सहमति बनाई...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अब वातावरण कौनसा खराब हो रहा है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सदन शांतिपूर्वक चले। बार-बार उन सुबह की बात का, शाम की बात का ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं यह कह रहा हूं, शांती धारीवालजी

(डा. दिगम्बर सिंह)

के जब इतना करने के बाद वातावरण खराब नहीं हुआ तो मैं कौनसी गलत बात कह रहा हूं? मैं वही बात कह रहा हूं जो वास्तविकता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको अपनी बात गम्भीरता से कहनी चाहिए।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह असंसदीय शब्द है। इन्हें कहें कि असत्य शब्द बोलें, झूठ शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करें। आप तो इतने सीनियर सदस्य हैं, आपको जानकारी होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) आज जिस तरह का जो है, झूठ के पुलिंदे पढ़ रहे हैं, यह कोई इनकी भाषा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: प्रोसीडिंग्स पढ़ी जावेगी, जो असंसदीय शब्द होगा उसको हटा दिया जाएगा। वह डिलीट हो जाएगा अपने आप ही। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक वरिष्ठ सदस्य इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: वही शब्द रहेंगे जो संसदीय होंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सवाल यह है कि वरिष्ठ सदस्य इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? प्रश्न तो यह है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं कह रहा हूं, राजस्थान सरकार के ...(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बोलने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आज सबसे ज्यादा असंसदीय अगर बात कही है तो माननीय सदन के नेता ने कही है और मैं इस बात को ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है इस बात पर। कोई असंसदीय बात इस सदन के नेता ने नहीं कही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात के लिए?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपके टाइम में आपके मंत्रियों ने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आपके मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के चार्जेज लगाए थे। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आप पर भ्रष्टाचार के चार्जेज लगाए थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन के नेता ने पूरा टू-दी-पाइन्ट हर बात का जवाब दिया है। अब आप गले में कोई अपराध डालेंगे किसी के ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): डीग से आने वाले माननीय सदस्य, सदन के नेता ने असंसदीय क्या कहा है, बताइए आप। असंसदीय क्या है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): असंसदीय क्या है, बताइए। उपाध्यक्ष महोदय, इनसे एक बार यह स्पष्टीकरण करवायें। आप बहुत बड़ा चार्ज लगा रहे हैं सदन के नेता पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हाउस को आर्डर में लाइए। हाउस को आर्डर में लाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार टोक रहे हैं, हाउस को आर्डर में लाइए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, आर्डर में कैसे आएगा?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आर्डर में कैसे आएगा? आप उचित बोलेंगे तब ही आएगा।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप पता करवाएं असंसदीय शब्द। (व्यवधान) असंसदीय का इस्तेमाल नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय को पता नहीं, क्या हो गया। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टिप्पणी की है, मेरा निवेदन है कि इसको एक्सपंज कराया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) प्रतापसिंह खाचरियावास की बैसाखियों के ऊपर चढ़कर के आप इस कुर्सी पर बैठे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिगम्बर सिंहजी, माननीय राजेन्द्र जी, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलें जिससे उत्तेजना फैले। अपने को सदन को आगे चलाना है। बहुत माननीय सदस्य बोलने हैं आपकी तरफ से। आ गई है लिस्ट आपकी तरफ से तो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है उससे ज्यादा असंसदीय बात और क्या हो सकती है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज कराया जाए। माननीय सदन के नेता के ऊपर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल से टिप्पणी कर रहे हैं ये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इनके शासन काल में इनके मंत्रियों ने इन पर चार्जेज लगाये हैं, इनके शासन काल में इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इन पर चार्जेज लगाए हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वही बात कही गई है। गलत क्या कहा गया है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप अभी सुनिए। सुनिए तो सही।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह जो भाषा बोल रहे हो आप, यह नम्बर बढ़ाने के लिए है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको कुश्ती वहीं लड़नी है। यहां आप नम्बर बढाओ, नेता के ऊपर चार्ज लगाओ। बात करो ना, अभिभाषण पर बात करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात कही है, मुझे एतराज है इस बात पर। सदन के नेता ने एक भी शब्द असंसदीय कहा तो आप बताइए। कौनसा शब्द असंसदीय है? कोई शब्द असंसदीय नहीं कहा। एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी नहीं कहा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या बात कह दी ऐसी? कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने जो कुछ कहा, सही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: कृपा करके हाउस को आगे बढ़ने दें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टिप्पणी की है माननीय सदस्य ने, इसको तो एक्सपंज कराया जाए। माननीय नेता महोदय के प्रति जो इन्होंने टिप्पणी की है असंसदीय भाषा के इस्तेमाल की, इसको एक्सपंज कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई असंसदीय होगा तो वह डिलीट हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। होगा तो डिलीट हो जाएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कम से कम दस मिनट शांती धारीवालीजी ने आम आदमी के ऊपर अपना व्याख्यान दिया, 'आम आदमी को किसने समझा', 'आम आदमी को किसने जाना।'

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ...(व्यवधान) क्यों दर-दर की ठोकरें खाता फिरा था? ए के जैन क्यों दर-दर की ठोकरें खाता फिरा? वह भी तो बेचारा ही था। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अरे, सुन तो लो। आम आदमी पर पांच मिनट तक शांति धारीवालजी ने बोला और इस सरकार का तीन साल से प्रसार-प्रचार हम यहां सुन रहे हैं कि आम आदमी की सरकार है; आम आदमी बहुत खुश है; आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं हैं; किसान को कोई तकलीफ नहीं है; स्टूडेंट को कोई प्राब्लम नहीं है; और गरीब, मजदूर और व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए और इस समाज में एक सेवा की भावना से माननीय वसुंधरा जी ने 108 एम्बुलेंस धन्वन्तरी योजना के नाम से चालू की थी। इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकती थी और उस समय ई एम आर आई कंपनी के साथ पांच साल का अनुबंध हुआ था। हालांकि यह प्रश्न के माध्यम से भी लगा परन्तु उस दिन पूरी बात लोगों तक पहुंच नहीं पाई, माननीय सदस्य तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एक एम्बुलेंस के ऊपर, 84 हजार रुपए पर-एम्बुलेंस, पर-मंथ का कान्ट्रेक्ट हुआ, एम ओ यू साइन हुआ जिसमें दवाई और कंज्यूमर बिल्स, जो ड्रग्स एण्ड कंज्यूमर बिल्स हैं वह भी इन्क्लूडेड था, वह भी कंपनी को खर्च करना था। इस 84 हजार में से पांच परसेंट शेयर उस ई एम आर आई कंपनी का था। तो सरकार के ऊपर एक एम्बुलेंस पर करीब 80 हजार का व्यय आता था। उस एम्बुलेंस के ऊपर तीन ड्राइवर जिन्होंने उनको पायलट का नाम दिया था और तीन ई एम टी जो मेडिकल टेक्निशियन थे...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो, उपाध्यक्ष महोदय, इतना पूछ लो कि इनके समय एम्बुलेंस थीं कितनी कुल? इनके काल में कुल एम्बुलेंस राजस्थान में कितनी थीं?

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न काल नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, तीन ड्राइवर, तीन टेक्निशियन, टेक्निशियन की सैलेरी 6,250 रुपए, ड्राइवर की सैलेरी 5,100 रुपए। पता नहीं, क्या हुआ, सरकार बदलने के बाद ई एम आर आई कंपनी का कान्ट्रेक्ट खतम कर दिया और कान्ट्रेक्ट दिया जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड

(डा. दिगम्बर सिंह)

एक कंपनी है उसको। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड बहुत बड़े लोगों की एक कंपनी है। इसके केवल पांच डायरेक्टर्स के नाम मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इसमें कार्तिक चिदंबरम, जो पी. चिदंबरम साहब, केन्द्रीय मंत्री के बेटे हैं; वायलार रवि के बेटे रवि कृष्णा इसके डायरेक्टर हैं; रवि कृष्णा जी की पत्नी श्रीमती कृष्णा इसकी डायरेक्टर हैं; एक कांग्रेस की राजस्थान की एक महिला नेता श्वेता मंगल, वह इसकी डायरेक्टर हैं और केरल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): श्वेता मंगल विष्णु मोदीजी की भानजी हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। थोड़ा-सा...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): केरल के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के दामाद साफी माथेड़ इसके डायरेक्टर हैं। इन लोगों से आनन-फानन में एम ओ यू करके और यह 108 एम्बुलेंस की जिम्मेदारी इन्होंने सौंप दी। इस कंपनी ने आते ही जो गोरखधंधा शुरू किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 94,899 रुपए में तो उनको कान्ट्रेक्ट साइन किया एक एम्बुलेंस पर एक महीने में। जो 80 हजार रुपए खर्चा आता था राजस्थान गवर्नमेंट पर, वह 94,899 रुपए प्रति एम्बुलेंस प्रति माह खर्चा आने लगा। ड्रग्स और कंज्यूमर बिल्स जो 80 हजार में इन्क्लूडेड थे, वह उसके एक्स्ट्रा...

श्री उपाध्यक्ष: इनकी बात करने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उसके दवाई के पैसे उठाने की बात उन्होंने उठाई है। इसके साथ-साथ ड्राइवरों की संख्या दो कर दी, तीन की जगह; ड्राइवर की आठ घंटे की जगह बारह घंटे की ड्यूटी कर दी, टेक्निशियन की बारह घंटे ड्यूटी कर दी। तीन की जगह दो ड्राइवर, दो टेक्निशियन और सैलरी 6,250 से...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह तो कल हो चुका था, दुरूमियां जी ने जवाब भी दे दिया था। वही रिपीट कर रहे हो आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 6,250 रुपए से घटा दिया, ड्राइवर की सैलेरी घटा दी।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): मैं पूछना चाहता हूं, डाक्टर साहब कह रहे हैं ...(व्यवधान) आनन-फानन में दिया गया; बिहार में क्या हुआ, डाक्टर साहब? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलने दो।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आपने तो आनन-फानन में वहां क्या किया? बिहार में तो आपकी सरकार है, आप पूछ लीजिए ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उनको बोलने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप राजस्थान की चिंता करोगे या बिहार की चिंता करोगे? (व्यवधान) आपकी समझ में तो कुछ आएगा नहीं, काहे को बिना बात टाइम खराब कर रहे हो?

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): सब समझते हैं हम। आनन-फानन में नहीं करते हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक आपको ऐसी इंसिडेंट बता रहा हूं मैं जो रिकार्ड था, इनका बिल पेश किया इस कंपनी ने और पैसे उठाए हैं। एक-एक व्यक्ति के दो-दो बार काल दिखा रखे हैं, एक ही बिल में। ऐसे कम से कम चार-पांच नाम मेरे पास हैं। संतोष नाम का पेशेंट था, उसके दो बार बिल उठाये; हनुमान सिंह नाम का पेशेंट था, दो बार बिल उठाये; माया नाम की पेशेंट थी, दो बार; काली नाम के पेशेंट के दो बार। और तो और, आप इस बात पर ताज्जुब करेंगे कि एक बार में एक एम्बुलेंस कितने लोगों को शिफ्ट कर सकती है, यह भी अपने-आप में एक रिकार्ड इन्होंने बना दिया। एक एम्बुलेंस ने एक बार में 221 आदमियों को शिफ्ट कर दिया। क्या सम्भव हो सकता है? कितना भ्रष्टाचार, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हुआ है।

सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो किया है, वह इसमें शुरू में जो समझौता हुआ था, इसमें समझौता था कि एम्बुलेंस जिस जगह खड़ी होगी, अगर टेलीफोन कॉल आता है तो वहां से एम्बुलेंस रवाना होगी और उस पेशेंट को जो भी नजदीक हास्पिटल है वहां शिफ्ट करेगी और वापस उसी जगह आकर खड़ी होगी। तो उसको एक ट्रिप कहते थे। इस कंपनी को फायदा देने के लिए अधिकारियों ने इस ट्रिप सिस्टम को चेंज कर दिया और तीस किलोमीटर का एक ट्रिप और 30 से ऊपर होगा तो दो ट्रिप। उसके कारण से इसको पैसे ज्यादा देने का जो काम किया है, वह इस सरकार ने किया है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा और भी जो इसमें घपले हुए हैं, वे मैं आपकी जानकारी

(डा. दिगम्बर सिंह)

में लाना चाहूंगा। इतने सब के बावजूद यह मेरे पास एक लैटर है जब 95 हजार रुपये में सौदा तय कर रही थी गवर्नमेंट तो GVKMRI ने लैटर लिखा इनको, उसकी लैंग्वेज पढ़कर सुनाता हूं, "…. once again reiterate that our operation cost per ambulance p.m. currently stands around Rs. 81 thousand p.m. including cost of medicines and disposals."

श्री उपाध्यक्ष: आपको 25 मिनट हो गये हैं। मैं नहीं कहता कि आप बैठिये लेकिन आपको 25 मिनट हो गये हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ये तो होंगे, साहब, कोई बात नहीं। और मैं आपको निवेदन करूं कि इसमें कम से कम पचास करोड़ रुपये का घपला है। सी बी आई से जांच राजस्थान सरकार को इसकी भी करानी चाहिए, यह हमारी मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जब पिछला बजट सत्र चल रहा था तो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम प्रसूताओं को गरम-गरम खाना देंगे, जब डिलिवरी होगी तब। तो मैंने उस समय भी टोका था कि मुख्य मंत्री महोदय डिलिवरी तो सबके घरों में ही होती है, इतना तो एक कामन आदमी भी जानता है कि गरम-गरम खाना डिलिवरी के टाइम पर नहीं दिया जाता, परन्तु फिर भी आपने घोषणा की तो मैंने कहा कि स्वागत योग्य है। मैं भी जब क्षेत्र में गया तो एक-दो अस्पतालों में जाकर मैंने चैक किया कि वास्तव में क्या है। आपने घोषणा कर रखी है कि पांच किलो घी हम प्रसूताओं को देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक किलो घी भी किसी प्रसूता को नहीं मिल रहा है और जो गरम-गरम खाने का दावा इन्होंने किया था केवल पारले-जी के बिस्किट बांट रहे हैं उसके नाम पर। इससे ज्यादा आम आदमी के साथ क्या धोखा कर सकती है सरकार?

आम आदमी-आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की सरकार की बात करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अभी निःशुल्क दवाइयों की, मुफ्त दवा योजना की बहुत तारीफ लोगों ने की है और वास्तव में यह योजना काबिले-तारीफ है, मैं इस भावना के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा परन्तु जिस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया, जिस ढंग से श्रेय लेने के लिए आनन-फानन में इसको शुरू किया, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पांच सदस्य चाहे कांग्रेस के ही हों, की एक कमेटी बना दीजिये और एक-एक अस्पताल में जाकर चैक कर लें, जितनी दवाइयों की लिस्ट है, वास्तव में

(डा. दिगम्बर सिंह)

उतनी दवाइयां उपलब्ध हैं क्या। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस इस योजना के बाद बढ़ गयी है। क्योंकि मरीज जाता है अस्पताल में, दो घंटे लाइन में लगा रहता है, दवाई लिखते हैं पांच और जब काउंटर पर जाते हैं तो दवाई मिलती हैं दो। तो उनको भी फेंक कर मरीज चला जाता है। लोग अब तो चर्चा करने लग गये कि अशोक गहलोत की सरकार में सांप काटे तब भी वह ही दवाई है और खांसी-जुकाम हो जाएगा, तब भी वह ही दवाई है। तो ऐसा जब मरीज का विश्वास उठ रहा है तो काहे की आपकी मुफ्त दवा योजना है?

मैं एक दिन आई हास्पिटल में गया था एस एम एस के अन्दर। मैंने देखा, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी पेशेंट्स की। मैंने देखा एक मरीज को, उसने दस रुपये की पर्ची कटवाई और पर्ची कटवाने के बाद जब काउंटर पर लगा लाइन में तो हाथ में थी सल्फा सीटामाइन ड्रोप्स, एस.एस. ड्रोप्स जिसको बोलते हैं, जिसकी कीमत है 1.75 रुपये। दस रुपये की पर्ची और मुफ्त दवाई लेकर जा रहा है एस.एस. ड्रोप्स और वह भी विवेक फार्मा की जिसकी कोई गारंटी नहीं है। वह कोई स्टैंडर्ड की कंपनी नहीं है। तो ऐसा मरीजों के साथ खिलवाड़ इस योजना के नाम पर जो कर रहे हैं, इसकी भावना को आपने समाप्त कर दिया और मैं निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूं कि इसका खामियाजा निश्चित रूप से आपको भुगतना जरूर पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत देर से तारीफ हो रही थी राहुल जी की और सोनिया जी की और...

श्री उपाध्यक्ष: आप कोई ऐसा व्यक्तिगत आक्षेप मत करना।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूंगा, मैं आक्षेप नहीं करूंगा। मेरे भरतपुर जिले के गोपालगढ़ की इस घटना का जिक्र तो मैं करूंगा। मेरा नैतिक अधिकार है। मैं भरतपुर जिले का रहने वाला हूं। भरतपुर जिले के अन्दर जो गोपालगढ़ कांड हुआ और उसमें जिस तरह से दस लोगों की मृत्यु हुई, आपके राहुल गांधी जी ने वहां विजिट किया। राहुल गांधीजी आये और भरतपुर जिले के शातिर बदमाश जिनके स्टैंडिंग वारंट निकले हुए थे उनकी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर राहुल गांधीजी ने यात्रा की। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वह मोटरसाइकिल बिना नम्बर की, चोरी की और राजस्थान सरकार को पता तक नहीं। राजस्थान के किसी अधिकारी को, मुख्य मंत्रीजी को, कांग्रेस के किसी नेता को पता नहीं। हां, पता था तो हमारे क्षेत्र के एक नेता को जरूर मालूम था जिन्होंने सारा ये...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ये आपको पता है क्या कि मोटरसाइकिल चोरी की है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बिलकुल, ये रही। मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे पास में फोटोग्राफ्स हैं, उसमें दो व्यक्ति एक सरफू नाम का और एक बिल्ला नाम का व्यक्ति है, ये दोनों स्टैंडिंग वारंट वाले एच.एस., हिस्टरी-शीटर हैं। इनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर यात्रा करके राहुल गांधी जी क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश में, इस राजस्थान में? एक आम आदमी की सरकार, आम आदमी से मिले राहुल गांधी जी और इसके साथ-साथ जब रवाना होने लगे राहुल गांधी महोदय, तो यह लिखा हुआ है 'गले लगाते हुए वापस' 'गले से लगा हुए रवाना'; गले से किसको लगाया राहुल जी ने, वह सरफू और वह बिल्ला जो एच.एस. हैं और वह कहकर गये हैं सबके सामने कह कर गये हैं कि कोई भी बात हो तो मेरे से दिल्ली में आकर मिल लेना। ये आम आदमी की सरकार दे रहे हैं, यह इनके युवराज का करेक्टर दिखा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की जब बात हो तो कम से कम ज्यादा बढ़-चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान है।

मैं आपको बिजली की जो स्थिति सरकार ने की है, उसमें मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दो सौ सदस्य हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, अगर दिल पर हाथ रखकर पूछें हमारे पक्ष वाले विधायक महोदयों से भी, तो बिजली का यह सत्यानाश हुआ तो हुआ कैसे, हमारी समझ में आज तक नहीं आया। पिछली सरकार के समय गांव में चौबीस-चौबीस घंटे, बाईस-बाईस घंटे डोमेस्टिक लाइट आठ-आठ घंटे जो कृषि की लाइट थी, वह मिलती थी। आज ट्रांसफार्मर्स की बिक्री हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय। बाजार के अन्दर बिक रहे हैं, पैसे दे आता है किसान तो ट्रांसफार्मर मिल जाता है। जब तक दस-दस बार विधायक सिफारिश नहीं करे तब तक ट्रांसफार्मर ए.ईएन इश्यू नहीं करता। तो आखिर हुआ तो हुआ क्या इन बिजली कंपनियों को? कितने तो दाम बढ़ा दिये, रेट्स बढ़ा दिये बिजली के। किसान के बढ़ा दिये, व्यापारियों के बढ़ा दिये। शहर में, गांव में, सब जगह बढ़ा दिये, उसके बावजूद लाइट अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्या सत्यानाश सरकार का तीन साल के अन्दर हुआ है?

मैं आपको थोड़ा सा, हमारे मंत्री महोदय गये क्या? अभी हमारे उद्योग मंत्री महोदय विराजे थे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बात करना चाह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: यहीं करोगे या अलग से मिलकर करोगे, दोनों?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, यहीं करूंगा। चौड़े-धाड़े ही करूंगा मैं तो।

कानून-व्यवस्था के जो हाल हैं, जेलों का जो हाल है, उपाध्यक्ष महोदय, शर्म आती है कई बार जब हम अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं। सारी जेलों में अभियान चल रहा है सर्च करने का। क्या जेल प्रशासन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जेल के अन्दर जो बंद हैं कैदी, उनको इस तरह की सुविधा मुहैया नहीं करायी जाए। कौन कराता है मोबाइल उपलब्ध उनको? कौन कराता है उपलब्ध उनको सिगरेट? कौन कराता है दारू उनको उपलब्ध वहां जेल के अन्दर? यह सारा जेल प्रशासन कराता है और पूरी ऊपर से नीचे तक की मिलीभगत का यह परिणाम है। जेल के अन्दर बैठा-बैठा शातिर बदमाश, वह कहता है कि तुम मर्डर करो तो उसकी आवाज मुझे सुनाना। वह अन्दर आवाज सुन रहा है कि फायर किया है और उसका मर्डर हुआ है। ये कानून-व्यवस्था है? ये आम आदमी की सरकार है? भाषण देने के लिए तो बहुत ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु वास्तव में जब तक धरातल पर नहीं आयेंगे, अभी तो हवा में उड़ रहे हैं, जनता ने वैसे तो एक तरह से तय ही कर लिया है कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है।

उद्योग में अभी जो एन आर आई की बात हुई थी, उस पर काफी अभी चर्चा हुई कि अभी यह जो एन आर आई का सम्मेलन हुआ, हमने तो उनको देश प्रेम की भावना के कारण बुलाया है, हमने निवेश के लिये नहीं बुलाया है। राजस्थान में आपका बहुत बड़ा उद्योग है, न कोई बेरोजगारी है, इतना पैसा हर आदमी के पास है कि हमें जरूरत ही नहीं निवेश की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश में वह वातावरण आप तैयार नहीं करेंगे, चाहे कितने भी उद्योगपति, कितने भी एन आर आई को बुला लीजिए, आप उनसे निवेश की उम्मीद नहीं कर सकते, आपने कितना भी पैसा खर्च किया होगा परन्तु राजस्थान को क्या मिला, राजस्थान को वही ढाक के तीन पात मिले, कुछ नहीं मिला। उसके ऊपर भी हमारे अहंकारी मंत्री का व्यवहार जो उनके साथ रहा है, मेरी एक-दो से बात हुई है तो बहुत तारीफ कर गये कि वाह, साहब, आपके कैबिनेट के कितने बढ़िया-बढ़िया मिनिस्टर आपके राजस्थान में हैं जो बाहर से आने वाले लोगों को कितना बेइज्जत इन लोगों ने किया है। हम एन आर आई को तो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं पर राजस्थान में हमारे खुद के जो निवेश करने वाले लोग हैं, जिनके बड़े-बड़े निवेश भी हैं, उनको कोई सुविधा देने का प्रयास नहीं करते। आज गुजरात की

(डा. दिगम्बर सिंह)

तरफ क्यों भागता है आदमी? यहां वातावरण क्रियेट हुआ था, यहां राजस्थान में वातावरण बना था परन्तु तीन साल में जो वातावरण उद्योग का था उसको समाप्त करने का श्रेय इस सरकार को गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। किसान हितैषी यह सरकार, आम आदमी की यह सरकार है, मैं अभी जोधपुर जा रहा था, बायतू में एक कार्यक्रम में गया था तो जोधपुर में किसानों ने रास्ते में मुझे रोककर एक ज्ञापन दिया। बोरानाड़ा एक गांव पड़ता है, बोरानाड़ा के किसानों की 3,151 बीघा जमीन का रीको अधिग्रहण कर रही है। मैंने कहा कि उनको जरूरत होगी, तो किसानों ने मुझे बताया 8 लाख स्क्वायर मीटर जमीन तो अभी खाली पड़ी है रीको में, कोई लेने वाला नहीं है और ये तीन हजार बीघा से ज्यादा में किसानों को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

तो मैं समझता हूं कि आम आदमी की सरकार इससे बढ़िया और क्या हो सकती है? किसान को उजाड़ दो, बरबाद कर दो। किसान की फसल पर तो बहुत जोरदार कर ही दिया, आपने कहा कि हम गिरदावरी करा रहे हैं, हम फलाना करा रहे हैं, कुछ नहीं मिलना है। किसान को तो रोना है, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह अंधी, बहरी और गूंगी सरकार किसान विरोधी सरकार है, एक गरीब का मजाक उड़ाने वाली सरकार है। यह वही पार्टी है जिसने कहा कि जो गांव में 26 रुपये कमाता है वह गरीब नहीं है, जो 32 रुपये शहर में कमाता है वह गरीब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 26 रुपये कमाने वाला, 32 रुपये कमाने वाला अपने बच्चों का पेट भर सकता है?

मैं कहना चाहूंगा कि यह जो राज्यपाल का अभिभाषण था यह बिलकुल एक असत्य का पुलिंदा है, इसमें बहुत ज्यादा असत्य बातें हैं और वास्तव में इस गवर्नमेंट का कोई अचीवमेंट ही नहीं है जिसको ये उसमें लिख सकते थे। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री करण सिंह राठौड।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता बड़ी आशा के साथ सरकार को चुनती है और

(श्री करणसिंह)

जनता का राजा चुनने का फैसला स्वयं का होता है और जनता परेशान होकर राजा को बदलती है। पिछली सरकार में कुछ कमियां रही होंगी, उस कारण से पूरे राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया और सरकार बनने के बाद राजा की सोच जनता के प्रति क्या रहे, उससे पता लगता है कि राजा कैसा है और जनता के बारे में कितना विचार रखते हैं। तीन वर्ष में तीन सौ फैसले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो लिये हैं, उनको आप उठाकर देखें, उसमें एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो गांव के गरीब या उसके जीवन स्तर को सुधारने का उसमें जिक्र नहीं किया गया हो। सारे फैसले उनके लिये किये गये हैं जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से पिछडे हुए लोग हैं। चाहे वे शहर में रहते हों, चाहे वे गांव में रहते हो, चाहे वे मजदूरी करते हों, चाहे वे खेती करते हों, चाहे वे धंधा करते हों, उस व्यक्ति को एक लक्ष्य बनाकर उनके लिये कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं।

मैं लगातार तीन दिन से बहस को सुन रहा हूं और तीन दिन की बहस को सुनने के बाद, अभी मैंने दिगम्बर सिंह जी को भी सुना, मैंने तिवाड़ी जी के चुटकले भी सुनें, राव राजेन्द्र सिंह जी के जो आर्थिक आंकड़े थे वे देखे और जसवंत सिंह जी यादव, जिनमें कोई दम नहीं है, उनकी बात भी सुनी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभी तो मैं बोलूंगा।

श्री करणसिंह (छबड़ा): अच्छा, मैंने आपका इसलिए बोल दिया ताकि आप व्यवधान नहीं करें क्योंकि अभी आपको बोलना है।

आज मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यह कहूंगा कि एक एक फैसले को हमने बड़ी गम्भीरता से सुना है। सरकार की जो योजना बनती है और सरकार क्या कर रही है, उसको विधान सभा में आकर राज्यपाल अभिभाषण के माध्यम से हमको बताते हैं और पूरी जनता में संदेश जाता है कि सरकार यह काम कर रही है। इसमें क्या कमियां हैं, जिस पर हम और आप बहस करें और उसका समाधान करें। राज्यपाल के अभिभाषण को लोगों ने असत्य का पुलिंदा बता दिया। मुझे शर्म आती है कि बिना पढ़े ही उसे 'असत्य का पुलिंदा' बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में 10 लाख गरीबों के लिये मकान बनाने की बात हमारे मुख्य मंत्री जी ने की। उस गरीब ने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा पक्का मकान बन जायेगा, उस गरीब ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि 50 हजार में मुझे सरकार मकान देगी, पक्का मकान बनेगा, आरसीसी की छत डलेगी; ईट लगाऊंगा; सीमेंट लगाऊंगा; जो कभी सोच नहीं

(श्री करणसिंह)

सकता था ...(व्यवधान) भाई साहब, प्लीज, आप थोड़ी देर साइलेंट रहेंगे? प्लीज, प्लीज। मेरा निवेदन यही है कि जिस तरह के फैसले लिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे छबड़ा क्षेत्र में गांवों में 2,200 मकान बन रहे हैं और जिस मकान में मैं घुस कर देखता हूं तो गरीब का परिवार भाग कर आता है और खुश होता है और कहता है कि यह मकान हमारे को अशोक गहलोत जी ने दिया है हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पक्का मकान होगा। उसको यहां असत्य का पुलिंदा बताया जा रहा है। बिना पढे असत्य का पुलिंदा, देखा ही नहीं, वह जिक्र तो आप कर ही नहीं रहे हैं। कौनसा मकान बन रहा है, कभी देखा ही नहीं। जिसका मकान बन रहा है, उसमें आपने कभी जाने का प्रयास ही नहीं किया। आपके दिमाग में यह घुस गया कि इसको कांग्रेस ने पैसा दे दिया है, इस गरीब का पक्का मकान बन गया है, यह अब हमारा है ही नहीं। इस तरह के विचार आप रखेंगे तो गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का लाभ आप नहीं देख पायेंगे। 3 लाख 94 हजार मकान हमारे बनने जा रहे हैं।

शहर को भी हमने नहीं छोडा। नगरपालिका क्षेत्र में भी, 5 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 15 लाख मकान हम बनाने जा रहे हैं। ऐसा फैसला गरीब के लिये आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया, इतिहास में नहीं है इस तरह का उदाहरण। अगर कोई बता दें तो मैं बहस करने को तैयार हूं ।

आप देखिए, सारी योजनाएं गरीब के प्रति हैं। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, कभी 2 रुपये किलो में अनाज हमने सोचा नहीं था कि गांव के आदमी को 2 रुपये किलो में अनाज मिलेगा। 2 रुपये किलो गेहूं जिसको मिलता है, उस गरीब के घर में आज खुशी है। क्योंकि हम देखते हैं और हमारे देश में होता आया है कि लोग भूख से मरते थे, कई लोग अकाल में भूख से मर जाते थे। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस तरह की योजना बनाई है कि आज घर-घर में लोगों के अनाज है। 2 रुपये किलो में अनाज लेता है और जो मिलता है, उसमें से भी बचाते हैं, उसको बेचकर वे लोग अपना खर्च चला रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। अगर कोई कल्याणकारी योजना चलती है तो उसका जिक्र हमें करना चाहिये, उसकी प्रशंसा करनी चाहिये चाहे सरकार कोई सी भी हो।

इसी तरह से गांव में आटा मिल रहा है, गांव में दाल मिल रही है और एक और बहुत अच्छा काम जो हमारे अशोक गहलोत जी ने किया है, उसका

(श्री करणसिंह)

मैं जिक्र करना चाहता हूं। बी पी एल को 2 रुपये किलो गेहूं और ए पी एल को जो गेहूं देते थे, उसको बंद करके जो आटे का सिस्टम किया है, मैं सभी माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, हर विधान सभा क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, आप अपने क्षेत्र में जाकर उस गरीब व्यक्ति को 8.60 रुपये में जो आटा मिलता है वह दिलाने का प्रयास करें। पहले क्या होता था, ए पी एल का गेहूं दाल मिलों में जाता था और दाल मिलों में जाकर बाजार में वह आटा 15-20 रुपये किलो बिक कर ब्लैक होता था। उसको रोकने के लिये 8.60 रुपये में आपको आटा मिलेगा। जब 8.60 रुपये में आटा खाएगा, गेहूं का बाजार भाव 12 रुपये होता है और 8.60 रुपये में अगर गेहूं का आटा मिलता है और अच्छी क्वालिटी का आटा मिलता है तो उस गरीब से पूछिये आप कि उस पर जो महंगाई की मार थी, उससे बचने के लिए जिस तरह सरकार की योजना चल रही है, वह गरीब के भले के लिए अच्छी कल्याणकारी योजना है।

साथ ही मैं मुख्यमंत्री आवासीय योजना के साथ नि:शुल्क दवा योजना, इतनी बेहतरीन और इतनी कल्याणकारी योजना हम जीवन में कभी सोच नहीं सकते थे। सबसे महंगा इलाज; सरकारी अस्पताल में जाए उसके लिए भी सोचना पड़ता था, जेब में पैसा होगा तो डाक्टर के पास जाने की सोचना पड़ता था। अब जेब में पैसा नहीं हो तो भी गरीब आदमी इलाज करा सकता है। फिर डाक्टर की फीस के पैसे की जरूरत अलग पड़ती थी और दवा के पैसे की जरूरत अलग पड़ती थी। आज दोनों चीजों को मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह किया है, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सरकारी अस्पतालों में आज जो भीड़ कम हो गई थी, अभी माननीय दिगम्बर सिंह जी ने कहा है, कमियां बहुत निकाल सकते हो, कुछ तो बड़ाई करो। गांव के गरीब आदमी की तरफ जाकर देखिये जिसको 500 की दवाई, 1000 की दवाई, ग्लूकोज की बोतल, हड्डी जोड़ने की दवाई, फ्री मेडिसिन जब उसको मिल रही हैं, उससे जाकर पूछिये किसने चालू की कल्याणकारी योजना, कौन सरकार कर रही है यह काम, आज तक किसी सरकार ने किया क्या। आप कमियां निकाल लाते हैं कि दवाईयां नहीं मिल रही, तीन दवाई मिल रही है, चार दवाई मिल रही है, बाहर जाना पड़ रहा है; व्यवस्था ठीक नहीं है; डाक्टर ठीक नहीं हैं, आप जान-बूझकर उस स्कीम को फैल करना चाहते हैं। सरकार की योजना है, गरीब को लाभ मिल रहा है। गांव-गांव घूमते हैं, गांव में जाने के बाद आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, गांव की जनता हमारी बात सुनने को तैयार है, कहीं

(श्री करणसिंह)

पर हमारा विरोध नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आम गरीब जनता पूरी तरह कांग्रेस की तरफ हो रही है। आज तक किसी सरकार ने इस तरह की योजना नहीं बनाई । फ्री इलाज, फ्री मेडिसिन, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

साथ ही साथ जननी सुरक्षा योजना, हमारे साथी ओम बिरला जी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, गांव में गरीब महिला का जापा होता था, इलाज के बिना मां मर जाती थी; उसके पेट में जो बच्चा होता था, वह भी मर जाता था। उसको बचाने का जिम्मा सरकार ने लिया है। उसका अस्पताल जाने का किराया हम देंगे, आने का किराया हम देंगे और गरम-गरम हलवा और दूध सरकार पिलाएगी। ऐसी योजना कभी थी क्या? अगर ऐसी योजना नहीं थी और हमने चालू की तो आपको धन्यवाद देना चाहिये राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त पर, परन्तु कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ तीन बातें बोल रहे है एक तो 108 का टेण्डर हो गया, 108 का टेण्डर क्यों बदल दिया, पता नहीं क्या गड़बड़ थी 108 के टेण्डर में,108 का टेण्डर होगा कोई दूसरी दुकान होगी उसको छीनकर इधर कर दी तो गड़बड़ लगा; दूसरे, आपके जो प्रवासी भारतीय आए उसमें दस करोड़ खर्च कर दिये, हम जब बोलेंगे एक-एक, दो-दो करोड़ तो आपने हाड़ोती उत्सव में, बूंदी उत्सव में इवेंट मैनेजमेंटों को करोड़ों रुपये लुटा दिये। अगर बोलेंगे तो पोल खुलेगी पर मेरा भाषण खतम हो जाएगा, इसलिए मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। लड्डू कितने बंटे, पटाखे कितने चले, ओम जी, क्या-क्या नहीं हुआ। क्या-क्या रंगारंग कार्यक्रम हुआ झालावाड़ में, हेमामालिनी नाची, धर्मेन्द्र आए। हेमामालिनी-धर्मेन्द्र गरीबों को दवा नहीं देंगे; हेमामालिनी, धर्मेन्द्र गरीबों को भोजन नहीं देंगे; हेमामालिनी, धर्मेन्द्र गरीब के लिए मकान नहीं बनायेंगे; और हेमामालिनी, धर्मेन्द्र किसी गरीब के मकान में लाइट नहीं लगायेंगे। गरीब के घर में लाइट लगाएगी तो कांग्रेस लगाएगी। कांग्रेस की आजादी के बाद से सोच रही है गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब आदमी को आगे उठाने के लिए। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, इनकी परिभाषा आप जानते ही नहीं हैं; सामाजिक न्याय, क्या होती है समानता। ओम बिरला जी मोटे, करण सिंह मोटे, पर गांव का हरिजन मोटा होना चाहिये, जब हरिजन मोटा हो जाएगा तो सामाजिक समानता होगी। एक मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग बनेगा तो सामाजिक समानता होगी। गांव का एक गरीब किसान आगे बढ़ेगा तो सामाजिक समानता होगी।

(श्री करणसिंह)

राज बदल गया, देश बदल गया और लोगों की सोच बदल गई, उस सोच के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा, ठुमका, क्रिकेट का मैच करा लेंगे, हम जीत जाएंगे। क्रिकेट से जीतने वाले नहीं हैं, गरीब के लिए योजना बनाइये। आज भी गांव का 80 परसेंट तबका गरीब है उसके बारे में आपने योजना बनाई? हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं, किसी को अछूता नहीं छोड़ा, सबको टच करने का प्रयास किया है, आप उठाकर देखिये। तीन साल में तीन सौ फैसले, पढिये तो सही। पिछली बार बजट सत्र चल रहा था, मैं भी परेशान था कि अभी तक सरकार की कोई उपलब्धि दिख नहीं रही है, मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा कि साहब, कुछ मजा ही नहीं आ रहा, मगर अब मजा आने लग गया। इस साल मजा आने लग गया और इस बजट के बाद तो और मजा आएगा, चिंता मत करिये आप। हम गांव में जाकर ऐसा बजट देंगे, ऐसा बोलेंगे कि आपका सूपड़ा साफ कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक साल पहले मुझे भी डर था, मैं भी मुख्य मंत्रीजी से लड़ता था; मैंने कहा, कुछ दिख ही नहीं रहा; वह मजबूरी थी हमारी। आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गए, लोक सभा आ गई, यह आ गए, हमने नियम बनाए उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा।

श्री उपाध्यक्ष: बिरला जी, समझ रहे हो ना?

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरे पुराने मित्र हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। (व्यवधान) वे गम्भीरता से सुन रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना, जब उस महिला के बच्चा होता है और जब जापा होकर भेजते हैं, करण सिंह पत्र लिखता है कि आपके बच्चा हुआ है आपको अस्पताल में दवाई, हलवा मिला या नहीं मिला, पैसा मिला कि नहीं मिला; कि नहीं, साहब, दवा भी मिली, दलिया भी मिला, बिस्कुट भी मिला और 1,400 रुपये लेकर आई हूं, किराया भी सरकार ने दिया है। लोग अभी बोल रहे थे, बी पी एल परिवारों को घी नहीं मिला, आप मुझे पांच नाम बता दें, मैं सदन में चैलेंज करना चाहता हूं, किसको बी पी एल का नहीं मिला, अगर कोई हो तो आप नाम दे दीजिए, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं बताऊं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नम्बर नहीं है। बिरला जी से पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे ।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बी पी एल में उसको मिलता है, आपको नियम की जानकारी नहीं होगी, पहली बी पी एल में पहला बच्चा होने पर ही मिलेगा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): आपसे कम पढ़ा-लिखा नहीं हूं, सब जानता हूं नियम कानून। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपको दूसरे बच्चे पर नहीं मिलेगा। हो सकता है, आपका दूसरा बच्चा हो। (व्यवधान) दूसरे-तीसरे पर आप इंतजार मत कीजिए, आप सोचो कि दूसरे पर मिल जाएगा, तीसरे पर मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): राठौड़ जी, मुझे तो यह लगता है आपके खुद के ही ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): पहले बच्चे पर देंगे, चहेते को देंगे, मोटे आदमियों को देंगे ही नहीं, गरीब को देंगे, चहेते को देंगे। (व्यवधान) आप इंतजार मत कीजिए, आप तो वैसे ही मोटे लग रहे हो।

इसी तरह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी कानून। कभी जनता सोच सकती थी कि गांव के गरीब आदमी को काम की गारंटी दी जाएगी? माननीय सदस्यों, जिस तरह का कानून बना है हमारे लिए और पूरी राजस्थान की जनता के लिए, बहुत ही लाभदायक योजना है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी जो निठल्ले थे, जो काम नहीं करते थे, गांव की गरीब जनता को परेशान करते थे, उनको पाबंद करके यह कानून बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इतिहास में पहली बार इस तरह के फैसले हुए हैं, जो फैसले अब होने वाले हैं, उन फैसलों को हमारी सरकार ने पहले ले लिये हैं। मैं विपक्षी लोगों से कहना चाहता था, आपने अपना समय लड़ाई-झगड़े में बेकार में व्यतीत कर दिया। तीन साल तक आपका कार्यकाल आरोप-प्रत्यारोप में गुजरा। आपका तीन साल का कार्यकाल था, एक-दूसरे के आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार की बातें चलती रहीं और हमारे तीन साल में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा और किसी के ऊपर दाग लगा उन मिनिस्टरों को हमने हटा दिया। एक मिनिस्टर नहीं छोड़ा हमने, एक मिनिस्टर नहीं छोड़ा। मगर आपके ऊपर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमराराम जी, आप बीच में नहीं आएं। सीधी बात हो रही है। यह दोनों एक ही....(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): जिसकी भी शिकायत मिली, उसको हटा दिया गया मगर अमराराम जी, इनके यहां तो एक को भी नहीं हटाया गया। इनको तो ले-लेकर फ्री करके ऊपर नीचे किया, हिसाब-किताब करके उसको ऊपर-नीचे

(श्री करणसिंह)

किया। पांच साल तक उन लोगों को बिठाए रखा जिनका लोग चेहरा नहीं देखना चाहते थे। वही पुरानी बोटल, वही पुरानी शराब, पुरानी शराब को पुरानी बोतल में भरकर वापस वैसा ही ...(व्यवधान) करना चाहते थे। वही पुरानी बोतल, वही पुरानी शराब। अब एट पी एम का जमाना नहीं रहा, ओम बिरला जी। अब एट पीएम कोई नहीं पीता, एट पी एम का टाइम गया। जब से आपका टाइम गया तब से एट पी एम गया, अब तो सिग्नेचर और ब्लेन्डर्सप्राइड, टीचर्स और ब्लैक डाग का जमाना आ गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि आपने कहा था कि आबकारी विभाग द्वारा आठ बजे तक का समय करने के बाद इतने परसेंट एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ गई, इतना फायदा कैसे हो गया। जमाना बदल गया, लोग महंगी शराब पीने लग गये। कच्ची शराब नहीं पीते हैं अब, लोग स्टैण्डर्ड से जीने लग गये। इन्कम सोर्स बढ़े हैं, अवैध धन्धें बंद हुए हैं, इसलिए, ओम बिरला जी, एट पी एम का जमाना गया। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे आबकारी विभाग का मैनेजमेंट सिस्टम है, किस- किस को बंद किया और रेवेन्यू को बढ़ाया । इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक-एक पाइंट का मैं जवाब दे सकता हूं अगर मुझे समय मिलेगा तो।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कहीं जाना भी है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): किसानों की बात करते हैं, हम किसान नेता हैं, किसानों को आपने जिस तरह से बरबाद किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, छबड़ा क्षेत्र के किसानों के लिए, अभी पाले की बात चल रही थी, 2006 में, आदरणीय भरत जी साहब बैठे हैं, मेरे झालावाड़ के लोग बैठे हैं, पूरे झालावाड़, बारां जिले में ओलावृष्टि हुई। पाले से मेरे क्षेत्र में अफीम नष्ट हुई, धनिया नष्ट हुआ, गेहूं नष्ट हुआ। एक किसान को मुआवजा नहीं मिला। सरकार किसकी थी? कौन जिम्मेदार था? कौन भाषण देता था यहां आकर के? यहां भाषण देने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई से सामने आइये आप। आपकी सरकार में आपने किसको दिया? किसानों को मुआवजा नहीं दिया। परवल में जमीन ले ली किसानों की, 30-35 हजार मुआवजा दिया। और इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने जब करण सिंह एम.एल.ए. बना और कांग्रेस के प्रति जनता ने विश्वास किया, तीन लाख रुपये बीघा का मैंने किसानों को मुआवजा दिलाया है। ये जितेन्द्रसिंहजी, बिजली मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, 20 मिनट हो चुके हैं आपके।

श्री करणसिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हाड़ौती से हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, 3 लाख रुपये बीघा दिया है मुआवजा! बाप रे बाप!

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको डिस्टर्ब मत करिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 3 लाख रुपया बीघा! विधान सभा में बोल रहे हो, चौपाल में नहीं बोल रहे हो। 3 लाख रुपये बीघा दिया है आपने?

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह 3 लाख बीघा पड़ा है। 2 लाख 85 हजार मिला है, बोनस मिलाकर। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप हाड़ौती के हैं, ओम बिरला जी हाड़ौती के हैं और पूर्व मुख्य मंत्रीजी भी हाड़ौती की हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अजमेर सम्भाग का हूं। थोड़ा सोच कर बोलिये आप, मैं अजमेर सम्भाग से हूं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): किसानों की बिजली दर हमने नहीं बढ़ाई; किसानों के लिये हमने मुआवजा बढ़ाया। आपको और सोनियाजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी हमारा भूमि अधिग्रहण का कानून बनने जा रहा है जिससे किसानों को जो डर बैठता था कि किसानों की जमीन हम सस्ते दामों पर ले लेते थे, आप पावर प्लाण्ट बनाएं, चाहे इण्डस्ट्री लगायें, आज हमारे मनमोहन सिंहजी के नेतृत्व में जो भूमि अधिग्रहण कानून बनकर आ रहा है, उसके लिये मैं तारीफ करता हूं। इस तरह के कानून बनने के बाद किसानों का शोषण नहीं होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस के शासन में पहली बार हाड़ौती के अन्दर सी.एस.आर. पालिसी अगर लागू की तो मेरे क्षेत्र में लागू कराई। 32 करोड़ रुपये मैंने सी.एस.आर. पालिसी के तहत गांव के डवलपमेंट के लिए लिये हैं। राजस्थान में हाइएस्ट मुआवजा मुझे मिला है, छबड़ा क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी ने मुझे दिये हैं। पूर्व मुख्य मंत्रीजी उठकर चली गयीं, मैं उनसे कहना चाहता था, मैं उनके पास गया था, किसानों की बात सुनो, किसानों को मुआवजा दो। मगर जो पूर्व मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी थे, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से मुझे नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा, करण सिंह कांग्रेस का है, अगर आप इससे मिलेंगे, यह कर देंगे तो यह हो जाएगा, इसलिये उससे मिलो ही मत। सारे किसान बरबाद हो गये। यह किसानों के प्रति आपकी सोच रही है।

आप बोल रहे हो, साहब, किसानों को खाद नहीं मिला। किसानों को

(श्री करणसिंह)

खाद की वास्तव में किल्लत रही है और यह गम्भीर विषय है किसानों का। इस साल किसान खाद के लिये परेशान रहे। मैं सदन को बताना चाहता हूं, किसान को खाद चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। इनकी समय पर व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो हमारा हाल भी वह हो जाएगा जो हाल इनका है। खाद की व्यवस्था में किसान परेशान रहे हैं और ब्लैक बहुत हुआ है। अधिकारियों की नेग्लीजेंस रही है, इस डिपार्टमेंट में इस बार। आदरणीय भरतसिंहजी को भी मालूम है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, खाद की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह शांती धारीवालजी को बता रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप आपका काम कर लेने दीजिए थोड़ी देर तो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक-एक डिपार्टमेंट ले लीजिए आप। ऊर्जा के क्षेत्र में, कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजली के क्षेत्र में। ओम बिरला जी और आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि हमारी सरकार ने हाड़ौती को नम्बर-एक पर छोड़ा है, हाड़ौती में हम उत्पादन के क्षेत्र में नम्बर-1 होने जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा बिजली उत्पादन का केन्द्र अगर बनने जा रहा है तो हाड़ौती बनने जा रहा है। इसके लिये मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका श्रेय भी कांग्रेस सरकार को जाता है। आपके राज में यूनिट लगी आनन-फानन में छबड़ा में, मगर किसान बरबाद कर दिये। कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे टाइम पर जो प्रोजेक्ट आये हैं, चाहे लेट हुए हों मगर उन प्रोजेक्ट से किसानों को बर्बाद नहीं होने दिया और जनता की भलाई की बात की। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, हाड़ौती क्षेत्र को उत्पादन नगरी बनाने वाले या उत्पादन जोन बनाने वाले, इसमें अशोक गहलोतजी को और हमारे बिजली मंत्रीजी को, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं कमी नहीं है। जिस तरह से हमारे पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 7750 मेगावाट, निजी क्षेत्र में 3,840 मेगावाट, सोलर ऊर्जा में कभी सोचा ही नहीं था, पवन ऊर्जा, बायो गैस पर इतने प्लाण्ट जिस तरह से हम कर रहे हैं और जिस तरह से, मंत्रीजी, आप कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी वालों का अगले साल मुंह बंद हो जाएगा। 24 घण्टे बिजली मिलेगी प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद और चुनाव जब

(श्री करणसिंह)

आयेंगे ना, बल्ब बंद नहीं होने देंगे। ध्यान रखना, अशोक गहलोतजी नाम है उनका, बल्ब बंद नहीं होने देंगे; बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका, हमारा बल्ब बंद नहीं होगा। बल्ब फ्यूज कर देंगे आपका। चिंता मत करो, अभी दो साल बाकी हैं। यह बजट सत्र अभी चल रहा है... (व्यवधान) गांव में जाएंगे और जा रहे हैं। गांव में अभी भी जा रहे हैं। अभी भी जा रहे हैं। कोई पाप नहीं किया कांग्रेस ने। कहीं डरने की किसी को जरूरत नहीं है, कांग्रेस के साथियों को। कोई गलत काम नहीं किया हमने। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की। गरीबों के उत्थान की बात की है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पाप करेंगे तो मरेंगे।

इसलिये मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से जनता के लिये, गांव के गरीब के लिये, किसान के लिये, बिजली में, इण्डस्ट्री में, सड़क पर, एजुकेशन में, राइट-टू-एजुकेशन, राइट-टू-एजुकेशन आ गया, ओम बिरलाजी, कहां सो रहे हो? राइट-टू-एजुकेशन आ गया, घबराइये मत आप, सारे स्कूलों के भवन बनाएंगे, सारे स्कूलों में भोजन कराएंगे बच्चों को। जो मास्टर विहीन स्कूल ऐसा होगा, सारे स्कूलों में मास्टर होंगे। (व्यवधान) सारा सिस्टम बदला जाएगा। एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा। जो मास्टर विहीन स्कूल हैं, उनमें भी मास्टर होंगे, हिन्दुस्तान में एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा।

तो आपको बताना चाहता हूं मैं, सारी जिस तरह की स्कीम्स बनकर आ रही हैं, केन्द्र से, राज्य सरकार से, उनमें कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस तरह हमारी योजनाएं चल रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनमें आम जनता को टच किया गया, गरीब को टच किया गया, अल्पसंख्यक को टच किया गया, एस.सी. को टच किया गया, किसान को टच किया गया और शहर के लोगों को भी टच करने का पूरा प्रयास किया गया है।

इसी के साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को बताऊंगा। ओम बिरलाजी ने एक बात कही थी, गांव का गरीब आदमी, भाषण बहुत जोर-शोर से, गांव के छोर पर बसने वाला, उस गरीब आदमी का कौन जिम्मेदार होगा। वह लाइट के बल्ब में पढ़ रहा है। ओम बिरलाजी, आजकल कोई चिमनी में नहीं पढ़ता है। आजकल तो गांव में घास काटने वाला भी हीरो-होण्डा पर जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इन दोनों के बीच में अपन न बोलें तो चलेगा।

श्री करणसिंह (छबड़ा): गांव में घास काटने वाला भी हीरो-होण्डा पर जाता है और साथ में मोबाइल लेकर जा रहा है। साथ में राजीव गांधीजी की जो स्कीम चलाई है, राजीवजी का सपना था, 21वीं सदी का भारत कैसा होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये डिस्टर्ब करेंगे, इनका नाम मत लो अभी। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज वह हमारा सपना पूरा हो रहा है। राजीवजी ने कहा था कि 21वीं सदी का भारत कैसा होगा। गांव का किसान आगे बढ़े और उसके तहत राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये गये। अभी राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की लोगों ने निन्दा की। मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, कृपा करके, उसकी निन्दा नहीं करें। उस राजीव गांधी सेवा केन्द्र को हम जिस तरह बनाने जा रहे हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये दिये। हमारे आदरणीय भरतसिंहजी ने पंचायत समिति में 25-25 लाख दिये। पूरे राजस्थान में आप अनुमान लगा लें कि नरेगा के माध्यम से हमने कितना पैसा दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर आ रहा है, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। उस गांव के आदमी को अब भटकना नहीं पड़ेगा, पंचायत समिति की तरफ। उस गांव के आदमी को नकल लेने के लिये तहसील में जाना नहीं पड़ेगा। उस गांव के गरीब के लिये, जन्म-मरण प्रमाण-पत्र के लिये शहर में नहीं जाना पड़ेगा। वह सारा सिस्टम राजीव गांधी केन्द्र पर हम करने जा रहे हैं।

दूसरी बात और कहना चाहता हूं, अब गांव पिछड़ा नहीं रहेगा। उस गांव को, पूरी पंचायत को पंचायत समिति से जोड़ देंगे और पंचायत समिति को कलेक्ट्रेट से जोड़ देंगे। कलेक्ट्रेट को भी मुख्य मंत्री कार्यालय से जोड़ देंगे और उसको प्रधान मंत्री कार्यालय से जोड़ देंगे। अगर आप करणसिंह के गांव तीतड़खेड़ी को भी निकालना चाहेंगे उस लैपटाप पर, www.com इंटरनेट के माध्यम से, तो गांव आज पूरे हिन्दुस्तान से, वर्ल्ड से जुड़ गया।

ऐसी सोच हमारे राजीव गांधी की थी, ऐसी सोच हमारे कांग्रेस के लोगों की रही है, ऐसी सोच गांव के आदमियों के बनाने की हमारे नेताओं की रही है। और आपकी सोच क्या रही है? बिगाड़ना, झगड़ा कराना, आग लगाना, दंगा कराना, जेहाद कराना। ये क्या नीतियां रही हैं? एक भी नीति आपके 5 साल में पहले ऐसी नहीं रही जिसका आप जवाब दे पायेंगे हमको। हमारे कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, उसका आपको विरोध करने का हम मौका नहीं देंगे। माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी ने कहा था...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय करणसिंह जी, समाप्त करें, आपको करीब 30 मिनट हो गये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मुझसे ज्यादा तो दिगम्बर सिंह जी बोल लिये, सर। 3 दिन में बड़ी मुश्किल से नम्बर आया। 5 मिनट में खतम करूंगा, 5 मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष: जल्दी करो थोड़ा, प्लीज।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेहमाननवाजी में पैसा खर्च कर दिया। 10 करोड़ खर्च कर दिया तो क्या हुआ? आपने तो पता नहीं, क्या-क्या किया। फिर लम्बा-चौड़ा उसमें जाना नहीं चाहता हूं।

दुर्घटनाएं बढ़ गयी तो लोगों का विकास बढ़ा है। लोगों के संसाधन बढ़े हैं, गाड़ी-घोड़े बढ़े हैं। एक घर में तीन-तीन कारें हो गयीं। जमाना बदल गया। अब कोई लेम्ब्रेटा पर घूमेगा क्या? जब गाड़ियां बढ़ गयीं तो एक्सीडेण्ट होंगे। ऊल-जलूल क्वेश्चन, ऊल-जलूल बातें कीं सदन के अन्दर आप लोगों ने।

उपयुक्त कैलोरी में भोजन नहीं है, यह भी कहा सदन में। आटा दे रहे हैं, शानदार आटा। अपने को वज़न कम करने के लिये आने वाले टाइम में साढे आठ रुपये का आटा खाना पड़ेगा। इतना शानदार आटा, खास-तौर से यहां डिपार्टमेंट की तरफ से देने वाले हैं।

आंगन-बाड़ी के तहत बच्चों को भोजन, स्कूलों में पोषाहार मिड-डे मील, इतनी शानदार योजना सरकार की तरफ से चल रही है। फिर भी आप कमियां निकालेंगे तो कमी तो बहुत हैं। सदन में बोलने के लिए कमियां हैं और पेपर में फोटो छपाने के लिए कमियां हो सकती हैं मगर आम जनता के बीच में कोई कमी नहीं है। आम गरीब के साथ जाइये गांव में, गांव का आदमी खुश है। गांव का आदमी ऐसा कोई नहीं है जो नाराज है।

राहुल गांधीजी के लिए कहा है कि राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठ गये एक गुंडे के साथ। कोई बड़ा नेता है तो उसको क्या मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं। पता नहीं, कौन खड़ा होकर आ जाता है और कौन बैठ जाता है। अपन भी कई बार गांव में जाते हैं तो कोई गलत आदमी आकर फोटो खिंचवा लेता है। तो बैठना पड़ सकता है, गलती से हो गयी होगी। इसको आपने मुद्दा बना लिया, इस चीज को।

श्री उपाध्यक्ष: आपने दुगना टाइम ले लिया जितना नियत था उससे। थोड़ा जल्दी करिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): उसको आपने मुद्दा बना दिया। इन सबको सारी चीज को, सदन में मेरी बात को रखा है। इतनी शानदार योजनाएं, सरकार की उपलब्धि को कोई भूल नहीं सकता। मैं चार-पांच चीजें और बोलना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र की हैं। उस पर मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें। (व्यवधान) नहीं, दो मिनट और लूंगा। बस, खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह विद्यार्थी मित्रों के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोचना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्र अच्छी पढ़ाई कराते हैं, स्कूलों में सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। एक, विधवा महिलाएं गांव-गांव में मिलती हैं, बच्चे खाना-पीना नहीं देते हैं। उन विधवा महिलाओं को आप, चाहे उसका पति कमाता था, जमीन हो, पर उस विधवा महिला के बारे में विचार करिये। उसको एक पेंशन बांध दीजिए। गहलोत साहब, इतना कल्याणकारी आप करेंगे तो कोई आपको हिलाने वाला नहीं है।

गरीब के घर में लाइट राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत लाइट लग रही है। मगर चरागाह में गांव के लोग बस जाते हैं, कोई फोरेस्ट की जमीन में बस जाता है। उस गरीब के यहां पर लाइट लगनी चाहिए। विद्युत मंत्रीजी, अगर आप यह कल्याण का काम करेंगे, शहर में अवैध मकान बनाकर लोग लाइट लगा लेते हैं और गांव में अगर मान लीजिए कि पठार/चरागाह में बसता है तो उसके घर में भी लाइट लगनी चाहिए और अगर आपने यह काम कर दिया तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

आंगनबाड़ी केन्द्र गांवों में चल रहे हैं। उसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 500 रुपये किराया आप देते हैं। उसका किराया एक हजार कर देना चाहिए।

एस.एस.सी. का और टी.एफ.सी. का पैसा, आदरणीय पंचायती राज मंत्रीजी से कहूंगा कि सी.सी. रोड भी इसमें अलाउ करनी चाहिए।

फसल की बम्पर क्राप्स आ रही है। रामनारायणजी मीणा साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसल की बम्पर क्राप्स, इस बार प्रकृति का बड़ा आशीर्वाद रहा है, उसकी खरीद के लिए पहले व्यवस्था होनी चाहिए। किसान फसल बेचने आएगा, ऐसा नहीं हो कि उसको फसल बेचने के लिए लाठी खानी

(श्री करणसिंह)

पड़े। जगह-जगह पर तुलाई केन्द्र खोलने चाहिए, नहीं तो किसानों की फसल सस्ती बिक जाएगी। किसानों के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज। कृपया समाप्त करें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक पाइंट और कहकर खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कहीं जाना भी है, लेट हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): बस एक बात, एक सेकण्ड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तांगे वाले...(व्यवधान)... आदरणीय मंत्री महोदय, सब ध्यान से सुन लेना, तांगे वाले, रिक्शा चलाने वाले, थड़ी पर काम करने वाले, धोबी का काम करने वाला, मोची, सब्जी बेचने वाला, अख़बार बेचने वाला, कुली रेलवे स्टेशन का, प्रेस करने वाला, अख़बार बेचने वाला, चाय की थड़ी लगाने वाला और घर पर पोंछा लगाने वाली बाइयां, इन सबको बी.पी.एल. में जोड़ कर इनका कल्याण कर दो, कोई आपको हिलाने वाला नहीं है पांच साल तक और। इनको कोई बोलने का मौका नहीं दूंगा। आटो वाले, तांगा वाले, रिक्शे वाले, गरीब आदमी जो गांव का परेशान है, शहर का परेशान है, उनके लिए यह कल्याणकारी योजना बनानी चाहिए।

इन्हीं के साथ-साथ मैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: थैंक यू। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मुझे बालने का मौका दिया, मैं इन्हीं के साथ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री करणसिंह (छबड़ा): अभी मैंने धन्यवाद नहीं दिया है। मैं राज्यपाल महोदय के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं, दे दिया, सबने स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को 'असत्य का पुलिंदा' बताने वालों की निंदा करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बाद में कर लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने गजेन्द्र सिंहजी का नाम पुकार लिया है, उसके बाद आप बोल लीजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक मिनट। पाइंट आफ इन्फार्मेशन, बहुत बड़ी घटना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलने दीजिए आप। क्या है, आप लिखकर दीजिए पहले। पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर यह सिस्टम है कि आप दो लाइन लिखकर दीजिए, उससे आगे नहीं जाएंगे। (व्यवधान) गजेन्द्र सिंहजी, आप बोलिये। आप चलिये। नहीं-नहीं, आप चलिये, नहीं तो दूसरे का नाम पुकार लूंगा मैं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, स्टार्ट करिये। मेरा सब माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लेगा। यदि लेगा तो दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया जाएगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभी बराबर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, आपके मुख्य सचेतकजी जो इशारा कर रहे हैं, वह सदन के सदस्य मान रहे हैं या नहीं मान रहे? दस मिनट; पन्द्रह मिनट, आप बता दीजिए। आपका सदन आप चलाओगे, समय आप निर्धारित करोगे। एक तो एक घंटा बोलेगा और एक पांच मिनट बोलेगा, तो ऐसे थोड़े ही चलेगा। समय तो बराबर बांटेंगे न अपना। तो फिर आप एतराज क्यों करते हो? आप एतराज मत करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने करण सिंहजी को दिया अभी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, करण सिंहजी का और आपका मामला अलग है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) करण सिंहजी आपसे ज्यादा ... (व्यवधान) माननीय गजेन्द्र सिंहजी, आप प्रारम्भ कीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको बधाई और मुझे जो बोलने का अवसर दिया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

आज की जो प्राथमिकता है, किसी भी स्टेट में या किसी भी सरकार में, वह है गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस जो है जिसने गुड गवर्नेंस की, एज पर ला आफ एवरेजेज, पांच साल एक सरकार आती है और फिर पांच साल दूसरी सरकार आती है; यह एक अपने देश के अन्दर एक लॉ आफ एवरेजेज रहा है परन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल गुड गवर्नेंस के ऊपर अपना पूरा ध्यान दिया है और उसका मैं एग्जाम्प्ल देना चाहूंगा जैसे नीतिश कुमार हैं और नरेन्द्र मोदी हैं, वे लगातार सी.एम. बनते आ रहे हैं क्योंकि they have done good governance. हमारा जो प्रदेश है, मुझे दु:ख है कहने में, गुड गवर्नेंस में हम बिलकुल जीरो हैं और इसका मैं कारण आपको बताऊंगा। आप देखिए कि ज्यादा जो एनर्जी है स्टेट में, कांग्रेस पार्टी में जो दो धड़े बने हुए हैं, तो कुर्सी बचाने के अन्दर लगी हुई है। ज्यादा जो एनर्जी है सी.एम. साहब की, अपनी कुर्सी कैसे बचाएं, उसके अन्दर लगी हुई है।

दूसरा, यह पहली बार है राजस्थान के अन्दर, अपने इतिहास के अन्दर कि बदले की भावना, बदले के बीज, ये पहली बार इन्क्वायरी करके बोये गये हैं। यह पहली बार हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसका परिणाम यही होगा कि अब यह एक तरह से कल्चर बन जाएगा स्टेट के अन्दर। यह शुरू कर दिया गया है।

रिकार्ड ट्रांसफर्स! आप देखिये कि इतने ट्रांसफर्स कभी नहीं हुए। कम्पलीट सेण्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स, मंत्री-बंत्री की किसी की नहीं चलती। सब केन्द्रित है सी.एम. के पास, सब पावर्स। इंडिया टुडे के अन्दर आप देखिये, वह तो बहुत इंडिपेंडेंट मैग्जीन है, भ्रष्टाचार के बारे में कितने आर्टिकल आये हुए हैं। अपन सब पढ़ चुके हैं।

नान-यूटिलाइजेशन आफ बजट, यह सरकार की खासियत रही है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. विभाग के अन्दर दो वर्ष पूर्व हमारी सरकार को केन्द्र सरकार 1,200 करोड़ प्रति वर्ष ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए दिया करती थी। दो वर्ष पूर्व इस बजट को घटाकर 600 करोड़ कर दिया गया है। सरकार के, यहां के अफसर लोग गये दिल्ली में, उन्होंने प्रयास करके एक वर्ष पहले इसको वापस 1,200 करोड़ कर दिया, मंत्रीजी भी यहां पर विराजे हैं, यह 1,200 करोड़ के अन्दर से 600 करोड़, अभी भी यूटिलाइजेशन उसका नहीं हुआ है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूअर गवर्नेंस इस स्टेट के अन्दर एक करेक्टर बन गई है।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

इसके अलावा बी.पी.एल. के अन्दर जो फोर्टिफाइड आटा दिया जाता है, वह सब बासी आटा दिया जा रहा है और जनता के पास, बी.पी.एल. के पास पहुंच भी नहीं रहा है। सरकार ने सब कुछ दिया है लेकिन it is not reaching the public. और सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्याएं हैं इस प्रदेश की, वे हैं बिजली और पानी।

अब मैं बिजली के ऊपर आना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण है गवर्नर साहब का, महामहिम का, उसमें यह लिखा है, मुझे यह खुशी है, बीते तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 3,380 मेगावाट की वृद्धि की गई है। ये पन्ने जो हैं डिपार्टमेंट ने छपवाकर सब विधायकगण को, कांग्रेस के जितने भी विधायकगणक हैं, उनको दे दिये और सबने अपने अभिभाषण में, सबने खूब इसके ऊपर तूती बजाई। आह, हम इतना कर रहे हैं; रिकार्ड है; हमारा यह है। उसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रदेश को गुमराह किया गया है। प्रदेश को कैसे गुमराह किया गया है? कोई भी पावर प्रोजेक्ट जो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कम से कम चार-पांच साल उसके निर्माण में लग जाते हैं। अब इन्होंने जो अभिभाषण में लिखा है कि 3,380 मेगावाट तीन साल में हमने पैदा किया; इनकी जो पहली परियोजना थी, कोटा थर्मल 195 मेगावाट, वह जून, 2009 के अन्दर आयी; इसका मतलब, उसका काम 2004 में शुरू हो गया था, 2009 में मिली। कोटा, सूरतगढ़ के 250 मेगावाट अक्टूबर, 2010 के अन्दर आई। ठीक है, साहब? छबड़ा का 500 मेगावाट, वह सितम्बर, 2010 और दिसम्बर, 2010 के अन्दर चालू हुई, उसको भी हमने शुरू किया, टेण्डरिंग किये, पांच साल पहले 2005 के अन्दर किया था। गिराल-2 125 मेगावाट जनवरी, 2009 के अन्दर वह चालू हुई। बरसिंगसर 2008 में 250 मेगावाट चालू हुई। और जो पहला प्राइवेट एंटरप्राइज है और हमारा जो लिग्नाइट है, वह पहली बार ही इतनी तादाद का लिग्नाइट यूज हुआ है, उसका भी हमने कार्य आज से पांच साल पहले शुरू किया था, 1080 मेगावाट 2009-10 और 2011 में उसकी पैदाइश हुई थी। विंड एनर्जी 500 मेगावाट जो हम छोड़कर गये थे, वह डेढ़-दो साल के अन्दर शुरू हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, 3,380 का जो ये बोल रहे हैं, वह तो सब हमारी लगाई हुई स्कीम्स हैं और परोसी हुई थाली हमने दी। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो अभिभाषण के अंदर बोला गया है, इसमें इस सरकार का क्या योगदान है? इस सरकार ने कितने प्रोजेक्ट्स खुद ने लगाये?

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

कम से कम जो तीन साल के अन्दर 3,380 मेगावाट के अन्दर 3000 मेगावाट हमने लगाई है। यह हम नहीं लगाते तो इस प्रदेश के अन्दर अंधकार होता। हमारी सरकार जब आई थी तो कांग्रेस सरकार 125 मेगावाट का गिराल का एक ही प्रोजेक्ट हमारे लिये छोड़कर गयी थी और वह भी खाली फाइनेंशल सैंक्शन करके।

अब इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कहा, राज्य सरकार प्राथमिकता से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कृत संकल्प है। अब यह बतायें कि कैसे प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा? इन्होंने कहा कि 6 सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स हमारे बनने वाले हैं। यह घोषणा की गयी और आठ हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। यह खाली कागज काले-पीले करने से क्या मतलब है? यह प्रोजेक्ट्स कब आयेंगे? इनकी क्या स्टेज है? सूरतगढ़ का 2,640 मेगावाट, छबड़ा 1,320, झालावाड़ 1,320, बांसवाड़ा 1,320 और प्राइवेट 1,320; इनको पूछो, साहब, एक का भी काम शुरू हुआ है? तीन साल सरकार को निकल गये हैं। अभी तो केन्द्र से लड़ते-लड़ते इनको दो साल तो निकल गये। कुश्ती किस बात की? सब डिवाइड हो गये। राज्य सरकार ने कहा कि हमें आप छत्तीसगढ़ के अन्दर कोयले की खानें दो। वहां पर माइन्स और कोल मिनिस्ट्री अड़ गयी कि हम नहीं देंगे पावर प्लांट को। वहां जयराम रमेश जी ने कह दिया कि हम फोरेस्ट क्लीयरेंस नहीं देंगे। इस कुश्ती के अन्दर दो साल निकल गये। अभी एक भी सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, जिसके अन्दर 8000 मेगावाट पैदा होनी है, उसके अन्दर खाली दो प्रोजेक्ट्स, उनको अब माइन्स अलाट हुई हैं। वे माइन्स भी हमने हमारे कार्यकाल के अन्दर अलाट कराई थीं। अब बाकी के जितने भी सुपर क्रिटिकल हैं, उनका क्या होना है? ये कह रहे हैं गैस का कोटा, छबड़ा, धौलपुर में 330-330-330, हजार मेगावाट हम और पैदा करेंगे। एक तो गैस की उपलब्धता नहीं है; दूसरा, गैस के प्राइसेज इतने वोलेटाइल और इतने चेंज हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इन प्रोजेक्ट्स को ला सकेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, दो साल के बाद बिजली की स्थिति बहुत ही गम्भीर होने वाली है। यह कैसे होगा? तो ये सब घोषणाएं हैं, ये तो खाली कागज को काला करना है और जनता को एक फाल्स आश्वासन दिया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, रावतभाटा के अन्दर आप देखें, जितनी भी परमाणु

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

इकाइयां लगाई हुई हैं, हमारी इतनी बड़ी-बड़ी झीलें काम में ली जा रही हैं। हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, हमारी जनता रिस्क पर है कि न्यूक्लीयर फ्यूल लीक नहीं हो जाये जैसे जापान के अन्दर हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, वे तो बहुत एडवांस थे, हमारे तो बहुत ही बैकवर्ड प्लांट्स हैं। लेकिन राजस्थान को इससे क्या मिल रहा है? हमारी जमीन, सब कुछ लेकर यह रिस्क फैक्टर से एक्सपोज करके हमें जो नये परमाणु बिजलीघर हैं, हमारा उनमें क्या परसेंटेज है? दो बिजलीघर ऐसे हैं जिनमें हमारा 15-20 परसेंट शेयर था, वे पुराने होकर बंद हो चुके हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो मुझे यह लगता है यह सब बातें करके इनको, एक्चुअली ये कैसे अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर इतनी बिजली पैदा करेंगे और अपने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनायेंगे? इसमें मैं सोचता हूं, यह बिल्कुल ही गलत बात है।

इसके अलावा बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, 20 हजार मेगावाट हम देंगे 2022 तक; राजस्थान पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब बनेगा। कैसे बनेगा सोलर हब, मुझे बताइये। अभी जो टेण्डरिंग हुई है, करीब 12 रुपये के अन्दर सोलर पावर में इन्होंने लोगों को, पार्टीज को इन्वाइट किया और बिड कराई है। लगभग 12 रुपये पर यूनिट की बिजली पड़ रही है। कौन खरीदेगा? केन्द्र सरकार कहती है कि हम आपसे खरीदेंगे। हमारे लग रहा है 550 मेगावाट, वे कह रहे हैं कि हम आपको 12 रुपये प्रति यूनिट देंगे, लेकिन हम आपको इन रिटर्न 225 देंगे साढ़े चार रुपये पर। अब आप एवरेज लगाओ तो पड़ती वही 12 रुपये है, 12 रुपये पड़ती है, कौन खरीदेगा 12 रुपये के अन्दर? हमारी जमीन यूज की जा रही है, प्रोजेक्ट सेंटर आ रहे हैं और बिजली कौन लेकर जा रही है, एन टी पी सी लेकर जा रही है।

(16.07 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, 16 हजार 500 एप्लीकेशंस सरकार ने ले ली हैं, 50 रुपये पर-मेगावाट के अनुसार से एप्लीकेशंस ले ली हैं। अब 16 हजार 500 एप्लीकेशंस को ये लोग कहां अकोमोडेट करेंगे? इन्होंने जो टेण्डरिंग की, खाली 40 पार्टीज को इन्होंने परमिशन दी है सोलर के पांच-पांच मेगावाट के प्लांट लगाने की। बाकी इन लोगों का क्या होगा?

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि वह जो 20 हजार मेगावाट का है, यह सब थोथे ढोल हैं, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' वाली बात है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कुकिंग काम्पीटिशन था इंडिया में दिल्ली के अन्दर। उसमें सब स्टेट्स को बुलाया गया कि आप अपना-अपना खाना बनाओगे, काम्पीटिशन में पैसा दिया जायेगा। राजस्थान के लोगों ने दाल-बाटी-चूरमा बनाया, कैर-सांगरी बनाई; पंजाब वालों ने मक्के की रोटी, सरसों का साग बनाया। ऐसे करके सब स्टेट्स ने बनाया। एक ऐसा स्टेट था, उन्होंने बैठकर एक कड़ाही ली और एक पलटा लिया और वह खाली कड़ाही के अन्दर फेर रहे थे। जब जज लोग आये देखते-देखते और उस स्टाल पर गये और जब उसे खाली देखा तो पूछा कि क्या बना रहे हो? साहब, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो यह बेवकूफ बनाने वाला ही सोलर मिशन है। कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। खाली कड़ाही और पलटा फेर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब यह सरकार आई थी, यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट सूचना आपको दे रहा हूं, यह सरकार आई थी तो डिस्काम का घाटा था 15 हजार करोड़ और हर साल 10 हजार करोड़ एडिशन हुआ है इसके अन्दर। आज की तारीख के अन्दर 35 हजार करोड़ का घाटा है और एक साल के अन्दर यह 45 हजार करोड़ रुपये डिस्काम के अन्दर पहुंचा देंगे। पिछले साल पूरे राजस्थान का बजट क्या था? राजस्थान का बजट था 28 हजार करोड़, जबकि डिस्काम का घाटा 45 हजार करोड़ पर पहुंच जायेगा। कैसे बिजली खरीदेंगे? कहां से पैसा देंगे? इसके लिये बैंकों ने भी हाथ खड़े करने शुरू कर दिये हैं। डिस्काम ने आज इससे लिया और जब उनको देने का टाइम हुआ तो शिवजीराम जी से ले लिया। आज इसकी टोपी, कल उसकी टोपी, रोज यही खेल हो रहा है। पैसे बिल्कुल नहीं हैं।

आज क्या है, सबको क्या चाहिये, आज समय बदलता जा रहा है, जो आदमी पंखा चलाता था, कूलर चला रहा है; जो कूलर चलाता था, वह ए.सी. चला रहा है। विद्युत की मांग बहुत बढ़ती जा रही है और आज जनता को क्या चाहिये, उनको चाहिये कनेक्शन, उनको चाहिये पर्याप्त बिजली और उनको चाहिये सस्ती बिजली। तो आप यह जो कह रहे हो, एक तो यह गलत बात बोल रहे हो कि हम इतना जनरेशन कर रहे हैं। मैंने आपको आंकड़े बता दिये कि कौन से पावर प्लांट कब आ रहे हैं। आप बता दो, इसके अलावा कोई पावर प्लांट हैं तो आप मुझे सूचना दीजिये। दूसरी चीज यह है कि यह जो

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

डिस्काम का घाटा है, आज आप इस प्रदेश को कैसे बिजली दोगे? आप कैसे आत्मनिर्भर बनाओगे? गवर्नर साहब के अभिभाषण में कहा गया कि राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, मुझे आत्मनिर्भर बनता नहीं दिखाई दे रहा है। दो साल के बाद में बिजली की गम्भीर सिचुएशन होगी। टोटल मिस-मैनेजमेंट हो रहा है। जो आपके टी एण्ड डी लोसेज हैं, हम लोग 26 परसेंट पर ले आये थे, अब आप आडिट करके बतायें कि टी एण्ड लोसेज आपके कितने हैं?

यहां पर कोई प्रोपर मानिटरिंग नहीं हो रही है। हमारी सरकार के टाइम में हर डिविजन लेवल पर मानिटरिंग होती थी। हमारे टाइम में मुख्य मंत्रीजी खुद मानिटरिंग करती थीं। डायरेक्टली करते थे, उनका अलग से एक सैल था। सरपंच सम्मेलन हुआ था, फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन हुआ था, इसलिए कि बिजली सही जा रही है या नहीं जा रही है। यह सब बन्द हो गया।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी घोषणा केन्द्र सरकार ने भारत निर्माण के तहत 2005 के अन्दर की थी। क्या घोषणा की थी, कि 2012 तक पूरे देश के हर घर के अन्दर बिजली का बल्ब जलेगा; कोई कनेक्शन चाहेगा, उसको कनेक्शन मिलेगा। मुझे तो हर घर में बिजली दस साल तक जाते नजर नहीं आ रही है। 'मुख्यमंत्री सबके लिए योजना' जो हमने शुरू की थी, जिसके अन्दर ढाणियों को साढ़े तीन हजार कनेक्शन दे रहे थे, उसके तहत 2010 के अन्दर सरकार ने आवेदन लेना ही बन्द कर दिया, इस सरकार ने। आप पूछ लीजिए, कहां गई वह स्कीम? आप क्यों नहीं दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, दूर दराज क्षेत्र के अन्दर जहां पानी नहीं है, जहां डवलपमेंट नहीं है? आपने वह स्कीम क्यों रद्द कर दी? फिर क्यों आप बिजली के थोथे ढ़ोल बजा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम यूं जनरेशन कर रहे हैं, खाली जनरेशन से क्या होगा?

सभापति महोदय, आखिरी में एक-दो पाइन्ट और कहूंगा। नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आठ बजे दारू की दुकानें बन्द हो जाती हैं, मैं कहता हूं कि सारी ब्लैक मार्केटिंग उसके बाद शुरू होती है। हरियाणा, पंजाब, यू पी के सब दारू के माफिया आ गये राजस्थान के अन्दर। दारू की दुकानें आठ बजे बन्द करने का मकसद क्या था? दारू की दुकानें बन्द हो गयीं लेकिन बार्स बढ़ गये हैं। दारू की सेल बैढ गयी है और व्यक्ति जो शराब लेकर आता था, वह अपने बीबी और बच्चों के कन्ट्रोल में था लेकिन वह बार में जाकर झगडे और कर रहा है। तो ये रिग्रेसिव पालिसीज हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे ट्यूरिज्म को भी घाटा है। ट्यूरिज्म के पिछले

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

तीन सालों में, ये कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार देगी, पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि लास्ट थ्री ईयर्स, जब से यह सरकार आयी है, आप आंकड़े देख लीजिए, ट्यूरिज्म का बिलकुल भट्टा गोल है। इसका कारण मैं बताऊंगा कि क्यों भट्टा गोल है, क्योंकि ट्यूरिज्म और फोरैन ट्यूरिज्म ऐसी चीज है कि हमारे देश के अन्दर हम पूरी दुनिया से कम्पीटिशन कर रहे हैं। We are competing with the world. आप बताइये कि आज यहां से आप होलीडे के लिए गोवा जाना चाहेंगे; आप कहेंगे कि गोवा नहीं, मैं मलेशिया, सिंगापुर जाऊंगा क्योंकि मेरा एयर फेयर चीपर है और मेरा होटल भी आधी रेट और डबल एज गुड एज इण्डिया है। आज होटल में आपका हजार रुपये का बिल आता है, उसके अन्दर केवल तीन सौ पचास रुपये तो केवल टैक्सेज के हैं। अब लिखकर लेते हैं तो उसके अन्दर टैक्सेज ही टैक्सेज हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें आप।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): Please give five more minutes. आप देखिए कि सब माननीय सदस्य ने पचास-पचास मिनट लिये हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। आप ही के यहां से यह डिसाइड हुआ कि पन्द्रह मिनट दिये जाने हैं आपको लेकिन अठारह मिनट हो चुके हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे को तीन मिनट और दिये जाएं।

तो हम कम्पीटिशन के अन्दर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के पास चाइस है, लोगों के पास आल्टरनेटिव्स हैं। इण्डिया नहीं जाएंगे तो श्रीलंका चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे। तो इण्डिया में ट्यूरिस्ट पिछले तीन साल से रिकार्ड लोएस्ट अराइवल आफ ट्यूरिस्ट है क्योंकि इस सरकार की भावना, इनकी पालिसीज जो हैं, वे एन्टी-ट्यूरिस्ट हैं। यहां पर आप देखिए कि राजस्थान दिवस हुआ था; वह एक तरह का मेला बन गया था जैसे कि पुष्कर का मेला होता है, जैसा कि जैसलमेर का मेला होता है। राजस्थान के एक सेक्शन का कल्चर बन गया था राजस्थान दिवस। मंत्रीजी से बात की तो कहा कि साहब, राजस्थान दिवस तो एक दिन का ही होता है। तो फिर मेले भी कैंसिल कर दो न, झण्डारोहण करके उस दिन ही छुट्टी कर दो। राजस्थान दिवस सात दिन का होता था। लोग आते थे, होटल वाले कमाते थे, ट्रेवल एजेंसीज कमाती थीं, दुकानदारों की सेल होती थी, एयरलाइन्स को फायदा होता

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

था, सबको फायदा होता था। वह भी इन्होंने हटा दिया। इनकी पालिसीज जितनी है, इन्होंने टैक्सेज बढ़ा दिए, यह दारू के ऊपर जो किया, यह सब एन्टी -ट्यूरिज्म है।

आपके स्पोर्ट्स के अन्दर फ्री-स्टाइल रेसलिंग कितनी जबरदस्त हुई, आप देखिए आर सी ए के अन्दर। वह उसकी टांग खींच रहा है, आप देखिए, फ्री स्टाइल। वह थाई बाक्सिंग, उसमें कोहनी ही नहीं लगाते, टांग से ठोकते हैं, लातों की लगाते हैं। फ्री स्टाइल थाई बाक्सिंग के अन्दर हुआ कि यहां सारे आई पी एल मैचेज गये। आई पी एल मैचेज आते थे तो क्या होता था, सभापति महोदय, होटल्स भरते थे, सभी लोगों को कारोबार मिलता था, लाइटें जलती थीं, तालियों की गड़गड़ाहट आती थी जब हम इधर-उधर निकलते थे। सब बन्द हो गया, सब खतम हो गया। यह इनकी नीति है।

मेट्रो के लिए हम आपको शाबासी देते हैं कि आप जयपुर के अन्दर मेट्रो लेकर आ गये। तो मेट्रो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आलवेज क्रोस चलता है। आपने सिटी में एक पाइन्ट से दूसरे पाइन्ट को जोड़ा है बाकी आप सब भूल गये हैं।

इसके अलावा, आखिरी में, इण्डस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर कभी नहीं आयेंगी क्योंकि आपने राजस्थान के अन्दर टैरिफ बढ़ा दिया इण्डस्ट्रीज का। इण्डस्ट्रीज दबा कर नहीं लगायी जा सकती क्योंकि वे धरने पर बैठकर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपने उनके लिए पावर महंगा कर दिया और उनको आप पर्याप्त बिजली भी नहीं दे रहे हैं। वे आपके कमाऊ पूत हैं। उनको बिजली भी नहीं दे रहे हो और उनका पावर रेट भी बढ़ा रहे हो। मतलब दोनों तरफ से शार्ट मार रहे हो आप उनको।

नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, अभिभाषण पर बात हो रही थी, कह रहे थे कि हमारे हेमाराम जी हैं, हमारे पूर्बाराम जी हैं, हमारे ये रामजी हैं; हमारे इधर तो राम जी भी हैं, श्यामजी भी हैं, राधेश्याम जी भी हैं, घनश्याम जी भी हैं। हमारे पास तो राम श्याम दोनों ही हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी दीवार। दीवार के अन्दर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन होते हैं। अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंगला है, तो शशि कपूर कहता है कि मेरे पास मां है। तो हमारे पास वसुन्धरा है।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार को कहूंगा कि धरती श्याम है, कुछ करो। यह मत करो कि आकाश तोड़ूं, तारे तोड़ूं। थारी धोती तो संभाल पहले। आकाश-तारे बाद में तोड़ना। तो थोड़ा समय है उसमें कुछ काम करो। थोड़ा प्रोग्रेस करो, गुड गवर्नेंस करो, स्टेट को फायदा दिलाओ। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं घोर निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको इजाजत अभी नहीं मिली है। कृपया विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कब मिलेगी?

श्री सभापति: मैंने नाम बोल दिया है, उसके बाद मिलेगी आपको।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। तीन दिनों के अभिभाषण पर वाद-विवाद में प्रतिपक्ष पर माननीय सदस्य के द्वारा अभिभाषण का बार-बार मखौल उड़ाया जा रहा था, कहा जा रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ खाली है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शायद कुछ दिखा नहीं, वह पूरा भरा हुआ है। आपके समय जो भी अभिभाषण पढ़े गये, उस समय क्या प्रक्रिया अलग थी, क्या भिन्न प्रकार से थी, मैं आपको पूछना चाहता हूं। यह बात भी बार-बार बोल रहे थे कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ लोकप्रिय मुख्य मंत्री जो जन सेवक हैं और एक तरफ महारानी हैं; महारानी में राजतंत्र होता है, लोक सेवक में लोकतंत्र होता है। दुनिया जानती है और हमें कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री के ऊपर आज दिन तक कोई अंगुली उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय तिवाड़ी जी लोकतंत्र के कामकाज की तुलना के आंकड़े बता रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तिवाड़ी जी को कि यह आदत आपकी पुरानी है और इस गम्भीर मुद्रा में, इस अन्दाज में बोला जाता है कि वे आंकड़े वास्तव में सही हैं। मैं

(श्री मदन प्रजापत)

पूछना चाहता हूं कि आज तीन साल सरकार को हो गये और तीन साल पहले आप थे, मात्र तीन साल में ही राजस्थान उसमें इतने नम्बर पर है, उसमें इतने नम्बर पर है; क्या तीन सालों में इतने नम्बर घट गये? आपके समय कितने नम्बर पर राजस्थान था?

सभापति महोदय, आज की योजनाओं से बार-बार इनको एलर्जी हो रही है। योजनाएं मुख्य मंत्रीजी के नाम से हैं, योजनाएं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी के नाम से हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके टाइम में भी मुख्यमंत्री सड़क योजना थी, नाम मात्र की सड़कें बनीं। जगह-जगह बोर्ड लगे हुए थे। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री जिन्होंने भारत को सब कुछ दिया, इक्कीसवीं सदी में भारत को ले जाने का सपना और कम्प्यूटर क्रांति के जनक, राजीव गांधी जी के नाम से है, आपको राजीव गांधीजी के नाम से एलर्जी आज से नहीं, शुरू से है। जब हमारी पहली सरकार बनी तो मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत बने और राजीव गांधी जी के नाम से स्कूल्स खोले। उनका नाम आपने राजीव गांधी का नाम हटाकर प्राथमिक विद्यालय किया। यह आपकी पुरानी आदत है, पुरानी एलर्जी है, आज से नहीं है।

सभापति महोदय, तिवाड़ीजी जैसे वरिष्ठ सदस्य के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। मैं भी सुनने लगा कि शायद गम्भीर बात है। आज जयपुर के बारे में, जयपुर में मेट्रो आ रही है, वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है और राजा-महाराजाओं की बात कर रहे हैं कि यह नोर्थ में जल था, पूजा हुई, महारानियों ने स्नान किया। आज देश कहां जा रहा है, समय कहां जा रहा है, आप हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हो और पुरानी मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके पास में सरकार को घेरने के लिए एक शब्द भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज बार-बार तिवाड़ी जी के मुंह से ये शब्द निकल रहे थे, मंत्रियों की नहीं चलती; आप तो कम से कम चुप रहो, वसुन्धराजी के समय आपकी क्या हालत थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि आज माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए लागू की हैं, आम गरीब जानता है, गरीबों का अगर विश्वास किसी के ऊपर है तो माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के ऊपर है।

माननीय सभापति महोदय, कल हमारे भाई महेन्द्र जी ने कहा, आज

(श्री मदन प्रजापत)

उस बात को गजेन्द्र सिंह जी खींवसर ने दोहराया, हमारे पास में वसुन्धरा जी हैं। आपके पास में वसुन्धराजी हैं महेन्द्र जी ने कहा, गंगा है, राम है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास में स्वयं अशोक हैं। और भी हैं। आज गंगा, यमुना और राम के साथ में बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि अशोक के पास में प्रताप भी हैं, रघु भी हैं, और भी हैं, शंकर भी हैं, सोना और मेवा भी हैं और परसादी भी हैं, भाई भरत भी हैं। आप किससे मुकाबला करोगे? सब हमारे पास में हैं, हमारा मुकाबला आप नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि बार-बार ये अयोध्या के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आप अयोध्या के हित में नहीं हैं। कभी अयोध्या के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, गंगा और यमुना के नाम पर, कभी गऊ माता के नाम पर आपने वोट लेना जरूर सीखा है लेकिन अगर आप वास्तव में ही राम के हितैषी होते तो राम के भक्त भाई हनुमान को आपने बाहर निकाल दिया। आप कौन से राम और हनुमान की बात करते हो?

माननीय सभापति महोदय, आज किसानों के पक्ष में प्रथम दिन जब अभिभाषण की शुरुआत की और ये फसलों का सैम्पल लेकर आये, हम भी किसानों का दर्द जानते हैं। पूरा राजस्थान जानता है कि किसानों के हित में कौन है, किसानों के हितैषी कौन हैं और यह सैम्पल लेकर ड्रामा करके आप यह नहीं जता सकते कि हम किसानों के हितैषी हैं। मैं आपके समय को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके समय मात्र ढाई परसेंट क्लेम दिया है, 1997-98 में और हमारे समय आज से एक साल पहले 95 परसेंट किसानों को बीमा का क्लेम दिया गया। साथ ही मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, माननीय यू.पी.ए. चेयरपर्सन और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने एक धड़ाके से 72 हजार करोड़ का कर्जा किसानों का माफ करके यह साबित कर दिया कि अगर किसानों की कोई हितैषी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है।

माननीय सभापति महोदय, आज किसानों और अन्य की जो बात करते हैं, आज और भी बात आयी कि यह निर्दलीय और ब स पाओं को ले लिया, यह सरकार चलती है, प्रलोभन दे दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री थे और 1993 से 1998 के बीच में आपकी सरकार थी, उस समय आपने कितने निर्दलीयों को लिया, निर्दलीयों के ऊपर आपने

(श्री मदन प्रजापत)

सरकार चलायी और इनको प्रलोभन दिया या नहीं दिया? हमारे सामने प्रत्याशी थे पूर्व गृह राज्य मंत्री को, और मैं आपको निवेदन भी करता हूं, माउंट आबू में आपने उनको लेने के लिए समाज को जमीन दी, और भी प्रलोभन दिया गया। सच्चाई क्या है, क्या नहीं है; दांत खाने के लिए अलग होते हैं और बताने के लिए ऐसे होते हैं। आपका अनुभव है, आपकी प्रैक्टिस है, आप सूखे चारे को हरे में बदल सकते हैं, आपकी पुरानी आदत है और भाषण के ऊपर आप वोट ले सकते हैं लेकिन विकास और कामकाज के ऊपर आप किसी तरह से कम्पीटिशन नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, हमें यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जितनी योजनाएं चलायीं, जो गरीबों के लिए किया, आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तीन सालों में जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की सरकार बनी, इन्होंने सबसे पहले गरीब और गरीब की क्या हालत है, गरीबी के साथ में उनका घर का गुजारा कैसे चलता होगा, इसलिए सर्वप्रथम योजना शुरू की मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा। उस योजना के मार्फत मात्र दो रुपये किलो में गेहूं दिया जाता है, 50 रुपये में 25 किलो का कट्टा। यह आपने नहीं किया। आप एक भी काम बता दें। मैं माननीय वसुन्धरा जी के पांच सालों के कार्यकाल के अभिभाषण भी लेकर आया हूं, बजट की पुरानी कॉपियां भी हैं। आप बारबार अभिभाषण के ऊपर कर रहे थे, यह तो अभी पहली झलकी है, सैम्पल है, अशोक गहलोत जी जब बजट पेश करेंगे, माल का पिटारा आयेगा, आप देखते रह जाओगे। और बातें कर रहे हैं, इधर आयेंगे, इधर वाले इधर आयेंगे; इधर नहीं घूम-घूम कर थोड़े कोने में आप रहोगे, पूरे भाग में भी आप नहीं रह सकते। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे कहने के लिए, बोलने के लिए सैकड़ों बातें हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान का कायाकल्प किया है, जो काम किया है, उसको आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, गरीब के लिए मकान फ्री, दवाई फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, पानी का टांका फ्री, डिलिवरी का टोटल खर्चा फ्री, जो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, सुहावड़ फ्री। और क्या योजना की बात करते हो आप, और कौनसी लागू, कोई बाकी ही नहीं रहा।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, आज राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार का देखें। जब नरेगा की शुरुआत हुई तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग हंसी उड़ा रहे थे कि क्या ये 365 दिन में आम आदमी को चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो ये सौ दिन का रोजगार दे सकेंगे, विश्वास नहीं था लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह साबित कर दिया। अगर मजदूर के हित में कोई फैसला ले सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी ले सकती है। माननीय सभापति महोदय, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा हो जो क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, यह आने वाला समय हमेशा- हमेशा के लिए याद रखेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व मंत्रीजी सदन में अभी विराजमान हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री हेमाराम जी का, कई राजस्व मंत्री आये, कई बार प्रयास भी किया, यह बात मैं मानता हूं लेकिन प्रयास के बाद में फैसला लेने की हिम्मत नहीं हुई थी, जो आज रास्तों का कानून बनाया। आज रास्तों की जो इतनी समस्या थी, भाई भाई का नहीं रहा, पडोसी पड़ोसी का नहीं रहा, झगड़े बढ़ गये, विवाद बढ़ गये। उसके बाद में माननीय हेमाराम जी ने इतना क्रांतिकारी कदम उठाया, यह फैसला लिया। मैं आप सब की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 18 तारीख को गवर्नमेंट की प्रैस में यह कानून प्रिंट हुआ और 18 तारीख की शाम को जो पीड़ित व्यक्ति थे वे कानून की कापी लेकर हमारे पास में आ गये। यह रास्ते का कानून कितना महत्व रखता है, यह आपने कर दिखाया।

माननीय सभापति महोदय, आज हम इनकी करें, वे हमारी करें लेकिन हकीकत यह है कि विकास और अभिभाषण में दावे का जो तरीका मैंने देखा, कल प्रभूलाल जी कृषि के ऊपर कर रहे थे, गजेन्द्र सिंह जी बिजली के ऊपर कर रहे थे, न जाने दो साल में मंत्रालय का भार आ जायेगा और हम मुश्किल में पड़ जायेंगे, यह कैसे होगा, क्या राजस्थान की हालत होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको तकलीफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके समय का एक भी बड़ा काम नहीं बता सकते और यह काम जो आपने किया है, यह मैं जरूर जरा याद दिलाता हूं। मुझे बड़ा दु:ख हुआ कि नरेगा के मार्फत जो बेस दिये गये और विधवाओं को भी सुहागन की चूड़ियां दी गयीं। उनके मन में कितना दर्द हुआ होगा!

(श्री मदन प्रजापत)

नरेगा में काम में जितनी विधवाओं को अगर सुहागन की चूड़ियां और चूनड़ी दी जाती है और तत्कालीन प्रभारी सचिव जोगाराम जी कह रहे हैं, लो। भाई, मैंने कहा है कि यह विधवा है, विधवा और चूनड़ी का क्या तालमेल है? यह बड़ा अफसोस होता है, ये फैसले आपके समय लिये गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं, कल भी बात आयी, हम नर्मदा का पानी लाये, हमारे गुजरात में वह हो रहा है, हमारे भाई नीतिश जी वह कर रहे हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि भाई रे साला रे बे टाबर है; आपां रे कीं काम कोनी आवे। नीतिश जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। आपने क्या किया? एक भी काम में उनका मुकाबला करते जो माननीय अशोक गहलोत जी ने योजना लागू की है। नर्मदा के मामले में इनकी आदत है, शिलान्यास करना, उद्‌घाटन करना। मैं बार-बार कह सकता हूं कि आज नर्मदा के बारे में एक बार भी बोलने का आपको अधिकार नहीं है। जो सुल्लु में पाइपों के जरिए एक टेम्परेरी व्यवस्था में पानी लाया गया और बड़ा आयोजन किया गया। इसी तरह हमारे विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुरा कस्बे में सिर्फ दो पाइप डाले गये और वसुन्धराजी की सभा में हजारों की संख्या में भीड़ हुई। शाम को ऐसा वातावरण हो गया कि मदन भाई, हजारों लोग आए, अपना क्या होगा? ये देखने आए हैं, ये इनके नहीं हैं, लेकिन उद्‌घाटन के पाइप आज भी मौजूद पड़े हैं।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास नहीं किया, न विधान सभा क्षेत्र में आए लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्य मंत्री जी भले ही मत आए लेकिन जोधपुर से उम्मेद सागर कल्याणपुरा पानी आ गया है और सीधा उद्‌घाटन करवाया जाएगा। हमें यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि दो महीनों के बाद बालोतरा जैसे नगर को नहर का मीठा पानी मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी और जलदाय मंत्री जितेन्द्र सिंह जी, हेमाराम जी उद्‌घाटन करेंगे। हकीकत में मैं कह रहा हूं। आप जो कहते हैं, वह करते नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को। और भी कई बातें हैं, हमें बड़ी खुशी है, आज दो-तीन कामकाज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, वे प्रक्रियाधीन हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये काम समय रहते होंगे और उनकी शुरुआत होगी।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, आज बालोतरा में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है और नियमों के अन्तर्गत है और प्रक्रियाधीन है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि बालोतरा के ओवरब्रिज की इस बजट में घोषणा करें ताकि आम अवाम जान सके कि मीठा पानी आया है, और ओवरब्रिज बन रहा है।

दूसरी मुख्य जो बात है आज राजस्थान में तैंतीस जिले होने के बाद सैंतीस डी टी ओ हैं। जिला परिवहन कार्यालय जो हमारा बाड़मेर में है, 150 किलोमीटर जाना पड़ता है। 150 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, राजस्व आय है, दो नेशनल हाइवे गुजरते हैं और मापदण्ड को पूरा करता है। मुझे विश्वास है वित्तीय स्वीकृति भी मिल गयी है, तो उस डी टी ओ आफिस के लिए, इन दोनों काम के लिए बजट में घोषणा करें ताकि जनता में एक सन्देश जाएगा कि बाड़मेर का विकास, राजस्थान का विकास अगर कोई करता है तो वह कांग्रेस पार्टी और माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत करेंगे।

हमें कहते हुए बड़ी खुशी है, गत साल भी मैंने बात रखी, इस साल भी मैंने 295 के अन्तर्गत बात की, लोग अदरवाइज ले रहे हैं कि यह मदन भाई बार-बार पेटीकोट कहां से लेकर आ जाता है। इसको अदरवाइज न लें। आज हमारा बालोतरा औद्योगिक नगरी है, पापलीन नगरी है; पूरे विश्व में कपड़ा बालोतरा से जाता है, चाहे बेडशीट हो चाहे पापलीन हो। इनके ऊपर कोई वैट और टैक्स नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर कपड़े के ऊपर वैट नहीं है, टैक्स नहीं है तो अगर सिले हुए वस्त्र मात्र नब्बे या सौ रुपये तक के जो गत बजट में आपने साड़ी फाल का वैट माफ किया, इसी तरह सिले हुए वस्त्र चाहे पेटीकोट हो, चाहे गाउन हो, मात्र सौ रुपये तक की कीमत को अगर वैट-मुक्त किया जाता है तो कोई आर्थिक नुकसान होने वाला नहीं है, कोई आर्थिक इन्कम में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे हजारों बेरोजगार और गरीब परिवार की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, घर बैठे कुटीर उद्योग चला सकते हैं।

मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में जब देश में हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, तब भी आपकी जमात के विपक्ष के लोगों ने श्रीमती इन्दिरा जी को हटाने का नारा दिया था। इतिहास गवाह है, 1971 के चुनाव में देश की जनता ने न केवल आपका सूपड़ा साफ किया बल्कि इन्दिरा जी को दो तिहाई बहुमत से प्रधान मंत्री बनाया।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, आज भी सत्ता में आने के जो हसीन सपने देख रहे हैं, राजस्थान की जनता अब भी वही हाल करने वाली है जो गरीबों के लिए इन्दिरा जी के समय हुआ। आप सपने देखना छोड़ें और हकीकत में जो मुद्दे हैं, यह बात उठाएं। मुझे खुशी होगी कि आप एक भी माननीय मंत्रीजी के ऊपर ऊंगली उठाएं और वह विथ सबूत उठाएं और एक भी अगर कह दें कि ये घोटाले में पकड़े गये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

यह पहली सरकार है, जब मुख्य मंत्री सम्पत्ति की घोषणा करता है, मंत्री करते हैं, आई ए एस अधिकारी हमारी सरकार में करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो अशोक गहलोत ने हिम्मत करके दिखाई है तो प्रतिपक्ष की नेता भी हिम्मत करें कि आपकी सम्पत्ति क्या है।

मुझे बड़ा फील होता है, मैं नहीं चाहता, कोई विवाद बढ़े; शांति से सदन चले लेकिन अगर वह व्यक्ति भाषण देना शुरू करे, कहावत है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, कहने का अधिकार वह रखता है जो अपने गिरेबान और पैरों में झांकता है, वह आदमी ताकत के साथ कह सकता है। आपके समय, हमने नहीं कहा, वरिष्ठ नेता, कैलाश जी मेघवाल ने क्या कहा है? कैलाश जी तो हमारे नहीं थे, आपके थे, उन्होंने क्या बात रखी? अभी थोड़ी देर पहले बात आयी, कांग्रेस में दो धड़े हैं, फूट है। कांग्रेस में फूट है या नहीं है, आप में क्या है वह सब जानते हैं। कल माननीय तिवाड़ी जी ने कहा, उपाध्यक्षजी, बहुत देरी हो गयी। उपाध्यक्ष जी की तो देरी हो गयी, लेकिन प्रतिपक्ष में क्या है, उनकी भी छुट्टी हो गयी बीच में। तो यह हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं।

इसलिए जो विकास करेगा, गरीबों के हित की बात करेगा, वह राजस्थान में शासन करेगा। जो बड़े-बड़े सूट-बूट पहनकर और बड़ी बड़ी बातें और भाषण का सहारा लेते हुए, एक बात कहते हुए मैं स्थान ग्रहण करूंगा; आपने काफी समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, एक साधारण कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति जोधपुर में अकाल पड़ने पर मजदूरी के लिए गया। उसने तांगा, बग्घी, घोड़ा गाड़ी खरीदी और मजदूरी नहीं होने के कारण हरा घास उनको पोसाता नहीं, तब उन्होंने सूखा घास घोड़े के आगे डालना शुरू कर दिया तो वह खाए नहीं और दिनों-दिन घोड़े की हालत पतली होने लगी। तब भारतीय जनता पार्टी का, शायद राजेन्द्र सिंह जी से ट्रेनिंग लिया हुआ, व्यक्ति बोला कि आपका घोड़ा दिनों-दिन पतला हो रहा है तो कहा कि हालत यह है

(श्री मदन प्रजापत)

कि हरा पोसाता नहीं, सूखा खाता नहीं। उसने कहा यह तो मामूली बात है। दो रुपये का हरा चश्मा लगाकर घोड़े के ऊपर बांध दिया, सूखा ही हरा दिख रहा है, जोर- जोर से खाने लगा। तब हमारे विचारधारा वाले व्यक्ति ने कहा, आपने तो कमाल कर दिया। भई, यह तो घोड़ा है, पशु है, हमने भगवान राम के साथ यह कर दिया। तो भगवान राम के साथ जो यह कर सकता है तो लोगों के साथ, कई पिटारा लेकर आयेंगे। लेकिन यह आने वाला डेढ़ साल मुकाबले का साल है और इस आने वाले बजट के बाद आप प्रतिक्रिया कर लेना, हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा इतना बजट का पिटारा लेकर आयेंगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी और शायद पांच तो क्या दस साल भी आप नहीं आ सकते। तब क्या हालत होगी, वह किसी से छिपी हुई नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पूरा समय दिया इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप थोड़ा पेशेन्स तो रखिये, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हरा चश्मा नहीं पहनेंगे कोई; कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई हरा चश्मा नहीं पहनेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया थोड़ा पेशेन्स रखिये। मैं आपका नाम बोलने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा भी था। माननीय सदस्य, ओम बिरला जी आपको केवल दो मिनट बोलने की इजाजत होगी पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन पर, दो मिनट।

सूचना

कोटा में डूबे व्यक्ति की लाश तलाशने में प्रशासन की नाकामी

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर में 27 तारीख को एक नौजवान, नहर में कूदने से उसकी मौत हो चुकी है; 28 तारीख को श्रीमती पिंकी, 27 तारीख को अंकुश गोयल जिसके पिता मोहनलाल गोयल हैं। पिछले तीन दिन से वहां का जिला प्रशासन व जो राजस्थान सरकार ने बनाया है, पूरे राज्य की आपदा स्टेट टास्क फोर्स उसको ढूंढने में इसलिये नाकाम हो रही है क्योंकि इस टास्क फोर्स के पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, पेट्रोल नहीं है, जिस टास्क फोर्स को राजस्थान सरकार ने बनाया हो, 5 लीटर पेट्रोल नहीं हो, हालात ऐसे हो गये...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक बात बताओ, यह जो बात आप कह रहे उससे...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): रिलेटेड इसलिये है, सचेतक जी, 5 लीटर पेट्रोल नहीं होने के कारण 3 दिन से उसकी आंख के आंसू नहीं सूख रहे। उसको उसके बेटे की लाश नहीं मिल रही...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में आपको सिर्फ इन्फोर्मेशन देनी है। इन्फोर्मेशन दे दी, अब दे दी आपने।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं इन्फोर्मेशन यह दे रहा हूं। राज्य के गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त वहां टास्क फोर्स के माध्यम से जिसका बेटा और जिसकी बेटी गयी है, ढूंढें और उनकी लाश को कैसे भी जाकर उसके पिता, उसकी मां को सम्भलाएं। राज्य सरकार को मैं यह इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति: श्री फतेह सिंह जी।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में दो दिन से चर्चा हो रही है। मैं भी इस मौके पर अपनी बात रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज के समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पिछले समय में और किसी की सरकार, बी जे पी की सरकार थी। हाउस में जितने भी हमारे माननीय सदस्य यहां आते हैं, वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं और यहां पर सारी बात करके आय जनता के पास हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में मौजूदा सरकार ने कई तरह की योजनाएं लागू कीं और उन योजनाओं को लागू करने के लिये हमने पूरे राजस्थान में वातावरण बनाया। हर नागरिक के सामने हमने यह बात कही कि हमने दवाइयां मुफ्त दी हैं, हमने आवास मुफ्त दिये हैं, हमने जमीन सरकारी थीं उन पर भी पट्टा देने का वायदा किया है, जननी सुरक्षा लागू की है और यह-यह काम हम करने जा रहे हैं। यह सारा वातावरण शुरू हुआ। उसके बाद आज भी हमारे माननीय सदस्य उन योजनाओं के बारे में रिपीट कर रहे हैं। मेरा यह मानना था, अच्छा होता, कोई भी माननीय सदस्य जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अन्दर कमी-खामी क्या रही, किस तरह की कमियां हैं और क्रियान्विति में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके बारे में कहते

(श्री फतेह सिंह)

और सोचते। तो मैं समझता हूं कि वह बात सही होती लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने यह कहा, हमारे मुख्य मंत्री ने यह कहा, हमारी सरकार ने यह किया, इसके अलावा कोई नयी बात सामने मुझे दिखती नहीं है। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि इस सरकार में जो कमियां हैं, उन कमियों को वे उजागर करें, उनको मार्गदर्शन दें। जनतंत्र में विरोध हमारा जरूरी होता है, उस हिसाब से काम करें।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि योजनाएं पिछली बार भी पिछली सरकारों ने लागू कीं। 'काम के बदले अनाज योजना' लागू हुई थी पिछली सरकार में; एन डी ए की सरकार में प्रधानमंत्री सड़क योजना भी लागू हुई थी; इंदिरा आवास योजना भी चल रही थी, जननी सुरक्षा भी चल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, कुछ बजट बढ़ाकर देना शुरू किया। तो यह कोई नयी बात नहीं है।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक योजना लागू की वन अधिकार के तहत एक योजना लागू की वन विभाग ने। जिन लोगों की जमीनें, जो लोग वनों में बैठे हुए हैं अपना कब्जा करके, किसान किसी भी समाज का हो, उन लोगों को 2005 तक के कब्जे दिये जाएं। उस बात को लेकर पूरा वातावरण बना आवेदन मांगे गये, कमेटी बनायी गयी और बाद में नतीजा यह हुआ कि 25 परसेंट भी लोगों को अधिकार पत्र नहीं दिया। यह भी एक खोखलापन हुआ। उसके बारे में कोई बोला नहीं।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना भी लागू हुई, भारत सरकार ने लागू की। उसके अन्दर बी पी एल के हर सदस्य को 2012 तक कनेक्शन देना था। ठेकेदार को काम दे दिया। उसके बाद उस ठेकेदार ने काम नहीं किया, काम छोड़कर चला गया। कहीं-कहीं पोल डाल दिये, उसके बाद खड्डे खोद दिये और लोगों को आज दिन तक कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं। जब हमने सारी बात खड़ी कर दी, वातावरण बनाया तो यह कितना भद्दा दिखता है कि सरकार ने उस योजना का कोई फायदा लोगों को दिया नहीं। इसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, अगर मन से राजीव गांधी के नाम से यह योजना लागू की है, उसमें ठेकेदारों को जो भी कठिनाई आती है उसको दूर करते हुए बी पी एल के लोगों को कनेक्शन दिये जाएं।

उसमें दिक्कत और आ रही है। विद्युत विभाग में जिन लोगों ने

(श्री फतेह सिंह)

आवेदन पेश किये घरेलू कनेक्शन के लिये, उसमें, मंत्री महोदय, विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि जब तक व्यक्ति आबादी का प्रमाण पत्र नहीं देगा तब तक उन लोगों को हम कनेक्शन नहीं देंगे। यह भी हमारे सामने एक परेशानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार कोई न कोई रास्ता निकालकर उन लोगों को कनेक्शन देने के लिये कोई कार्यवाही करे।

अन्तयोदय योजना में जो लोग काश्तकार हैं, टी ए डी मद से जो डिमाण्ड आती 10,000 रुपया, 10,000 के बदले 5,000 वह व्यक्ति खुद जमा करेगा और 5,000 रुपया टी ए डी मद से जमा करना था उसके खाते में, लेकिन यह सरकार आये 3 साल होने को आये, टी ए डी मद का पैसा जो जनजाति क्षेत्र में दिया जाता था, उसको बिलकुल बन्द कर दिया। मैं उस बारे में कहना चाहूंगा, सरकार उस योजना को बन्द करके उन पैसों को रोककर उस क्षेत्र की जनता के साथ क्या अन्याय करना चाहती है? मैं अपील करूंगा कि पुन: विचार करके उसकी खोज करे कि वास्तव में शुरू से अब तक जो पैसा दिया जा रहा था किसानों को उदयपुर सम्भाग में, वह पैसा क्यों रोका गया? पैसा रोका गया। लोगों की डिमाण्ड जमा हो गयी, आधा पैसा, उसके बाद उनको कनेक्शन देना था। विभाग ने नोटिस दे दिया, जब तक आपके अनुदान का पैसा जमा नहीं हुआ और आप पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपका यह कनेक्शन खारिज कर दिया जायेगा। तो फिर कब नम्बर आयेगा? उसके बारे में भी आपको सोचना है।

राज्य सरकार ने कई सारी योजनाएं लागू की हैं लेकिन उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हमारे माननीय सदस्य को सोचना चाहिये। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति: मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं, प्रश्न यह है कि सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए, आपकी अनुमति हो तो?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं निवेदन कर रहा था, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना में 10 लाख लोगों को आवास देने की बात करके काम भी चालू कर दिया। उनके खाते में पैसा भी चला गया और उसके अन्दर हुआ क्या? नीचे स्तर के जितने आपके नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं खुल करके कहना चाहूंगा +++ यह बिलकुल सही बात है लेकिन बात यह सामने आ रही है, उनको डराया जा रहा है कि आपने यह बात खोल दी तो आपका पैसा जो 25,000 रुपये या 50,000 रुपये स्वीकृत हुआ, वह खारिज हो जायेगा तो आप फंस जाओगे। ऐसा करके उनको डराया जा रहा है। उसके बारे में भी आप जांच करें। उस गरीब आदमी को पैसा दिया जा रहा है, उसके बाद में उससे पैसा लूटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, एक-दो उदाहरण तो प्रस्तुत करिये ना नाम के साथ कि इन-इन ने पैसा लिया और यह पार्टी के सदस्य हैं...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मंत्री महोदय, मेरे पास सारे डाक्यूमेंट हैं... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप आरोप अगर लगाएं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको पता है...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैंने आरोप नहीं लगाया...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आरोप लगाने के अपने नियम हैं, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको पता है। (व्यवधान) आरोप लगाने के अपने नियम हैं। आप उस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई बात पेश करिये। (व्यवधान).

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैंने आरोप लगाया है? (व्यवधान) यह सारे लोग आरोप लगा रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि आप आरोप प्रमाणित करो ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इस तरह के आरोपों को तो आप एक्सपंज करिये कार्यवाही से। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मेरे पास भी प्रूफ है (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ ...(व्यवधान) बिना किसी प्रमाणिकता के इस तरह का आरोप सदन में लगे ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): हर कोई माननीय सदस्य यह बोल रहा है। मैंने किसी एम एल ए के ऊपर आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आपसे यह आशा नहीं है ना, इसीलिए तो निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान) आप जैसे वरिष्ठ सदस्य जो नियमों, परम्पराओं को जानते हैं, मर्यादा में रहकर के मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगायें और बिना तथ्यों के आधार पर, बिना नाम के आधार पर बात करें। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे ...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं गलत बात बोल रहा हूं क्या? (व्यवधान) मेरा भी अधिकार बनता है। मैं सही बोलूं या झूठ बोलूं, वह बात अलग है, आप उस बात की जांच करने के बाद में चाहे मुझे जो भी दंड देना चाहें, वह आप दे सकते हैं। लेकिन मैं सही आदमी हूं, ईमानदारी के साथ में बात की है और मैं प्रमाणित करने के लिए भी तैयार हूं। मेरे पास उनके शपथ-पत्र हैं। (व्यवधान) यह बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप नाम लाइये ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप नाम दे दो और वह पार्टी का एफिलेशन भी दे दो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): टेबल कर दीजिये आप।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): जरूरी नहीं है कि आज की आज हम दे दें। (व्यवधान) लेकिन हमने यह आरोप लगाया है, यह सरकार की कमजोरी मैं मानता हूं। यह इतना सारा ढिंढोरा पीट दिया ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): किसकी जांच करायेंगे? सभापति महोदय, अगर कोई नाम है तो रख दें टेबल पर। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): आप बोलने नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक चीज है तो रख दो आप। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): रखनी तो है ही ...(व्यवधान)... कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं। किसी भी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता जो यहां उपस्थित नहीं है, उनके बारे में कोई भी दोषारोपण करना उचित नहीं होगा। मैंने बोला, किसी भी पार्टी या दल के। अच्छा यह रहेगा कि आप जो भी उचित कार्यवाही करना चाहें वह करें। लेकिन चूंकि इसका कोई सबूत आज सदन में नहीं है, इसको अंकित नहीं किया जाये।

एक माननीय सदस्य: बहुत बढ़िया।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पूर्व में दिये गये हुए को भी अंकित नहीं ...(व्यवधान) उनको भी एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): अंकित मत करो। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय धारीवाल जी, संसदीय मंत्री कह रहे थे और सब लोग चिल्ला-चिल्लाकर जो आरोप लगा रहे थे, इन्होंने सबूत पेश किये क्या? (व्यवधान) इन्होंने सबूत रखे क्या? (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इन्होंने कौनसा सबूत दिया है? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इन्होंने सबूत पेश किये हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनें। यह व्यवस्था अब से दी है ... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप सबूत की बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आप उधर की बात सुन रहे हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं आप (व्यवधान) हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) गरीब लोगों के साथ बहुत लूट-खसोट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। (व्यवधान)

श्री सभापति: फतेह सिंह जी बोलें, आपका टाइम खराब हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मुख्य मंत्री जी ने जो आरोप लगाये थे, उसके क्या तथ्य पेश किये? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मुख्य मंत्रीजी के जो आरोप हैं, उनको एक्सपंज कराओ। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के आरोप को ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): जो सही बात है, उसको गलत पेश कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपने मुख्य मंत्रीजी को नहीं टोका कि आप बिना तथ्य के सदन में बोल रहे हो, उनको नहीं टोका ...(व्यवधान) और जो प्रूफ के साथ में, एफिडेविट पेश करना चाह रहे हैं उनको रोकना चाह रहे हो आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): करो ना, पेश करो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): हो जायेगा, पेश हो जायेगा, चिंता मत करो। (व्यवधान) पेश कर देंगे। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने जो बोला, उसके क्या तथ्य हैं आपके पास ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, वैसे तो आसन सर्वोपरि है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के मंत्री ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जो भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुबह आरोप लगाये, वह सारे राजस्थान की जनता जानती है। (व्यवधान) उन आरोपों की बात क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह कांग्रेस खुद ही भ्रष्टाचारी ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): पूरे समुद्र में डूबी है भ्रष्टाचार के ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सबूत गलियों में बिखरे पड़े हैं पूरे प्रदेश के। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये। (व्यवधान) और सदस्य हैं बोलने के लिए ...(व्यवधान) अगर आप इतना समय जाया करेंगे तो आपके सदस्य नहीं बोल पायेंगे। मैंने क्या व्यवस्था गलत दे दी है? मैंने बोला किसी पार्टी के ... (व्यवधान) जो कार्यकर्ता यहां उपस्थित नहीं हैं, उनके ऊपर दोषारोपण करना

(श्री सभापति)

उचित नहीं होगा। (व्यवधान) अगर उचित है तो आप करिये। इसके लिए जो कार्यवाही आप उचित समझें वह करिये। यह मैंने कहा है, कोई गलत बात नहीं कही है। (व्यवधान) मैंने कोई गलत नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो नहीं दे रहे लेकिन कांग्रेस को दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस को। (व्यवधान)

श्री सभापति: इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बाकी 20 सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पूरे जीम गये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: फतेहसिंह जी, मैंने आपको चांस दिया, आप बोलिये वरना मैं दूसरे आदमी का नाम पुकारूंगा।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): ये बोलने ही नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये ना। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): हाउस को आर्डर में तो लायें। .(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने व्यवस्था मांगी, मैंने दे दी व्यवस्था। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): भ्रष्टाचार की बात जो प्रमाणित है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, कृपया विराजिये, ओम बिरला जी। (व्यवधान) बोलिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मैंने जो बात कही है वह बात प्रमाण सहित है। जो इस हाउस के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम हमने लिये हैं, लेकिन यह कुल मिलाकर के इस सरकार के ऊपर आता है। इन्हीं के लोग हैं और इन्हीं के लोग जनता की लूट करना चाहते हैं। इसलिए यह आरोप तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के विरोध में हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप उधर क्यों हो? (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): बोलने दीजिये। मैं निवेदन यह कर रहा था

(श्री फतेह सिंह)

कि यह सरकार राजस्थान में कांग्रेस की जब से आयी है, तब से लगाकर के इन्होंने क्या किया कि सरकार बनने के साथ ही पूरे इलाके में मंत्री, प्रभारी मंत्री, सब पूरे राजस्थान में पुरानी सरकार के कामों को उद्‌घाटन किया। डेढ़ साल तक तो इन्होंने वही कार्यक्रम किया। उसके बाद इन्होंने ये योजनाएं नयी लागू कीं, उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया। (व्यवधान) आप चुप रहो। (व्यवधान) आप कौन होते हो? (व्यवधान) मैं कोई गलत बोल रहा हूं क्या? (व्यवधान) जो किया, वह कह रहा हूं।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): आप कांग्रेस वालों की कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा यह अधिकार बनता था...(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): शिलान्यास कर दिया इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। (व्यवधान) बिना स्वीकृति, बिना सैंक्शन ही कुशलपुरा में बायोलाजी खोलने का शिलान्यास का भाटा लगा दिया, आज भी लग रहा है चौमूं में। इन्होंने सामुदायिक भवन का शिलान्यास कर दिया। आज भी भाटा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ...(व्यवधान) और वहां एक ईंट नहीं लगायी। ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिये फतेह सिंह जी को। उनकी तबीयत खराब है, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। आप बोलिये, फतेह सिंह जी।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं यह नहीं कहता, उनका विरोध नहीं करता, उद्‌घाटन किया, जो भी किया, उनका फर्ज बनता था किया, सरकार में थे तो। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और जब भी वहां कोई कार्यक्रम, सरकारी प्रोग्राम रखा मंत्रियों ने तो जिला प्रशासन ने हमको एक तरफ रखा। हमको खबर ही नहीं दी और चुपके-चुपके इन्होंने उद्‌घाटन किया। यह कोई तरीका होता है क्या? हम भी उस क्षेत्र से चुनकर के आये हुए हैं। आज मैं छठी बार इस हाउस में सदस्य हूं और उस क्षेत्र की जनता ने हमको इज्जत दी है। ये उद्‌घाटन करने के लिए गये और हमको नहीं बुलाया तो वहां लड़कों के अलावा कोई भीड़ ही नहीं थी, कोई लोग ही नहीं थे। योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए आये तो जनता तो आनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): वे क्या करते हैं, उन्होंने भी चुपके से कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं है बोलने की, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): मजदूर करके भाटा लगाया और आ गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): यह कांग्रेस के नेताओं की फितरत है ...(व्यवधान) झूठे भाटे लगाते हैं (व्यवधान) कांग्रेस के नेता झूठे भाटे लगाते हैं, झूठे उद् घाटन करते हैं। (व्यवधान) मेरे क्षेत्र किशनगढ़ बास में भी यह ... (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): सारे भाटे किशनगढ़ से ही आते हैं। (व्यवधान) ये लगने वाले सारे भाटे किशनगढ़ से ही आते हैं। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपने भी उप-तहसील बनाने के लिए ...(व्यवधान) वह आज तक उप-तहसील नहीं बनी (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): आपने भी तो चुनावों में भाटा लगाया है, रातों में। (व्यवधान) कोई काम ही नहीं किया, कोई योजना ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): यह सारे भाटे किशनगढ़ से ही आते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप जो बोल रहे हैं, आप कृपया दूसरे लोगों को सहयोग करें, उनको बोलने से वंचित ना करें। ...(व्यवधान)... अभी 20 आदमी बोलने वाले हैं, अगर आप इस किस्म का व्यवहार करेंगे तो वे लोग वंचित हो जायेंगे। (व्यवधान) आप कृपया बोलने दें। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं निवेदन करना चाहता था कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) आप बैठें कृपया। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): ये हमारे साथ भेदभाव करेंगे तो मैं इस

(श्री फतेह सिंह)

हाउस में यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार किया जायेगा तो निश्चित रूप से हम भी इतने कमजोर नहीं हैं, हम हमारे क्षेत्र में किसी भी कांग्रेसी मिनिस्टर को वहां पर प्रोग्राम नहीं करने देंगे। यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जनता मेरे साथ है।

मैं निवेदन यह करूंगा कि जैसे ही इनकी सरकार बनी, हमारे क्षेत्र में डाक्टरों की भर्ती थी, कुछ कम थे; अध्यापकों की कुछ कमी थी लेकिन पद भरे हुए थे; कालेज में लेक्चरर वगैरह भरे हुए थे; आते ही उस क्षेत्र से डाक्टरों को हटा दिया, मास्टरों को हटा दिया, कालेज में लेक्चरर्स को हटा दिया। सब तरह से लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी हमने जोड़ दी, कुशलगढ़ की एक कड़ी बाकी है, उसको जोड़ा जाए। उस विधान सभा क्षेत्र के लिए षड्यंत्र रचना, यह कहां का न्याय है? खैर, चुनाव में ये जीत जाते हैं और हमारी सीट ले लेते हैं तो हमें कोई दु:ख नहीं है लेकिन उस क्षेत्र की जनता के हित में जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनको पार्टी के आधार पर सारों को हटा दिया। अब धीरे-धीरे ये हमारे दयाराम जी परमार उच्च शिक्षा मंत्री बने; कालेज से सारे लेक्चरर्स और सब स्टाफ हटा दिया, एक आदमी सिर्फ था; ये मिनिस्टर बने, इसके बाद हमने इनको चिट्ठी लिखी, इसके बाद में उस क्षेत्र में कुशलगढ़ कालेज में उन्होंने स्टाफ भर दिया। तो जो काम सही करता है, उसके लिए हम बहुत बुरा नहीं कहते हैं। सरकार आपकी है, जो कमियां हैं उन कमियों को आप दूर करने का काम करें; उस क्षेत्र में विकास में जो कमी रही है उस कमी को दूर करें, आप उनकी पूर्ति करें।

अब हम यह क्यों नहीं कहते कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस समय लागू की थी, गांव-गांव में सड़क बनी, 250 और 500 तक की आबादी के पूरे ग्रामीण इलाके में सड़क फैला दीं। 250 तक की आबादी के गांव रहे हैं। लेकिन उस समय की सरकार के समय टेण्डर हुए थे, रोड बनी थीं, उसके अलावा आपकी सरकार बनने के बाद से एक भी टेण्डर नहीं हुआ। इस सरकार में पी एम जी एस वाई में जो रोड बननी थीं, उसका एक भी टेण्डर नहीं हुआ। यह एक अजीब बात है। क्या कारण है इसका? फिर आप कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास किया। विकास आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी सरकार बनी है और जनता ने आपको विश्वास देकर पावर दिया है, उसके लिए आपको काम करना चाहिए लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, हम भी सदस्य हैं, हमको भी विश्वास में लेकर काम करना चाहिए।

(श्री फतेह सिंह)

मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार में बैठे लोगों का इस तरह से एक तरफा व्यवहार और व्यवस्था रही तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में बी ए और बी एड पढ़े हुए लड़के हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही है। भ्रष्टाचार भी इतना फैल चुका है और छोटे-छोटे कामों में पैसा लेकर काम किया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, यह आम लोग जानते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो जगह खाली हैं अध्यापकों की, डाक्टरों की, उनको आप भरें। यह आपकी ड्यूटी बनती है। हमने तो आपके सामने कह दिया, हम चिट्ठी पत्री लिखते हैं लेकिन एक ही कारण कि राजस्थान में जनता दल का एक ही विधायक है और इस क्षेत्र को हमें अपने कब्जे में करना है, इस तरह का दिमाग बनाकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम कतई बरदाश्त नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं इस हाउस में आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि किसी तरह से हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न करें और जो कमियां हमारे इलाके में हैं और जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है, उन लोगों को रोजगार दें। अगर यही स्थिति रही उदयपुर संभाग की तो मैं कह सकता हूं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक समूह है और अन्दर ही अन्दर यह चर्चा चल रही है, ऐसा न हो जाए कि भील सूबा बनाने के लिए वहां पर लोग तैयार हो जाएं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): इसलिए मैं अपनी बात कहते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी काम सरकार करे, वह सोच-समझकर करे और हम लोगों को भी विश्वास में लेकर करे।

कुल मिलाकर राज्यपाल महोदय के द्वारा यह जो अभिभाषण पढ़ाया गया है, उसका मैं विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, आज वैसे तो यू डी एच मंत्री ने बहुत बातें स्पष्ट कर दीं, उन्होंने खुद ने हमको पाण्डव बता दिया और सत्ता पक्ष को कौरव। (व्यवधान) यहां दो ही भाग हैं।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पर दुर्भाग्य की बात है, माननीय मंत्रीजी, आपने चेता दिया कि जो दुर्गति कौरवों की हुई थी, क्योंकि वे मद में थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वे चाहे जो कर रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि समय क्या पुकार रहा है, यही स्थिति सत्ता पक्ष की है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोलते हैं कि वसुन्धराजी के समय में रंगीन चुनरियां विधवाओं को नरेगा में दी जाती थीं। (व्यवधान) बोलने से पहले कुछ तो समझा करो, गरीब भी इसी दुनिया में रहता है। स्वर्गीय राजीव गांधीजी की धर्म पत्नी +++ ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, देखो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप क्या बोले। आपने उनको +++ कहा संसद के अन्दर। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इसको एक्सपंज किया जाए। यह भाषा ठीक नहीं है। यह सुनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। (व्यवधान) आपने वाजपेयी जी को +++ बताया। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने जो बात कही है वह सुनिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने संसद में वाजपेयी जी को +++ बताया और आज आप सोनियाजी पर टिप्पणी कर रहे हो, यह आपका मानसिक असंतुलन है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सुन तो लो आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इसको एक्सपंज कीजिए, नहीं तो यह गलत परम्परा पड़ेगी। (व्यवधान) क्या तरीका है? यह भाषण दो, हमारी आलोचना करो, सब करो लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुत्ते को वसुन्धराजी ने गोली क्यों मारी? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, ये शब्द एक्सपंज करवाइए, हमारी ऐसी पुरजोर प्रार्थना है। इस तरह की परम्परा सदन में नहीं चलनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): या तो मुख्य सचेतकजी मेरी बात सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए। मेरी जो भावना है, ...(व्यवधान) आप बैठिए तो सही, मैं दुबारा स्पष्ट कर रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इसको एक्सपंज कीजिए। यह गलत परम्परा पड़ेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, विशेष तौर से आपसे कि आदरणीय माननीय सोनियाजी, जो कुछ भी उनका सामाजिक स्टेटस है, आपने जो कहा, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है पर ऐसी कोई बात नहीं कहें जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। कृपया इस तरह की बात से जहां तक हो सके बचें और इसको अंकित नहीं करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सरकार की आलोचना करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं यह कह रहा हूं कि मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं कि हमारे एक सदस्य ने ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने वाजपेयी जी के लिए जो कहा उसके लिए कायम हो क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने यह कहा कि वसुन्धराजी ने गरीब विधवाओं को नरेगा में रंगीन चुनरियां बंटवा दीं। मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए, वे गरीब थे इसलिए रंगीन नहीं पहन सकते थे। मैंने कहा है, आदर के साथ कहा है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप इन बातों को रहने दो। (व्यवधान) आप रहने दो इन बातों को। कोई फायदा नहीं है इससे। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, इनको बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है इसलिए कही हुई बात को दोहरा रहे हैं। आप सरकार को घेरने की तैयारी करो, आप में हिम्मत है तो करो। कौन क्या पहनता है और कौन क्या नहीं पहनता है, यह मुद्दा नहीं है पर, माननीय सभापति महोदय, बार-बार सोनियाजी का नाम लिया तो मैं आज कह रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): तो क्या हो जाएगा?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): तो आप बता दो, कुत्ते को गोली क्यों मारी?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपने वाजपेयी जी के लिए कह दिया तो किसी के लिए भी कह सकते हो आप। आपने +++ बताया था उनको।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने आदरणीय सोनियाजी कहा है

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उनको। +++ या ...(व्यवधान) यह बता दो। (व्यवधान) मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये बी जे पी के एम पी थे, तब इन्होंने बोला था वाजपेयीजी के लिए कि +++ हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजिए। हो गई न बात। अब बोलिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा टाइम अब शुरू होगा। इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपने खुद किया है, हमने थोड़े किया है। (व्यवधान) आपकी बात पुरानी हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : पहली दफा है कि सत्ता पक्ष की यह मंशा है। हमने भी तय कर लिया है कि आपके कुकर्मों को उजागर करके रहेंगे, चाहे जितना बहाना कर लो, आपको, सरकार को इस बार भागने नहीं देंगे और इसकी शुरुआत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने असंसदीय शब्द बोल कर की। फिर यू डी एच मंत्री का तो पता ही नहीं है, ये क्या क्या बोलते रहें। (व्यवधान) आपके मंत्रियों के लिए आप कहते हो, ईमानदार आदमी, मैं आपकी बातों से ही लेता हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो, माननीय सदस्य, सर्वदलीय व्यवस्था के आदमी हो ...(व्यवधान) आप हर विचारधारा के व्यक्ति हो ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जो मर्जी आए करते रहो। (व्यवधान) किसान का बेटा हूं, तेरी तरह ब्राह्मण होता तो पता नहीं, क्या कर लेते।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अब देखिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आप बोल रहा हूं और वे तू बोल रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अच्छा, आप, आप, माफ कीजिए (व्यवधान) सुनो, अब आपके क्या हो रहा है? हम थोड़े ही कह रहे हैं। आपकी घबराहट है वसुंधरा जी के नाम से, तो हम क्या कर सकते हैं? (व्यवधान) जनता ने तो तय कर लिया है, अब कौरवों को नहीं दिखाई दे तो उसका कोई

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इलाज नहीं। जनता ने तय कर लिया है कि वसुंधरा जी की कम से कम 170 सीटें आएंगी, आएंगी, आएंगी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पूरे दो सौ बोलो ...(व्यवधान) 30 किस को दे रहे हो? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब आप सुनिए, हम तो अगर वसुंधरा जी की चिलम भरें तो कुछ समझ में आता है, आप डूबते हुए मुख्य मंत्री की, डूबती कांग्रेस की चिलम भरो, क्यों अपने आपको मारने पर जा रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखिए, आपने खुद चिलम भरी है, आपने सब जगह चिलम भरी है मेरे सामने, इसलिए काहे को इन बातों पर जा रहे हो?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब मुझे बोलने दीजिए, रघु जी। आप, सभापति महोदय, हमने तो नहीं कहा, हमारे मिड-वे के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपसे सीख ली है शायद इन्होंने। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आये, उन्होंने दो बातें बड़ी अच्छी कहीं, यह कहा कि अगली बार तो सरकार बी जे पी की आएगी; मैं खड़ा सामने तो मुझसे कहा कि आपकी आएगी और यह कहा कि हमारी कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यू डी एच मंत्री ने सही कहा ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप चन्द्रभान जी का नुकसान करने पर क्यों तुले हुए हो? आप तो यह बताइए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि सरकारी मुख्य सचेतक का कर्तव्य है, सदन ठीक चले ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, हमने जो कुछ सीखा है, आपसे सीखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): साहब, एक-एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जो कुछ सीखा है, आपसे सीखा है। (व्यवधान) आप जिस तरह खड़े होते हो ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, समय मेरा खराब हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मुद्दे पर बोलिये न। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) हमारे विद्वान लर्नेड शिक्षा मंत्रीजी स्कूलों में बच्चों को जाकर कहते हैं, गजनी शिक्षा लाओ। इस भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हमारी ही बात नहीं, इंदिरा गांधी की ही कह देते, महाराणा प्रताप की बात कह देते, शिवाजी की ही बात कह देते, एक विदेशी आक्रमणकारी की बात शिक्षा मंत्री पढ़ायें तो सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो?

आज कहते हैं, साहब, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा; हम नहीं कह रहे हैं, माननीय सचेतक जी चले गये, भरत सिंह के लिए सबसे पहले अगर किसी ने एलीगेशन लगाये थे तो डा. रघु शर्मा ने लगाये थे कि यह भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं पंचायती राज के कामों में। उसके बाद, हम नहीं कह रहे हैं, सुबह कर्नल साहब चिल्ला रहे थे कि मेरे यहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। फिर माननीय मुख्य मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है, मुख्य मंत्री हैं, स्वस्थ परम्परा डालते, कह देते कि मैं इन 5 कलक्टरों के खिलाफ सदन में जांच समिति बैठा दूंगा, पर उनको बचा रहे हैं। कितने करोड़ों रुपये के। इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार का क्या नमूना है कि यू डी एच मंत्रीजी घोषणा कर रहे हैं, किसान के हितों की बात करते हो, 135 किलोमीटर नया जयपुर बसाने के लिए हम लोग जमीन लेंगे; किसानों ने बेचारों ने औने-पौने दामों पर अपनी जमीन को बेच दिया। (व्यवधान) इसमें क्या ईमानदारी दर्श रही थी? ऐसा ही गांव के अन्दर हाल कर रखा है।

अब यह कहते हैं, मुख्य मंत्री वह होता है जो पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, वह किसी पार्टी का नहीं होता, वह किसी पार्टी का नहीं होता, चुनाव के समय पार्टी का होता है। एक जोधपुर और मण्डोर के विकास से राजस्थान का समग्र विकास नहीं हो सकता और जोधपुर के अन्दर भी जोधपुर के हमारे सूरसागर के विधायक और सारे लोग रोते हैं कि आई आई एम ले गये जोधपुर, हो गया सारे राजस्थान के नौजवानों का विकास? आई आई टी ले गये जोधपुर। अलवर के नौजवानों ने क्या बिगाड़ा था कि जो माननीय श्रीमती

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

वसुंधरा जी ने जिस पूरे राजस्थान का चहुंमुखी विकास करना चाहती थीं, उस मत्स्य विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। इससे ज्यादा एक मुख्य मंत्री के लिए दोहरी सोच हो नहीं सकती; इससे ज्यादा मुख्य मंत्री राजस्थान को बरबाद कर नहीं सकता। (व्यवधान)

अब ये एजुकेशन की बात करते हैं, धन्यवाद है हमारे शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूर्व केन्दीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी जसौल लाए, अशोक जी गलत नहीं हैं ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप मेरा टाइम ले रहे हैं, मैं इस विवाद में नहीं हूं। (व्यवधान) आप ऑर्डर में लाइए हाउस को, यह मेरा काम नहीं है। (व्यवधान) शिक्षा की बात करते हैं, इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में एक लाख 33 हजार बच्चे पांचवीं के बाद स्कूल छोड़कर चले गये और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे जोधपुर के विधायक बैठे हैं, आपको तो मुख्य मंत्रीजी को गौरवान्वित करना चाहिए कि 26 हजार बच्चे अगर पढ़ाई छोड़कर गये, स्कूल छोड़कर गये तो वह जोधपुर के अन्दर है। आपके 16 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें मिडल स्कूल नहीं हैं, 382 गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं और धन्यवाद आपका है कि तीन साल में आपने सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल तो क्रमोन्नत ही नहीं कराये। इसके लिए तो आप एजुकेशन की बात करते हो।

सबसे ज्यादा आज के नवभारत टाइम्स में छपा है, हिन्दुस्तान के अन्दर किसी का, जो जननी सुरक्षा की बात बार-बार कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं केन्द्र ने भेजी हैं, आप तो उनकी रखवाली भी नहीं कर सकते हैं, उनको चला भी नहीं सकते, उनका पूरा पैसा भी नहीं उठा सकते हैं, पर शर्म कहां आती है? आप कहते हैं, साहब, आज के नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट छपी है, जननी सुरक्षा की बात करते हैं, 40 परसेंट बच्चे अगर कुपोषण के शिकार हैं तो वे राजस्थान में हैं।

आप किसान की बात कर रहे थे कि साहब, यह तो किसान के पक्ष की बात है, अब तो मेरे भाई, कुछ बोल भी जाते अपने मन में, यह भी कह देते कि साहब, खाद नहीं मिल रहा है। तो फिर किसान की बात कर रहे हो। किसान को सिर्फ खाद क्यों नहीं मिल रहा है? जब किसान को जिस चीज की जरूरत होती है, वही चीज गायब हो जाती है। यह सरकार बिजली के लिए 8

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

घंटे की दर से किसान से फ्लैट रेट लेते हो, बिजली दे रहे हो आप लोगों को दो घंटे, तीन घंटे और वह ट्रिपिंग के साथ में, इससे बड़ा अन्याय क्या कर सकते हैं? पाला पड़ गया, आपको कौन रोक रहा है? सारे किसान आपकी जेबों में गये। जब आप गिरदावरी और उसकी बात कर रहे हो, हमारे यहां सरसों कट चुकी है; पता ही नहीं लगता, कितना नुकसान हुआ; आधी तो कट ली। किसान की बात करते हो, आप घोषणा करो न सब मिलकर के, हम तो जिसने जो फसल बोयी है, उसके हिसाब से मुआवजा देंगे। करो, कौन रोकता है आपको? सब सहयोग करेंगे, तालियां और बजाएंगे हम लोग।

फिर बिजली कनेक्शन की बात करते हो। किसान को बिजली नहीं दे सकते, सामान नहीं है। एक-एक विधायक आप में से जानता है वे इस बात को कि मीटर आपके पास नहीं, इन्सुलेटेड वायर आपके पास नहीं, ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं। पहली दफा हो रहा है। इस राजस्थान के इतिहास में वसुंधरा जी के समय में 48 घंटे के अन्दर ट्रांसफार्मर बदल जाता था, सरप्लस में पड़े रहते थे। आपके यहां क्या हाल हो रहा है? सारे दिन किसी भी विधायक के पास में अगर फोन आते हैं, आपके साथ में बीतती होगा, पर मजबूरी है, नहीं बोल सकते हैं आप लोग; डेढ़ महीना, एक महीना, 15 दिन, 2 महीने, ये हालात चल रहे हैं ट्रांसफार्मर के। जो आता है, साहब, ट्रांसफार्मर दिलवा दो; साहब, ट्रांसफार्मर दिलवा दो। कहीं 8 दिन, कहीं 10, कहीं 15 दिन ट्रांसफार्मर नहीं दे पाते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसको जैसे-तैसे सुधार लो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह खाली आलोचना की ही बात नहीं है, आप आज से ही करें कि हम 48 घंटे के अन्दर अवेलेबल कराएंगे; देखें, हम तो आपकी बड़ाई करेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 72 घंटे में मिल रहा है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप सरकार के मंत्री हो और वह भी निर्दलीय हो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 72 घंटे में मिल रहा है।(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सरकार को डर है कि आप छोड़ कर चले गये तो फिर बखिया उघड़ जाएगी। (व्यवधान) इसलिए ध्यान रख रहे होंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ट्रांसफार्मर जला हुआ 72 घंटे में रिप्लेस हो रहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे यहां भी यह करामात करवा दो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपके भी करवा देंगे। (व्यवधान) डा. साहब, आप दिल्ली रहते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। दिल्ली से सीधे जयपुर आते हैं, यहां से दिल्ली जाते हैं, ट्रांसफार्मर का पता नहीं है। ट्रांसफार्मर दिल्ली के कहीं बीच में नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है। अब आप किसान की बात करते हो, आपको कोई मना कर रहा है, सारे विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, मंत्री और विधायक बैठे हुए हैं और आप ही लोग वाहवाही लो, जब किसान को ब्याज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में एक परसेंट, बिहार में 3 परसेंट और उसी किसान से आप 5 परसेंट लेते हैं। आपने 5 कर दिया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 4 परसेंट।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 4 कर दिया, फिर भी ज्यादा है। अभी तो आप किसान के बेटे बन रहे थे। एक परसेंट करो। जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में कर सकते हैं तो आपको कौन रोक रहा है? किसान के हितैषी हो तो करो ना। किसान को जरूरत थी ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपके समय 13 था, 4 पर आ गये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे समय में क्या था, वह बात मत करो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपने तो 13 से 12 ही नहीं किया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप एक परसेंट करो ना।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप किसान की बात करते हो, 13 से 12 पर ही नहीं आये। हम 13 से 4 पर आ गये और देखें अभी बजट का हमारा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सरकार में थे तब भी कम था, तब आपने मध्य प्रदेश की नकल क्यों नहीं की? बताएं आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, फिर आप लोगों

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

को ताव आएगा। अभी हमारे फतेह सिंह जी ने कोई बात कही, सभापति जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जब खाद का ब्लैक चल रहा था तब कौनसी पार्टी के लोग थे जो खाद की दुकानों पर खाद बिकवा रहे थे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): बीजेपी के।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बी जे पी वालों की दुकान तो हम बंद कर देते हैं एक मिनट में। आपके ही थे। जब किसान रो रहा था तो आपके लोग डी एस ओ को रोक रहे थे कि हमारे आदमी ब्लैक कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। उस समय आप कहां चले गये थे, पर शर्म-लिहाज तो सारी आपने छोड़ दी। ताज्जुब की बात यह है ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): खाद 3.5 लाख मैट्रिक टन हमने राजफैड के माध्यम से सब जिलों में दी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): फिर 900 रुपये कर दिया, 1100 रुपया और 900 रुपया कर दिया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): डी ए पी की कहीं भी पूरे स्टेट में प्रोब्लम नहीं आयी। यूरिया में जरूर भारत सरकार की वजह से कुछ देर हुई इसलिए वहां पर दिक्कत आयी थी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुझे ताज्जुब यह आता है, यहां बैठकर जो मर्जी में आये कर लो, मगर सच्चाई यह है कि बस में चले जाओ, रेल में चले जाओ, गांवों में चले जाओ, चौपाल में चले जाओ, आपको या तो सुनायी नहीं दे रहा है या उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। 100 परसेंट लोग यह कहने लग गये कि वसुंधरा जी आएंगी और गांव का आदमी तो यह कहता है वसुंधरा जी आएंगी और यह तय है। (व्यवधान) पहले बात तो सुनिए। हमारे गृह मंत्रीजी बैठे हैं, मैं गृह मंत्रीजी के साथ खुद चलने को तैयार हूं, एक थाना तो ढूंढ लाओ जिसमें नीलामी नहीं होती हो, जिसमें नीलामी के आधार पर एस एच ओ न लगते हों। रोजाना चोरी, रोजाना डकैती, रोजाना बलात्कार, शायद ऐसा जंगल राज, गृह मंत्रीजी, जब से आपने पद संभाला है, इससे ज्यादा जंगल राज कहीं नहीं हो सकता। अलवर जिले का तो मुझे पता है, एक मिनट में भैंस खोल ले जाते हैं, एक मिनट में मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं, एक मिनट में कत्ल हो जाता है। हमारे बहरोड़ जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में दस से ज्यादा कत्ल हो लिये और मेवात की तो बात ही छोड़ दो, आप ही नहीं जा सकते, आपकी गाड़ी छीन ले जाएंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अलवर में यह क्या हो रहा है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हम तो यह सोच रहे थे कि आप आए हैं, कुछ संभालेंगे। (व्यवधान) बात वसुंधरा जी की करते हो, वसुंधरा जी जो कहती थीं वह करती थीं; वसुंधरा जी के पास अपना विजन था; वसुंधरा जी के पास अपनी सोच थी; वसुंधराजी राजस्थान को बहुत आगे ले जाना चाहती थीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सच-सच बोलिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सत्य बोल रहा हूं, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रहा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना आता है, आपको सपना आ रहा है। 2003 से 2008 के हालात को बयान कर रहे हो? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपके प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा था, उसे दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यही हालात रहे तो हमारी 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, आपके प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): 50 नहीं कहा था, उन्होंने कहा है कि 150 आएंगी; आप वाली 50 गिन रहे थे वे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अख़बार भी पढ़ना नहीं आता आपको। दुबारा पढ़ लेना।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप इधर आ जाओ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब डूबते हुए हो, पहले बात करते तो सोचते भी। अब तो डूबती नाव में कौन बैठे? पहले प्रपोजल रखते तो कुछ सोचते। हमारे जात के लिए तो वैसे ही ठीक नहीं हो, एक हमारा एम एल ए था उसको भी आपने धूल चटा रखी है। इतना इंटेलीजेंट, इतना अच्छा; एक तो मंत्री बना देते; कम से कम सब जातियों को साथ ले लेते। इसलिए मैं आकर क्या करूंगा? मेरे साथ उनसे भी बुरी होगी।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री का अपना एक विजन होता है कि मुझे राजस्थान को किधर ले जाना है, यह सोच होती है। इतना जबरदस्त अखबारों में छपा प्रवासी भारतीयों का, आम आदमी के दिमाग में यह बैठा दिया कि यह भारत सरकार का नहीं है, हम ही करा रहे हैं और पता नहीं, इससे राजस्थान का क्या कायापलट करा देंगे। जवाब देना पड़ा कि हम तो कुछ ले ही नहीं

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पाये, लेना ही नहीं चाहते थे, पर आपका प्रजंटेशन कितना पूअर रहा कि आपके मंत्री पुकार रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है सही बात करने की। इसका सारा फायदा गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी ले गये और आपकी यह दुर्गति हुई कि लोग हंसते हुए गये आपके ऊपर कि ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जिसको कुछ पता ही नहीं हो। कितना खर्च हो गया, 8-10 करोड़ जो भी खर्चा हुआ, एक मौका मिला था, सुनहरा मौका था, राजस्थान की एक छवि बन सकती थी, पर इसके लिए राजस्थान की जनता आपको दण्डित करेगी। आपने राजस्थान की छवि की बिलकुल ही धूल चटा दी। मंत्री पुकार रही हैं, ट्यूरिज्म मिनिस्टर, ट्यूरिज्म एक इण्स्ट्री बन सकता था, हब बन सकता था, आपकी सेक्रेटरी साहिबा प्रजंटेशन देने को तैयार नहीं हैं। आपकी मंत्रीजी कह रही थीं, वे समझीं कि यह विधान सभा है और मैं सत्ता पक्ष हूं। इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं सकता। आप शराब की बात करते हो, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बात करिए, आज अमेरिका इतना एडवांस क्यों है जहां 24 घण्टे शराब मिलती है। आज लंदन क्यों इतना एडवांस है? आज कनाडा क्यों एडवांस है, गोवा क्यों एडवांस है? आपने तीर मार लिया, पता नहीं, क्या कर दिया, 8 बजे बंद कर दी। इसलिए कर दी क्योंकि आपने शराब माफिया से मोटी रकम ली है जिससे वे ब्लैक कर सकें। एक भी जगह आप मुझे दिखा दें, सिद्ध कर दो, मेरे साथ चलो, आपके साथ मैं चलूंगा, जितनी चाहो शराब पूरी रात ले लो। खिड़की बना रखी है दुकानदारों ने। ये बातें हम कहते-कहते थक लिये, पर आपके कानों पर जूं नहीं रेंगती। यह हम बिकवा रहे हैं? रात को दारू हम बिकवा रहे हैं? मिल किससे रही है? वेरी गुड, गांधीवादी नेता, जय हो; ऐसे सुशासन की जय-जयकार हो। 8 बजे दारू इसलिए बंद कर दी कि दारू माफिया के लोग आपके समर्थक हैं और आप चाहते थे कि मोटी कमाई करें, उनके दबाव में यह कदम उठाया था। क्या फर्क पड़ता है, दिन में मिले या रात में मिले? जिसे, पीनी है पिएगा; जिसे नहीं पीनी है, नहीं पिएगा। सारा अमेरिका बरबाद हो गया होगा? सारा इंग्लैंड बरबाद हो गया होगा?

मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी काम करो, जब बात आयी प्रवासी भारतीय सम्मेलन की कि हमने यह किया; जब सवाल आया कि आपने उनसे कुछ इनवेस्टमेंट लिया, तो कहते हैं कि भारत सरकार का आयोजन था, हमारे तो मत्थे पड़ गया और हम कुछ ले नहीं पाये। यह आपका फेल्योर नहीं है?

एक चीज बता दें, आपने खूब कहा था कि हम हर ग्राम पंचायत को

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

बसों से जोड़ देंगे, जोड़ पाये क्या? जुड़ गई होंगी सारी? सारी बसेज चल रही हैं? अब आप कहते हो, भारत सरकार का पैसा है। वाहवाही आप लूटना चाहते हो कि हमने तो भारत निर्माण राजीव गांधी भवन बना दिये, जब आप स्कूलों में टीचर नहीं दे सकते, कालेज नहीं दे सकते तो इतना पैसा कहां से ले आवोगे कि इस राजीव गांधी भवन में सारी सुविधाएं दे दोगे? एक खण्डहर खड़ा करना था जो कर दिया। जनता का पैसा था, नरेगा का पैसा था। आप में जो विषमताएं हैं, दहाड़-दहाड़ कर कहते हो कि नरेगा में हर मजदूर को काम मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? क्यों चिल्ला रहे हो? 119 रुपया और उसी पंचायत में दूसरी मद से अगर कोई दूसरा काम हो रहा है तो वह 135 रुपये में हो रहा है। आप इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हो। मांडण के अन्दर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिस जननी सुरक्षा की आप बात करते हो, वहां मुझे जाने का मौका मिला। वहां ए एन एम नहीं, जी एन एम नहीं, डाक्टर नहीं और एक चपरासी ने महिला की डिलिवरी कराई। इरादा यह होता है कि जहां भी चले जाओ, जितना जननी सुरक्षा में आप देते हो उससे ज्यादा तो आप अस्पताल में लुटवा देते हो। फिर भी हम खुश हैं। ये योजनाएं तो भारत सरकार की हैं, पूरे हिन्दुस्तान में लागू हो रही हैं, कोई आप नई नहीं ला रहे हैं।

मुख्य मंत्रीजी ए पी एल, बी पी एल की बात कर रहे हैं, जो रियल बी पी एल आदमी थे उनका गला काटकर उनको स्टेट बी पी एल बना दिया। हमारे माननीय मंत्रीजी गये थे और बोले कि मुख्यमंत्री बीपीएल के लिए हम लोगों को चैक बांटेंगे, एक भी नहीं बांटा। चैक बांटें इन्दिरा आवास के और कह दिया कि मुख्यमंत्री के बांट रहे हैं। हमने कहा कि इतनी बात तो मत करो कम से कम, इतना पैसा क्यों खर्च करवा रहे हो, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो।

सड़कों की आप बात करते हैं, आपके यहां तो पता नहीं, सड़कों की क्या हालत है लेकिन अलवर जिले के अन्दर एक दिन मुख्य मंत्रीजी दौरा कर लें और शाम तक ठीक आ जाएं तो मेरी गारंटी है। उनकी कमर के अन्दर जो स्पोंडिलाइसिस है उसमें छह गुणा दर्द हो जाएगा। हर मीटर पर गड्ढा है।

ताज्जुब की बात है, कल मैं सेंट्रल पार्क से घूमकर जा रहा था, जिस वर्ल्ड क्लास सिटी की आप बात करते हो, आज भी एम.आई. रोड पर पेट्रोल पम्प के सामने एक स्कूटर वाला बुरी तरह गिरा। पता नहीं, बचे या नहीं बचे और उनको लेकर के गये। वह आज 10 दिन से यों का यों है। यह है आपका वर्ल्ड क्लास सिटी।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

कहना बहुत आसान है, योजनाओं का नाम लेना आसान है, भारत सरकार की योजनाएं हैं, आप उनका पूरा पैसा नहीं उठा रहे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ एक ही फोबिया हो गया, वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा। वसुंधरा बिना तो हम सब अधूरे हैं। यह धरती है, पवित्र धरती का नाम वसुंधरा है, कल्पना का नाम वसुंधरा है, वसुंधरा के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे। वसुंधरा तो आयेगी, आपसे रोका जा सके तो रोक लो, चाहे कितना ही चिल्लाओ। एक निवेदन है कि आपकी एक-एक बखिया उधेड़ सकें, ऐसा अपना आवरण मत बनाओ कि आप हाउस छोड़कर भागो। जनता जान चुकी है कि यह सरकार टिकनी मुश्किल है।

भ्रष्टाचार की बात करते हो, क्या यह सरकार ईमानदारी पर बनी है? क्या यह सरकार पहले दिन ही भ्रष्टाचार की नींव पर नहीं बनी? उस मायावती के नाम पर, मायावती के वर्करों के नाम पर जो जीत कर आये, उनको आपने प्रलोभन दिया और गलत तरीके से उनको शामिल किया। इसे भ्रष्टाचार नहीं बोलते हैं क्या? भ्रष्टाचार का नाम क्या है? आज वे जानें जो इनकी दुर्गति हो रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया छोटा करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं तो जब आप कहेंगे तब बैठ जाऊंगा। मैं आपकी पीड़ा भी जानता हूं, मेरी पीड़ा भी जानता हूं, जनता की पीड़ा जानता हूं। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, जनता परेशान है। हर विभाग की बात है। 2-4 मंत्री हैं जो अच्छे लोग हैं। सारी बातें अच्छी हैं, मैं यह तो नहीं कहता; परसादी लालजी बैठे हैं मैं इनके बारे में कभी नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं कि ईमानदार आदमी हैं; बृजकिशोरजी चले गये, अच्छे हैं। आपकी सरकार की ऐसी हालत हो रही है कि ''अंधा बांटे रेवड़ी और घर-घर खाने को दे''। कुछ पता ही नहीं है कि कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, दिशाहीन सरकार है। ये आंकड़े उठाकर देख लो। कहते हैं कि हमने तो 3,380 मेगावाट बिजली बढ़ा दी। फिर वह गई कहां? मैं तो नहीं कह रहा, हर गांव का किसान कह रहा है। आपके विधायक दल की चर्चा तो बाहर तक आती है। इसमें कहोगे कि जिक्र नहीं करें। आपके विधायक दल में क्यों असंतोष था? क्यों कह रहे थे कि मंत्री हमारे काम नहीं करते? क्यों कह रहे थे कि हमारे यहां काम नहीं होते? यह हमने कही बात? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कह लो पर ये मेघवालजी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा, बोले कि मैं अच्छा काम कर रहा था, मेरी छवि बढ़ रही थी,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसलिए कांग्रेस के लोग नहीं चाहते किसी एक दलित वर्ग के आदमी की छवि। आप दलित विरोधी भी हो।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): हनुमान बेनीवालजी क्या कह रहे हैं, वह सुनो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): करणसिंहजी, माननीय मेघवालजी वक्तव्य दे नहीं रहे हैं पर उनका नाम इसलिए नहीं कटा, उनका इसलिए कटा था कि अख़बार में खबर आ गई कि वे मुख्य मंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसलिए उनका नाम कटा था।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से और मंत्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान को आगे बढ़ायें, इसमें सबको खुशी होगी क्योंकि हम सब राजस्थान के हैं। यू डी एच मंत्रीजी कह रहे हैं कि आप हमसे मांग रहे हो; हम मांग नहीं रहे हैं, हम जीतकर आये हैं, हमारा प्रदेश है, हमारा हक है। इस विधान सभा में, इस सरकार के अन्दर सबका साझा है। सरकार किसी पार्टी की बने पर यह प्रदेश कांग्रेस का नहीं है, सबका है; गरीब का है, अमीर का है, ईमानदार का है; सबका है। इसलिए हम मांग नहीं रहे हैं, हम हक से लेना जानते हैं और हक से लेकर रहेंगे। यह बात दुबारा नहीं आनी चाहिए।

आप कहते हो कि हम तो किसान के बहुत हितैषी हैं, करणसिंहजी, मेरी बात सुन लेना, नरेन्द्र मोदी अपने गुजरात का विकास करने के लिए, वहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसान से जमीन लेता है, किसान से बात करता है और फिर उसका 30 साल का किराया देता है। आपसे बढ़िया तो हुड्डा हैं हरियाणा के मुख्य मंत्री, उन्हीं से सीख लो। मोदी तो कितना ही अच्छा काम कर लें, उनके नाम से तो आपके पेट में दर्द हो जाता है पर हुड्डा तो आपका है जो 27 साल का किराया दे रहा है। आपके यहां क्या हाल हो रहा है? किसान की बात कहना अच्छी बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें, 5.40 हो गये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बस, एक मिनट में कर रहा हूं।

पहले दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी की हम किसान की मर्जी के बिना जमीन नहीं लेंगे और लेंगे तो हरियाणा और गुजरात की तर्ज पर लेंगे। क्या हुआ? ये सभापति महोदय बैठे हैं, इनके क्षेत्र में ही दुनिया भर की जमीन ले ली और जो जमीन एक करोड़ बीघा के हिसाब से है, वह

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

जमीन सात लाख बीघा में हड़प ली। किसान कहां जायेगा? उनको फैक्टरी में नौकरी नहीं मिलती। अब इसमें दे दिया कि जापानी जोन नीमराना में बन गया; कहने में ही शर्म कर लो, यह जापानी जोन वसुंधराजी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था और तब वे फैक्ट्रियां लगी थीं। आप जबरदस्ती ही वाहवाही लूटना चाहते हो। आपको पता ही नहीं है कि कौनसी फैक्टरी कब चालू हो रही है। एक फैक्टरी तो बता दो जो तीन साल के आपके कार्यकाल में भिवाड़ी, नीमराना और अलवर में लगी? फैक्टरी लगती है तो 3-4 साल उनको चलने में लगते हैं, चाहे होंडा सिटी हो, चाहे जापानी जोन की हों। इसलिए मैं कहता हूं कि झूठी बातें करने से जनता पर असर नहीं होता और मैं सत्य कह रहा हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, पर हे मेरे कौरव बन्धुओं, समय को समझो, अच्छे-बुरे को समझो, आपकी नाव डूब रही है, भागना हो तो भाग लो। राम-राम, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव जी आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस ढंग का जुल्म इस प्रदेश में हुआ है, अत्याचार इस प्रदेश में हुआ है, मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि धन्यवाद तो मुख्य मंत्रीजी को दे रहे हैं जबकि यह धन्यवाद है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, लेकिन महामहिम राज्यपाल तो राजस्थान में हैं ही नहीं। किनको धन्यवाद दें? अगर मुख्य मंत्री जी को ही धन्यवाद देना है तो आप उनको उनके चैम्बर में जाकर, उनके घर में दे सकते हो, यहां सदन में क्यों समय खराब कर रहे हो हमारा भी और अपना खुद का भी? यह समय खराब करने के लिए नहीं है। सदन तो जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए यहां पर समस्याएं उठाने के लिए है।

मैं जिस जुल्म की बात कर रहा था, वह शुरुआत करना चाहता हूं, श्री शांती धारीवालजी उस राजकपूर के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने कहा, कई नाम लिये, उनमें उन्होंने राजकपूर का भी लिया जो 'अनाड़ी', 'आवारा', 'दीवाना', 'श्री 420', 'मेरा नाम जोकर'। आप खुद भी +++ दिखा रहे हैं शांती धारीवाल साहब, उन फिल्मों के जनक रहे, उनके हीरो रहे थे। अब उस समय कुल तीन हीरो थे, आज की तरह 500 हीरो तो थे नहीं, 500 हीरोइनें थीं नहीं। जितना भाषण उन्होंने दिया, उसके बारे में तो बाद में बोलूंगा लेकिन 'आवारा',

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

'छलिया', 'अनाड़ी', दीवाना, श्री 420 के दीवाने शांती धारीवाल साहब को धन्यवाद कि वे मेरा नाम जोकर भी हैं।

जिस जुल्म की बात मैंने की है, वह है सी बी आई। आप सबके रोंगटे खड़े हो जायेंगे, मैं कंडेम करता हूं सदन में सी बी आई को। आपने अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं किया, आपने अपनी पुलिस पर अविश्वास करके उनको अकर्मण्य कर दिया, उनको अयोग्य मानकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं किसी देवी का, उसका अपहरण किया गया, उसको मारा गया, उसके बारे में कोई नाम नहीं लेना चाहता। शाम का समय है, हमारे देश में देवता पर्यटन करते हैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब समझते हैं। (व्यवधान) ले लूं नाम? अब हमने कई मीटिंग में बोला कि भई, कांग्रेसियों के क्या हाल हैं, कहे कि भंवरी; कहां जा रहे हो, कि भंवरी; तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं, कि भंवरी। आपके यहां भंवरी और हमारे यहां है भंवर। भंवर और भंवरी के चक्कर में हमारा अलवर जिला पिस रहा है, राजस्थान पिस रहा है। नाम लेने के लिए माननीय देवीसिंहजी ने कह दिया, इसलिए लिया। मैं कहना चाहता हूं, सी बी आई ने आपको, एक भी मंत्री जो यहां बैठे हैं, बाकी तो चले गये हैं... (व्यवधान) जोशीजी, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में दिमाग होता है और यह जब खराब होता है तो या मृत्यु होती है या लकवा होता है या आदमी पागल होता है या रीढ़ की हड्डी में से तीन नसें जाती हैं। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो कम से कम दिशा ठीक दें। बीच में न बोलें, मैंने किसी को नहीं टोका। मैं परसों से, तीन दिन से सुन रहा हूं, मैंने किसी को नहीं टोका, आप कृपा करें।

घटनाक्रम जब सी बी आई को जांच के लिए सौंपा गया, उससे आगे बढ़ें। जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने हत्या की, उनको चाहे जो सज़ा दे सी बी आई और आपकी सरकार लेकिन क्या कसूर है, हमारे एक विधायक रहे, भले ही उन्होंने अपराध किया, अभियुक्त हैं तो सज़ा पायेंगे जब प्रूव होगा, प्रूव हो जायेगा लेकिन उनके पोतों को सी बी आई के अफसरों ने कोर्ट में बुला लिया; माननीय सभापति महोदय, उनकी पोतियों को बुला लिया; उनकी बहुओं को बुला लिया, और तो और, आपकी और हमारी जननी, मातृ शक्ति, यहां बहनें भी बैठी हैं और माताएं भी बैठी हैं, मातृ शक्ति, उनकी 85-90 साल की मां को बुला लिया। धृतराष्ट्र हो गये अशोक गहलोत साहब, आंखें बंद हो गईं मुख्य मंत्रीजी की और आप सब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आप भीष्म पितामह बनकर। शांती धारीवाल साहब बोल रहे थे कि इधर चीरहरण हो रहा था, चीरहरण तो उधर हुआ, सी बी आई ने किया। किसी दो कास्ट, एक जाट होगा, एक विश्नोई होगा, मान लो, उन्होंने गलती की तो क्या सारे जाट दोषी हो गये? सारे विश्नोई दोषी हो गये? दो लोगों ने मैडम +++ इन्दिरा गांधी की हत्या की तो क्या सारा खालसा, सारा सिक्ख समाज दोषी हो गया? और आपको तो हत्या करने की, भ्रूण हत्या करने की आदत पड़ी हुई है ना, 1984 में हजारों सिखों को मार दिया तो मां को बुलाया गया, मां-जननी को। हमारे देश में मां की पूजा है, गीता माता, गंगा माता, गऊ माता और अपनी जननी माता, धरती माता, मातृ शक्ति को पूजा गया, यह मातृ शक्ति यहां बैठी है, आपने उस मां को कोर्ट में बुलाया और कोई नहीं बोला। शर्म की बात है, कोई बोला नहीं और किसी ने कुछ कहा नहीं, सी बी आई अपना नंगा नाच खेलती रही। मैं आप सब, सदन में बाकी विधायक तो कम हैं, हैं नहीं, हम लोग कम हैं लेकिन मैं चाहूंगा, सदन में प्रस्ताव पास हो, निंदा प्रस्ताव पास हो उस सी बी आई के खिलाफ जिसका दुरुपयोग आपने किया है चाहे दारिया कांड में किया है, चाहे भंवरी देवी कांड में किया है और चाहे गोपालगढ़ कांड में किया है।

गोपालगढ़ में पहले तो गुजरात के ऊपर आरोप लगा, माननीय नरेन्द्रजी मोदी के ऊपर। पहले तो आपने अल्पसंख्यकों को गोलियों से भूना। क्या एस.पी. और कलक्टर की हिम्मत है? हम सब राजनीति में हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, एस.पी. और कलक्टर की हिम्मत नहीं है कि वहां गोलियां चला दें। निश्चित रूप से तत्कालीन गृह मंत्री, शांती धारीवाल साहब का आदेश होगा। मुख्य मंत्रीजी की बिना कन्सेंट के वहां पर एक छोटा सा सम्मेलन हुआ, 10 बार मुख्य मंत्रीजी गये, कलक्टर और एस.पी. अलवर को फोन आया। गोविन्दगढ़ में हिन्दू सम्मेलन हुआ, मुझे बुलाया गया। तो आपकी सरकार के गृह मंत्री के, मुख्य मंत्री के बिना कंसेंट के, बड़े हितचिंतक हैं मुसलमानों के, बड़े हितचिंतक हैं अल्पसंख्यकों के, गोलियों से भून दिया और 10 तो लाशें मिलीं और उन 10 लाशों के अलावा लगभग 40 लाशें हैं अल्पसंख्यकों की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पता है, सभापति महोदय, अलवर और भरतपुर जिले के सब लोगों को, उनको ट्रकों में ले जाकर चम्बल में डाल दिया गया। एस.पी., कलक्टर की गलती नहीं थी, एस.पी., कलक्टर की गलती नहीं है, गलती है गृह मंत्रीजी की और मुख्य मंत्रीजी की जिन्होंने पहले

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अल्पसंख्यकों को मारा। आप मारो भी और रोने भी मत दो। उसके बाद शांती धारीवाल साहब गये, उनके बयान कुछ आये और मुख्य मंत्रीजी गये, उनको चैन नहीं पड़ा, भागे-भागे गये। वोट कट रहे हैं। वोट तो तुम्हारे कट गये। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह आयेंगी चार सीटें। आपको पता लग जायेगा कि अल्पसंख्यक आपके बारे में क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में। उत्तराखण्ड और पंजाब में इतने हैं ही नहीं। आपको पता लग जायेगा। आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, सी बी आई ने जिस ढंग से नंगा नाच किया। हमको आपने पांडव कहा, पांडव तो आप हो कि चीरहरण हुआ मां का, द्रोपदी का नहीं, पांडवों की पत्नी का नहीं, मां का। एक विधायक छोड़ दीजिये, एक साधारण नागरिक छोड़ दीजिये। एक मां का, उसकी मां का चीरहरण हुआ और हम टुकुर-टुकुर, टुकुर-टुकुर देखते रहे, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

आप कानून-व्यवस्था की बात करते हो, विधायक बैठे हुए हैं यहां हमारे श्रीमान् बाबूलाल बैरवा, इनके घर पर आती हैं कांग्रेसी नेता, क्योंकि वे इस सदन में नहीं हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा, इनके घर में पांच बार चोरी हुई है; प्रभारी मंत्री हैं माननीय पंडित बृजकिशोरजी शर्मा, ब्राह्मण हैं, मैं उनके चरण छूता हूं पांच बार उनके घर में चोरी हुई है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार। क्योंकि उन्होंने खेड़ली में मकान बना लिया, खेड़ली में वे खुद रहते हैं कांग्रेसी नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इनसे हारे हुए हैं, उन्होंने पांच बार चोरी करा दीं और अलवर का पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। उसी दिन और दूसरा समाचार आया है, विधायक के मकान के चार जगह चोरी, यह समाचार है कल का। यह कानून-व्यवस्था है?

आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, मैंने बताया कि सी बी आई का जो नंगा नाच है, कैफी आजमी, शबाना आजमी, हीरोइन के पिताश्री, उन्होंने बड़ी अच्छी शेरो-शायरी लिखी हैं, हमारे राजेन्द्रजी ने कहा कि आप बात को शेर से शुरु करें, मुझे बीच में ध्यान नहीं रहा, उन्होंने लिखा है, ''इस जुल्म को देखा है, तवारीख की नजरों ने, तवारीख मतलब इतिहास, हमारी इंसाफ साहिबा जानती हैं और बाकी लोग भी समझते हैं, ''इस जुल्म को देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई'' आप सज़ा पाइये क्योंकि मां को प्रताड़ित किया गया है, चीरहरण किया गया है;

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आप सज़ा पायेंगे क्योंकि अल्पसंख्यकों को मारा गया है; आप सज़ा पायेंगे कानून-व्यवस्था के नाम पर। क्या कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई आपने। क्या किया गृह मंत्रीजी ने? अब तो खुद गृह मंत्रालय माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है, फौरी तौर पर हमारे बेनीवाल साहब हैं, तदर्थ गृह राज्य मंत्री बेनीवाल साहब हैं। मैं उनको तदर्थ, एडहाक कहूंगा। राजेन्द्रजी, 334 जगह पुलिस पिटी है, प्रशासन पिटा है। मेरे पास डैटा हैं, पुलिस और प्रशासन 334 जगह पिटा है। हमारे आजाद साहब बार-बार खड़े होते हैं एम एल ए सवाई माधोपुर। ले गये वहां सी.आई. को फूल मोहम्मद को, जिंदा जला दिया; तड़पा-तड़पा कर पत्थरों से मारा, फिर जिंदा जला दिया। आज जयपुर में ए.एस.आई. की हत्या हुई थाने में, सब-इंस्पेक्टर की हत्या हुई, बलात्कार हुए थाने में। 334 जगह पुलिस और प्रशासन पिटा। माननीया वसुन्धराजी का जब राज था, दिल्ली में थे माननीय अशोक गहलोत साहब, सी.एम. साहब, आते थे 15 दिन में एक बार और आकर प्रेस वक्तव्य देते थे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्यों? अब जरा कहिये न, 334 जगह जो पुलिस पिटी है, प्रशासन पिटा है।

सरे-आम हमारे यहां मेवात में हत्या, लूट, बलात्कार, गौकशी, गौ तस्करी, मोटर साइकिल, जीप, बोलेरो की चोरी। गवर्नर महोदया की बोलेरो चोरी हो गई, विधायकों की बोलेरो चोरी हो गई। बाद में आंख मसल कर, थूक से मुंह धोकर के, थूक से, और कहते हैं कि नहीं, नहीं, वह बोलेरो गवर्नर साहब की, महामहिम कमलाजी की बोलेरो मिल गई। आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हो, वर्ल्ड क्लास सिटी, हैण्डसम सिटी बनाना चाहते हैं जयपुर को, रोज एवरेज तीन चेन चोरी हुई हैं, एवरेज दो मर्डर हुए हैं, एवरेज दो बलात्कार हुए हैं और लगातार जयपुर में वारदातें चल रही हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। गोल्ड सुख के उद्‌घाटन करने वाले बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही नहीं, बेचारे सी आई को रगड़ दिया, सब-इंस्टपेक्टर को रगड़ दिया। ऐसे ठगी के केन्द्रों का उद्‌घाटन करने वाले आप लोग, मंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी ठगी, चार-सौ-बीसी, आठ-सौ-चालीसी, सोलह-सौ-अस्सी, तैंतीस-सौ-साठ, चार-सौ-बीस का भी पांच गुना, ऐसी ठग विद्या करने वाले आप लोग, बातें करते हैं कानून-व्यवस्था की।

अब मैं उस कानून-व्यवस्था के जिसकी आपने धज्जियां उड़ाई हैं, मैंने आपको उदाहरण दिये, आपके ही एक विधायक के बच्चे का अपहरण हो जाय

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और मर्डर हो जाय, +++ चुल्लू भर पानी नहीं है तो अलवर में अभी पानी है सीलीसेढ में, वहां से भिजवा देता हूं टैंकर। एक विधायक के बेटे का अपहरण हो जाय, मर्डर हो जाय और आपकी कार्यवाही कितने दिन, महीने लेट चली, वह सारा पढ़ा।

मैं इस विषय को और अधिक नहीं बोल करके एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, तीसरा विषय है, शराब की बात करते हैं; कुछ विधायक हमारे कहते हैं, आठ बजे बाद भी दुकानें खुली रहती हैं; कुछ ने भाषण दिया कि आठ बजे बाद बार चलते हैं, गलियों में बिकता है। क्यों बिकता है? आप शराब को नहीं चाहते, गहलोत साहब? +++ गांधीवादी गहलोत साहब, +++ गांधीवादी गहलोत साहब, कलयुग के गांधीवादी बनना चाहते हैं। वह गांधी तो सतयुग का था, वह गांधी, महात्मा गांधी तो, लेकिन महात्मा गांधी को भी तो आप लोगों ने खराब कर दिया न, महात्मा गांधी को भी तो आप लोगों ने बदनाम कर दिया न। रिजर्व बैंक के पांच सौ और हजार रुपये के नोट पर है। इसलिए किसी कवि ने लिखा, "वाह रे महात्मा गांधी, खूब चली तेरी आंधी; तुम तो रहे जिंदगी भर लंगोट में, पर अब तुम्हें छाप दिया कांग्रेसियों ने पांच सौ और हजार रुपये के नोट में, आपने उस गांधी को, जब से गांधीजी का फोटो छपा, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता। शराब की बात की, शराब क्यों चले राजस्थान में? गुजरात में शराब नहीं चलती। माननीय बृज किशोरजी, मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, गुजरात में शराब पर पाबंदी है लेकिन गुजरात का जो विकास हुआ है... (व्यवधान) जाड़ावत साहब, आप उपाध्यक्ष नहीं बनें तो आप शांत रहो, आप तो कम से कम हमारा समर्थन करो। गुजरात में शराब बंद है, वहां शराब नहीं बिकती, आबकारी से अरबों रुपये नहीं कमाये जाते, खरबों रुपये नहीं कमाये जाते तो क्या गुजरात का विकास नहीं हुआ। इस समय वर्ल्ड में; एशिया में नहीं, वर्ल्ड में पूरे में गुजरात का नाम है। कइयों ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, उद्योगपति दौड़-दौड़ कर आते हैं।

एक सर्वोदयी नेता ने पत्र लिखा है, गांधीवादी मुख्य मंत्री का शराब प्रेम, रातों-रात, आबकारी मंत्री अभी हैं नहीं, हमारे पारीक साहब, पंडितजी, रातों-रात शराब की दुकान की एक साल की बजाय दो साल की नीति निकाल दी। आप नीति और आयोग बहुत बनाते हैं, आप समितियां बहुत बनाते हैं, आप कमेटियां बहुत बनाते हैं, उन कमेटियों का क्या हश्र हुआ? कितनी समितियां,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कितना पिछले अभिभाषण में जो सामने आया, एक भी योजना सफल हुई क्या?

बिजली का खींवसर साहब बोल चुके। सिंचाई का, मैं कहूंगा, सिंचाई में मेरे अलवर जिले में एक रुपया भी सिंचाई के बजट में नहीं आया, एक भी। शराब का बजट जरूर आया। शराब के बारे में पत्र लिखा है, शराब ठेकेदारों को दो वर्ष का अवसर दिया। शराब की आय को महात्मा गांधीजी ने पाप की आय कहा था। मुख्य मंत्री ने सभी मर्यादाएं ताक पर रखकर, यह पत्र लिखा है एक सर्वोदयी ने, यह आपका हश्र है। क्यों खुलनी चाहिए आठ बजे से पहले? शराब पर बिलकुल पाबंदी होनी चाहिए और शराब पर पाबंदी हो, फिर देखिये राजस्थान का कैसा विकास होता है। आप इस बात को लेकर के कितने दिन मुंह बचायेंगे?

अब राज में आने के बाद, वसुंधराजी, माननीय वसुंधराजी की बहुत बड़ाई करते थे, राज में आने के बाद में क्या हुआ? भरतपुर, ब्रज में एक छोटी सी कहानी है; राजेन्द्रजी, सुनिये आप; राजेन्द्रजी, जरा ध्यान दें; भरतपुर, ब्रज में एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया राई बिलो रही थी दही से मक्खन निकालने के लिए। अब मक्खन निकालते-निकालते, बड़ा सारा घड़ा था, मक्खन निकालते-निकालते जब बहुत सारे मक्खन का एक डला ऊपर आया तो बुढ़िया ने एक मक्खन का लिया गोला हाथ में और वह रखा कटोरे में और एक गोला निकाला, वह लिया मुंह में और फिर एक गोला निकाला मक्खन का, हाथ में और फिर कटोरे में; बेटे ने देख लिया, बेटे ने कहा, मां, जे का है रहे है, ब्रज में कि मां, जे का है रहो है; बोली, लाल, जब से तुम्हारे पिताजी मरे हैं, न मोहे होश ही ना है कि मक्खन कटोरे में जा रहा है कि मुंह में जा रहा है।

मुख्य मंत्री बनने के बाद इनको होश ही नहीं है। सोनियाजी की स्तुति कर लीजिये लेकिन आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई विभाग नहीं है जिसमें मैं आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूं, लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से हुई? माननीय सभापति महोदय, नाम इसलिए ले रहा हूं कि शांति धारीवालजी ने नाम लिये, वरना मैं नाम किसी का नहीं लेता जो कि सदन में नहीं हैं। भ्रष्टाचार की शुरूआत हुई पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी के समय। पांच मुख्य मंत्रियों की शिकायत लेकर लोग गये। राजस्थान के स्वर्गीय श्री मोहन लाल सुखाड़िया, पंजाब के स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह कैरो, तमिलनाडु के, पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं, श्रीभक्त वत्सलम, पश्चिम बंगाल के घोष, मध्य प्रदेश के डी.पी.

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मिश्रा, इनकी शिकायत लेकर गये लोग, वहां की जनता कि ये बहुत गबन-घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पण्डितजी जवाहर लाल नेहरू का मैं बहुत सम्मान करता रहा, उन्होंने जवाब क्या दिया, वह जवाब रिकार्ड में है, लोक सभा के रिकार्ड में हैं, उन्होंने जवाब यह दिया कि भाई, देश का पैसा देश में ही तो है, अगर इनके पास जा भी रहा है, मुख्य मंत्री के पास। उस समय तो देश का पैसा देश में था लेकिन अब क्यों करोड़ों-करोड़ रुपया किस परिवार का जमा है, उसकी सारी कलई खुलेगी, उसके बारे में जब नाम आयेंगे तभी बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पांच मिनट, साहब। अभी तो...

श्री सभापति: पांच नहीं, अब एक-दो मिनट, बस।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): देखिये, साहब, पौन-पौन घंटा लोग बोल गये। कृपा करें आप मेरे ऊपर।

श्री सभापति: आप ही के मुख्य सचेतक ने यह अनुशंसा की है, दोनों मुख्य सचेतकों ने, पन्द्रह मिनट; आपके बीस मिनट हो गये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप चरित्र की बात करें, तो बजट के बारे में तो अभी बोलना बकाया है।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): गवर्नमेंट आपकी आ जायेगी तो...(व्यवधान) इसलिए आप तो रहने दो चुपचाप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं आपके उत्तर का जवाब नहीं दूंगा, मेरे मित्र हो। ऐसा है कि शांती धारीवाल साहब ने बड़ी चरित्र की बात की और कई जगह एक व्यक्ति का नाम लिया। भाई साहब, घनश्यामजी तिवाड़ी ने जवाब भी दिया, केन्द्र सरकार हिल जायेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, पिछली विधान सभा में जो लोग थे, सभापति महोदय, हमारे श्री मदन दिलावर, तत्कालीन विधायक, उन्होंने आरोप लगाया। तब मैं भी एम एलए था, माननीय गहलोत साहब, मुख्य मंत्री, तब भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री शांती धारीवाल एक लड़की को लेकर के भाग गये, यह आरोप लगाया और उस पर जवाब धारीवाल साहब ने क्या दिया, वह सुनिये, रिकार्ड में है, विधान सभा के रिकार्ड में है। मैं कपोल-कल्पित पत्रकारों के सामने बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, विधान सभा के रिकार्ड में है। धारीवाल साहब खड़े हुए,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बड़े शांतचित्त, मेरा नाम जोकर, आवारा, छलिया, अनाड़ी, दीवाना, राजकपूर के भक्त तो हैं ही, बड़े शांतचित्त होकर खड़े हुए तो लोगों ने कहा उत्तर देना, कि हां उत्तर देना, मंत्री थे, उस समय शांती धारीवाल मंत्री थे, उस समय भी यही विभाग थे, गृह मंत्री और स्वायत्त शासन, लूटने के लिए, नजूल सम्पत्ति एण्ड कम्पनी और दिलावर विधायक थे, मैं भी विधायक था। अब धारीवाल साहब ने जो जवाब दिया, वह सारे कांग्रेस के विधायक भी सुनिये; माननीय भंवरलालजी मेघवाल साहब, सुनिये; उन्होंने जवाब दिया कि भाई, देखो, ऐसा है, जो दिलावर आरोप लगा रहा है, आरोप में आधी सत्यता है, आधा झूठ है; बोले, क्या है; बोले, लड़की को लेकर मैं नहीं भागा था, यह धारीवाल साहब का जवाब था, लड़की को लेकर मैं नहीं भागा था, लड़की मेरे को लेकर भागी थी। यह रिकार्ड में है। अब बताइये आप, यह चरित्र की बातें करते हैं आप लोग।

आप बातें करते हैं रोजगार की, कई सारी बजट में बातें कहूं मैं और शिक्षा की, वे सारी बातें आ चुकीं, और भी मैं बोलता, लेकिन अब चूंकि सभापति महोदय का अनुशासन मानूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त, कभी हमारे प्रताप सिंहजी खाचरियावास साहब राजीवजी, सोनियाजी और इंदिराजी के बारे में क्या बोलते थे, अब अचानक बोल गये, अटलजी की बात बोल गये, अटलजी तो हमारे भावुक, कवि हृदय, साहित्यकार उन्होंने बोला। समय की बात थी, उन्होंने देश की अखंडता के लिए काम किया, बांग्लादेश को मुक्त कराया, पाकिस्तान के टुकड़े करवाये। उन्होंने बोल दिया उसको।

लेकिन इंदिराजी के समय नागर वाला काण्ड किसने किया? आप यह बताइए कि राजीवजी के समय बोफोर्स काण्ड कैसे हुआ? इतना ही कहूंगा, मैं आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं, बीच में न बोलें आप लोग, जवाब न दें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): रामप्रसाद बिस्मिल एक शहीद हुए हैं, सुनिए, जाड़ावत साहब।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जब आरोप लगा रहे हो तो फिर बताओ बोफोर्स काण्ड का अंत क्या हुआ? पांच साल तक आपकी सरकार रही केन्द्र में, क्या कर पाई वह? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपका समय हो गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) बावन साल राज किया राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) कभी इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हो, कभी जवाहर लाल नेहरू का, उन्होंने देश बनाया है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री सभापति: मैं नाम बोल रहा हूं आगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह जो विकास की बातें करते हैं, आंकड़ों सहित बहुत डैटा है। मेरे यहां चार थाने हैं और आपको भी पता है, आपके यहां भी पूरी नफरी नहीं है, चार थानों में 30 प्रतिशत स्टाफ कम है; स्कूलों में 32 प्रतिशत स्टाफ कम है और चिकित्सालयों में 40 प्रतिशत ए एन एम, डाक्टर, नर्स कम है। इसी प्रकार से बिजली के ट्रांसफार्मर दो-दो महीने में मिलते हैं, सामान है नहीं, कनेक्शन मिलते नहीं और 30 सड़कों की हालत खराब है। यह मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह रहा हूं। 52 में से 30 पंचायतों में 148 गांवों में पानी की भारी समस्या है। रजिस्टर्ड शराब की दुकानें मेरे यहां चार हैं लेकिन दुकानें 92 खुली हुई हैं। कोई सरकार की पकड़ नहीं है। गांवों में रात को 11-11 बजे तक शराब बिकती है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। चर्चा समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आधा मिनट है। तहसील में 12 प्रतिशत स्टाफ कम है, एस डी एम में 15 प्रतिशत और बी डी ओ एक साल से है नहीं।

अंत में एक शेर से अपनी बात खतम करूंगा। इकबाल एक शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा- 'इकबाल तेरे इश्क ने, इकबाल तेरे इश्क ने सब खंभ दिए निकाल, टेढ़ापन, बाकांपन। इकबाल तेरे इश्क ने सब खंभ दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई।' आपका जो टेढ़ापन बांकापन है, जनता सीधा कर देगी। माननीय वसुंधराजी आई, सिंहासन खाली करो कि वसुंधराजी आती

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

है; सिंहासन खाली करो कि जनता आती है; सिंहासन खाली करो, आप उधर आते हैं और आप भाग जाते हैं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो आ रहे हो ना वापस? आप आते हो तो शुभ हो हमारे लिए।

श्री सभापति: आप कृपया शांत रहें, कान्ता जी, शुरू करें आप।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): सभापति महोदय, 27 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय का सदन में अभिभाषण हुआ और महामहिम के इस अभिभाषण द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तस्वीर इस सदन में प्रस्तुत हुई, जिसका मैं स्वागत करती हूं। आज तीसरा दिन है, बहस चल रही है और दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य ने बढ़ चढ़कर के इस बहस में भाग लिया, अपनी-अपनी बात को अपने-अपने ढंग से यहां पर रखा और मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना। सभापति महोदय, सभी ने इस अभिभाषण के एक-एक शब्द को बारीकी से पढ़ा और हमारे माननीय विपक्ष के सभी सदस्य ने कहा कि हमने इस अभिभाषण को तीन-तीन बार पढ़ा लेकिन तीन-तीन बार पढ़ने के बाद भी इसके अन्दर जन कल्याणकारी योजनाओं का एक भी ठोस तर्क तलाश नहीं पाये। सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्यों की बहस में दो ही बातों पर उनकी बहस केन्द्रित रही, एक तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन और दूसरा था गोपालगढ़ काण्ड की घटना। हम भी मानते हैं कि मेहमान नवाजी हमारी सांस्कृतिक परम्परा है। लेकिन जो विपक्ष के लोग गरीब की बात करते हैं, उस गरीब की चिंता किसे हैं? उस गरीब की पीड़ा का अहसास किसे हैं? मैं विपक्ष से कहना चाहूंगी कि गरीब का नाम लेकर के मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। आपकी पूंजीवादी विचाराधारा छिपाये नहीं छुपेगी। क्योंकि इस अभिभाषण में आम आदमी से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हुआ, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए थी, यदि आप गरीब के हितैषी हैं। बार-बार गोपालगढ़ काण्ड के गीत गाने से पूर्ववर्ती सरकार के गुनाहों पर पर्दा आप नहीं डाल सकते। सभापति महोदय, चूंकि जनता सब जानती है, सिर्फ वक्त का इंतजार करती है और वक्त आने पर आपको जवाब भी दे देगी।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस अभिभाषण की मात्र आलोचना नहीं करें, समालोचना करें

(श्रीमती कान्ता भील)

जैसे कि वरिष्ठ माननीय सदस्य, फतेहसिंहजी ने की है। इस अभिभाषण की सराहना करें, इन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करें। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है। राजस्थान विधान सभा चुनाव 2008 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने पर हम राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। हमने न केवल वादा किया बल्कि वादों के साथ जन-आकांक्षाओं पर हम खरे भी उतरे हैं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने दो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं लागू कर क्रियान्वित की हैं जिनका सीधा-सीधा लाभ आम आदमी को मिला है। अभी सभी मजाक उड़ा रहे थे उन जन कल्याणकारी योजनाओं की, जिनका उस गरीब से वास्ता है। नि:शुल्क दवा वितरण योजना हमारी सरकार ने लागू की है। इस योजना से पहले उस गरीब की हालत किसी ने देखी? डाक्टर की पर्ची लेकर दवा की दुकान पर जाता था और सबसे पहले उस दुकानदार से उस दवाई की कीमत पूछता था और अपनी जेब में पैसा टटोलता था। डाक्टर ने दस दिन की दवाई लिखी, वह दो दिन की दवाई लेकर घर आता था। बीमारी दो दिन की दवाई लेने से दब जाती थी। फिर कुछ दिनों बाद वापस गम्भीर रूप से बीमार होता था, मां और पत्नी के गले-शरीर से जेवर उतार करके गिरवी और बेचे जाते थे। आज वह मरीज, वह गरीब व्यक्ति उस अस्पताल से पूरी दवाई लेकर के आता है, अपना इलाज कराता है।

सभापति महोदय, जननी शिशु सुरक्षा की बात को लेकर के बार-बार यहां पर मखौल उड़ाया गया, केन्द्र की योजना है। केन्द्र में भी हमारी सरकार है, उसने यह कार्यक्रम लागू किया है। जब गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से कराहती है एक तरफ और दूसरी तरफ उसका गरीब परिवार आस-पड़ोस से पैसे के जुगाड़ में रहता है। समय पर उसके पास में पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है, समय पर उस महिला को इलाज नहीं मिल पाता है। किसी की रास्ते में डिलिवरी हो जाती है। चिकित्सा के अभाव में कई सारी बहनों की अकाल मृत्यु हो गई।

सभापति महोदय, इन महत्वपूर्ण योजनाओं का हमारे विपक्षी भाइयों को स्वागत करना चाहिए। विपक्षी बात करते हैं, मुख्य मंत्री आवास को लेकर के मजाक उड़ाते हैं। मैं उन विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि कभी कच्ची झोंपड़ी में झांक करके देखा? उस समय बरसात की ऋतु में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हम तो सब महलों से आये हैं? महलों में पैदा हुए हैं?

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): सम्माननीय कटारिया साहब, आपकी बात को मैं बहुत गम्भीरता से सुनती हूं। क्षमा करें, अगर ये बात, मेरी बात का जवाब देना है तो आप अलग से जवाब दें इसका। सभापति महोदय, उस गरीब की झोंपड़ी की बरसात में क्या हालत होती है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप महलों से नहीं आये पर महलों वाली के राज में रहे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अभी भी आपको लगता हो न, तो मेरे घर से आटा-साटा कर लो। अगर आपको अभी भी यह लगता हो तो आटा-साटा कर लो।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि आप महलों से नहीं आये, मुझे भी पता है, मैं भी आपके घर आया हूं पर महलों में रहने वालों के नीचे राज में आये हो। इसलिए कह रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया, आप दोनों बीच में क्यों आ रहे हैं? आप शुरू करें।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): सभापति महोदय, बरसात के दिनों में उस झोंपड़ी में जाकर के देखा? जब उसकी दीवार गीली हो जाती है, दीवार में सीलन आती है और उसका फटा-टूटा बिस्तर, उसमें भी सीलन आती है, किस तरीके से वह परिवार अपना गुजारा कर रहा होगा वहां पर? हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने उस गरीब को आवास दिया है। मैं धन्यवाद देती हूं अशोक जी गहलोत को जिन्होंने हमारे बांसवाड़ा ज़िले में इस वर्ष पच्चीस हजार आवास स्वीकृत किये और मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच हजार आवास स्वीकृत किये जो आज शुरू कर दिये लोगों ने।

सभापति महोदय, हमारी सरकार की पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किये जाते हैं। पहले उस मजदूर की मजदूरी का जब भुगतान होता था तो भुगतान करने वाले लोग आधा भुगतान करते और आधा भुगतान ले जाया करते थे। अब उन मजदूरों के खाते खोले गये और खाते में सीधे उसका पेमेंट जमा होता है, जो सीधे-सीधे उसके पास में पूरा-पूरा जाता है। यह पारदर्शिता नहीं है?

(श्रीमती कान्ता भील)

हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता सप्ताह सुनिश्चित किया है जिसके तहत इस सप्ताह के अन्दर हर उपभोक्ता उस दुकान पर जाकर के राशन की सामग्री लेता है। इससे पहले महीने में एक-दो दिन कब खोली जाती थी दुकान, पता नहीं। नाम मात्र की खोली जाती थी और कहा जाता था कि वितरण हो गया, सामान खतम हो गया, अगले महीने आना। लोग भटकते थे। लेकिन आज जब समय पर दुकान नहीं खुलती है तो उपभोक्ता शिकायत करता है कि दुकान नहीं खुली और उसका जितना भी सामान आता है, उसका हिसाब-किताब रखा जाता है। यह भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है तो क्या है? आज कालाबाजारी पर अंकुश लगा है।

सभापति महोदय, मैं यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी, जो काश्तकार की हिमायत करते हैं, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की और मैं धन्यवाद देती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में करोड़ों रुपया काश्तकारों के खाते में जमा हुआ बीमा राशि का। उस काश्तकार को जब ज्यादा बरसात होती है उसकी फसल खराब होती है; कम बरसात होती है, उसकी फसल खराब होती है और तो और, वह उसका खाद-बीज तक उसके खेत से उपजा नहीं सकता है। उस काश्तकार को फसल बीमा मिला है।

सभापति महोदय, मैं यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि आप सभी और हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अच्छे सुझाव देंगे तो निश्चित हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी उस सोच का सम्मान करेंगे, आपके सुझावों का सम्मान करेंगे। कुछ कमियां रह सकती हैं लेकिन उन कमियों को सुधारने में आपके अच्छे सुझाव होंगे तो निश्चित ही उन कल्याणकारी योजनाओं का आम व्यक्ति को लाभ मिल सकेगा।

मैं आज के इस अवसर पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, इसका मैं पुरज़ोर शब्दों में स्वागत करती हूं, समर्थन करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओटारामजी देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सभापति महोदयजी, राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान की 13वीं विधान सभा के आठवें सत्र में दिये गये अभिभाषण द्वारा उपलब्ध कराये गये असत्य आंकड़ों का पुलिन्दा कहते हुए मुझे कोई

(श्री ओटाराम देवासी)

सरोकार नहीं है। जिस तरह से आपने इसमें पैरा नं. 11 में दिया हुआ है मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से मेरे पूरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में नि:शुल्क दवा योजना है, करीब दो महीने पहले विधान सभा क्षेत्र रेवदर के एक गरीब परिवार को कुत्ते ने काटा। रेबीज के इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो जिला हैडक्वार्टर होते हुए भी वह परिवार वहां रेवदर से रवाना होकर सिरोही आया और सिरोही आते ही वहां के सी एम एच ओ ने कहा कि हमारे पास में रेबीज के इंजेक्शन नहीं हैं। जब ये बात मेरे को पता चली तो मैं उसी समय हास्पिटल पहुंचा और कलक्टर साहब से बात की तो कलक्टर साहब ने वे रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करवाये।

मैं आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस तरह से सरकार कह रही है, जननी सुरक्षा योजना...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बातचीत न करें। कृपया व्यवधान न करें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ... जिस तरह से डाक्टरों की

अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी और 23 दिसम्बर, 2011 को उसे सार्वजनिक अस्पताल सिरोही में लाया गया। सिरोही में डाक्टर हड़ताल पर थे, उसे उदयपुर रेफर किया गया। प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण उस प्रसूता की 23 दिसम्बर, 2011 को प्रात: चार बजे उसकी मृत्यु हो गई। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने जननी सुरक्षा योजना लागू की और उसमें अगर प्रसूताओं की मौत होती है तो उसके लिये क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है?

इसी माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यलय है और मुख्यलय पर सार्वजनिक अस्पताल की बात करें तो वरिष्ठ विशेषज्ञ 6 में से 3 पद रिक्त है। जिसमें शिशु रोग, हड्डी रोग, मेडिसिन के पद रिक्त है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के 15 में से 10 पद रिक्त है। रेडियोलोजिस्ट, स्कीन, पैथोलोजिक, अस्थि, नेत्र, गायनिक, मनोरोग व शिशु रोग के पद रिक्त है। चिकित्सा अधिकारियों के 12 में से 6 पद खाली चल रहे हैं। हमारा सिरोही क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं लाई जैसे निशुल्क दवा योजना, जालौर और सिरोही से दिन के कम से कम 250 गाडियां गुजरात जाती है इलाज के लिये।

(श्री ओटाराम देवासी)

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं जिस सरकार के शासन में बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं और बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये जाते हैं, वहां जब हास्पिटल में जाते हैं, हास्पिटल का निरीक्षण करते हैं तो डाक्टर लोग कहते हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जब मेडिसिन की बात आती है मै आपको बताना चाहता हूं कल ही चिकित्सा मंत्रीजी ने मुझे पूरी लिस्ट दी कि आपके यहां पूरी पीएचसी भर दी है। सिरोही में पैथोलोजी के अभाव में ब्लड बैंक की जो सुविधा है वह आम जन को नहीं मिल रही क्योंकि ब्लड बैंक बंद होने के कगार पर है। शिवगंज विधान सभा क्षेत्र में पांच डाक्टरों के पद खाली हैं, पालडीएम में एक, कालंदरी में तीन। जिले में 6 में से 5 सीएचसी हैं जहां तीन तीन डाक्टर लगाये गये हैं जबकि सबसे पुरानी तहसील है पर मात्र एक ही डाक्टर लगाया गया। जिला हैड क्वार्टर होते हुए यह बहुत बडी दिक्क्त है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जिला मुख्यलय पर नव निर्मित ट्रौमा सेंटर की बात करूं, ट्रौमा सेंटर का भवन बन कर तैयार हो गया पर आज दिन तक न तो इसमें संसाधन उपलब्ध हुए, न डाक्टरों की नियुक्ति हुई। सिरोही जिले में नेशनल हाई वे 14 पर बारीघाटा, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, राजमार्गों पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। समय पर सुविधा नहीं मिलने के कारण हजारों की जान जा रही है। ट्रौमा सेंटर के अभाव में उनको या तो आबू रोड या गुजरात लेकर जाना पडता है। आज पूरे सिरोही जिले में डाक्टरों की कमी है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्हें तुरन्त भरा जाये ताकि आने वाले समय में लोगों को सुविधा मिल सके।

पूर्ववर्ती सरकार में माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने पशुपालकों के लिये जो योजना बनाई, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं, पशुपालकों के लिये पशुपालन बोर्ड का गठन किया। उसके अन्तर्गत पशुपालक बीमा योजना, पशुपालकों को नि:शुल्क पट्टा, सुरक्षा की दृष्टि से जो माइग्रेशन करते हैं उनको शस्त्र देने की योजना, पशु धन बीमा योजना लागू की। वर्तमान सरकार ने उन सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे क्षेत्र में कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। कुम्भलगढ़ के आस पास हजारों पशुपालक निवास करते हैं और उन पशुपालकों की जो दशा है,

(श्री ओटाराम देवासी)

आने वाले समय में जिस तरह से रानीवाड़ा से हमारे भाई रतनजी देवासी त कर आये हैं, वहां भी सुन्ना माताजी का जो पर्वत है उसको भी भालू के नाम से रिजर्व किया जा रहा है। पशुपालकों के लिये चराई की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुम्भलगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पशु पालकों को दृष्टिगत रखते हुए और वहां के सभी ग्रामीणों को दृष्टिगत रखते हुए कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कैंसिल किया जाये। यह हम सब की भावना है और हम सब इस बात को आपके बीच में रखना चाह रहे थे।

आज जितने भी पशुपालक यहां से माइग्रेशन करते हैं, हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, माइग्रेशन की जो व्यवस्था है, उसमें भी मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें इस तरह का एक पास बना कर दिया जाये ताकि जहां भी जाये, पशुपालन विभाग एक पास जारी करे ताकि गुजरात जाये, हरियाणा में जाये या मध्य प्रदेश में जाये, उनके लिये अच्छी व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी नर्मदा का पानी जालौर जिले में लेकर आईं। उसमें हमारे सिरोही जिले के 100 गांवों को भी पानी देने की योजना बनी थी कि सिरोही जिले के 100 गांवों को पानी दिया जायेगा। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी राजे को, उनके लिए यह कहना चाहता हूं कि ''काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन बन जाए, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि निशान बन जाए।'' आज जिस तरह से पेयजल की जो समस्या है, नर्मदा की योजना जालौर जिले के लिए बनी, सभापति महोदय,

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से सिरोही विधान सभा क्षेत्र में 100 गांवों को जोड़ने की योजना है, उनको भी जोड़ा जाए और जोड़कर के वहां सिरोही की जनता को भी नर्मदा का पानी दिया जाए, यही मेरी भावना है।

जिस तरह से पहले सिरोही विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक है, जिसका दुष्परिणाम लोगों के जोड़ों में बढ़ता दर्द व कमर से झुकने की स्थिति के रूप में सामने आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा सिरोही विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइड-रहित पानी पीने की कोई योजना नहीं करने के कारण आज भी आम जनता फ्लोराइड-युक्त पानी पीने को मजबूर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): अभी तो मुझे दस मिनट ही नहीं हुए।

श्री सभापति: 17 मिनिट हो गए।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): 17 मिनट ही हुए हैं ना।

श्री सभापति: आपके नेता ने ही...

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): विभाग द्वारा तखमीना अनुमानित 825 करोड़ की लागत से गोड़ाना-दुर्बाना पेयजल योजना तैयार की गई थी, राज्य सरकार को भिजवाई गई थी और पूर्ववर्ती सरकार ने यह योजना बनाई थी। इस सरकार ने इसको भी ठण्डे बस्ते में डाल दिया और आज तक जो पांच गांवों की योजना थी, वह जनता के सामने नहीं आई। सभापति महोदयजी। अब मैं आपको शिक्षा व्यवस्था के बारे में, सरकार ने लोगों को शिक्षा का अधिकार तो दिया, नियम बनाकर बता दिये लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बिना यह अधिकार किस काम का? आज जिस तरीके से हर स्कूल में शिक्षक नहीं है, यह बहुत बड़ी तकलीफ है। सभी चाहते हैं, देश-प्रदेश आगे बढ़े लेकिन इसकी पहली सीढ़ी पर तो सरकार गम्भीर नहीं है, नहीं तो जो भर्ती अब तीन साल के बाद निकाली, यह पहले निकलती। निकाली तो प्रदेश की जनता को सरकार ने ताश में लड्डू दिखाते हुए जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती निकाली। इसमें भी सोची-समझी साजिश थी कि आरटैट के उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को लेकर, दो में आवेदन नहीं करने का ऐसा किया प्रदेश में लाखों डिग्रीधारी बेरोजगारों का भविष्य अंधकारमय कर देगी। साथ ही, पूरी भर्ती प्रक्रिया न्यायिक रूप से नहीं होने के कारण बाधित होगी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): किसानों के लिए, किसानों की बात करें तो सिरोही जिले में पाले की प्राकृतिक आपदा से किसानों को 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। जो फसलों का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार केवल मौसम आधारित बीमा के तहत फसल का बीमा कराये जाने वाले किसानों को मुआवजा न देकर, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित समस्त किसानों को उनकी फसलों, सब्जियों व फलों आदि का बाजार भाव के अनुसार, आज सिरोही जिले में सबसे ज्यादा अरंडी और टमाटर की खेती होती है, उसका बहुत बड़ा मुआवजा देकर राहत प्रदान करें।

(श्री ओटाराम देवासी)

सभापति महोदय, आज इसी तरह से कृषि निदेशालय, जयपुर के आदेश दिनांक 3.8.2011 के तहत महको मैनेजमेंट कार्य योजना आइसोपाप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत किसानों को कृषि यंत्र अनुदान की पत्रावली स्वीकार करने के संबंध में रोक लगाई गयी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, वरना मैं अगला नाम बोलने वाला हूं।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): पांच मिनट।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं, एक मिनट और ले लीजिए, बस।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): किसानों के हितों के विरुद्ध, मैं तो मेरी विधान सभा में ही पहली बार बोल रहा हूं और आप दबा रहे हो।

श्री सभापति: इस हिसाब से तो 12 बजे तक चलेगी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): चलेगी तो चलेगी।

श्री सभापति: आपका टाइम हो गया, सबको टाइम मिलना चाहिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): किसानों के हितों के विरुद्ध है। जिला स्तर पर कृषि यंत्र अनुदान, पत्रावलियों के जमा कराने पर वरीयतानुसार अनुदान देने की मांग करता हूं। सिरोही जिले में वर्ष 2001-02 में भू-प्रबंधन विभाग, जोधपुर द्वारा की गई सेटलमेंट की कार्यवाही में किसानों को कृषि भूमि का नवीन सेटलमेंट किया गया जिसमें संबंधित किसानों की जानकारी में दिये बिना ही भूमि का तरमीम कार्य किया गया जिसमें बड़े पैमाने पर भारी त्रुटि हुई जिसके कारण 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज काश्तकार जो अपनी खातेदारी भूमि में कब्जे काश्त करते आ रहे हैं। उनकी जमीन वहां से गलत सेटलमेंट के कारण से कहीं और अन्य जगह और अन्य दूसरे किसान के कब्जे में बोल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह आपके क्षेत्र की समस्या है और इसे आप बाद में भी दे सकते हैं। अभी तो अभिभाषण पर बोलना है आपको । हो गया।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): किसानों ने लाखों रुपये खर्च करके कुएं खोदे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने निश्चित स्थान पर पधारें। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): जिस तरह से खातेदारी भूमि में काश्त करें, उनकी जमीन वहां से गलत सेटलमेंट की वजह से कहीं और अन्य जगह हो गई। किसानों ने लाखों रुपये खर्च करके कुएं खोदे, भूमि को समतल करके खेती करने लायक बनाई, उस पर बिजली कनेक्शन लिया, सरकारी योजनाओं से ऋण लिया पर गलत सेटलमेंट के कारण यह किसानों में आपसी तनाव की स्थिति का कारण यह बनता जा रहा है। सरकार के तीन साल से मामला ध्यान में लाया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अतः इस प्रकार की गलती को सुधारते हुए लघु सेटलमेंट करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मेरे क्षेत्र में बिजली की समस्या मेन है। पहले 8 घंटे मिल रही थी अब तो 4 घंटे ही मिल रही है। यह बहुत बड़ी तकलीफ है। बिजली विभाग की लगातार हो रही कटौती से क्षेत्र में लोगों का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थी, व्यापारी, किसान वर्ग, सभी बिजली कटौती के कारण भविष्य के प्रति चिंतित है। बिजली कटौती के कारण पेयजल की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदले जा रहे हैं, नये कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, न ही विद्युत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उपभोक्ता के विद्युत मीटर खराब तथा बंद पड़े हैं, जबकि मीटर रीडर के द्वारा मीटर रीडिंग लेते समय... (व्यवधान) बदलने का प्रावधान है।

श्री सभापति: श्री अमराराम।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सेनापतिजी, सभापतिजी (व्यवधान) मैं आपको सेनापति तो सेना के लिए कह रहा हूं, इसलिए सेनापति कह रहा हूं, मैं तो आपको सभापति कहता हूं, मैं आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी का 22 फरवरी को पाली, जालौर और सिरोही, तीन जिलों का दौरा था। उसमें पाली जिले वालों ने प्रदूषण के लिये एक बहुत बड़ी समस्या रखी थी। मुख्य मंत्रीजी ने इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद में जालौर में किसानों ने बहुत बड़ी समस्या रखी कि हमारी फसलों को नुकसान हुआ है। उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद में सिरोही में किसानों ने फसलों के नुकसान के बारे में बात करनी चाही। मैं तो यह बात कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी वाकई में गांधीवादी हैं और जिस तरह से गांधीवादी हैं, गांधीजी ने भी तीन बातें कही थीं कि राजस्थान में जो भी देख रहे हो, आंखें बंद कर लो, कान

(श्री ओटाराम देवासी)

से सुनना बंद कर दो और तीसरा था, मुंह से बोलना बंद कर दो। इस तरह से मुख्य मंत्रीजी को मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपकी तरफ से मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबको जय हिन्द, जय भारत माता की।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है और उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए, राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार का, मिलीजुली सरकार का चौथा अभिभाषण है, मैं समझता हूं इस अभिभाषण में असत्य और थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ भी इसके अन्दर नहीं है। सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण, निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार को राजस्थान की जनता ने परास्त किया लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार करके, जिस तरह से ब.स.पा. के विधायकों को राजनीतिक प्रलोभन देकर के, निर्दलीयों को प्रलोभन देकर के, सरकार के मंत्रिमण्डल में 40 प्रतिशत वे मंत्री हैं जो कांग्रेस को परास्त करके आये हैं। राजस्थान में यह राजनीतिक भ्रष्टाचार का रिकार्ड जो इस सरकार ने बनाया है, शायद सन् 1952 से लेकर आज तक 13 विधान सभाओं में पहले कोई रिकार्ड नहीं है। 13 संसदीय सचिव, क्योंकि संविधान में यह प्रोविजन कर दिया कि 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से 13 संसदीय सचिव बनाकर के राजनीतिक भ्रष्टाचार का रिकार्ड कोई कायम किया है तो इस सरकार ने कायम किया है। मैं समझता हूं, इससे पहले भी यही स्थिति 1993 में आई थी, उन्होंने यही राजनीतिक भ्रष्टाचार का काम किया था और जब पांच साल बाद जनता के बीच में गये तो मात्र 33 बचे थे।

(18.44 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप उस तरफ बताओ ना, हमें क्यों बता रहे हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसमें आप भी हो। आप भी उस राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रोडक्ट हो।

(श्री अमराराम)

इसलिये मैं समझता हूं, जहां इस अभिभाषण में कहलवाया गया, महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से कि यह राजस्थान की मिलीजुली सरकार, जो शुद्ध-के-लिये-युद्ध की बात करती है, खुद अशुद्ध है; वह इनसे कहलवाया गया कि सरकार गांव, गरीब और किसान के लिये प्रयासरत है, मैं समझता हूं कि गांव के प्रतिनिधि, पिछले विधान सभा सत्र में, अपनी सभी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को छोड़कर, जो गांव के चुने हुए सरपंच 9,178, जितने थे, उनमें से 90 प्रतिशत सरपंच, महिला सरपंच जब अपने गांव के विकास में जो बाधाएं इस सरकार ने आते ही खड़ी की थीं, उनकी समस्याएं लेकर के तमाम राजस्थान के 90 प्रतिशत सरपंच इस राजस्थान की सरकार के सामने, विधान सभा के सामने आये, तो गांव की बात करने वाली सरकार ने उन सरपंचों के साथ जो व्यवहार किया, उनका स्वागत लाठियों से किया, उनका पानी की बौछारों से स्वागत किया। सभापति महोदय, जब हम स्टेच्यू सर्किल पर गये तो उन महिलाओं की चप्पलें, उन सरपंचों के रूमाल दर्जनों वहां पर धाराशायी थे। न केवल लाठियों से किया, आधी रात को ढाई बजे जाकर इस राजस्थान सरकार के आदेश से उन सरपंचों को, सोए हुए सरपंचों पर निर्मम लाठी-चार्ज करके जिस तरह से पुलिस थानों में ले जाकर बंद करने का रिकार्ड, शायद पहली बार उन ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ जो व्यवहार राजस्थान की सरकार ने करके रिकार्ड कायम किया है, मैं समझता हूं, उससे पहले कभी नहीं हुआ है।

गांव के साथ विकास, गांव के विकास में जो, नरेगा में न केवल विकास होता था, बल्कि गांव का वह गरीब, और उनमें भी 80 प्रतिशत महिलाएं, जो नरेगा में काम करती थीं उनको रोजगार मिलता था, आय होती थी और उनमें 80 प्रतिशत एस.सी. और एस.टी. की महिलाएं थीं। मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो 07-08 में पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जब लागू किया गया था, मैं समझता हूं, जितने लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया गया था, उनके बनिस्बत इस साल 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं मिला है। जिस तरह के निर्देश, राजस्थान की सरकार ने इस गांव के विकास को रोकने का काम इस सरकार के आने के बाद, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की मुख्य मंत्री ने तो कह दिया कि इसमें भ्रष्टाचार है इसलिये नरेगा को बंद कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कौन से विभाग में नहीं है? वर्तमान सरकार ने घोषणा तो नहीं की, लेकिन नियम और नीति इस तरह से बना दिये कि जिससे गांव का विकास, उस गरीब का विकास, उस गरीब के घर में

(श्री अमराराम)

जो नरेगा के माध्यम से जो राशि जाती थी, उसको रोकने का काम, मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ा अपराध राजस्थान की सरकार ने किया है। जिन्होंने इनको वोट देकर के यहां भेजने का काम किया है, उस नरेगा में राजस्थान में जितने लोगों को काम मिलता था, उसमें 90 प्रतिशत काम ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलता था। मात्र 10 प्रतिशत, जो विभाग कोई भी जो कमीशन पर लगे हुए हैं, वे विभाग काम देते थे मात्र। 90 प्रतिशत काम ग्रामीण विकास में पंचायती राज देता था, उसको समाप्त करने का काम किया है। मैं समझता हूं, इससे बड़ी कोई किसान की जहां बात करें, उसको, गांव के गरीब को तबाह करने का काम किया। गांव के विकास को अवरुद्ध करने के काम में इस सरकार ने रिकार्ड बनाने का काम किया है।

किसान की तो बात छोड़िये, उस किसान का जब 48 लाख मीट्रिक टन बाजरा इस खरीफ की फसल में 2011 में हुआ, सरकार ने घोषणा भी की समर्थन मूल्य पर खरीद की, लेकिन अफसोस, इस सरकार की जहां राजस्थान की जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़कर दिल्ली तक जोड़ी, उस किसान की कड़ी तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। सभापति महोदय, बाजरे की खरीद का समर्थन मूल्य देश की सरकार ने 980 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया? लेकिन 13 दिनों में घोषणा करने के बाद, मैं समझता हूं, हमारे जिलों में, नागौर हो, सीकर हो, एक किलो बाजरा भी सरकार ने केवल मापदण्ड का बहाना करके राजस्थान के किसान को खरबों रुपये का नुकसान पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। आज यह सरकार यह नहीं कह सकती कि दिल्ली की सरकार हमारी नहीं मानती है। बहुत से जो किसान माननीय सदस्य हैं, मैं नहीं समझता कि राजस्थान में या राजस्थान के अलावा भारत में या दुनिया में कहीं सफेद बाजरा पैदा होता है। इस सरकार में बैठे हुए लोगों को इतना भी नहीं है कि आज से 25 साल पहले जो भी बाजरा निकलता था, वह पशुओं द्वारा गायका कर निकालते थे। लेकिन आज एक किलो बाजरा भी कोई पशु द्वारा गायका कर नहीं निकालता है, थ्रेशर से निकालते हैं। मापदण्ड में लिख दिया कि सौ दानों में से अगर तीन दाने भी फूट गये तो वह बाजरा खरीद के मापदण्ड में नहीं आएगा। इसलिये चाहे वह बाजरे की खरीद का सवाल हो, चाहे डी.ए.पी. में, आपने रिकार्ड बना दिया। मैं समझता हूं कि जो 485 की डी.ए.पी. है, पहली बार इस प्रदेश और देश के किसान को एक हजार रुपये में और वह भी ब्लैक में।

(श्री अमराराम)

मैं समझता हूं कि इस तरह से किसानों को बदश्हाल करने का काम और पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे भाई, अभी कह रहे थे कि यह किसान तो नाटक कर रहा है, अफसोस है, इस देश की सरकार ने, कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इस देश के अन्दर जब से उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां लागू की हैं, इस देश का अन्नदाता पिछले 13 साल में, 2 लाख 56 हजार किसान कर्जे में दब कर आत्महत्या कर चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, आज भी 24 घंटे के अन्दर 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिर भी अगर सरकार दावा करती है कि उस गरीब के लिए, किसान के लिए हम सरकार चला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

इस सरकार के रहते हुए ही मैं समझता हूं कि महंगाई की दर दो डिजिट में रही है। आप पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वह तो नहीं मिला लेकिन उन जमाखोरों को लूटने का खुला निमंत्रण जो सरकार ने दिया है? मैं समझता हूं कि ऐसा रिकार्ड न किसी पूर्ववर्ती सरकार के समय में रहा है। महंगाई से लूटने का सवाल हो, बीज के नाम से लूटने का सवाल हो, खाद के नाम से लूटने का सवाल हो, मैं समझता हूं कि सरकार की प्राथमिकता गांव और गरीब नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अगर गांव और गरीब होती तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के बीस हजार गांव आज भी शुद्ध पेयजल के लिए तरसते हैं, आज भी बीस हजार गांवों में या तो फ्लोराइड का पानी पीते हैं या खरीद कर पानी पीते हैं। उनके लिए पैसा नहीं है राजस्थान की सरकार के पास लेकिन राजस्थान की राजधानी में मेट्रो चलाने के लिए 17 हजार करोड़ रुपया होगा। राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता में राजस्थान के गांव का गरीब नहीं है, गांव का किसान नहीं है। आजादी के 64 साल के बाद अगर राजस्थान के बीस हजार गांव प्यासे मरते हैं तो इसके लिए गुनाहगार सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी है। उनकी प्राथमिकताओं में राजस्थान के किसान और गांव के गरीब नहीं हैं। न उसको पानी मिलेगा, न उसको भाव मिलेगा, न उसको समय पर खाद मिलेगा, न उसको बिजली मिलेगी।

बिजली में तो इन्होंने रिकार्ड बना दिया, बिजली नहीं देंगे। वह किसान, जो गांव की ढाणी में बैठा हुआ है, आदिवासी जो मजरे में बैठा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, आज से तीन साल पहले चाहे कोई भी सरकार रही,

(श्री अमराराम)

राजस्थान में ढाणी और मजरे में बसे हुए किसान को दस पोल भी लगते थे तो भी कनेक्शन मिलता था। यह सरकार आने के बाद उनका फार्म लेना भी बंद कर दिया और एक आदेश निकला है कि अब उनको सामान्य में नहीं मिलेगा क्योंकि वह खेत में बसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या वह गुजरात का किसान है, क्या वह पंजाब और हरियाणा का किसान है, क्या वह बांग्लादेश और पाकिस्तान का किसान है जो उसने गुनाह कर दिया? वह जमीन चीर कर, कलेजा चीर कर अन्न पैदा करता है, उसका बच्चा रोशनी में पढ़ सके, उसके लिए बिजली का कनेक्शन नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने आदेश निकाला है कि पांच किसान मिलकर ग्रुप में सेल्फ फाइनेंस में कनेक्शन लेंगे क्योंकि यह राजस्थान के किसान के साथ, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कृषि कनेक्शनों में लूटने का काम किया, कभी नर्सरी के नाम से, कभी स्पेशल के नाम से, कभी चन्द्रभान चोर योजना के नाम से, तो कभी फार्म हाउस के नाम से। पांच किसानों से लाख से सवा लाख रुपया लिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इससे भी खतरनाक, 100 रुपये पर, अभी हमारे ऊर्जा मंत्रीजी चले गये, 100 रुपये के स्टाम्प पर उस किसान से अंगूठा लगवाएंगे और शायद राजस्थान ही नहीं, देश में भी कहीं यह आदेश नहीं होगा, उन उपभोक्ताओं का अगर घरेलू कनेक्शन का ट्रांसफार्मर जलेगा तो उससे 45 हजार रुपये उन किसानों को भुगतना पड़ेगा; अगर चोरी हो गया तो उसका भी खामियाजा उन उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बाकी के ट्रांसफार्मर चोरी हो गये तो क्या सरकार उस ए.ईएन से लेने का काम करेगी? बिजली नहीं मिलेगी और इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं कि जिस तरह की रेट राजस्थान की सात करोड़ जनता से जो वादा करके, जो वोट लेकर आये हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो राजस्थान में जनता में जो बिजली की रेट बढ़ाकर जनता को लूटने का काम किया है, हम छूट देने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछली साल चार हजार करोड़ रुपये सालाना की वृद्धि कर दी। अभी फिर 90 पैसे का प्रस्ताव सरकार के निर्देश से विद्युत वितरण कम्पनियों ने आयोग के सामने भेजा है। माननीय सभापति महोदय, यही 1999 में यह ही सदन, इसी विधान सभा के फ्लोर पर राजस्थान विद्युत बोर्ड को खतम करके जब पांच कम्पनियां

(श्री अमराराम)

बनाकर निजीकरण किया गया था, यही मुख्य मंत्रीजी थे, हमारे अशोकजी गहलोत जिन्होंने कहा था कि यह पांच हजार करोड़ रुपये का घाटा समाप्त हो जाएगा, अन-ट्रिप्ड बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, मांगते ही कनेक्शन मिलेगा और आज कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, पांच हजार करोड़ का घाटा समाप्त नहीं हुआ; आज कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, चालीस हजार करोड़ का घाटा है। यह चालीस हजार करोड़ का घाटा राजस्थान की...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 53 हजार करोड़ है। 53 हो जाएगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, अब 53 हजार करोड़ हो गया। जो यह वादा करके कि यह पांच हजार करोड़ का घाटा समाप्त हो जाएगा, अब चालीस हजार करोड़, 53 हजार करोड़, यह घाटा किसने डाला है? राजस्थान के किसान और आम उपभोक्ताओं ने नहीं। उसने तो आपने जो भी बिल दिया, उसने उसको चुकाने का काम किया है। चाहे वह दुकान में हो, घर में हो, कुए में हो, कारखाने में हो, फैक्टरी में हो, जो भी आपने, कम्पनी ने बिल भेजा है वह बिल चुकाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, जिस दिन नहीं चुकाया, उसका आपने कनेक्शन काट दिया। फिर यह 53 हजार करोड़ का घाटा, अगर राजस्थान की सरकार में बैठे हुए मंत्री और अफसर घोटाला करके घाटा डालने का काम करें और राजस्थान की जनता उसको भरने का काम करे तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता न तो बरदाश्त करेगी और अगर फिर भी सरकार रेट बढ़ाकर उस जनता को लूटने का काम करेगी, वी.सी.आर. के नाम से लूटने का काम करेगी, एवरेज चार्ज के नाम से लूटने का काम करेगी, मीटर नहीं देकर मनमर्जी का बिल भेजकर लूटने का काम करेगी, तो मैं समझता हूं कि वह जंग होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान की सरकार, जिस तरह से दोनों ने मिलकर किसान को मारने का काम किया है, राजस्थान में खेती के अलावा किसान का दूसरा कोई आय का जरिए था तो वह पशुपालन था और पशुपालन में भी बछड़ा। मैं समझता हूं कि आज से 15-20 साल पहले एक बछड़ा सवा या डेढ़ साल का, वह नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का किसान जो नागौरी नस्ल की गाय पालता था, उसका और एक बछड़ा, सवा साल का, डेढ़ साल का बछड़ा, उसकी जितनी कीमत मिलती थी, उसमें दो से तीन तोला सोना आता था। उस बछड़े को मारने का काम, 1995 में इसी राजस्थान के इतिहास में उसको रोकने का

(श्री अमराराम)

कानून बनाने का काम किया। मैंने पूछा सवाल, माननीय सभापति महोदय, उस बछड़े को मारने का काम, उस कानून ने कर दिया, उस गाय को मारने का काम कर दिया, उस किसान को मारने का काम कर दिया। इसमें हजारों करोड़ रुपया हर साल राजस्थान के, मैंने सवाल पूछा, यह आपके सामने है, माननीय सभापति महोदय, हजारों करोड़; आज हालत यह है कि जब यह कानून लागू हुआ, परबतसर, मेड़ता, नागौर में दो-दो, ढाई-ढाई हजार बछड़े जिनसे एक बछड़े की कीमत से तीन तोला सोना आता था, उन बछड़ों को किसान से कोई लेने वाला नहीं था। इसलिए वे छोड़कर गये। आज वह बछड़ा भी मारा गया, गाय भी मारी गयी, किसान भी मारा गया। आज वह गाय दर-दर की ठोकरें खा रही है। आज वह आवारा गाय कोई बाहर से नहीं, कोई गुजरात से नहीं आयी, न पंजाब से आयी है, उसी किसान ने छोड़ दी जो इन्कम का एक स्रोत था। उसको तबाह करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वोट के लिए गाय का नाम लेकर, बछड़े का नाम लेकर वोट के लिए किया लेकिन जो किसान आस करता था कांग्रेस से, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उस किसान को मारने का काम किया, उस भारतीय जनता पार्टी को सरकार से 32 में लाने का काम किया, कांग्रेस को 156 दिया लेकिन पांच साल में किसान को जिंदा करने के लिए, कानून बनाने के लिए उस कानून में एक लाइन लिखनी थी कि इस बछड़े पर लगी हुई रोक के कानून को समाप्त करने का काम करेंगे लेकिन सरकार उत्तर दे रही है, माननीय सभापति महोदय, हम यदि... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, प्लीज। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य के लिए मैं घंटी बजाना भी उचित नहीं समझता हूं। 23 माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं तो वह कह रहा हूं जिससे हजारों करोड़, इस अभिभाषण में कहा गया है कि गांव, गरीब और किसान के लिए हम सरकार चला रहे हैं तो जिनसे आस थी, जिस कांग्रेस पार्टी से किसान आस करता था, उस आस के लिए 156 विधायकों को चुनकर भेजा लेकिन पांच साल में नहीं किया तो 156 में से 100 उड़ाने का काम उस राजस्थान के किसान ने किया। अभी उत्तर दिया है, माननीय सभापति महोदय, हमने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है और यह एक कमेटी, मैं समझता हूं, तीन साल में तो निर्णय नहीं कर पाई। आने वाले दो साल में भी निर्णय नहीं करेगी तो मैं समझता हूं, उस किसान को सिवाय इस बात से, एकजुट होकर इस

(श्री अमराराम)

सरकार से लोहा लेने की आवश्यकता है। अगर सरकार, जिसमें असल में एक पैसा नहीं लगे, सभापति महोदय, एक लाइन का प्रस्ताव, मैं समझता हूं, अगर पास कर देगी तो बछड़ा भी बच जायेगा, गाय भी बच जायेगी। न गौशाला बनाने की जरूरत है और किसान की जेब में करोड़ों रुपया आयेगा। लेकिन सरकार अगर उसके लिये कर पायेगी तो मैं समझता हूं कि फिर तो यह सरकार और अभिभाषण किसान के लिये है।

सभापति महोदय, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने बहुत लम्बी बात कह दी, मैं लम्बा नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार की बात में वे कर्नाटक भी चले गये, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, यह रिकार्ड, भ्रष्टाचार में रिकार्ड बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की यू पी ए सरकार ने किया है। एक लाख 76 करोड़, किसका मंत्री था, यू पी ए का मंत्री था। खेल के नाम से कांग्रेस का सांसद सुरेश कलमाड़ी, 50 हजार करोड़, और कोई शहीद का कफन खाता है तो कांग्रेस के हमारे संसदीय मंत्रीजी को महाराष्ट्र की वह आदर्श सोसायटी याद नहीं आती है, जिसमें 130 फ्लैट महाराष्ट्र के कारगिल के शहीदों की विधवाओं को देने के लिये बनाये गये थे, लेकिन अफसोस जब अलाटमेंट किये, 130 में से एक फ्लैट भी देने का काम नहीं किया है। चाहे वह खान आबंटन का सवाल हो। आज राजस्थान में, मैं समझता हूं, भ्रष्टाचार की जो आंधी आई हुई है, संवेदनशील, पारदर्शी, आज भी हमारी सरकार के दो मंत्रियों पर, डेयरी मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी पर जांच चल रही है। यह सरकार की पारदर्शिता है।

मेरा तो आपसे निवेदन है, सरकार में बैठे हुए लोग, जिस तरह से गोपालगढ़ का कांड हुआ, जिस तरह से पुलिस ने 10 लोगों को, याद दिलाता हूं गुजरात की घटना, नरेन्द्र मोदी को, आज इस देश का तमाम अल्पसंख्यक यह महसूस करता है कि हमें जिन्दा जलाने का काम नरेन्द्र मोदी ने किया है, वही आज राजस्थान में गोपालगढ़ में इस कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है। इन तीन सालों में 40 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। सराड़ा में लोगों को जिन्दा पुलिस की मौजूदगी में जलाया, उनके घर जलाये जायें, उनको दो-दो महीने तक अपने घर-बार से दूर रहना पड़े। आज मैं समझता हूं, सरकार अल्पसंख्यकों की बात

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(19.02 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री अमराराम)

करती है, गरीब की बात करती है, 2007 में रंगनाथ मिश्र आयोग, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आये चार साल हो गये, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, जिनका वोट 1952 से लेकर आज तक लेती आई है, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया। जो तुष्टिकरण के नाम से आरोप लगाते थे, आज उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर हो गयी है, लेकिन उनको सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बराबर लाने के लिये, जो रंगनाथ मिश्र आयोग ने उनको सबल बनाने के लिये, बराबर बनाने के लिये किया, उपाध्यक्ष महोदय, उनको आज तक राजस्थान की सरकार ने लागू नहीं किया है।

मेरा तो आपके माध्यम से यह निवेदन है, जो सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं एक ही नमूना देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह साधारण जनता का तो क्या हाल होगा...

श्री उपाध्यक्ष: आदेश फरमाइये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी कर्मचारी, एक शिक्षक, जिसका ढाई साल का वेतन है 3 लाख 28 हजार 384 रुपये जो 2009 में ब्लाक शिक्षा अधिकारी, दांतारामगढ़ ने पास कर दिया, इस ढाई साल का साढ़े तीन लाख रुपये उसकी तनख्वाह और बोनस का 2009 में पास कर दिया, बी ई ओ ने पास कर दिया, अकाउंटेंट ने पास कर दिया, लेकिन आज 2012 तक उसको पेमेंट इसलिये नहीं हुआ क्योंकि बी ई ओ साहब 10 प्रतिशत कमीशन मांग रहे हैं। 35 हजार रुपये देगा तब उसका पेमेन्ट होगा। अभी हमारे गृह राज्य मंत्रीजी और फतेह सिंहजी यह कह रहे थे कि आप सबूत दे दो। क्या सरकार में बैठे हुए मंत्रीजी, यहां हमारे शिक्षा मंत्रीजी जरूर विराज रहे हैं, हिम्मत है क्या? उस ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने, जिसने 2009 में साढ़े 3 लाख का पास करने के बाद में भी आज 2012 तक उसको पेमेन्ट नहीं किया और महज इसलिए नहीं किया कि उसको 10 प्रतिशत कमीशन नहीं दिया। क्या सरकार कह सकती है कि ऐसे भ्रष्ट बी ई ओ को, जिसने 2009 में पास करके नहीं दिया आज तक और बी ई ओ उससे 10 प्रतिशत मांग रहा है और आज की तारीख तक उसको पेमेन्ट नहीं हुआ? वह सरकारी कर्मचारी है, गांव के उस गरीब का क्या हाल होगा? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है, राजस्थान

(श्री अमराराम)

में जहां भी आप अगर नहीं बतायेंगे कि मैं रामनारायण मीणा, राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष हूं तो कोई भी जमीन की रजिस्ट्री बगैर दो और तीन प्रतिशत के नहीं होगी। केवल रामनारायण मीणा बतायेंगे तो राजस्थान के किसी भी रजिस्ट्रार आफिस में, तहसील के आफिस में बगैर दो या तीन प्रतिशत कमीशन के रजिस्ट्री नहीं होगी। आज यह हालात हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा व्यवसाय अस्पताल का व्यवसाय, शिक्षा का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय और हमारे मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर जनता के सामने कहते हैं कि राजधानी जयपुर में ऐसे निजी अस्पताल हैं, जो मरने के बाद भी डैड बाडी को दो दिन रखकर दो-दो लाख रुपये लूट रहे हैं। वेंटिलेटर पर रखकर दो-दो लाख रुपये लेते हैं। आज आप कहने वाले नहीं, आप काम करने वाले हैं, मुख्य मंत्रीजी। एक भी ऐसा अस्पताल, जिसकी सूचना इनके पास आई, लोगों ने जाकर शिकायत की, एक भी ऐसे निजी अस्पताल जो राजस्थान की जनता को लूट रहे हैं, उस पर ताला लगाते तब तो बात हमारी समझ में आती।

राजस्थान का मुख्य मंत्री कहता है, राजस्थान के थाने में जो भी चोरी होती है, उस चोर का थानेदार को पता है। बात समझ में आती, मुख्य मंत्रीजी, अगर पांच-दस ऐसे थानेदारों को लिफ़ाफ़ा पकड़ाकर घर भेज देते। ये आज कहने वाले नहीं, उनके हाथ में ताकत दी है। चाहे वह किसी भी येन-केन-प्रकारेण, किसी भी तरीके से उन्होंने पावर ली है, लेकिन आज करने की हिम्मत नहीं है। इसके लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिये।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि ये हालात, राजस्थान के गांव, जो 40 साल से गांव का किसान, गांव का गरीब जिस ट्यूबवेल से पानी पीता था, 40 साल से सरकार उसका बिल चुका रही थी, अप्रैल से सरकार ने कह दिया कि अब यह वाटर वर्क्स नहीं चुकायेगा, गांव वाले चुकायेंगे। पंचायत राज को सशक्त कर रहे हैं, सशक्त ऐसे होगा? आज दर्जनों गांवों के पीने के पानी के ट्यूबवेल के कनेक्शन कट रहे हैं।

राजस्थान के अस्पतालों में डाक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं। जो पूरे राजस्थान के लिये आर पी एस सी से भर्ती होती थी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बस, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। उससे पहले

(श्री अमराराम)

जिलेवाइज भर्ती होती थी, लोगों के डाक्यूमेंट्स फाड़े जाते थे, जब परीक्षा देने जाते तो उनके साथ झगड़े होते थे। आज फिर वही व्यवस्था लाकर राजस्थान के उन इलाकों के साथ जिन्होंने शिक्षा में अग्रणी काम किया, जहां से हजारों लड़के आज भी बी.एड. और टैट किये हुए हैं, अगर उन आठ जिलों में, जहां प्रतिबन्धित जिले हैं, जहां के बच्चे आज तक नहीं पढ़ पाये और आगे नहीं बढ़ पाये, अगर वहां परीक्षा देने जायेंगे तो वही हाल होगा। तो क्यों नहीं जिसमें प्रतिभा है, जो मैरिट में आयेगा, वह सलेक्ट होगा? क्या राजस्थान की आर पी एस सी पर भरोसा नहीं है? गांवों को पीने का पानी नहीं देंगे, स्कूलों में मास्टर नहीं देंगे। निजी शिक्षा माफियाओं के हवाले करने का काम कर रहे हैं।

इसलिये मैं समझता हूं कि जो राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में इस सरकार ने थोथी घोषणाएं और असत्य पुलिन्दा दिलवाया है, मैं समझता हूं, राजस्थान की 90 प्रतिशत जनता के लिये नहीं, वह माफियाओं के लिये है, वह बड़े-बड़े लोगों के लिये है। वह राजस्थान के आम अवाम, गांव, गरीब और किसान एवं मजदूरों के लिये नहीं है। उसका नतीजा 28 तारीख को न केवल राजस्थान के बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ वे तमाम झण्डों को छोड़कर, चाहे वह कांग्रेस के नेतृत्व में चलते हैं, चाहे वे सी पी एम और बी जे पी के नेतृत्व में चलते हैं, इस देश के उस मजदूर ने पूरे देश में 28 तारीख को एकता स्थापित करके कह दिया कि ये नीतियां जो कम्पनियों को मालामाल करने वाली हैं, वे किसान और गरीब को उजाड़ने वाली हैं, मजदूर को उजाड़ने वाली हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ, मैं समझता हूं, बदलाव आयेगा।

इसलिये मैं इस अभिभाषण का विरोध करते हुए आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हुआ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

(अनुपस्थित)

श्री रामलाल मेघवाल।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): सभापति महोदय, मैं 27 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण पर वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

(श्री रामलाल मेघवाल)

तीन दिन से अभिभाषण पर चर्चा दोनों पक्षों की ओर से सुन रहा हूं। अभिभाषण का प्रतिपक्ष की तरफ से जो विरोध हो रहा है, उसमें कोई नयी बात नहीं है क्योंकि इनका तो धर्म है। विपक्ष में बैठकर नीतियों के खिलाफ बोलना इनका धर्म है। जनता ने चुनकर आपको विधान सभा में भेजा है। आप चुनाव के समय गलत भाषण दें वह तो दें लेकिन यहां पर आप इस अभिभाषण का समर्थन करें क्योंकि आपने इसमें सभी पहलुओं को देखा है, सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं को देखा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं है। कौनसा ऐसा मुद्दा है जो गरीब, किसान, अल्पसंख्यक, व्यापारी या किसी वर्ग से अलग है? आप एक भी ऐसा मुद्दा बता दें।

अभी-अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जमीन जो अवाप्त की जाती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। उनकी सरकार की मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव के समय ढकोसला करके पाइप लगाकर नर्मदा नहर का उद्‌घाटन किया और उस उद्‌घाटन में पचास किलोमीटर दूरी पर गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्रजी मोदी के पोस्टर लगवाये गये लेकिन वे उस उद्‌घाटन में सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि चुनाव के समय की फार्मेलिटी थी। उस समय हमारे जालौर जिले को पानी पिलाने के लिए 624 गांवों की योजना का शुभारम्भ किया, वह ऐसी ही पड़ी रही। उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया तो वह काम रुका हुआ रहा। माननीय अशोकजी गहलोत ने डी एल सी रेट को छोड़कर किसानों के हित को ध्यान में रखकर उन किसानों को प्रति बीघा पांच लाख पच्चीस हजार रुपये देकर उस जमीन को किसानों से अवाप्त की और उसके बाद जमीन पर काम चालू हुआ।

इसके अलावा खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि लाइट की उपलब्धता नहीं है। लाइट जो पहले चार घंटे मिलती थी, इस रबी की फसल में और गत रबी फसल के समय में किसानों को पता है कि छह घंटे किसानों को रेगुलर लाइट मिली और उससे किसानों की अच्छी फसल पकी। पाला पड़ने से जरूर नुकसान हुआ है। वह तो आपदा की स्थिति है। उसमें न तो सरकार का दोष है और न आपका और न ही हमारा। उसके लिए भी आप और हम सब मुख्य मंत्रीजी से मांग रहे हैं कि किसानों के हित की बात सोचें और उनको मुआवजा दें। उस पर मुख्य मंत्रीजी बहुत गौर से सोच रहे हैं और मुझे आशा है कि मुख्य मत्रीजी बहुत ही जल्दी फैसला करेंगे और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

(श्री रामलाल मेघवाल)

इसके अलावा विद्युत के सम्बन्ध में मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बताऊं। तीन साल के कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र इर्रिगेटेड एरिया है, कुएं, बेरें और ट्यूबवैल हैं। उन्होंने बीस 33 केवी के जी एस एस दिए। एक 22 केवी का ग्रिड स्टेशन दिया और एक 132 केवी का ग्रिड स्टेशन दिया। इनसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी किसानों को, जो ट्रिपिंग हो रही थी, वोल्टेज कम मिले रहे थे, उसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ।

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण बता रहे हैं कि मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना, जब बी पी एल वालों के लिए तीन या चार इन्दिरा आवास आते थे और दो-तीन इन्दिरा आवास आने से बी पी एल की पूर्ति नहीं हो रही थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को गम्भीरता से लेते हुए दस लाख राजस्थान बी पी एल आवास योजना जो बनाने का काम किया वह ऐतिहासिक है। बी पी एल का सदस्य कभी यह सपने में नहीं सोच रहा था कि मेरा पक्का मकान होगा, पक्की ईंट के साथ सीमेंट लगेगा। उनका भी सपना साकार हुआ।

साथ-साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र 7,775 पंचायतों और सभी पंचायत समितियों में, पच्चीस-पच्चीस लाख रुपये समिति हैडक्वार्टर पर देकर और दस-दस लाख रुपये पंचायत मुख्यालय पर देकर जो कार्य किया है, वह एक ऐसा इतिहास साबित होगा कि ग्रामीण लोगों को शहरों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। कम्प्यूटर से उनको जमाबन्दी की नकल वहां मिलेगी, बिजली के बिल वहां जमा होंगे, साथ ही अगर किसी को रेलवे का सफर करना होगा तो रेल के टिकट भी वहीं मिलेंगे। यह एक अच्छा काम होगा और गरीबों के हित में होगा। किसानों के हित में, किसान भी वहां बैठा-बैठा जयपुर, भरतपुर, गुजरात के भाव, किस किस्म का क्या भाव है, राजीव गांधी सेवा केन्द्र से पता कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क दवाइयां जो चालू की गयी हैं, वह किसी जाति का आदमी हो, व्यापारी हो, बी पी एल हो, ए पी एल हो, सभी को मुफ्त दवाई, जननी सुरक्षा योजना और ऐसी-ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं। आजादी के बाद पहली बार ये योजनाएं माननीय अशोकजी गहलोत ने जनता को सुपुर्द की हैं।

इसके अलावा एक बात और कि प्रधान और प्रमुख जो चुने जाते थे,

(श्री रामलाल मेघवाल)

उनको बी डी ओ के वहां यह कहना पड़ता था कि हमें क्षेत्र के लिए गाड़ी दें तो बी डी ओ चुने हुए प्रधान और प्रमुख को दस दिन के लिए गाड़ी देता था। तो बिना भेदभाव, चाहे किसी पार्टी का प्रधान हो, किसी पार्टी का प्रमुख हो, मुख्य मंत्रीजी ने उन जन-प्रतिनिधियों के क्षेत्र में जाने के लिए सभी प्रधानों को बोलेरो गाड़ियां मुहैया करायी और जिला प्रमुखों को जो मंत्रियों के पास सफारी है, ऐसी गाड़ियां मुहैया करायीं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): साहब, अभी तो चालू ही हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने वालों को पता नहीं चलता है। आप घड़ी देखो, काफी कुछ बोल गये आप।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): अच्छा, ज्यादा बोल गया।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत अच्छे सजेशन दिये हैं आपने।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): तो, साहब, ऐसा है कि बोलने वाले को पता तो नहीं लगता है लेकिन अभी खड़ा तो हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: देख लो आप। जल्दी समाप्त करो।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): तो माननीय मुख्य मंत्रीजी पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह और बेरोजगारों के हितैषी हैं और जो अशोकजी की सरकार ने, कैबिनेट ने मिलकर के फैसले, निर्णय किये हैं, वे ऐतिहासिक हैं।

एक किसानों के हित में जो है, जो भाई अपने भाई को रास्ता नहीं दे रहा था, पड़ोसी पड़ोसी को रास्ता नहीं दे रहा था और उसका किसानों के बीच में बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था, किसी को खेत में जाने को रास्ता नहीं मिल रहा था, किसी को ट्रैक्टर ले जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, उससे वे फसल बोने से वंचित हो रहे थे। मगर इस कैबिनेट ने और राजस्व मंत्री हेमारामजी पहल करके यह कानून लाए और कानून लाकर के उन किसानों के रास्ते का जो समाधान किया है, वह ऐतिहासिक है, 60 साल के बाद, आजादी के बाद पहला कदम है। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार है, नहीं तो पहले कांग्रेस की सरकारें भी बहुत रही हैं लेकिन ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं किसी ने लागू नहीं की हैं। जो राज्यपाल महोदय ने इस सरकार के कार्यों को अपने श्रीमुख से वर्णित किया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामलाल गुर्जर।

यह दोनों पक्षों ने निर्णय किया है कि कम से कम समय लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा दस मिनट एक माननीय सदस्य, नहीं तो रात का काफी समय हो जायेगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरों को आधा-आधा घंटा दिया तो हमारे लिए कम से कम 15 मिनट तो हों।

श्री उपाध्यक्ष: यह दोनों पक्ष, इधर के और इधर वालों ने निर्णय लिया है। मुख्य सचेतक ही करते हैं।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पठित अभिभाषण के बेस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सत्ता पक्ष द्वारा तीन दिन से बहुत वाहवाही की गयी जैसे सभी कुछ कर दिया हो। तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया, हमने भी सोचा कि बहुत अच्छा, शानदार काम हुआ और महामहिम राज्यपालजी द्वारा पठित इस अभिभाषण की शुरुआत हमने देखी तो सात जनवरी से नौ जनवरी तक जो अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन था, वह सबसे पहले दिया। लेकिन अप्रवासी भारतीयों का जो सम्मेलन था, उसमें आप सब को मालूम है कि अपने को क्या देखने को मिला, किसी ने निवेश नहीं किया। और तो और, जो यहां अप्रवासी भारतीय आये, आखिर में उनको नाराज होकर जाना पड़ा। जब यहां के मंत्रीजी भी उनको बोले, रास नहीं आये और उनको वे रास नहीं आये। अब इससे तो आप अंदाजा लगा लो कि क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 18 साल से 28 वर्ष तक के लिए, जो युवा हैं, वे यहां राजस्थान में आयेंगे तो उनके लिए 90 परसेंट हवाई किराये में जो छूट दी है, यह कम से कम 90 परसेंट आप गरीबों को देते तो कुछ फायदा ही होता लेकिन यह समझ के बाहर है।

यह राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये, 'भारत निर्माण' नाम रखा, 'भारत निर्माण' अच्छी बात है लेकिन जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये, बनाये पंचायत हैडक्वार्टर पर लेकिन बहुत दूर-दराज कहीं जाकर के बना दिये तो हो सकता है, वे किन के काम आए रात को, यह तो ऊपर वाला ही जानेगा। जंगल दूर-दराज में बना दिया, वहां जहां ज्यादा लोगों की आवक-जावक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क दवा योजना आपने शुरू की, अच्छी बात है, योजना अच्छी है लेकिन अभी जो दवा हैं, वे हास्पिटल में पूरी

(श्री रामलाल गुर्जर)

उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ जो सस्ती दवा है वो सस्ती दवा दी जा रही है और सस्ती दवा से डाक्टर द्वारा जो इलाज किया जाता है, वह इलाज नहीं हो पा रहा है। फिर लोगों को प्राइवेट हास्पिटल का सहारा लेना पड़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना जो चालू की, अच्छी बात है, की तो लेकिन जिनके मकान बने हुए हैं, उनके दुबारा मकान बन रहे हैं और जो पक्के मकान पहले बने हुए हैं, फिर उनके पक्के बन रहे हैं। अभी माननीय सदस्य, फतेह सिंहजी ने जैसा कि बताया है, वहां पर कितना इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसी योजना से क्या जिसकी देखरेख नहीं हो सकती, संभाल नहीं कर सकते हैं? जिनके नहीं बनना है, उनके बन रहा है। तो एक यह भी कोई ज्यादा उचित कदम नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्न सुरक्षा योजना है, यह जो गरीबों के लिए 15 किलो गेहूं बी.पी.एल. के लिए और 10 किलो आटा दिया जाता है, आटा भी ठीक नहीं। ए.पी.एल. को जो आटा दिया जाता है, वह भी ठीक नहीं। जो खराब गेहूं है, जो खराब किस्म के हैं, जो कहीं पर बिकते नहीं, उसका आटा निकलवा कर आटा दिया जा रहा है। तो यह कोई उचित नहीं है। इससे कुपोषण के शिकार होंगे।

विद्युत, अब विद्युत का मामला ले लें, सबसे मोटा आंकड़ा दिया है कि 3,380 मेगावाट बिजली हमने पैदा की है। बी.जे.पी. शासन में जो मेगावाट माननीय वसुन्धरा राजे जी के टाइम में हुआ था, उसका उजागर यहां किया, उसको भी यहां जोड़ दिया और 3380 मेगावाट बताया। तो यह कहां गायब हुई, इसका मुझे तो मालूम नहीं पड़ा। शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं आया होगा, पहली बार इतनी कटौती हो रही है रात को। आपको मालूम है कि रात को लाइट नहीं आती है, आती है तो दस बजे बाद। गांवों में सिंगल फेज लाइट भी नहीं आती, जबकि माननीय वसुन्धरा राजेजी के टाइम में 24 घंटे गांव में लाइट आती थी, कहीं 20 घंटे, 22 घंटे लेकिन काश्तकारों के लिए कोई कमी नहीं थी। अब तो इतना जरूर है कि यह कह देते हैं, हमारे बिजली विभाग वालों से जानकारी करते हैं, जयपुर से करते हैं तो फिर यहां यह कह देते हैं फ्रिक्वेंसी डाउन हो गयी। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि यह फ्रिक्वेंसी डाउन सरकार की डाउन हो रही है बाकी तो यह फ्रिक्वेंसी डाउन-डाउन, आखिर में सात-आठ-दस महीने हो गये अब तो कम से कम यह फ्रिक्वेंसी सुधर जाती।

(श्री रामलाल गुर्जर)

और घाटा, घाटा 40 हजार करोड़ का घाटा। इससे मोटा और क्या हो सकता है? ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, महीने, डेढ़-डेढ़ महीने तक, फसलें चौपट हो जाती हैं, लगाने वाला कोई नहीं है। ये मुकदमे दर्ज हों, मुकदमे दर्ज टाइम पर होते नहीं, करवाते नहीं और पुलिस वाले भी करते नहीं क्योंकि गृह विभाग ही ऐसा है जो शांति धारीवालजी के पास है, तो गृह विभाग का रखवाला भी ऊपर वाला ही है। और यही नहीं, जो ट्रांसफार्मर के यह मीटर लगा पास में, ऊंचाई तक, तो मीटर रीडिंग वाले भी पूरा लेते नहीं और दस से बीस हजार यह बिजली के बिल निकाल देते हैं और रीडिंग नहीं लेकर के भी कर देते हैं।

अब आप ले लीजिए कि शहरों में, छोटे शहरों में और बड़े शहरों में जो मास्टर प्लान बनाया है, मास्टर प्लान में कैसे हालात हैं, आप सब को मालूम है। हमारे भी मास्टर प्लान के लिए आसींद और गुलाबपुरा के लिए नगर नियोजक, अजमेर ने बनाया था, टोकलियाजी, आपको मालूम होगा, अखबारों में आया और कितने करोड़ों का घोटाला किया, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए रख दिया। तो अब यह तो कैसे, यह तो आप ही जानते हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसी अनदेखी है। अब आप क्या अंदाज करें, टोकलियाजी का अखबारों में खूब छाया, मेरे हिसाब से पूरे सदन को, पूरे राजस्थान को मालूम है। तो वह मास्टर प्लान बना रहे हैं, ऐसे मास्टर प्लान बनाने वाले।

अब कृषि विभाग को ले लें, कृषि विभाग के हालात खराब हैं। क्रय केन्द्र समर्थन मूल्य के समय पर नहीं खुलते हैं। काश्तकारों की फसल मुश्किल से थोड़ी बहुत होती है, उसको भी ये सेठ-साहूकार को सस्ते भाव में बेचना पड़ता है, जैसे कि बाजरे का समर्थन मूल्य 9 रुपये 80 पैसे लेकिन अभी पांच-छह रुपये किलो बाजरा बिका। तो ये तो हालात बहुत खराब हैं। इधर अपन खाद का भाव ले लें, खाद जो 500 रुपये कट्टा था, वह 1100 रुपये कट्टा हो गया, डी.ए.पी. खाद। तो इससे आगे और क्या हो सकता है। प्याज का भाव ले लो, प्याज डेढ़-दो रुपये किलो, तीन रुपये किलो काश्तकारों के पास है और मार्केट में जाओ तो दस रुपये किलो और थोड़ा टाइम स्टाक करके फिर 25-30 रुपये के भाव चले जायेंगे। तो इसलिए समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र जल्दी से जल्दी सरकार सभी फसल के लगाएं।

नर्मदा योजना का जो पानी है, माननीय वसुन्धराजी के टाइम में गुजरात से लाकर किया गया। तो वह चिन्ता सबको होनी चाहिए, कम से कम

(श्री रामलाल गुर्जर)

पानी के लिए सब सोच-विचार करें। जैसाकि पिछली बार केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा नदियों को जोड़ने का और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा आखिर में नदियों को जोड़ो नहीं तो मामला गम्भीर है।

गृह विभाग के हालात देख लो, जेल में जेलर को मारा गया; सी आई को फूंका गया, जलाया गया। यह गोपालगढ़ की घटना; और एक सबसे मोटा काम क्या किया कि जन-प्रतिनिधियों पर, सरपंचों पर लाठीचार्ज किया। राज्य सरकार ने यह मोटा काम किया इनकी निगाह में तो। एक ओर कहते हैं उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील, लोक कल्याणकारी सरकार है, शिक्षा विभाग के हालात देख लो, स्कूलों के हालात देख लो। चाहे उच्च माध्यमिक हों, चाहे माध्यमिक हों, उच्च प्राथमिक विद्यालय हों, प्राथमिक विद्यालय हो, लाखों पद खाली पड़े हैं। तीन साल से हो रहा है कि लाख की भर्ती करेंगे, कभी सत्तर हजार की भर्ती करेंगे, कभी पचास हजार की भर्ती और अब निकाला है, चालीस हजार थर्ड ग्रेड की भर्ती, इकतालीस हजार करेंगे। अब यह आर पी एस सी से होती तो हो भी जाती समय पर।

जिलेवार जो भर्तियां कीं, अभी निकाली वेकेन्सी, अब इसमें भी कई अडंगे निकले; बी एड का तो है ही लेकिन टैट का और नये सिरे से लगा दिया। जिन्होंने टेट की परीक्षा पास नहीं की, उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जो ओवरएज हो रहे हैं। यह कितने नुकसान की बात है। वसुन्धराजी के टाइम पर जो प्रबोधक थे, एक लाख प्रबोधकों को परमानेंट करके लगाया और यही नहीं, लाखों की संख्या में नौकरी दीं। लेकिन अब तीन साल का समय हो गया, नौकरी दी हो, यह कोई नजर नहीं आ रहा है, किसी को नौकरी दी।

स्कूलों में मिडडे मील का जो भोजन बनता है, कैसा है? बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो किसी को रहम तो आए। आप सबका भी नैतिक दायित्व है कि कम से कम जानकारी करें।

चिकित्सा विभाग के हालात भी, डाक्टरों की हर जगह कमी है, नर्से, कम्पाउण्डर मरीज परेशान हैं। यही नहीं, हास्पिटल की क्या दशा है, आपको मालूम है। जब मरीज को चूहे कुतर कुतर कर खा जाते हैं, इससे मोटा तो और क्या हो सकता है? शिशुओं की मौत हो रही है, प्रसूताओं की मौत हो रही है। वसुन्धरा जी द्वारा जो एम्बुलेंस 108 धन्वन्तरि योजना द्वारा लागू की गयी थी, उसमें भी जो टेंडर, वगैरह यह अस्सी हजार के बजाय 94 हजार 899 । अब

(श्री रामलाल गुर्जर)

इनका भी कल तर्क-वितर्क काफी हुआ था लेकिन पूरा सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए।

इसके अलावा, नरेगा के हालात जानें तो नरेगा में तो भगवान ही मालिक है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पांच आई ए एस अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ जांच की लेकिन जांच को बताने के लिए हमने सवेरे मांग की थी कि इनकी जांच करवाई जाए, तो उस नाते आरोप-प्रत्यारोप जड़े गये। जबकि जांच होनी चाहिए, जांच वाजिब है। चाहे सी बी आई द्वारा जांच हो, जांच होनी चाहिए, असलियत सामने आ जाती है।

यही नहीं, नरेगा में मजदूरी बी जे पी के शासन के समय, माननीय वसुन्धराजी के समय सौ रुपये मजदूरी मिलती थी, सबको रोजगार मिलता था लेकिन अब रोजगार भी नहीं। अब तो रोजगार भी सौ दिन पूरे नहीं भर पा रहे हैं। इधर एक कम्प्यूटर सिस्टम कर दिया और कह देते हैं कि वह सर्वर फेल हो रहा है कि अभी यह पूरी लिस्ट नहीं बनी है, वह लटकाए रखते हैं। इसके अलावा, रेट आती है, कितनी आती है, बीस रुपये, तीस रुपये। अब बीस-तीस रुपये में अगर मजदूर मजदूरी करेगा तो पेट कैसे भरेगा वह? आप सबको विदित ही है। तो नरेगा के हाल बहुत ही बुरे हैं। यही नहीं, गांव में सी सी ब्लाक पर जो निकाले थे, उसमें भी पाबन्दी लगाई कि ढाई मीटर बनाए जाएं, पौने चार मीटर बनाए जाएं।

अब आगे रहा जयपुर को विश्व स्तरीय सिटी बनाने के लिए, अब जयपुर के हालात देखिये, जयपुर की सड़कों के हालात देख लें। यही नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्री महोदय ने खुद ने कहा है कि यह नगर निगम नहीं है, नर्क निगम है। तो अब आप अन्दाजा लगा लो, यह कैसा जयपुर सिटी बनेगा।

राजस्थान में माननीय वसुन्धराजी के समय पर जो काम हुआ, आज भी पब्लिक सब चाहती है कि डेढ़-दो साल कब निकलें, कब माननीय वसुन्धरा जी का टाइम आए, कब बी जे पी का शासन आए। इसी आशा पर सब टिके बैठे हैं।

आपने समय दिया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी। समय का थोड़ा ध्यान रखना।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, समय का पूरा ध्यान रखूंगा।

27 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण वर्तमान सरकार के तीन साल की उपलब्धियां, योजनाओं का उल्लेख किया, सदन में रखा, उसके लिए हमारे सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य, खाचरियावासजी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने टीका टिप्पणी ही नहीं की बल्कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जो विधान सभा के प्रक्रिया नियमों और आर्थिक आंकड़ों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, विद्वान, पण्डित घनश्यामजी तिवाड़ी व प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने कहा कि इस अभिभाषण पर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अभिभाषण मान्य ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1990 से 1998 तक, 2003 से 2008 तक क्या ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि कार्यवाहक महामहिम ने अभिभाषण पढ़ा हो? अब ये धारीवाल साहब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री बता रहे थे कि कब-कब उन्होंने पढ़ा। तो प्रतिपक्ष जब सत्ता में था तो उनको मना कर देना चाहिए था, भारत सरकार को कह देना चाहिए कि स्थाई गवर्नर लगायेंगे तब ही अभिभाषण करवायेंगे। अपना सदन आहूत कर लेते और अभिभाषण नहीं करवाते। इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, जब इधर बैठते हैं तो क्या बात करते हैं और सामने बैठते हैं तो क्या बात करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जिन-जन कल्याणकारी योजनाओं का, नीतियों का तीन साल का लेखा-जोखा यहां प्रस्तुत किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि योजनाएं तीन साल में इतनी आयीं कि जन कल्याण की योजनाओं का पिटारा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खोल दिया। दो रुपये किलो आटा, एक बहुत बड़ी योजना जिसका लगभग 39 लाख परिवारों को फायदा मिल रहा है। इसी तरह इन्दिरा आवास, मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना, दस लाख इन्दिरा आवास दिये जायेंगे; लगभग चार लाख इन्दिरा आवास योजनाओं की स्वीकृति जारी कर दी गयी। अभी बहरोड़ से

(श्री भगवान सहाय सैनी)

आने वाले माननीय जसवन्त सिंहजी यादव कह रहे थे कि योजनाओं का क्या, योजनाएं तो आती रहती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनका भी पांच साल शासन रहा, राइट-टू-इन्फोर्मेशन, राइट-टू-एजुकेशन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये अपने समय में क्यों नहीं लागू कीं? जब भारत सरकार से आ रही थीं तो इन्होंने लागू क्यों नहीं कीं? क्या इनकी क्षमता नहीं थी? लेकिन ऐसा नहीं था। माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत आम आदमी की बात सोचते हैं, आम आदमी के लिए योजनाएं लाते हैं, पूरे राजस्थान प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं, वे कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं और राजस्थान का विकास करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

माननीय जसवन्त सिंहजी कह रहे थे कि किसानों को चार परसेंट का ऋण दे रहे हैं और इनके समय तेरह परसेंट का ऋण था कोआपरेटिव के माध्यम से, अब जो चार परसेंट कर रहे हैं। कितना फर्क है। ये किसानों के हितैषी, अभी अमरारामजी किसानों की बात कर रहे थे; जननी सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। रात को 12 बजे भी यदि प्रसूता को डिलिवरी की आशंका होती है तो सरकार उसके लिए गाड़ी भेजेगी, हास्पिटल लाएगी और डिलिवरी के बाद वापस अपने खर्चे पर उसको भेजेगी। इतनी बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई।

बी जे पी में जो संयंत्र लगाये, उसमें ही हुआ। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो 33 के वी ए, 132 के वी ए जी एस एस ग्रिड बन रहे हैं, तो बी जे पी वालों ने क्यों नहीं बनाये? आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में छह 33 के वी ए जी एस एस, दो 132 के वी ए जी एस एस सैंक्शंड हैं और उनका निर्माण कार्य गति पर है। तो यह हर विधान सभा क्षेत्र में हो रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि जब तक 33 के वी ए, 132 के वी ए जी एस एस अधिक नहीं बनायेंगे तो छीजत भी अधिक होगी और किसान को वाल्टेज भी कम मिलेंगे। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गांवों में 33 के वी ए और 132 के वी ए जी एस एस की स्थापना की गयी है।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब आदमी, जो बी पी एल में भी नहीं है, जिसका आपरेशन होना है, चाहे 5 लाख रुपये लगें, चाहे 6 लाख रुपये लगें, उसमें 40 परसेंट मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से

(श्री भगवान सहाय सैनी)

दिया जा रहा है। हजारों लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 साल में लगभग 400 लोगों को 20,000 से 60,000 रुपये तक मिला है जिससे उनका आपरेशन का इलाज हुआ है। एक बहुत बड़ी योजना है।

उद्‌घाटन की बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने तो बी जे पी के शासन में जो योजनाएं स्वीकृत हुईं उन्हीं का उद्‌घाटन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बासा में जीव विज्ञान विषय खुला ही नहीं और जनवरी, 2008 में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने उसका उद्‌घाटन कर दिया। वह शिलालेख आज भी लगा हुआ है। मेरे चौमूं में सामुदायिक भवन बना ही नहीं और उसका शिलान्यास 2008 में ही कर दिया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जब ये सत्ता में होते हैं तो बात कुछ और करते हैं, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो बात और करते हैं। इन्होंने सेज में क्या किया? 90 बी में क्या किया? जमीनों का सौदा इन्होंने किया।

किसानों की बात कर रहे थे कि कांग्रेस किसान की मानी जाती है, बी जे पी व्यापारियों की मानी जाती है; व्यापारी जब माल को लेकर इनके सामने आये, प्रदर्शन किया तो उनके डंडे इन्होंने ही मारे थे। बी डी कल्ला जी हमारे कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने शरण देकर थाने में जाकर इनकी जमानत करायी। यह भारतीय जनता पार्टी है।

यह गोपालगढ़ की चर्चा करते हैं, सोहेला, घड़साणा और महुवा में 90 लोगों को इन्होंने मरवाया। गोपालगढ़ में तो आपस में झगड़ा हुआ, उस कारण मृत्यु हुई लेकिन सोहेला, घड़साणा और महुवा में पुलिस के, सरकार के आदेश से गोली चली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने मरवाया। यह इनको ध्यान नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेट्रो रेल परियोजना, एक बहुत बड़ी योजना जो जयपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी लाये हैं और शहर में यह मेट्रो जब चलेगी, दौड़ेगी तो निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास सिटी का नजारा नजर आयेगा। बहुत बड़ी योजना है और यह आगे जाकर पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण की चर्चा कर रहे थे तो अगर उत्तर में जायेगी तो हमारे चौमूं में भी जायेगी, मैं मानता हूं।

'शुद्ध-के-लिये-युद्ध' एक ऐसी योजना है कि आज हम सब, राजस्थान का हर नागरिक शुद्ध भोजन कर रहा है। आप चाहे मसाला लो, दूध लो, मावा

(श्री भगवान सहाय सैनी)

लो, सब नकली आ रहा था। जब एक साल पहले 'शुद्ध-के-लिये-युद्ध' चालू किया, लगभग सवा लाख परीक्षण किये, 32 हजार सैम्पल लिये गये और आज निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिलावट में बहुत कमी आयी है। मिलावट करने वाले भी इन्हीं के लोग थे इसलिये इनको दिक्कत आ रही थी कि लेबोरेटरी मशीन क्यों जा रही है? ये सैम्पल क्यों लिये जा रहे हैं? लेकिन आज राजस्थान के हर नागरिक को खाने के लिये शुद्ध दूध, घी, मावा और मसाले मिल रहे हैं जिसका राजस्थान के निवासियों की सेहत पर अच्छा असर रहेगा।

108 एम्बुलेंस की चर्चा कर रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीस-पच्चीस 108 एम्बुलेंस चलाकर ये वाहवाही लूटना चाहते हैं। आज लगभग 400 एम्बुलेंस हर सी एच सी पर, मेरे यहां 2 सी एच सी पर और 1 नेशनल हाइवे पर 3 एम्बुलेंस 108 चल रही हैं। निश्चित रूप से उसका फायदा हो रहा है। इन्होंने तो केवल उसका नजारा पेश किया था। आज मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने हर सी एच सी पर, हर नेशनल हाइवे पर देकर एक बहुत अच्छी सेवा प्रदान की है। हमने इनकी तरह काम नहीं किया। कांग्रेस काम करने में विश्वास रखती है, वाहवाही लूटने में विश्वास नहीं रखती।

मैं एक बात कहूंगा, हमारी सरकार ने, विद्वान पंडित घनश्यामजी बैठे हैं, 300 संस्कृत विद्यालय भी खोले हैं, प्राथमिक संस्कृत विद्यालय तो नये खोले हैं जिससे संस्कृत का प्रचार-प्रसार भी होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय की चर्चा भी प्रतिपक्ष ने की कि माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले गये। पंचायत मुख्यालय पर कई विद्यालय नहीं हैं। इन्होंने शिक्षा पर राजनीति की। एक ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं तो मुख्यालय पर न खोल करके छोटे गांव में इन्होंने खोल दी। हमारी सरकार ने आते ही, कांग्रेस सरकार ने आते ही हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने का काम किया और आज मैं मानता हूं कि पूरे राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में, चाहे मुख्यालय पर नहीं हो, पहले से जहां खुलीं वहां नहीं खोली, हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय आज स्थित है।

राजीव गांधी आई टी केन्द्र की स्थापना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर आई टी केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसमें हर तरह के काम, किसान को जमाबंदी, नकल, कोई भी लेने के लिये शहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं की वहीं मिल जायेंगी। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले महीने पाला पड़ने से जो किसानों को हानि हुई उसका मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिये चाहे वह बिजली के बिल माफ हों, चाहे गिरदावरी करवा कर मिले।

ऊर्जा विभाग जो गैर-आबादी में किसान को विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहा है, वे विद्युत कनेक्शन निश्चत रूप से चालू होने चाहिये क्योंकि किसान खेतों में रहते हैं।

आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की कार्यवाही आधा घंटे और 8.30 बजे तक, बढ़ाने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: स्वीकृति हो तो सदन की कार्यवाही 8.30 बजे तक के लिये बढ़ा दी जाए?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही 8.30 बजे तक के लिये बढ़ायी गयी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के अष्टम सत्र के इस बेबुनियाद, अवसादपूर्ण अभिभाषण जो आफिशिएटिंग महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़वाया गया, वह निरर्थक और +++ का पुलिन्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट नम्बर 3 में आपने पढ़ा है ''मातृभूमि से नयी पीढ़ी को जोड़े रखने और उन्हें यहां की विरासत से रूबरू कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को बुलाया गया।'' यह राजस्थान की जनता के साथ धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें लिखा था, ''अठारह से लेकर अट्ठाइस तक के जो भी यात्री यहां आयेंगे, उन्हें नब्बे प्रतिशत राशि सरकार द्वारा मुहय्या करायी जायेगी।'' बड़े शर्म की बात है। इससे तो अच्छा यह होता, जो हमारे प्रदेश और देश से बाहर के देशों में जा रहे हैं, गरीबों को

(श्री हरिसिंह रावत)

एक जून की रोटी नहीं मिलती, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनके ऊपर यह खर्च कराया जाता तो मैं समझता हूं ज्यादा फ्रूटफुल होता। अफसोस है कि इनको तो वाहवाही लूटनी थी और अन्त में क्या मिला, सब जितने भी अप्रवासी भारतीय या राजस्थानी जो गये, कटु सत्य है कि वे सब बेरूखे होकर गये। न ही उन्होंने कोई घोषणा की और न ही राजस्थान को कोई फायदा मिला। मेरा तो निवेदन है कि ऐसी घोषणाएं न करें, ऐसा खर्चा न करें जिससे कि जनता पर भार पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने वाहवाही लूटने के लिये कहा कि हमारे यहां सरकार तो बहुत ही विकास कर रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक आपने जनता में कड़ी से कड़ी जोड़ी है। उसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा यही रहा कि भूख, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, चेन चोरी और पता नहीं, क्या-क्या इस देश के साथ में हो रहा है। इसके ऊपर एक शेर सुनाना चाहता हूं, चोरों की जो यह मंडली है दिल्ली से लेकर जयपुर तक, 'बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, जहां हर डाल पर उल्लू बैठा हो अंजामे चमन क्या होगा।' तो यह स्थिति इस राजस्थान सरकार की है। इन्होंने आज तक तो कुछ विकास कराया नहीं, जहां देखो भूख, भय, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, स्थिति यह है, वाहवाही लूटने के लिये हमारे पक्ष के जितने भी विधायक विराजमान हैं, बड़ी गाथाएं, बड़े लम्बे-चौड़े भाषण दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह किया, वह किया।

मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले जब वसुन्धराजी की सरकार थी, तब उस सरकार ने एक विजन बनाया था कि अगर राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाना है तो हमें गांवों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पांच अहम मुद्दे बनाये थे, सर्वप्रथम तो शिक्षा, फिर सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य; ये हर गांव, ढाणी में हों ताकि कोई भी गांव का व्यक्ति शहर की तरफ मुंह ना करे। उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने योजना बनाई और उस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम शिक्षा को महत्व देते हुए सरकार ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कूल खोलें और स्कूलों के साथ-साथ शिक्षकों की भर्ती भी की। उपाध्यक्ष महोदय, इससे विकास अग्रसर हुआ और साथ में सड़कों से गांव, ढाणियों को जोड़ा।

उस समय जब हमारी सरकार थी तो हमारे विपक्ष में बैठने वाले

(श्री हरिसिंह रावत)

कांग्रेस के भाई बोलते थे कि यह सब योजनाओं का पैसा तो सेंटर से आ रहा है। जब सेन्टर से आ रहा था, तो अब दिल्ली और जयपुर में आपकी ही सरकार है फिर क्यों नहीं पैसा आ रहा है? फिर क्यों नहीं विकास हो रहा है? क्यों नहीं मास्टरों की भर्ती की जा रही है? क्यों नहीं डाक्टर्स की भर्ती की जा रही है? क्यों नहीं गावों में सचिवों की भर्ती की जा रही है? क्यों नहीं पटवारियों की भर्ती की जा रही है? क्यों नहीं आफिसों में स्टाफ लगाया जा रहा है? कुछ नहीं, केवल थोथी बातें, थोथी घोषणाएं हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के विधायक बड़ी ऊंची-ऊंची डींगें मारते हैं कि हमारे यह हुआ, वह हुआ, मैं सोचता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। यह तो जवाब सरकार देगी 2013 में, जनता बतायेगी आपको कि वास्तव में सरकार ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। वसुन्धरा सरकार ने जो काम किया, अगर आज देखा जाये तो उसका 30 परसेंट भी काम नहीं हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह झूठी वाहवाही नहीं लूटें और वास्तव में सरकार को निर्देशित करें। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी, अगर जनता में वास्तव में आपका कुछ बचा है तो जनता के लिए कुछ करिये। खाली झूठे आश्वासन, झूठी बातें करने से कुछ भला होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कई ऐसी योजनाएं बनायीं, उन योजनाओं के अन्तर्गत आपने किसानों की बात की। यह राष्ट्र किसान प्रधान देश है। किसान -प्रधान देश का कृषक अगर रात को भूखा सोता है तो वह किस चीज का किसान-प्रधान देश हुआ? आज हालात यह हैं कि गांवों में जाकर के बात करें तो वहां बिजली नहीं मिलती। जहां सरकार आठ-आठ घंटे की बातें करती है, वहां चार घंटे बिजली नहीं मिलती है और इन चार घंटों में भी ट्रिप होती है, हर 15 मिनट बाद ट्रिप हो जाती है। अगर एक बार खेतों में पानी स्टार्ट होता है और 15 मिनट बाद ट्रिप होती है तो पानी वहीं का वहीं रह जाता है। गरीब आज परेशान है। जब भी हम फोन करते हैं कि लाइट हमें दिन में दीजिये तो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, वे बोलते हैं कि सरकार ने हमें आदेश दिया है, लाइट अगर लगानी है तो रात को लगायें, थ्री-फेज कनेक्शन का अगर उपयोग लेना है तो रात को लीजिये, चूंकि दिन में 13 रुपये यूनिट लगता है, रात को 2 रुपये यूनिट आता है। उपाध्यक्ष महोदय, वह किसान जब इतनी ठंड पड़ती थी, माइनस 2, माइनस 3 के टेम्प्रेचर में उनको मजबूर होकर के रात को 2 बजे,

(श्री हरिसिंह रावत)

3 बजे, 4 बजे तक खेतों में रहना पड़ता था। मेरा निवेदन है कि बिजली तो कम से कम सही दीजिये ताकि गरीबों का भला हो सके।

बिजली की बात करें तो हमारे कार्यकाल में बी पी एल परिवारों को कनेक्शन की बात हुई तो करीब 6 हजार कनेक्शन बाकी रह गये थे। जब हमने हमारे विद्युत विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मजबूर होकर के शायद 200 विधायकों में पहला विधायक हूं, मैंने करीब डेढ़ करोड़ रुपये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लाइट के लिए मेरे एम एल ए-लैड से दिये। यह बड़े ही शर्म की बात है। आज यह पैसा और काम में लगना चाहिए था। लेकिन मैंने एक विजन बनाया था कि जो हमारी वसुन्धराजी का सपना था कि हर गांव, ढाणी में स्कूल हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो और स्वास्थ्य हो, उसी के अनुरूप मैंने काम किया। जहां-जहां भी जिस गांव और ढाणी में समस्या थी, उसमें मैंने प्रयत्न किया कि वहां परिपूर्ण काम हों।

इसी के साथ ही विद्युत में इतनी भयंकर चोरी, आज डायरेक्ट कनेक्शन ले रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां आपके अधिकारी जाते हैं और पैसे जेब में लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम चलाओ। यह स्थिति हो रही है भ्रष्टाचार की।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों के लिए खाद की बात करें हम, वह जो 550 रेट थी, वह 1,100 रेट हो गयी। क्या आप किसानों की बातें करते हो? मेरा निवेदन है कि यह जो खाद का रेट बढ़ाया है इसको वापस कम किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की बात करें, नरेगा की बात करें, नरेगा में तो भ्रष्टाचार का एक आयाम कायम हो गया है। नरेगा मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी किस हद तक; मैं तो कहता हूं कि राजीव गांधी जी ने भी जो बोला था कि अगर दिल्ली से एक रुपया जाता है तो गांव में केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी सब तो बंदरबांट हो जाती है, उसी के अनुरूप नरेगा में यही काम हो रहा है। नरेगा के लिए मेरा यह निवेदन है कि वहां केवल मिट्टी का काम ना करके परमानेंट असेट्स बनायी जायें। हर गांव, ढाणी में नाली नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, आंगनबाड़ी नहीं हैं, स्कूल भवन नहीं हैं, तो ऐसे भवन बनाये जायें जो परमानेंट असेट्स बन सकती हैं। यह बड़ा ही फ्रूटफुल होगा।

(श्री हरिसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा की बात करूंगा। चिकित्सा में भी आपकी सरकार ने बोला था कि आम जन को हम दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं, क्या खाक मुफ्त में दे रहे हैं? मैं बताता हूं कि जब हम सी एच सी में गये और वहां पता किया हमने, जो दवाइयां मिलती हैं उनका रजिस्टर चैक किया, वहां बोर्ड पर लिखी हैं 128 दवाइयां और जब फिजिकली चैक किया तो केवल 28 दवाइयां मिलीं। जब कोई पेशेंट आया तो रजिस्टर में लिखा एन ए; तो पूछा कि यह क्या है, तो कहा कि नाट अवेलेबल। पेशेंट से पूछा कि दवाई कहां से लाये तो कहा कि बाजार से लाये। इस पर हमने वहां डाक्टर से पूछा कि यह दवाई फ्री में दी क्या? आपने पेमेंट किया, नहीं किया तो फिर क्यों जनता से धोखा किया जा रहा है? जो दवाई आपको फ्री में देनी चाहिए या लेकर के देनी चाहिए, वह दवाई नहीं दी उन्होंने। वह दवाई जब बाजार से लेकर के आता है, तो फिर किस दवाई के फ्री वितरण की बात करते हैं आप?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि हास्पिटलों में डाक्टर नहीं। हमारे पिछले कार्यकाल में, हमारी वसुन्धरा सरकार में ट्रौमा अस्पताल की व्यवस्था हुई थी भीम में, उसके लिए करीब 65 लाख के उपकरण आये हुए पड़े हैं। लेकिन वहां डाक्टर नहीं हैं, ना एनेस्थेशिया का डाक्टर है, ना वहां पर कोई आर्थोपेडिक सर्जन है जिसकी वजह से वे सारी मशीनें धूल चाट रही हैं। हमने भवन बनाया है, वहां मैटेरियल लगाया है और वहां स्टाफ नहीं है तो फिर वह किस चीज का भवन बना? इसमें मेरा निवेदन यही है कि जहां डाक्टरों की कमी है, वहां डाक्टर्स लगाइये और जहां जो व्यवस्था नहीं है वहां वह व्यवस्था सुचारू रूप से कराइये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं बी पी एल की बात करूं, सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई है, उस आवास योजना के अन्तर्गत उनको केवल 50 हजार रुपये मिलने थे। 50 हजार रुपये से आज के जमाने में कुछ नहीं होता है, एक खिड़की के किवाड़ भी नहीं लगता है। अगर आपको वास्तव में गरीबों का भला करना है तो मेरा निवेदन है कि सामूहिक रूप से जमीन अलाट की जाये और उसके बाद जिस भी गांव, ढाणी में बी पी एल के परिवारों को बसाना है तो बसायें। आप बी पी एल परिवारों के लिए जमीन अलाट कराइये और उसके बाद सामूहिक रूप से भवन बनाकर के उनको दीजिये। इसमें कम से कम डेढ़ लाख तो होना ही चाहिए तो मैं सोचता हूं कि इससे गरीबों का घर जरूर बन सकता है। यह जो 50 हजार की बात करते हैं, इसमें

(श्री हरिसिंह रावत)

केवल बंटरबांट होती है। उसमें जो वास्तविक यूजर हैं बी पी एल परिवार, जिनके लिए पैसे मिल रहे हैं, वहां तक 30-35 हजार से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि इसमें सामूहिक रूप से पट्टे दिलायें। इसमें मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी, मैंने कहा कि यह आपने दो साल में जो पैसे दिये, उनके पट्टे हैं? तो कहा कि पट्टे तो नहीं हैं, अगर पट्टे नहीं हैं तो फिर किस बात का भवन बनेगा? इसके लिए पहले प्रारूप तैयार करिये, उसके बाद ही यह योजना फ्रूटफुल होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि हमारे यहां राजसमन्द जिले में मार्बल का बहुत बड़ा व्यवसाय है। मार्बल के लिए किशनगढ़ या ब्यावर तक रेलवे लाइन से जोड़ा जाये। आप बांसवाड़ा तक बनाने की बात कह रहे थे, अगर वैसे ही हमारे मावली से मारवाड़ जंक्शन तक जो लाइन जाने वाली है, उसको अगर ब्यावर तक जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि किशनगढ़ के लिए जो मार्बल का व्यवसाय है, उसमें सरकार को काफी रेवेन्यू मिलेगी और उसका हमें फायदा मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि लास्ट दो महीने पहले हमारे मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत दिवेर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उदघाटन करवाया गया था। वह कहावत है कि 'नाचे नेकली खावे खेतली' वह वाला काम हुआ। मेवाड़ काम्प्लेक्स के लिए जो साढ़े 6 करोड़ रुपये हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने दिये थे, उसका उद् घाटन करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी आये और आकर के क्या असत्य बातें कहते हैं राष्ट्रपतिजी को, कि देखिये, कितनी खुशी की बात है कि 2009 में हमने यह बनाया और आज आपके कर कमलों से उदघाटन हो रहा है। कितनी शर्म की बात है कि मुख्य मंत्रीजी राष्ट्रपतिजी को ऐसी असत्य बात बोलते हैं। उस वक्त तत्काल मैंने बोला था कि राष्ट्रपति महोदया यह मुख्य मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं, यह हमारी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधियाजी और जब आप राज्यपाल थीं, तब 2005 में आपने अभिभाषण में पढ़ा था कि साढ़े 6 करोड़ रुपये में मेवाड़ काम्पलेक्स का, जहां महाराणा प्रताप व अकबर का युद्ध हुआ था, उस रणस्थली को उदघाटन के लिए उन्होंने सैंक्शन दी थी पैसे की।

लेकिन ये असत्य ख्याली पुलाव खाते हुए बोलने लगे कि हमने खर्चा किया और हमने यह बनाया। तो कितने शर्म की बात है। एक मुख्य मंत्री

(श्री हरिसिंह रावत)

अगर ऐसी भाषा बोलता है तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता।

मैं शिक्षा मंत्रीजी के बारे में बात करना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी अभी कुछ दिन पहले हमारे देवगढ़ साइड में पधारे थे, उनसे हमने बात की कि देवगढ़ में हमारे राजकीय महाविद्यालय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको 15 मिनट हो गए, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों पक्ष यही चर्चा कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): कालेज नहीं था। तो उन्होंने 2002 में कालेज की एक असत्य घोषणा जरूर की थी। कालेज वहां हुआ नहीं लेकिन इस सरकार ने कालेज देवगढ़ में है, कालेज देवगढ़ में है, करके हमारे आज तक जो कॉलेज खुलने वाला था खुला नहीं जबकि मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हर तहसील हैडक्वाटर पर कालेज खोलेंगे। अफसोस है कि सपने खाली सपने ही रह गये, असत्य आश्वासन रह गए। मेरा निवेदन है कि देवगढ़ में कालेज खुला नहीं है, मैं मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो कालेज खुला नहीं है तो आने वाले बजट में कम से कम राजकीय महाविद्यालय खोलें ताकि हमारे बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है, वह सुगम हो सके।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और यह जो अभिभाषण दिया है, उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मेजर ओ पी यादव।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपनी सटीक और टू-द-पाइण्ट, निश्चित अवधि में बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एजेण्डा रिपीट भी न हो।

27 और 28 तारीख को हमारे एक साथी ने और बीच में एक-दो और साथियों ने भी यह बात की, अपनी मंशा जाहिर की, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात नहीं करके ज्यादा उन्होंने अपनी रुचि महामहिम राज्यपाल के प्रति दिखाई। मैं समझता हूं कि वह निरर्थक था और निरर्थक है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसका कारण है कि after all, Governor is the

(मेजर ओ.पी. यादव)

Head of a State or States, and performs and discharges all his duties and responsibilities in accordance with the Constitution. उसके अलावा उनका एक ऐसा स्टेटस है हमारे सारे अपनी स्ट्रक्चर में कि मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी टिप्पणी की जाए जो महामहिम की गरिमा पर कोई असर डालती हो। पर इसका शायद ध्यान नहीं रखा माननीय सदस्य ने। मैं समझता हूं कि वे किसी पार्टी के नहीं होते, he is not part of any party, he is above party politics. यह पहले भी जब महामहिम प्रभा रावजी थीं तब भी यह कोशिश की गई थी और तब भी मैंने खड़े होकर यह बात कही थी। हमारे यहां वैसे भी हिन्दुओं में राजस्थान में एक कहावत है कि एक घर तो डाकण भी छोड़ देती है, तो महामहिम का तो एक ऐसा स्टेटस है जिनके प्रति, मैं समझता हूं कि हमारी रुचि महामहिम में तो होनी चाहिए, आदर और सत्कार के साथ लेकिन वह क्या पहनता है, क्या खाता है या क्या करता है, यह सब बातें भगवान की दया से न कही गई पर बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डैटा आजकल इन्टरनेट पर बहुत आसान है, डैटा लेकर बोलना भी बहुत आसान है, it is very impressive also, पार्लियामेंटरी स्पीच भी बहुत अच्छी बनती है लेकिन आम आदमी को रचनात्मक कार्यों से क्या मदद मिलती है, यह सोचने की बात है। तो मैं समझता हूं, यह सच है कि अभिभाषण जो पढ़ा गया, राज्यपाल का वह अभिभाषण जो होता है वह मेनिफेस्टो के बेसिस पर होता है और हर पार्टी अपनी सरकार के बनने के बाद उस घोषणा पत्र, मेनिफेस्टो के अकोर्डिंग अपनी पालिसीज बनाती है। इसी संदर्भ में हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर और उन बाबुओं के साथ भी मिलकर जिनका जिक्र किया गया, वे ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं जब उनकी बारी आती है, वह बाबू हो जाते हैं जब दूसरों की बारी आती है। I think, the appropriate word will be .. why can't we call them the 'public servants'? तो पब्लिक सर्वेंट्स की मदद लेकर भी यह काम होता है उसके बाद में वह पब्लिक डाक्यूमेंट और गवर्नमेंट डाक्यूमेंट हो जाता है। गवर्नमेंट डाक्यूमेंट पर जो अभिव्यक्ति महामहिम करते हैं, वह अपने विजन से, अपने एनालाइसिस से, अपना देखने के बाद वही उनकी अभिव्यक्ति होती है, इसी को महामहिम का अभिभाषण कहते हैं। मैं समझता हूं कि महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, महामहिम पर चर्चा कम होनी चाहिए थी, ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच है और मैं कहना चाहूंगा कि इस गरिमा को हमेशा सदन में बनाए रखा जाए।

(मेजर ओ.पी. यादव)

साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज भी देखा गया और मुझे लगता है, बड़े दु:ख की बात है कि एक पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के लिए सदन के अंदर 'नोनसेंस' शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई हल्की बात नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि ऐसे वक्त पर ऐसे शब्दों को एक्सपंज किया जाए और वह कोई भी हो चाहे पूर्व मंत्री हो, उनको जरूर यह हिदायत दी जाए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया। इसके बाद वक्त आया तो वर्तमान सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने आम आदमी की बात सोची। यह बिलकुल सही है, I am not a hypocrite. I am totally convinced. That's why I am saying so on this floor. यह बिलकुल सही बात है कि उन्होंने आम आदमी की बात सोची और आम आदमी की सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि कुछ करें। सबने मिलकर फिर एक व्यवस्था की और उसी के साथ चलकर हम आज तीन साल से काम कर रहे हैं।

भूख, रोजी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मैं समझता हूं, हर समाज में हरेक नागरिक की जरूरत होती हैं, हर समाज की संरचना उसी के आधार पर चलती है और जिसने इस बारे में सोच लिया, इस पर कुछ कर दिखा दिया तो मैं समझता हूं कि अशोक द ग्रेट खाली अशोक नहीं है, जहां तक देखा गया है और ऐतिहासिक तौर पर आज भी सच है कि वसुन्धरा के ऊपर राज अशोक-द-ग्रेट ने ही किया है और आने वाले समय में भी अशोक-द-ग्रेट ही राज करेगा कांग्रेस के साथ मिलकर, यह एक सच्चाई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूख; भूख के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं आर्म्ड फोर्सेज से हूं, यह सबको मालूम है। सन् 1971 की लड़ाई के अन्दर, बिलकुल सच्ची घटना सुना रहा हूं, भूख की बात क्योंकि भूख ऐसी चीज है जिसको लगती है वही जानता है; भूख होती क्या है, जिसने देखा हो वही जानता है कि भूख क्या होती है; उस लड़ाई के अंदर एक जगह थी, मसाराम जंगल्स, वहां पर एक वायरलेस आपरेटर जो बेरी गांव का था, चरखी दादरी के पास से, उस आदमी की वायरलेस सेट के पास डैथ हो गई, जो बम्बार्डमेंट हुआ। मेरा एक हाथ भी चला गया था, यह जो हाथ आपके सामने है वह ग्राफ्टेड है।

श्री उपाध्यक्ष: एतराज हो रहा है कि आप बैठ कर बात कर रहे हैं। अपनी-अपनी सीट पर पधारें, कृपया।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): मैं यह कह रहा था, मैं भूख की बात कर रहा हूं आपसे कि भूख के अन्दर यह हुआ कि जब उस आदमी के भाई रणवीर को हमने बुलाया पास से तो वह जब आया तो उसने खाने की तरफ देखा वहां पर। मैं समझता हूं कि घनश्यामजी तिवाड़ी यह बात नहीं सुनें तो ज्यादा अच्छा है। वहां पर हल्का सा बार्बेक्यू बन रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उद्योग मंत्रीजी, उनको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मेजर साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके अपने स्थान पर पधारें।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): बार्बेक्यू टाइप चीज बनी हुई थी जंगल में, जो आग लगाकर बनाते हैं, वह आदमी वहां गया, उसने वह खाया पहले, बाद में अपने भाई की शक्ल देखी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन का यह कर्तव्य है कि जो बोलें माननीय सदस्य, उनकी आंख में आंख डालकर देखें। आप इधर क्यों डाल रहे हो?

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): मैं यह कह रहा भूख के बारे में। जब उस आदमी को कहा गया कि आप अपने भाई के आखिरी दर्शन कर लो, तो वहां पर ग्राउण्ड शीट होती है, कफन तो होता नहीं, उसको हटाने के बजाय वह आदमी गया और उसने पहले खाया और खाने के बाद फिर उसने दर्शन किए अपने भाई के। यह दूसरी बात है कि उसके बाद उसने 7 जवानों को मारा।

मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास मकान नहीं है, उससे पूछो कि मकान की जरूरत क्या होती है; जिसके पास दवाई नहीं है उससे पूछो कि दवाई की कितनी जरूरत है। हमारे पास अगर एनासिन नहीं होती है तब भी हम परेशान हो जाते हैं। गरीब आदमी के पास अगर टाइम पर कोई चीज नहीं मिलती है, उसको पैसा नहीं मिलता है, माननीय सदस्य कान्ता भीलजी ने अपनी बात हो सकता है कि ज्यादा भावनात्मक तौर पर पेश की हो, पर यह सच्चाई है जो बात वे कह रही थीं। ऐसा होता है और जहां ऐसा होता है, वहां पर अगर आप समझें कि रोटी न हो आदमी के पास, जैसा मैंने बताया, मकान नहीं हो, दवाई नहीं हो तो वह आम आदमी तरसता है उस टाइम पर कि कैसा राज है। हमने तो यहां तक किया, हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने यहां तक किया कि स्वास्थ्य के प्रति चिंता की। इन सब चीजों का जिक्र बहुत विस्तार से हो चुका है, जैसा मैंने कहा कि रिपीट नहीं करूंगा, इससे वक्त जाया होता है सदन का।

(मेजर ओ.पी. यादव)

शिक्षा की बात हो चुकी है, राइट-टू-एजुकेशन भी हो चुका है और जितनी बातें यहां पर होती हैं॰ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सब इस वजह से होती हैं कि सबको राइट-टू-इन्फोर्मेशन है। सब लोग बड़े आराम से इन्फोर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, विदिन-द-गिवन-टाइम ले सकते हैं और साथ-साथ आज हम इन्टरनेट पर एक सुविधा की बात करते हैं, डैटा की बात करते हैं और डैटा को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वह सब भी देखा जाए तो इसी सरकार और इसी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के ही प्रधान मंत्रियों ने अपनी सोच के मुताबिक मोबाइल, इंटरनेट और आये, जो हमारे पास में कम्प्यूटर है, यह भी उसी सोच के साथ में आया था। उसी की वजह से आज हम इतनी बहस कर पाते हैं, इसी की वजह से आज हम इतनी इंफार्मेशन लेकर बात कर सकते हैं। इसका मतलब हमने जो कुछ दिया, वह सकारात्मक दिया। आने वाले समय में भी हम सकारात्मक सोच रखते हैं। इसीलिए आदरणीय हमारे गृह मंत्रीजी ने भी कहा, हमारे शांति धारीवालजी ने भी कहा कि हम सुझावों का आदर करते हैं, आने वाले समय में लोग सुझाव दें, रचनात्मक बात करें। माना कि उनका धर्म है कि वे हमारी खिलाफत ही करेंगे हर बात पर, पर साथ-साथ एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ। यह तो सही है कि हर आदमी को दवा चाहिए, हर आदमी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वह आज हमारी सरकार ने दिया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं, कम है और कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहिए हमें अपने मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ आज यह साबित कर दिया कि वे वास्तव में अशोक-द-ग्रेट हैं, अशोक-द-ग्रेट रहेंगे। अगर मेरे साथियों को यह कहीं वहम है थोड़ा सा कि आने वाले समय में वे इधर बैठने वाले हैं, मैं समझता हूं कि अगले 10 साल तक वहां इंतजार करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।

इसी के साथ में, एक बार फिर मैं अपनी बात को यह कहते हुए कि अभिभाषण का समर्थन मैं पुरज़ोर शब्दों में करता हूं और साथ-साथ आपको धन्यवाद कि आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, 11 मिनट में ही समाप्त कर दिया।

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, रामगंजमण्डी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण पर मैं भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

व्यक्त करना चाहूंगी, कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। मैंने इस अभिभाषण की प्रति को कल से आज तक तीन बार पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद जो कुछ विचार मेरे मन में आये हैं और जो कुछ कमी इसके अन्दर मुझे नजर आई है, उस कमी को मैं यहां व्यक्त करना चाहूंगी।

सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये लेकिन आज हमें जिस आशा और विश्वास के साथ गांव की जनता ने यहां पर जिता कर भेजा है, अगर हम उनके हितों की बात नहीं करें, मात्र वाहवाही लूटने के लिए इस अभिभाषण की प्रति की हम बहुत प्रशंसा करें तो मुझे लगता है कि मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हूं और जनता ने मुझे जिस भावना के साथ यहां जिता कर भेजा है, मैं उनकी भावनाओं की कसौटी पर शायद खरी नहीं उतर रही। इसलिए मुझे लगता है, मैं इस अभिभाषण के प्रति कहना चाहूंगी कि पहले, दूसरे और तीसरे पैरों में जो माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में बात कही और इस सरकार ने जो वाहवाही लूटी, मुझे लगता है, वह सरासर गलत है। आप देखिए, इस 10वें अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह जगजाहिर है और पूरे मीडिया के माध्यम से इस पूरे राजस्थान की जनता ने उसे पढ़ा है, देखा है और उसके बारे में सुना है। आप देखिए, हम धरातल की बात करते हैं, आज ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग जीत कर आते हैं, क्या हमें मालूम नहीं है कि गांव की जनता की क्या दुर्दशा है? ठीक है, हमने बोल दिया कि हम प्रवासी भारतीयों को या युवाओं को हवाई यात्रा करवाएंगे और उसमें 90 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। मैं इस बात को सही नहीं मानती क्योंकि इस राजस्थान के अन्दर आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें दो टाइम खाना नसीब नहीं है। जो भी प्रवासी भारतीय और जो इस राजस्थान के धरती से, इस देश के धरती से प्रेम रखता है, मुझे अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, मुझे लगता है कि वह बिना 90 प्रतिशत किराया देने के बावजूद भी यहां आएगा और इस भारत देश की चिंता करेगा, इस राजस्थान की चिंता करेगा।

जैसा कि पैरा नम्बर 4 में कहा गया कि यह पारदर्शी सरकार है, बिलकुल मैं इस बात को खारिज करती हूं। मैं न तो कोई गलत बात यहां बोलूंगी, मात्र मेरी आंखों के सामने, मेरे गृह जिले में, मेरी विधान सभा क्षेत्र में किस तरह के क्या कारनामे हुए, वही यहां पर उजागर करना चाहूंगी। आप देखिए, हम पारदर्शी सरकार होने की बात बोलते हैं, हम यह भी बोलते हैं कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इस राजस्थान में नरेगा योजना को चलाकर इस राजस्थान की गरीब जनता को दो समय का भोजन मुहैया करवा दिया यानी कि उसकी गरीबी मिटा दी लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह पारदर्शी सरकार और नरेगा में भ्रष्टाचार नहीं है, यह बात बोलने वाली सरकार के कुछ कारनामे, मैं अभी 25 तारीख को राजीव गांधी सेवा केन्द्र का उद्‌घाटन करने पहुंची, मुझे गांवों के कम से कम चार सौ महिलाएं और वहां के मजदूर भाई सारे लोग रोड़ पर बैठे हुए मिले, मैंने उनसे कहा कि आपकी नरेगा चल रही है, बहुत अच्छा पेमेंट आपको मिल रहा है, आप रोड पर धरना देकर क्यों बैठे हुए हो तो उन्होंने मुझे बताया कि बहनजी, पूरा एक वर्ष नरेगा के अन्दर हमने काम किया है और एक वर्ष का पेमेंट हमें नहीं मिला, हमें इसके बदले थाने में बंद भी करवा दिया गया, अगर हमने पेमेंट मांगा। आप देखिए, उन महिलाओं के घरों में उनके डिब्बे में आटा नहीं था। मुझे कुछ व्यक्तियों ने बताया कि यहां पर इन महिलाओं के घर में आटा नहीं होने के कारण हमें इनको पैसा देना पडा। आप देखिए कि मीडिया में इतनी बड़ी-बड़ी हैड लाईस में यह बात छपी। मुझे बड़ा दुःख होता है कि हम पारदर्शिता की बात करते हैं।

दूसरी बात बताना चाहूंगी कि कानून-व्यवस्था जो हम स्वच्छ कानून इस राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं, उस कानून-व्यवस्था, लॉ-एण्ड-आर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून-व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। आप देखिए अगर दो महीने के अन्दर एन एच-12 पर, जो हमारा नेशनल हाइवे-12 है, उस पर मात्र आधा घंटे के अन्दर दो लूट की घटनाएं हो जाएं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। दो महीने के अन्दर अगर चार घटनाएं एक ही जगह लूट की हो जाएं तो इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात यहां निवेदन इसलिए कर रही हूं कि कहीं न कहीं मेरे मन की इस पीड़ा को जिस माध्यम से जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझे जिता कर भेजा, मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, मैं इसीलिए अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं कि सरकार को पता लगे कि हकीकत में क्या हो रहा है। आपको बताना चाहूंगी कि जो शादी में से एक परिवार लौट रहा था, मैं रात को 12 बजे उसी जगह से निकली, मात्र मेरी गाड़ी से पीछे, 15 मिनट बाद में मेरे पास काल आया कि बहनजी, हमारे साथ ऐसी-ऐसी घटना घटित हो गई। आप देखिए, आधे घंटे पहले लूट की वारदात हुई, वे थाने में गये, मोड़क थाने में, वहां जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। आधे घंटे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तक कोई पुलिस प्रशासन का आदमी वहां तक नहीं पहुंचा। आधे घंटे बाद दुबारा लूट की वारदात हुई और 15 तोला सोना और 10 हजार की नकदी उन लोगों से छीन ली गई। उन लोगों ने जैसे ही देखा कि पुलिस की कोई गाड़ी आ रही है, उसको रोका, उनसे कहा, देखिए, चोर भाग रहे हैं, पकड़िये। तो पुलिस के जो हमारे कांस्टेबल थे, उन लोगों का यह कहना था कि भाइयों, अगर हम पकड़ेंगे तो हमें मार देंगे। उन लोगों ने उनको विश्वास दिलाया और आगे-आगे वे महिलाएं दौड़ीं व पुरुष दौड़े, उसके बाद कांस्टेबल वहां से दौड़े। यह बहुत शर्म की बात है। देखिए, आये-दिन बहुत सी चोरियां हो रही हैं, इतना सब कुछ यहां पर मेरी कांस्टिट्यूएंसी के अन्दर हो रहा है और फिर भी हम यह बोल दें कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं।

आपने देखा होगा, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण में क्या हुआ? चाहे हम चेचट की घटना को लें, एक महिला का थाने में बलात्कार और उसके बाद इतने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, उसका सिर काट दिया गया और राजस्थान की इस सरकार ने वादा किया कि उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी, आज तक उसको नौकरी नहीं मिली। यह शर्म की बात है।

एक बात और कहना चाहूंगी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, पैरा नम्बर 8 में कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की समृद्धि, खुशहाली के कार्य को अपना लक्ष्य मान रही है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे इस भारत देश की आत्मा गांवों में निवास करती है। हम किसान परिवार से हैं, क्या हमें नहीं दिखाई देता कि इस गांव के किसान की दुर्दशा इस सरकार ने कर रखी है। सर्दी के मौसम में? यानी गांव के किसान को जब बीज की आवश्यकता हो तब बीज नहीं मिले, जब उसे पानी की आवश्यकता हो नहर में सिंचाई के लिए तब उसे पानी नहीं मिले, जब उसे बिजली की आवश्यकता हो तब बिजली नहीं मिले और जब उसे खाद की आवश्यकता हो तब उसे खाद नहीं मिले। अगर खाद भी उसे मिल जाए तो देखिए, कोटा के अन्दर खाद के कट्टे दिये गये, यूरिया के कट्टे दिये गये, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगी कि आपने यूरिया खाद के कट्टे के साथ सेलटोन नाम का जो पैकेट दिया, जिस पर सऊदी अरब की मोहर लगी हुई थी, जो 60 रुपये का पैकेट था, वह पैकेट लेने के लिए किसान को क्यों बाध्य किया गया? जब हम लोगों ने इस बात का प्रचार-प्रसार गांवों में करना शुरू किया तब उस पैकेट को देना बंद कर दिया। यहां तक कि कोटा की जनता ने इस मामले को

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हाई कोर्ट तक पहुंचाने की मंशा बनायी। यह बहुत गलत बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को कृषि यंत्रों पर जो भी अनुदान मिलता है, वह अनुदान आज की तारीख में कोटा जिले को नहीं मिलता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके गृह जिले की बेटी हूं और मुझे लगता है, आप इतना सा ध्यान रखेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल योजना चल रही है, पहले यह इंदिरा आवास योजना के नाम से चलायी जाती थी। आपको बताना चाहूंगी कि प्रभारी मंत्री जब गांवों में गये और पूरी जनता को गांवों से बुलाया, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर इसका कार्यक्रम रखा और वहां जाकर एक लैटर उस गरीब को थमा दिया गया कि आपका बीपीएल आवास का जो मकान है वह मकान सैंक्शन हो गया। आप देखिए, अभी जब पिछले महीने जन सुनवाई हुई तो जिला कलक्टर मेरी बगल में बैठे हुए थे, उस समय भी गांव के लोग उन सैंक्शन लैटरों को लेकर आ रहे थे कि इस सरकार ने हमें आवास के नाम पर जो लैटर दिया है, जो चैक दिया है, वह चैक क्यों नहीं पास हो रहा है? बड़े खेद की बात है कि अभी तक उन लोगों को एक पैसा भी नहीं मिल पाया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि तुरन्त उन लोगों को जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको पैसा दिलाया जाय।

एक बात और कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना आपने चालू की, मैं इस बात के लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी लेकिन इस योजना के नाम पर किसी गरीब को लूटा जाय, यह गलत है। क्योंकि हम गांवों में घूमते हैं, धरातल पर रहते हैं, मुझे यह मालूम है कि जो व्यक्ति एक किलो आटा खरीदकर नहीं ला सकता, वह व्यक्ति चाय बनाने के लिए शक्कर और चाय की पत्ती खरीद सकता है? मैं आपके माध्यम से बताती हूं कि कोटा के अन्दर, मेरी कांस्टिट्यूएंसी के अन्दर, पीपल्दा गांव के अंदर, और भी जगह की हमें शिकायतें मिलीं कि अगर केरोसिन भी उसे दिया जाता है, अगर उसे तीन लीटर भी केरोसीन दिया जाता है तो उस केरोसीन के साथ उसे 250 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट लेने के लिए उसे पाबंद किया जाता है तब उसे केरोसीन मिलता है। वहां खनन क्षेत्र है, लोग स्टोव पर खाना बनाते हैं और उनको इस तरह से पाबंद नहीं किया जाय। शक्कर की क्या स्थिति है, यह मैं आपको बताना नहीं चाहती।

मैं आपके माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था की जो स्थिति हमारे कोटा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

शहर के अन्दर और रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी। भले ही मुख्य मंत्री महोदय ने कितनी ही नि:शुल्क दवा योजना चालू कर दी, लेकिन ऐसे-ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं कि किसी बी पी एल व्यक्ति को जो सांगोद विधान सभा क्षेत्र से आता है, इस योजना के चालू होने के बाद डाक्टर उसको दवा लिखकर देता है कि तुम्हें यह दवा बाहर से लानी पड़ेगी और वह व्यक्ति मेडिकल स्टोर जाता है और उसे वह दवा 6 हजार रुपये में उपलब्ध होने की बात कही जाती है तो वह पसीने में गीला हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी में नवजात शिशु को कुत्ते उठाकर ले गये; आपकी जननी शिशु सुरक्षा योजना चालू होने के तीसरे दिन उस महिला की किस स्थिति में रामगंजमण्डी हास्पिटल के अन्दर मृत्यु हुई जो न्यामद छेड़ी गांव की रहने वाली थी; पूरे रामगंजमण्डी क्षेत्र की जनता का सिर शर्म से नीचे हो गया। यह स्थिति वहां के डाक्टरों की है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं पहले भी इस बात को इस सदन में कह चुकी हूं और बार-बार आपसे निवेदन करती हूं कि कहीं न कहीं जो हमारा खनन क्षेत्र है, जो मजदूर वर्ग रहता है, उसके बारे में विचार किया जाय, उसके बारे में सोचा जाय ताकि उनको कुछ फायदा मिले वरना आपने अभिभाषण में जो बातें लिखी हैं कि हमने इतनी-इतनी योजनाएं शुरू कर दीं, वे सब योजनाएं कोरे कागजों में हमें पढ़ने को मिलेंगी और कोरे कागजों में रह जाएंगी। जब तक जनता को इनका पूरा फायदा नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा काम आपकी सरकार कर रही है, पूरे दो लाख से ज्यादा आपने स्वयं सहायता समूह बनाये हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है, एक लाख 75 हजार स्वयं सहायता समूह हमारी पिछली वसुंधराजी की सरकार बना चुकी थी, साइकिलें हम भी दे चुके थे, आप भी दे रहे हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि जो पेयजल की स्थिति हमारे यहां बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बोराबास-पदमपुरा योजना, नयागांव-अचलगढ-कथार योजना स्वीकृत कीं, उन्हें तब से लेकर आज तक ठण्डे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)
बस्ते में डाल दिया है। वहां की जनता के लिए हम लोगों को, जो हमारी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी कुछ पानी के टैंकरों की व्यवस्था हम लोगों को वहां करनी पड़ती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो योजनाएं सैंक्शन हुई हैं, उन्हें तीन साल से ठण्डे बस्ते में डाल रखा है। हमें पता लगा है, उसके टेण्डर हो चुके हैं। अगर टेण्डर हुए हैं तो कब तक इस काम को शुरू करने का मन सरकार बनाती है? मैं एक बार और निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी इन सब योजनाओं का फायदा जनता को मिले ताकि जो लाखों-करोड़ों का खर्चा सरकार पेयजल पर करती है, वह पैसा सरकार का बचेगा।

मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद और मैं जो अभिभाषण की प्रति है, इसके अन्दर जो बातें लिखी हैं, उसमें सरकार के माध्यम से कुछ सुधार किया जाय वरना इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: 8.30 तक सदन चलना है, दो मिनट बाकी हैं। श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनका भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ा दें, यह तो आसन कर सकता है। आप बोलना चालू करो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष: 8.35 तक सदन का समय इजाजत हो तो बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8.35 तक बढ़ाया जाता है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष जी, आपने समय बढ़ाया 8.40 तक, आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: 8.35 तक।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की प्रति जो हमें दी गयी है, जो राज्यपालजी ने पढ़कर सुनाया है और पढ़ा भी ऐसे कि उनके खुद के गले में

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

घरघराहट रही और उनको भी लगा कि मैं दूसरी बार यह भाषण दे रहा हूं या पढ़ रहा हूं तो मैं क्या नया कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया। कारण पहले भी अभिभाषण पढ़ा तब भी वही का वही, अब भी अभिभाषण पढ़ा वह भी पहले जैसा है, इसमें नया कुछ नहीं है। नया तो तब होता जब इनकी योजनाएं और नीति जो लागू कीं वे जनता के बीच में आतीं,

उनको जनता अपने हित में, अपने फायदे के काम में लेती। लेकिन जैसा मुझे पता है, जनता के बीच में ऐसी कोई योजना इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। कोई भी आपकी योजना है, चाहे वह 108 को ले लीजिये, चाहे जननी सुरक्षा को ले लीजिये, चाहे महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कीजिये, किसी को भी ले लीजिये, कोई भी रूरल एरिया के अन्दर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन पर मुझे कभी-कभी हंसी आती है कि धन्यवाद देते हैं, तालियां पीटते हैं और धीरे-धीरे जब भाषण की समाप्ति होती है तब अपना रोना रोते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि फिर ये बड़ाई क्यों करते हैं कि हमारी सरकार ने यह किया, हमारी सरकार यह योजना लाई? यह मजबूरी क्यों है? जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? जनता अंधी नहीं है, जनता सब देखती है। केवल इस सदन के अन्दर बैठकर हम वाह-वाही कर लें, हम अपनी सरकार का जो भी बजट हो या अभिभाषण है, उस पर तालियां पीट लें, उससे कुछ फर्क नहीं होता। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक धनवान आदमी ने महात्मा जी से पूछा कि महात्माजी, बताओ कि जीवन में क्या काम करना चाहिए। महात्माजी ने कहा कि सामने जो खिड़की है, उधर जाओ और बाहर देखो। वह धनी युवक खिड़की से बाहर देखता है तो उसको रोड पर चलते हुए कुछ आदमी नजर आते हैं और एक अंधा भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। उसने महात्माजी से कहा कि महात्माजी, कुछ आदमी घूम रहे हैं और एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा है। फिर महात्माजी ने कहा कि चलो, अब आप जो दर्पण है, उसमें देखो। उस युवक ने दर्पण में देखा तो उसको उसमें अपना चेहरा नजर आया। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्माजी, इसमें तो केवल मैं ही नजर आ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि खिड़की का जो शीशा था, उसमें से आर-पार दिख सकता था और दर्पण के पीछे एक चांदी की परत

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

लगी हुई होती है, पेंट किया होता है तो उसमें अपने आपको देखा। इसलिए जब तक आपकी आंखों से यह चांदी की परत नहीं उतरेगी तब तक आप जनता को नहीं देख पाओगे या लोगों को नहीं देख पाओगे। यह सत्ता पक्ष वालों के लिए है कि आपने अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर चांदी का पर्दा लगा रखा है, उसको हटाओ और जनता के बीच में जाकर देखो कि कौन-कौन सी योजनाएं, कौन-कौन सी आपकी नीतियां काम कर रही हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि हमने इतने सामूहिक संगठन बनाये। एक बात मेरे विचार में आई, कुछ दिन पहले मैंने न्यूजपेपर में पढ़ा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ऐसी टिप्पणी महिलाओं पर करती हैं कि जिससे हमको शर्म आ जाती है। हम हिन्दुस्तान में रहते हैं और हम मानते हैं कि हम कितने भी माडर्न हो जाएं, कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लें लेकिन हम रहेंगी हिन्दुस्तानी नारी। उस टिप्पणी पर मैं यह कहना चाहूंगी कि सारी महिलाओं को शर्मसार कर दिया है। मैं वह टिप्पणी नहीं बोलना चाहती क्योंकि वह शब्द ही इस तरह का है लेकिन इतना कहूंगी कि पार्टी के मेम्बर्स इस तरह की बात करते हैं और यहां पर आप आकर कहते हैं कि हम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इतने सामूहिक संगठन बनाये हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर वे बालिकाएं या महिलाएं काम करने जाएंगी, कुछ पैसा, धन कमाने जाएंगी, नौकरी करेंगी और अगर कोई वह टिप्पणी कर देगा तो क्या वे जा सकती हैं? बाजार में निकल सकती हैं? फिर काहे का आर्थिक सशक्तिकरण? मैं तो कहती हूं कि जैसे ही कोई पद या कुर्सी मिल जाती है तो वह चांदी का पर्दा अपने आप आ जाता है और वे कुछ भी बोल देते हैं चाहे वे आपके अध्यक्ष हों, चाहे आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हों।

दूसरी बात मैं 108 पर कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि आपने 108 एम्बुलेंस चलाई....

श्री उपाध्यक्ष: प्रमिलाजी, एक मिनट। सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2012 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.35 बजे गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर जिले में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना

43. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में कोई भी सरकारी बालिका महाविद्यालय नहीं है? क्या सरकार उक्त जिले में सरकारी बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जिला धौलपुर में सरकारी बालिका महाविद्यालय नहीं है। परन्तु धौलपुर जिले में दो निजी व एक जनसहभागिता आधारित महिला महाविद्यालय संचालित है।

सीमित संसाधनों के कारण जिला धौलपुर में सरकारी बालिका महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

सिरोही जिले के अणगौर बांध में पानी आवक हेतु कार्य योजना

44. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में जिला सिरोही की तहसील आबूरोड के बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर उसके ओवरफ्लो पानी को धान्ता बांध में तथा धान्ता बांध के ओवर फ्लो से अणगौर बाँध में लाने की योजना तैयार की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना की क्रियान्विति क्यों नहीं हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले की तहसील आबूरोड, पिण्डवाडा व सिरोही क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा में बढ़ोत्तरी के साथ दिनोंदिन गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए बत्तीसा नाला पर बांध बनाकर उसके ओवर फ्लो पानी को धान्ता बांध में तथा धान्ता बांध के ओवरफ्लो से अणगौर बांध में लाने की योजना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। बत्तीसा नाला पर प्रस्तावित बांध के ओवरफ्लो का पानी धान्ता बांध में तथा धान्ता बांध के ओवरफ्लो से अणगौर बांध में लाने हेतु कोई योजना तकनीकी दृष्टि से फिजिबल नहीं होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली स्थित राज्य की सम्पत्तियां

45. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सम्पदा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के स्वामित्व वाली कितनी जायदाद/सम्पत्तियां दिल्ली में कहां-कहां स्थित हैं? वर्तमान में और सम्पत्तियों पर किस-किस का कब्जा है और वर्तमान में इन सम्पत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्पत्तियों/जायदादों जिन पर राज्य सरकार का कब्जा नहीं है को अपने कब्जे में लेने के लिये क्या कोई कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली सम्पदा विभाग के अधीन नजूल सम्पत्तियां जो कि दिल्ली में स्थित है, का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। चूंकि दिल्ली स्थित राजकीय नजूल सम्पत्तियां राजकीय उपयोग में आ रही हैं। अतः इनके मूल्य का आंकलन नहीं किया गया है।

(2) नई दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस जो कि राज्य सरकार के स्वामित्व की नजूल सम्पत्ति है, पर दिल्ली सरकार का कब्जा है, जिसे प्राप्त करने के प्रयास राज्य स्तर पर किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	सम्पत्ति	पता	सम्पत्ति पर काबिज
1	बीकानेर हाउस	पण्डारा रोड नई दिल्ली	माननीय मुख्यमंत्री एवं सांसद सैल, कन्वेशन हाल, एडवोकेट चैम्बर्स, आवासीय आयुक्त कार्यालय, रीको, आर.एफ.सी. वी.आई.पी. पर्यटन, बीकानेर कैफे (पर्यटन निगम के अधीन) बीमा, राजस्थान परिवहन निगम, सूचना केन्द्र, ए.टी.एम. (एक्सीस बैंक) सरस पार्लर, एस.टी.डी.पी.सी.ओ., के अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर्स एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय संचालित है।
2	जोधपुर हाउस	25, औरंगजेब रोड नई, दिल्ली	वी.वी.आई.पी. गेस्ट हाउस
3	राजस्थान हाउस	7, पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली।	सरकारी गेस्ट हाउस
4	उदयपुर हाउस	15, राजपुरा रोड नई दिल्ली	दिल्ली सरकार के कब्जे में है। दिल्ली सरकार से कब्जा प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।
5	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित दो भूखण्ड	प्लाट नं. 1, 7898.86 वर्गगज, प्लाट नं. 2, 4128.52 वर्गगज	इस सम्पत्ति पर राज्य सरकार का कब्जा नहीं है। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की तृतीय बैठक दिनांक 22.02.2003 में उक्त लीज होल्ड सम्पत्ति को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

रविन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर में रिक्त पद

46. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रविन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में सहायक आचार्यों (असिस्टेंट प्रोफेसर), सह आचार्यों (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं वरिष्ठ प्रदर्शकों (सीनियर डेमोस्ट्रेटर) के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त महाविद्यालय में किन-किन विभागों में आचार्य के सभी पद रिक्त हैं?

(3) उक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु क्या किया जा रहा है?

(4) उक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कितने चिकित्सक कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) रविन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है-

पद नाम	**स्वीकृत**	**रिक्त**
सह आचार्य	77	27
सहायक आचार्य	90	54
वरिष्ठ प्रदर्शक	32	06

(2) उक्त महाविद्यालय में निम्न विभागों में आचार्य के सभी पद रिक्त हैं-

1. फोरेन्सिक मेडिसिन
2. नेत्र रोग
3. फार्माकोलोजी
4. ईएनटी
5. न्यूरोलोजी
6. एनाटोमी

(3) माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं की जा सकी जिसके कारण पदोन्नति कोटे के पदों पर नियमित नियुक्ति सम्भव नहीं हो पा रही है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अर्थनायें राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

(4) उक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं है।

जोबनेर-नावां-कुचामन मेगा हाइवे निर्माण कार्य

47. **श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नागौर वाया जोबनेर-नावां कुचामन स्टेट हाइवे-2 सरकार द्वारा घोषित 16 मेगा हाइवे में सम्मिलित है? क्या उक्त मेगा हाईवे का अभी निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त मेगा हाइवे का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर-नागौर वाया जोबनेर नावां-कुचामन स्टेट हाइवे-2 सरकार द्वारा घोषित 16 मेगा हाइवे में सम्मिलित है।

जी हां। उक्त मेगा हाइवे का निर्माण अभी नहीं किया गया है क्योंकि इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति दिनांक 23.01.2012 को जारी की गई है, जिसमें इस परियोजना को आर.एस.आर.डी.सी.सी. लि. द्वारा कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की फोटो प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

इस कार्य हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त मेगा हाइवे के निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा आमन्त्रित की गई है जो दिनांक 28.03.2012 तक प्राप्त की जाकर 30.03.2012 को खोली जावेगी। (संलग्न परिशिष्ट-2)

कार्य की निर्माण अवधि 2 वर्ष प्रस्तावित है। (संलग्न परिशिष्ट-3)

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बछड़ों की राज्य से बाहर निकासी पर रोक

48. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम)

(1) क्या सरकार राज्य के बछड़ों को राज्य से बाहर जाने पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रोक लगने के बाद बछड़ा-गाय व किसान तीनों को एवं राज्य को भारी नुकसान हुआ है?

(3) राज्य में पाबन्दी लगने से पहले पशु मेले में कितने बछड़े मेलेवार बिक्री होती थी तथा पाबन्दी के बाद कितने बछड़े बिक्री हुए? तुलनात्मक मुख्य मेलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 27.01.2000 की पालना में तीन वर्ष से कम उम्र के गोवंश के राज्य से बाहर निर्यात संबंधी विधेयक "राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955" में संशोधन के लिए मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) तीन वर्ष से कम उम्र के गोवंश रोक के पूर्व से सन् 1991-92 से ही पशु मेलों में इनके आमद एवं विक्रय में निरन्तर कमी आ रही है । रोक के कारण भारी आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है ।

(3) प्रदेश में राज्य से बाहर गोवंशीय पशुओं को ले जाने पर लगी पाबन्दी से पहले एवं बाद का राज्य स्तरीय पशु मेले का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

संलग्नक

राज्य स्तरीय पशु मेलों में गौवंशीय पशु आमद संख्या विवरण

वर्ष	श्रीगोमती सागर पशु मेला झालरापाटन	श्री गोगामेडी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़	श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर	श्री जसवन्त प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर	श्री कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर	श्री चन्द्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़	श्री रामदेव पशु मेला नागौर	श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली	श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाडा बाड़मेर	श्री बलदेव पशु मेला मेड़तासिटी नागौर	योग
1991-92	10055	1185	29921	9051	12535	8939	25566	18233	25770	17548	158803
1992-93	11599	21360	50578	12213	25985	12465	32669	18040	36483	21772	243164
1993-94	11763	680	30144	6405	11021	8381	26900	12927	22541	14243	145005
1994-95	10771	865	20469	0	9541	5864	23994	15458	30634	11633	129229
1995-96	9541	726	17644	4033	9469	4887	20662	16274	28896	11676	123808
1996-97	5815	996	25336	4189	4905	5806	18919	13412	24276	7606	111260
1997-98	7727	1029	16653	4457	4426	2739	15828	6062	23920	7348	90189
1998-99	8972	813	14310	4858	5954	2491	17980	14367	14847	7663	92255
1999-2000	7067	644	13520	5705	4676	3684	10414	14960	4862	2778	68310
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माह जनवरी 2000 से 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की राज्य से बाहर निकासी प्रतिबंधित है।											
2000-01	7868	158	7552	6501	4249	3695	13605	12277	7429	5257	68591
2001-02	0	380	8863	6891	3366	4910	15167	12728	9448	5392	67145
2002-03	0	305	9209	5936	3928	4285	7402	9519	721	2324	43629
2003-04	0	143	7197	4851	4373	1883	10551	11293	8109	5455	53855
2004-05											56716
2005-06	0	107	7595	6148	5826	4073	10813	11972	7228	3625	57387
2006-07	0	76	9329	9637	5216	2134	9703	12219	7823	4879	61016
2007-08	4544	23	9569	6363	3884	3833	10987	11897	8450	5757	65307
2008-09	0	6	10696	11533	4177	3970	11346	11082	8060	6367	67237
2009-10	0	5	8256	6545	5319	4632	10119	14999	4016	5282	59173
2010-11	0	3	7440	4536	3352	5717	11915	11629	7430	7290	59312

वर्ष	श्रीगोमती सागर पशु मेला झालरापाटन	श्री गोगामेडी पशु मेला गोगामेडी हनुमानगढ़	श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर	श्री जसवन्त प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर	श्री कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर	श्री चन्द्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़	श्री रामदेव पशु मेला नागौर	श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली	श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाडा बाड़मेर	श्री बलदेव पशु मेला मेड़तासिटी नागौर	योग
1991-92	4148	743	23044	3297	3826	1789	14462	9198	8403	9912	78822
1992-93	4409	690	10177	3207	4315	1533	12116	6134	11927	7118	61626
1993-94	3151	469	12376	3363	3556	1975	12670	6747	12597	7013	63917
1994-95	4349	587	13506	0	3104	1740	12658	9100	17615	6430	69089
1995-96	3002	526	12996	3116	3944	920	12352	7241	15252	4670	64019
1996-97	1446	524	9708	2617	2820	1032	10836	6936	13642	5701	55262
1997-98	3822	621	11479	3021	3234	1221	12375	5436	11358	6782	59349
1998-99	3462	340	9249	2712	2185	1061	13550	7048	8990	5948	54545
1999-2000	2352	484	5970	3304	2087	1002	5820	4301	1337	1505	28162
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माह जनवरी 2000 से 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की राज्य से बाहर निकासी प्रतिबंधित है।											
2000-01	3784	73	5044	5843	2813	1036	10149	7321	3440	1418	40921
2001-02	0	91	7004	6792	2898	1285	7325	7750	2758	2457	38360
2002-03	0	110	4875	5838	1990	1839	3880	7767	571	1724	28594
2003-04	0	87	3968	3244	1162	893	4534	4681	4436	3465	26470
2004-05	0	45	7230	5569	3085	1071	7578	8576	3549	3603	40306
2005-06	0	15	5269	5892	2515	1403	8155	9881	3843	3363	40336
2006-07	0	42	7655	7676	2625	1382	7065	9135	3507	3440	42527
2007-08	1795	7	7194	5393	2695	2128	7701	7539	4298	3345	42095
2008-09	0	0	7632	9863	2460	2073	8237	9530	4258	4301	48354
2009-10	0	0	6127	5809	2915	2798	6936	10247	2141	3304	40277
2010-11	0	0	4227	3685	1035	2566	6025	9088	2115	2558	31299

औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में एच.टी. लाइनों हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

49. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पावर ग्रिड भिवाड़ी से औघोगिक क्षेत्र नीमराणा के लिये 400/220 के.वी. की एच.टी. लाइनों का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त लाइनों में विद्युत पोल लगाने में कितनी भूमि का उपयोग किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा तक कितने पोल कहां-कहां व किन-किन किसानों के किस-किस खसरा नम्बरों की भूमि में लगाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त लाइनों में लगे विद्युत पोलों में उपयोग की गई भूमि का किसानों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 220 केवी सिंगल लाइन 220 केवी जी.एस.एस. नीमराणा से 220 केवी जी.एस.एस. खुशखेडा का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो अन्ततः 400 केवी पावर ग्रिड भिवाड़ी से जुडेगी। उक्त लाइन में टावर के निर्माण हेतु कम से कम 7.0 मीटर x 7.0 मीटर भूमि तथा ज्यादा से ज्यादा 14.0 मीटर x 14.0 मीटर भूमि का उपयोग किया जाता है। परन्तु टावरों के नीचे आने वाली भूमि कृषि उपयोग में ली जा सकती है।

औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा तक 168 टावरों का कार्य किया गया है। इन टावरों को जिन किसानों के खसरा नम्बर में लगाया गया है, का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। विद्युत अधिनियम-2003 के सैक्शन-164 के तहत लाइन एवं टावरों के नीचे आने वाली भूमि का कोई मुआवजा देय नहीं है इस संबंध में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। परन्तु लाइन खींचते समय यदि फसल का नुकसान होता है तो उसका संबंधित राजस्व अधिकारी के निर्धारण के अनुसार फसल के नुकसान का मुआवजा संबंधित किसानों को दिया जाता है। उक्त लाइन के निर्माण में हुए फसल के नुकसान के एवज में दिये गये मुआवजे का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-50

(स्थगित)

महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय को आबंटित बजट

51. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एवं शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो किस-किस की?

(3) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु बजट आबंटित किया गया है?यदि हां, तो कब-कब और कितना-कितना? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर को संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा के बजट सत्र 2008-09 की अनुदान मांगों का जवाब देते समय प्रदेश में तीनों विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी ।

(2) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कालेज शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को क्रमशः सीकर, अलवर एवं भरतपुर में प्रस्तावित विश्वविद्यालयों हेतु विशेषाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था:-

1. रतनलाल मिश्रा, 2. नन्द सिंह नरूका,

3. मनरूप सिंह मीणा

तत्पश्चात वर्तमान सरकार द्वारा 1. श्री झाबरमल, 2. श्री एम.एल. असवाल एवं 3. डा. ए.के. गर्ग को नियुक्त किया गया था।

(3) जी नहीं ।

(4) वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी ।

कोटा सम्भाग के क्षतिग्रस्त बांध/तालाबों की मरम्मत

52. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा संभाग में अतिवृष्टि के कारण गत वर्ष कितने बांध एवं तालाब टूटे या क्षतिग्रस्त हुये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त तालाबों एवं बांधों की मरम्मत के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त जलाशयों के टूटने के तकनीकी कारणों की जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा बांध एवं तालाब के टूटने के कारण की जांच में दोषी पाये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग में अतिवृष्टि के कारण गत वर्ष कुल 3 बांध टूटे या क्षतिग्रस्त हुए, जिनका जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कोटा संभाग के अन्तर्गत जिला बारां के छतरपुरा बांध एवं उम्मेदसागर बांध की मरम्मत का कार्य जिला आपदा प्रबन्धन एवं सहायता से प्राप्त राशि रुपये 34.00 लाख द्वारा करवा दिया गया है एवं जिला झालावाड़ के पृथ्वीपुरा बांध की मरम्मत एवं शेष रहे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का दायित्य संबंधित संवेदक का था। जिसके विरूद्ध धारा 2 व 3 की कार्यवाही कर नये संवेदक को कार्य आबंटित किया जा चुका है जो प्रगति पर है।

(3) जी हां। छतरपुरा बांध एवं पृथ्वीपुरा बांध की जांच रिपोर्ट की प्रतियां प्रपत्र-'ब' एवं 'स' पर संलग्न है जबकि उम्मेदसागर रियासतकालीन बांध है जिसमें इस वर्ष वर्षा के दौरान स्लिपवे की चुनाई में क्षति हुई। इस क्षति हेतु कोई जिम्मेदार नहीं है।

(4) जी हां। छतरपुरा एवं उम्मेदसागर बांध टूटने के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नही है तथा पृथ्वीपुरा बांध की जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्टेट मोटर गैराज में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही

53. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कई अनियमिततायें पाई गई हैं? यदि हां, तो अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 व 2009-10 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों/ दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सामुदायिक/प्राथमिक/ उप स्वास्थ्य केन्द्र

54. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 01 जनवरी, 2004 से 31 नवम्बर, 2008 तथा 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, कितनी पीएचसी, सीएचसी नवसृजित अथवा क्रमोन्नत की गई? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीकर जिले में नेछवा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम जाजोद, लालासी व राजास में पीएचसी स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 01 जनवरी, 2004 से 30 नवम्बर, 2008 तक 84 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 110 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1025 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 537 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। विधान सभा क्षैत्रवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर संदन की मेज पर रख दी गई है।

01 अप्रेल 2011 से फरवरी 2012 तक 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी की गई है।

(2) वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

झाडोल विधान सभा क्षेत्र के सड़क मार्ग रहित ग्राम

55. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाडोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कई गांव सड़क मार्ग से नहीं जुडे हुए हैं? यदि हां, तो कितने व कितनी आबादी के?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल के अन्तर्गत 250 एवं अधिक आबादी के 7 गांव एवं 250 से कम आबादी के 74 गांव डामर सड़क से नहीं जुडे हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल जनजाति क्षेत्र की श्रेणी में है जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के 250 एवं अधिक आबादी (जनगणना वर्ष 2001) की सभी बसावटों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कुल 322 गांवों में से 315 गांव डामर सड़क से जुडे हुए हैं एवं 7 गांव डामर सड़क से जुडे हुए नहीं हैं। इन 7 गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, परन्तु इनका एलाइनमेन्ट वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन मार्गों पर डामर सड़क निर्मित नहीं की जा सकी है। इनमें से एक सड़क महाद से बेडाधर का मैटल स्तर पर मय सीडी वर्क्स का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कराया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जा चुका है एवं शेष 6 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ना मय सीडी वर्क्स निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा कराये जाने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2009 को हुई बैठक में लिया गया था। अतः इन 6 गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्रेवल स्तर तक सड़क बनाने का कार्य वन विभाग द्वारा वन पथ के नाम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। 250 से कम आबादी के 26 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 74 गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। इन 74 गांवों में से 33 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृति है एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इन कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का विभाग का लक्ष्य है, परन्तु कार्य पूर्ण कराने की समयावधि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत उक्त कार्यों हेतु श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। वर्तमान में इन सड़कों पर लगभग 40 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है।

250 से कम आबादी के शेष 41 गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति वर्तमान में नहीं है। इन गांवों को सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

फतेहगढ़ तहसील क्षेत्र (जैसलमेर) में फसल खराबे की गणना में अनियमितताएं

56. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर की तहसील क्षेत्र फतेहगढ़ में संवत् 2066 में बाजरा फसल का खराबा शत प्रतिशत रहा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संवत् में फसल कटाई में लिए गये सभी 20 प्रयोगों में खराबा शत प्रतिशत रहा? यदि नहीं, तो सभी 20 प्रयोगों की फसल खराबा रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि फसल खराबा 100 प्रतिशत रहते हुए भी 4 प्रयोगों में उत्पादन संबंधी कालम में उपज का वज़न दर्शाया गया है? यदि हां, तो खराबे के कालम में कौन सी सूचना दर्ज है?क्या खराबे के कालम में 100 प्रतिशत खराबा दर्ज है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों तथा उक्त गलती के लिए कौन जिम्मेवार है?

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(4) क्या सरकार किसानों को मुआवजे का निर्धारण फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर न कर उसे गिरदावरी में खराबे के आधार पर करवाने के लिए केन्द्र सरकार को लिखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील क्षेत्र में खरीफ संवत 2066 (2009-10) बाजरा फसल का खराबा निम्नानुसार रहा है :-

क्षेत्रफल : हैक्टर में ।

क्षेत्रफल	**सिंचित क्षेत्र**	**असिंचित क्षेत्र**	**योग**
बोया गया	79	44530	44609
खराबा	22	44530	44552
खराबा प्रतिशत में	28	100	99.87

(2) जी हां । सभी 20 फसल कटाई प्रयोगों की रिपोर्ट की छाया प्रतियां परिशिष्ट-1 पर सलंग्न हैं, जिनमें 100 प्रतिशत नुकसान दर्शाया गया है।

(3) जी हां । नुकसान की मात्रा 100 प्रतिशत दर्शाई गई है । सुखाई का विवरण कालम में दुबारा तुलाई के दिन भुट्टों की संख्या एवं उनका तौल अंकित किया है, परन्तु ज्वार, बाजरा, मक्का के भुट्टों से निकाले दानों व अन्य जिन्सों के दानों का तोल के कालम में वजन शून्य है । प्रकरण की जांच कर जिम्मेवार कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, जैसलमेर एवं राजस्व मण्डल, अजमेर को लिखा जा रहा है ।

(4) जी नहीं । वर्ष 2010-11 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य में लागू नहीं है । खरीफ 2010 से राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किए जाने का प्रावधान नहीं है ।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की उम्मेद सागर-कल्याणपुर पेयजल योजना

57. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पेयजल व्यवस्था हेतु उम्मेद सागर-कल्याणपुर-खण्ड पेयजल परियोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त परियोजना का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है व इस परियोजना हेतु सरकार द्वारा कितनी वित्तीय स्वीकृति कब-कब दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां । क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप पार्ट-तृतीय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह फरवरी, 2007 में राशि रूपये 364.93 करोड़ तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह सितम्बर, 2011 में राशि रुपये 575.46 करोड़ की जारी की गई । उक्त योजनान्तर्गत तख्तसागर से उम्मेदसागर के मध्य पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा उम्मेदसागर से समदड़ी वाया कोरना, नागाणा, बरनावा जागीर, कलावतसर तक आधारभूत संरचना कार्य (यथा पाइप लाइन, मुख्य जलाशय आदि) का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) उक्त परियोजना अन्तर्गत दिनांक 6 फरवरी, 2012 से समदड़ी शहर में आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है । योजना के अन्य पैकेजों के तहत मुख्य जलाशयों से मुख्य गांवों को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु कलस्टर पैकेज वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है।

उक्त परियोजना पर अब तक आबंटित राशि रुपये 233.00 करोड़ के विरुद्ध माह जनवरी, 2012 तक 231.07 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है । उक्त परियोजना के शेष रहे कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाकर इसे शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे ।

परिशिष्ट-अ

स्वीकृत क्षेत्रीय जल योजना उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप की अब तक की प्रगति का विवरण

योजना की पैकेजवार प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैकेज का नाम	बेसिक स्वीकृत राशि (रु. करोड़ों में)	विवरण
1	मृदा परीक्षण व सर्वे का कार्य	0.39	आवश्यकतानुसार प्रगति पर है।
2	तख्तसागर से उम्मेदसागर के मध्य रॉ वाटर पाइप लाइन का कार्य	6.97	तख्तसागर से उम्मेदसागर के मध्य 1100/600 मिलीमीटर व्यास की पाइप लाइन (4.9 किलोमीटर) बिछाने का कार्य एकल दायित्व निविदा के अन्तर्गत रु. 6.97 करोड़ का कार्यादेश दिया गया है एवं 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
3	उम्मेदसागर से समदड़ी तक आधारभूत सुविधा का कार्य	218.36	उम्मेदसागर से समदड़ी वाया (कोरना, नागाना), बरनावा जागीर, कलावतसर तक आधारभूत विकास का कार्य एकल दायित्व निविदा के अन्तर्गत रु. 219.08 करोड का कार्यादेश दिनांक 17.7.2008 को दिया गया था। कार्यादेश के तहत कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज में किये गये मुख्य कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैकेज का नाम	बेसिक स्वीकृत राशि (रु. करोड़ों में)	विवरण
			1. पाइप लाइन

क्र.सं.	साईज (मिलीमीटर)	प्रकार	लम्बाई (किलोमीट)
1	1000	एम.एस.	18.0
2	900	एम.एस.	78.9
3	450	डी.आई.	8.2
4	400	डी.आई.	6.9
5	300	डी.आई.	7.5
6	200	डी.आई.	11.3

2. मुख्य जलाशय

क्र.सं.	स्थान	क्षमता (किलोमीटर)
1	कोरना	1650
2	नागाणा	1000
3	कलावतसर	950
4	बरनावा जागीर	2500
5	समदडी भाखरी	700

क्र. सं.	पैकेज का नाम	बेसिक स्वीकृत राशि (रु. करोड़ों में)	विवरण
			उक्त सभी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर मुख्य जलाशयों में पानी पहुंचाया जा चुका है तथा समदडी शहर में आंशिक जलापूर्ति शुरू की जा चुकी है।
4	मुख्य जलाशय से मुख्य गांवों तक मूलभूत सुविधा का कार्य	189.29	समस्त 180 गांवों (सर्वे उपरांत 10 गांव और जुड गये हैं) का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पैकेज तकनीकी स्वीकृति पूर्व जांच की प्रक्रिया में है।
5	मुख्य गांवों से अन्य ढाणियों में पाइप लाइन	42.12	पैकेज 4 के स्वीकृति के पश्चात् कार्य शुरू किया जाना प्रस्तवित है।
6	समदडी शहर में पाइप लाइन	2.58	प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
7	प्रचार-प्रसार की गतिविधियां	4.60	पैकेज 4 के स्वीकृति के अनुरूप कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

मनरेगा कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती

58. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर एम.बी.ए. उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की भर्ती की जायेगी? यदि हां, तो कितने व किन-किन पदों पर कब तक? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी? यदि हां, तो किसके माध्यम से व कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा आधार पर एम.बी.ए. उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को संविदा आधार पर अनुबन्धित करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिनांक 29.04.2011 एवं 29.06.2011 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। राज्य की समस्त 248 पंचायत समितियों में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 1 पद पर, इस प्रकार कुल 248 पदों पर संविदा आधार पर कार्मिक अनुबन्धित किये जायेंगे। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.04.2011 एवं 17.06.2011 के अनुसार संविदा पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, अतः सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा अनुबन्ध पर भी स्वतः रोक है।

(2) जी नहीं। उक्त पदों पर सीधी भर्ती नही की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद की सेवाओं हेतु संविदा आधार पर अनुबन्ध किये जाने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.04.2011 एवं 17.06.2011 के अनुसार संविदा पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संविदा अनुबन्ध पर भी स्वतः ही रोक है।

परिशिष्ट–अ

सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा आधार पर स्वीकृत पद

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत पद
1	अजमेर	8
2	अलवर	14
3	बांसवाड़ा	8
4	बारां	7
5	बाड़मेर	8
6	भरतपुर	9
7	भीलवाड़ा	11
8	बीकानेर	6
9	बून्दी	5
10	चित्तौडगढ़	11
11	चूरू	6
12	दौसा	5
13	धौलपुर	4
14	डूंगरपुर	5
15	श्रीगंगानगर	8
16	हनुमानगढ़	7
17	जयपुर	13
18	जैसलमेर	3
19	जालौर	8
20	झालावाड़	6
21	झुन्झुनूं	8
22	जोधपुर	10
23	करौली	5
24	कोटा	5

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत पद
25	नागौर	11
26	पाली	10
27	राजसमंद	7
28	सवाईमाधोपुर	5
29	सीकर	8
30	सिरोही	5
31	टोंक	6
32	उदयपुर	11
33	प्रतापगढ़	5
		248

राजकीय विधि महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण

59. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सभी राजकीय विधि महाविद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं? क्या सरकार इनके भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी? प्रत्येक महाविद्यालय अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों हेतु नवीन पद सृजित कर उन्हें भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। 2 राजकीय विधि महाविद्यालयों के स्वयं के भवन हैं। 5 राजकीय विधि महाविद्यालयों के भवन हेतु भूमि चिन्हित है तथा 8 राजकीय विधि महाविद्यालयों के भवन हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है।

8 राजकीय विधि महाविद्यालयों-बीकानेर, सीकर, अलवर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर के भवन निर्माण हेतु राशि रु 16 करोड़ स्वीकृत किये जा चुके हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जी हां। राज्य में संचालित 15 राजकीय विधि महाविद्यालयों हेतु प्राचार्यों के 15 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 8 राजकीय विधि

(उच्च शिक्षा मंत्री)

महाविद्यालयों हेतु वरिष्ठ लिपिक के 8 पद स्वीकृत किये गये हैं। उपरोक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नगर विधान सभा क्षेत्र में नहरों की मरम्मत पर व्यय राशि

60. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग सहित) में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कौन से बांध व नहरें आती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? मनरेगा के तहत गत तीन वर्षों में उक्त बांधों व नहरों पर कितनी-कितनी राशि कहां-कहां स्वीकृत की गई व कितनी राशि का उपयोग हो चुका है एवं कितना कार्य हुआ और कितना कार्य बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नहरों में पानी की आवक क्षमता क्या है? क्या यह सही है कि Slit के कारण डीग एस्केप व गुडगांव कैनाल का पानी नहीं लिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने इस हेतु क्या उपाय किये और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग सहित) में जल संसाधन विभाग (सिंचाई विभाग) के अन्तर्गत 10 बांध एवं सीकरी बांध से निकलने वाली 28 नहरें आती हैं इसके अलावा गुडगांव नहर एवं डीग एस्केप भी है। बांध व नहरों की सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में सभी बांध व नहरों की स्थिति संतोषजनक है। महानरेगा के तहत गत तीन वर्षों में उक्त बांधो व नहरों पर कुल राशि रुपये 418.87 लाख स्वीकृत हुई जिसके विरुद्ध राशि रुपये 26.62 लाख व्यय किया गया। स्वीकृत राशि व व्यय राशि के अनुसार कुल 6.36 प्रतिशत कार्य हुआ एवं 93.64 प्रतिशत कार्य किया जाना शेष है। कार्यवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(3) सभी 28 नहरों, गुडगांवा नहर एवं डीग एस्केप की कुल आवक क्षमता 1750 क्यूसेक्स है।

जी नहीं।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये)

निःशुल्क दवा वितरण योजनान्तर्गत उपलब्ध दवाएं

61. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नि:शुल्क दवा वितरण का कार्य कब से एवं कितने अस्पतालों में शुरू किया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नि:शुल्क दवा वितरण योजनान्तर्गत कितनी दवाओं को आमजन को उपलब्ध कराया जाना तय किया गया एवं वर्तमान में कितनी दवाएं सरकारी केन्द्रों पर वितरित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नि:शुल्क दवा वितरण योजना लागू करने के उपरान्त भी मरीजों को बाजार से स्वयं के खर्चे पर दवा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण का कार्य 2 अक्टूबर, 2011 से राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रारम्भ किया गया है। जिसके तहत राज्य के 108 चिकित्सालयों, 196 डिस्पेन्सरी, 380 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 1528 ग्रामीण एवं 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 एडपोस्ट (शहरी), 11487 उप स्वास्थ्य केन्द्रों मे उक्त योजना शुरू की गई है जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित 31 अस्पतालों में भी उक्त योजना शुरू की गई है। नामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली लगभग 400 दवाइयां आमजन को उपलब्ध करवाया जाना तय किया गया है।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन के द्वारा वर्तमान में 293 दवाईयां व 42 सर्जिकल सूचर्स उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

इसके अतिरिक्त लगभग 79 दवाइयों के क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं। जो शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगी, सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाइयां ही वितरित की जा रही हैं। इन दवाओं के माध्यम से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक रोगियों का उपचार सम्भव है। इसके अतिरिक्त दवाइयों के स्थानीय क्रय हेतु 10 प्रतिशत का बजट चिकित्सालय स्तर पर दिया गया है। जिससे और दवाइयां ली जा सकें। यदि चिकित्सक द्वारा नि:शुल्क दवाओं के अतिरिक्त अन्य दवायें लिखी जाती हैं तो वे दवाइयां लाइफलाइन ड्रग स्टोर से बाजार से कम मूल्य पर क्रय की जा सकती हैं।

(विवरण व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

माण्डण-कान्हावास (बहरोड़) सड़क निर्माण कार्य की जांच

62. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बहरोड़ में माण्डण हरियाणा बोर्डर से कान्हावास तक सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाई बढ़ाने हेतु स्वीकृति जारी हुई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो इसकी जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है?

(3) उक्त अधिकारियों द्वारा कब-कब उक्त सड़क की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गादोज-तसींग-बहरोड़-माण्ढण-परतापुर-रामचन्द्रपुरा सड़क (एम.डी.आर.-78) के कि.मी. 31/0 (कान्हावास) से 40/400 (माण्ढण हरियाणा बोर्डर) तक चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 10-08-2011 द्वारा राशि रुपये 816.41 लाख की स्वीकृति केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उक्त कार्य दिनांक 21.01.2012 को ही प्रारम्भ हुआ है एवं इसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री एवं कार्य की प्रगति के दौरान कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु सहायक अभियन्ता उपखण्ड शाहजहांपुर, अधिशासी अभियन्ता खण्ड बहरोड़, अधिशासी अभियन्ता गुण नियंत्रण खण्ड अलवर, अधीक्षण अभियन्ता

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वृत अलवर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सम्भाग जयपुर द्वितीय एवं मुख्य अभियन्ता (एन.एच.) अधिकृत हैं।

(3) उक्त सड़क की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई जांच का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(प्रतिया व विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये)

परम्परागत बीज संरक्षण के लिए बीज बैंक की स्थापना

63. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के परम्परागत बीजों के संरक्षण के लिये समुदाय आधारित बीज बैंक बनाया हुआ है? यदि हां, तो कहां -कहां और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब राज्य में उक्त बीज बैंक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नही । स्थानीय किस्मों को संरक्षित करने हेतु उसी क्षेत्र में संग्रहित करने की दृष्टि से राजस्थान में कहीं भी समुदाय आधारित बीज बैंक स्थापित नहीं है । स्थानीय किस्मों को संरक्षित करने के लिये विभिन्न फसलों के बीजों को एकत्रित कर देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित राष्ट्रीय फसल अनुसंधान निदेशालयों द्वारा एक जगह पर रखरखाव किया जा रहा है । उपरोक्त के अलावा नेशनल ब्यूरो आफ प्लान्ट जेनेटिक रिर्सोसेज (एन.वी.पी.जी.आर.) नई दिल्ली पर भी इन सबके बीजों को अनुसंधान की दृष्टि से सुरक्षित रखा हुआ है ।

(2) परम्परागत बीजों के संरक्षण के लिये समुदाय आधारित बीज बैक बनाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रायोगिक तौर पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा कृषि नवाचार परियोजना के तहत जैव विविधता संरक्षण का कार्य लघुस्तर पर वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में एन.आर.डी.डब्ल्यू.एस.पी. योजना के तहत लाभान्वित ग्राम

47. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में एन. आर. डी. डब्ल्यू. एस. पी. योजनान्तर्गत ट्यूबवैल मय सिंगल पम्पसैट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कौन-कौन से गांव लाभान्वित हुए हैं? लाभान्वित गांव, स्थान एवं लागत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में वंचित गांवों को उक्त योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 33 जिलों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति की 1757 एवं अनुसूचित जनजाति की 1112 बाहुल्य बस्तियों में सिंगल फेज पम्प सैट मय नलकूप व अन्य योजनाओं से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्यों के विरूद्ध माह जनवरी, 2011 तक क्रमशः एवं 1163 एवं 803 बस्तियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है । शेष बस्तियों को वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक लाभान्वित करने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे । जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के 6 ग्रामों की अनुसूचित जाति की 3 बस्तियों में भू-जल की उपलब्धतानुसार 3 सिंगल फेस पम्प सैट मय नलकूप तथा समस्त 6 बस्तियों में 9 वर्षा जल संग्रहण टांका, 14 स्थानों पर कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण कार्य एवं 23 स्थानों पर स्वच्छता हेतु सुधारात्मक कार्य स्वीकृत किये गये हैं । 3 सिंगल फेस नलकूप निर्मित कर चालू कर दिये गये हैं तथा शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । उक्त समस्त कार्य मार्च, 2012 तक पूर्ण करना लक्षित है । वांछित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी हां । विधान सभा क्षेत्र, नसीराबाद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य की क्रमश: 20 एवं 4, इस प्रकार कुल 24 बस्तियों में से उक्तानुसार 6 बस्तियों को मार्च, 2012 तक लाभान्वित करना लक्षित है । शेष बस्तियों हेतु वार्षिक कार्य योजना बनाकर आगामी वर्षों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्राथमिकता पर इनको लाभान्वित किया जावेगा।

परिशिष्ट-अ

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य के समस्त जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्तियां

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियां		अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियां	
		लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां
1	अजमेर	242	38	63	28
2	अलवर	87	55	80	76
3	बांसवाड़ा	0	0	0	0
4	बारां	8	4	39	18
5	बाड़मेर	42	93	20	45
6	भरतपुर	36	1	24	1
7	भीलवाड़ा	113	87	115	54
8	बीकानेर	27	24	0	0
9	बून्दी	10	9	47	12
10	चित्तौडगढ़	0	32	0	24
11	चूरू	56	20	0	0
12	दौसा	43	68	66	118
13	धौलपुर	16	5	9	4
14	डूंगरपुर	3	4	50	71
15	श्रीगंगानगर	77	40	0	0
16	हनुमानगढ़	8	4	0	0

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियां		अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियां	
		लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां
17	जयपुर	33	31	36	102
18	जैसलमेर	65	8	25	1
19	जालौर	60	25	25	18
20	झालावाड़	13	7	18	34
21	झुन्झुनूं	2	3	5	0
22	जोधपुर	186	262	62	42
23	करौली	62	10	120	10
24	कोटा	14	9	5	22
25	नागौर	255	145	4	1
26	पाली	75	42	23	13
27	प्रतापगढ़	0	0	0	0
28	राजसमंद	7	25	19	12
29	सीकर	48	32	9	7
30	सिरोही	40	30	3	2
31	सवाईमाधोपुर	38	6	15	7
32	टौंक	80	34	80	18
33	उदयपुर	11	10	150	63
	कुल योग	**1757**	**1163**	**1112**	**803**

परिशिष्ट-ब

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में अनुसूचित जाति बस्तियों के लाभान्वयन संबंधी विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	मजरा/ढाणी का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण				कुल लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
				सिंगल फेस	टांका	कृत्रिम भूजल पुनर्भरण	स्वच्छता हेतु कार्य		
1	बुधवाडा	बुधवाडा	भोंपो की ढाणी	1	1	2	3	18.77	प्रगतिरत कार्यों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्ण करना लक्षित है।
2	लीडी	लीडी	कनोडा का बाडिया	1	1	2	2	11.43	
3	जेठाना	जेठाना	रेल्वे क्वार्टर		1	2	3	8.13	
4	भटसूरी	भटसूरी	हनुवंतपुरा		2	2	5	14.86	
5	लीडी	लीडी	गनगरा	1	2	4	3	17.51	
6	करनौस	करनौस	रतनगढ़		2	2	7	18.42	
			कुल योग	**3**	**9**	**14**	**23**		

भूमि अवाप्ति, पुनर्वास एवं पुनः स्थापिन नीति

48. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति पुनर्वास एवं पुनःस्थापिन नीति 2011 बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु नीति बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न संख्या-49

(स्थगित)

अलवर जिले में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

50. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में गोचर (चरागाह) भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो राजस्व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गोचर भूमि पर किस-किस अतिक्रमी द्वारा कब-कब से अतिक्रमण किया हुआ है? राजस्व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गोचर भूमि गोधन के चारे के लिये अतिक्रमण मुक्त एवं सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त जिले के किस-किस राजस्व ग्राम में कितनी-कितनी गोचर भूमि अतिक्रमियों से मुक्त करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चरागाह भूमि को स्थाई रूप से अतिक्रमण मुक्त रखने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही करने की योजना बनाने विचार एवं मंशा रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में गोचर (चरागाह) भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण की राजस्व ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) अलवर जिले में गोचर (चरागाह) भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण की राजस्व ग्रामवार सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। पिछले तीन वर्षों में जो गोचर भूमि अतिक्रमियों से मुक्त कराई गई है उसकी ग्रामवार सूची संलग्न है।

(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने व अतिक्रमी के विरूद्व सजा के पर्याप्त प्रावधान है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की विशेष आडिट

51. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विशेष आडिट कराई गई थी?यदि हां, तो विशेष आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विशेष आडिट रिपोर्ट में प्रदेश में उक्त मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवासीय सुविधाओं, ड्रग वेयर हाउस निर्माण, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटरों की खरीद, लेप्रोस्कोप, लेप्रोकटर की मरम्मत, वार्षिक रख-रखाव, स्वयंसेवी संस्थाओं को विभिन्न कार्यों के आवंटन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डीजल जेनरेटर सैट खरीद, जरूरत से ज्यादा दवाइयां और उपकरणों की खरीद सहित कई मामलों में अनियमितता की जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई तथा इससे कितनी राशि की हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विशेष आडिट में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितता में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माह जून, 2005 से दिसम्बर, 2006 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विशेष आडिट स्टेट हैल्थ सोसायटी का किया गया था। अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। विशेष आडिट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित प्रकरणों में निम्नानुसार अनियमित राशि बताई गई है:-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवासीय सुविधा व ड्रग वेयर हाउस के निर्माण कार्यों की निविदाओं की अतार्किक स्वीकृति से वित्तीय भार व उन्य अनियमितताएं रूपये 523.66 लाख (पैरा सं.1)

2. ब्लड बैंक रफ्रीजरेटर्स के अनियमित क्रय से वित्तीय हानी रू. 112.78 लाख (पेरा सं. 2)

3. लैप्रोस्कोप/लैप्रोकेटर की मरम्मत वार्षिक रख-रखाव व स्पयेर पार्टस के क्रय संबंधी अनियमितताएं रू. 138.91 लाख (पैरा सं. 3)

4. गैर सरकारी संगठनों को योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो/कंसलटेन्सी के आवंटन/स्वीकृति में अनियमितताएं (पैरा सं. 4)

5. एनेस्थिसिया प्रशिक्षण हेतु मैनिक्वीन के अनावश्यक क्रय से वित्तीय हानि राशि रू. 14.83 लाख (पैरा सं.5)

6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 36 डीजल जनरेटर सेट पर अवरूद्व राशि रू. 72.59 लाख (पैरा सं. 6)

7. स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप सेवा केन्द्र/योग्य दम्पति पंजिका व अन्य प्रपत्रों के मुद्रण में अनियमितताएं रू. 1.55 लाख (पैरा सं. 7)

इस प्रकार अनुच्छेद अनुसार कुल रू. 864.32 लाख की वित्तीय अनियमितता हुई है।

(3) विशेष आडिट रिपोर्ट के अनुसार पाई गई अनियमितताओं के लिए विभाग ने श्री वीरेन्द्र मेहता, तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी को दोषी माना है। दोषी अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियमानुसार आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त (राजस्व) विभाग को भिजवाया जा चुका है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) दोषी पाये गये अधिकारी श्री वीरेन्द्र मेहता, तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी के विरूद्व नियमानुसार आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र तैयार किए जाकर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी (वित्त विभाग, राजस्थान सरकार) को भिजवाए जा चुके है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य के चिकित्सालयों में संचालित आपरेशन थियेटर्स में संक्रमण

52. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के चिकित्सालयों व उनमें संचालित आपरेशन थियेटर्स में बैक्टीरिया संक्रमण के लिए माइक्रोबायोलाजी टेस्ट कराये गये हैं? यदि हां, तो संबंधित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के चिकित्सालयों में संचालित आपरेशन थियेटर्स में बैक्टीरिया संक्रमण निर्धारित मात्रा से ज्यादा है? यदि हां,तो निर्धारित मानकों की तुलना में कितनी अधिक मात्रा में हैं?

(3) क्या सरकार राज्य के चिकित्सालयों व आपरेशन थियेटर्स को बैक्टीरिया संक्रमण मुक्त कराने व उनकी नियमित सफाई के लिए कोई कार्य योजना बनाकर लागू कराने का विचार रखती है? यदि हां,तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संबंधित रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिकांश आपरेशन थियेटर में बैक्टीरिया संक्रमण निर्धारित मात्रा से ज्यादा नहीं पाये गये। जिन अस्पतालों के आपरेशन थियेटर्स में बैक्टीरियल काउन्ट ज्यादा पाये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है, वहां पर दुबारा फ्यूमिगेशन किया गया। जिसके पश्चात् संक्रमण नहीं पाया गया।

आपरेशन थियेटर में 7 से 15 दिवस में नियमित रूप से फ्यूमिगेशन किया जाता है। कल्चर रिपोर्ट में बैक्टीरियल काउन्ट ज्यादा होने पर आवश्यकता अनुसार इस अवधि के बीच में भी पुन: फ्यूमिगेशन किया जाता है।

(3) जी हां। प्रोटोकाल व दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बायतू विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद

53. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बायतू में चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालय में कौन-कौन से व कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाटाडू, बायतू, कानोड़, पाटोदी व नवातला में चिकित्साधिकारी लगाने का विचार रखती है? यदि हां तो, कब तक और नहीं, तो, क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार रिक्त दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है। विधान सभा क्षैत्र बायतू के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के उक्त रिक्त पदों के अतिरिक्त शेष सभी स्वीकृत पदों पर चिकित्सक कार्यरत/पदस्थापित है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटोदी एवं नवातला में आदेश दिनांक 03.01.2012 के द्वारा क्रमशः डा. पंकज कुमार शर्मा एवं डा. दीपेन्द्र का पदस्थापन कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त चिकित्सक कार्यरत है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायतू में आदेश दिनांक 26.12.2011 के द्वारा डा. शेरसिह दडिया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाटाडू में आदेश दिनांक 03.01.2012 एवं 03.02.2012 के द्वारा क्रमशः डा. रंजना बेनीवाल एवं डा. सिद्वार्थ मेहता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड में आदेश दिनांक 03.02.2012 के द्वारा डा. मनोज शर्मा का पदस्थापन किया गया। उक्त चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है, कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार रिक्ती दिनांक सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती दिनांक
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायतू	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	30.05.2011
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	03.01.2012
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	15.06.2011
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	15.06.2011
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	01.01.2007
		नेत्र सहायक	1	01.09.1997
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाटाडू	चिकित्सा अधिकारी	1	03.02.2012
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	10.01.2012
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	10.01.2012
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड	चिकित्सा अधिकारी	1	04.01.212
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	15.06.2008
		लैब टेक्निशियन	1	10.01.2012
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सवाउ पदमसिंह	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	10.01.2012
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिडा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	18.10.2011 10.01.2012
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1.01.2007
		महिला स्वास्थ्य कार्यकता	1	10.01.2012
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाक	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	29.08.2006

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती दिनांक
		लैब टेक्निशियन	1	29.08.2006
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हीरे की ढाणी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	10.08.2011
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	10.08.2011
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	10.08.2011
		लैब टेक्निशियन	1	10.08.2011

हनुमानगढ़ जिले में कुपोषण उपचार केन्द्रों के लिए आबंटित राशि

54. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बच्चों (0-6 वर्ष) में कुपोषण की रोकथाम के लिये जिला हनुमानगढ़ के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो शहरी व ग्रामीण उपचार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में प्रारम्भ से वर्ष 2011 तक कितने कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया? उपचार किये गये कुपोषित बच्चों की केन्द्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चे एवं उनके माता -पिता को किस प्रकार की सुविधायें एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये अब तक कितनी राशि का आवंटन किया गया तथा आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि अब तक व्यय की गई?जिलेवार/केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां! जिला हनुमानगढ़ में जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ टाउन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया, रावतसर एवं नोहर में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये है। उक्त समस्त उपचार केन्द्र शहरी क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण उपचार केन्द्र नहीं खोले गये है।

(2) उक्त कुपोषण केन्द्रों में प्रारम्भ से लेकर माह दिसम्बर, 2011

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

तक कुल 160 कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा चुका है। उपचार किये गये कुपोषित बच्चों का केन्द्रवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान नाम	कुल उपचार किये गये कुपोषित बच्चों की संख्या
1.	राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़	143
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर	0
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया	17
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर	0
		160

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चे एवं उसके साथ रूकने वाले संरक्षक (माता) को रू. 30/- प्रतिदिन तथा बच्चे को प्रतिदिन दिन में तीन बार पोषाहार दिया जाता है। बच्चों को इलाज के दौरान समस्त चिकित्सा सुविधाऐं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

(4) उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माह दिसम्बर 2011 तक आबंटित राशि एवं व्यय की गई राशि का केन्द्रवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान नाम	कुल आवंटित राशि	कुल व्यय राशि
1.	राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़	1990000.00	996406.00
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर	185000.00	0.00
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया	185000.00	29070.00
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर	185000.00	73869.00 (बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यय)
	कुल योग	**2545000.00**	**1099345.00**

चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा की गई हड़ताल के दौरान मृत्यु

55. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राज्य के किन-किन राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा कितने-कितने दिवसों की हड़ताल किन कारणों से की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हड़ताल की अवधि के दौरान किन-किन चिकित्सालयों में कितने पुरूष, महिला एवं बच्चों की मृत्यु हुई? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवधि में जिन मरीजों की मृत्यु हुई है, उन्हें मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को हड़ताल पर जाने से रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि के दौरान किन-किन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अवधि के दौरान किन-किन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन की क्या-क्या मांगें थी तथा सरकार द्वारा उक्त यूनियनों के साथ क्या समझौते किये गये? उक्त यूनियनों के द्वारा समय-समय पर दिये गये मांग पत्र व समझौते की प्रति तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों में गत 3 वर्षों में चिकित्सकों द्वारा की गई हडताल का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

राजस्थान राज्य सेवारत चिकित्सक संघ के आव्हान पर राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में सेवारत चिकित्सकों द्वारा केन्द्र के समान वेतनमान, पदोन्नति, एनपीए, 20 वर्ष की राज्य सेवा अवधि पर पूर्ण पेन्शन देने तथा सेवारत चिकित्सकों हेतु पृथक कैडर भत्ते इत्यादि सहित अन्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लम्बित मांगों के संबंध में विगत तीन वर्षो में की गई हड़ताल का चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्त सभी राजकीय चिकित्सालयों के 173 चिकित्सक तथा 13887 पैरामेडिकल स्टाफ दिनांक 09.04.2011 से 19.04.2011 तथा 19.12.2011 से 25.12.2011 तक संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने, नियमित होने तक राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध ईकाई एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई के बढ़े हुए मानदेय के अनुपात में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी, वंचित संवर्गो को ग्रामीण भत्ता व हार्ड डयूटी भत्ता, अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप 10/20/30 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का भुगतान, संविदा कर्मियों के विरूद्व दर्ज मुकदमे वापस लेने, प्रतिवर्ष बांड भरवाया जाना बन्द करने, स्थानान्तरण आदि की उचित नीति बनाने सम्बन्धी मांगों के कारण हडताल की गई।

(2) मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों की सूचना परिशिष्ट -स पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ चिकित्सालयों में हडताल की अवधि के दौरान हुई मृत्युओं का चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। जिन मरीजो की मृत्यु हुई है वे गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे मुआवजा दिये जाने का कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। उक्त अवधि में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं में चिकित्सकों द्वारा सामूहिक अवकाश लेने एवं सामूहिक त्याग पत्र दिये जाने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिणामस्वरूप जन समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करने की परिस्थितियों के मध्यनजर राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृह (ग्रुप-9) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह-9/88 दिनांक 20.12.11 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया था। इस अधिसूचना के क्रम में राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृह (ग्रुप-9) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.20 (2)गृह-9/88 दिनांक 20.12.11 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं में सामूहिक अवकाश लेने एवं त्याग पत्र दिये जाने को आगामी तीन माह तक के लिये प्रतिषेध घोषित किया गया है, जारी अधिसूचना एवं आदेशों की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

सेवारत चिकित्सकों की अधिकांश मागें जो उचित एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत थी, उन्हें हड़ताल पूर्व ही लागू किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की मांगों के प्रति राज्य सरकार सावचेत व संवेदनशील है। इन पर नियमानुसार उचित कार्यवाही प्रक्रियारत है।

(5) सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल की अवधि में चिकित्सा महाविधालय कोटा में डा. अजय जौहरी चिकित्सा अधिकारी को पुलिस द्वारा रेस्मा के तहत गिरफ्तार किया गया और चिकित्सकों के मामले में राज्य स्तर पर गठित की गई मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय विचाराधीन है।

पुलिस विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार गिरफ्तार कर चिकित्सकों एवं पेरामेडिकल स्टाफ के विरूद्व की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 65 चिकित्सकों को राज्य सेवा से निलम्बित किया गया, तथा 12 चिकित्सकों को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-र पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा दिनांक 9 अप्रेल, 2011 से 19 अप्रेल, 2011 तक की गई हड़ताल के दौरान दिनांक 11.04.2011 को पुलिस द्वारा एनआरएचएम के सर्व श्री रंग राव पुत्र साधुराम जीएनएम, सत्यवीर पुत्र काशीराम जीएनएम, अशोक कुमार पुत्र भगवान सहाय कम्प्यूटर ऑपरेटर, लियाकत पुत्र श्री मोहम्मद खान जीएनएम, दीपक पुत्र जालाराम जीएनएम, श्री कान्त पुत्र शैतान जीएनएम, लोकेश पुत्र शान्ती लाल लेखाकार, श्याम सुन्दर पुत्र भैरू लाल जीएनएम, राहुल पुत्र घीसा राम जीएनएम, राजेन्द्र स्वर्णकार पुत्र श्री बालमुकुन्द जीएनएम तथा रतनसिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह जीएनएम कुल 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। इस पर पुलिस विभाग द्वारा आई.पी.सी. की धारा 322,353,147,186,188,152 तथा 3 पीडीपी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये जो कि न्यायालय में विचाराधीन है । जबकि इन कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति को अन्य कर्मचारियों के साथ अवकाश में परिवर्तित किए जाने के आदेश संख्या 996 दिनांक 23.05.2011 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

(6) राजस्थान राज्य सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र/ ज्ञापन तथा इन पर सरकार द्वारा किये गये समझौते/कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ल पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विभिन्न नर्सेज एवं पैरामेडिकल एसोसियेशन से प्राप्त ज्ञापनों पर राज्य सरकार/निदेशालय स्तर से कोई समझौता नहीं हुआ है।

नर्सेज एसोसियेशन से प्राप्त ज्ञापनों के संबंध में समय-समय पर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर एवं माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई।

प्राप्त ज्ञापनों पर राज्य सरकार/विभाग के स्तर पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन हैं। प्राप्त मांगपत्र/ज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट -व पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों/पैरामेडिकल कर्मचारियों की मुख्य मांग नियमितिकरण से सम्बन्धित थी। इन पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.04.2011, 28.11.2012, 23.12.2011 तथा 26.12.2011 को कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आयोजित कर निर्णय लिये गये। इनकी मांगों के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-श पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोयला में चिकित्सालय की स्थापना

56. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत सोयला में चिकित्सालय नहीं है? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम सोयला पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में ग्राम सोयला में नियमानुसार/गुणावगुण/आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र

57. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में गत तीन वर्षों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुये? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत नांद, दूदाबेरी, सांजटा एवं बेरीवाला तला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पहाड़ी एवं रेगिस्तानी एरिये में प्राथमिकता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वित्तीय वर्ष 2009-2010 से 31 जनवरी, 2012 तक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत/क्रमोन्नत हुये हैं। स्वीकृत/ क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम विधान सभा क्षेत्रवार निम्न प्रकार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
जैसिन्धर स्टेशन (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत)	शिव
कानासर	शिव
हीरे की ढ़ाणी	बायतू
बिजराड	शिव

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम नांद एवं दूदाबेरी पंचायत समिति बाड़मेर तथा ग्राम साजटा एवं बेरीवाला तला पंचायत समिति सिणधरी के अन्तर्गत आते है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में नियमानुसार/गुणावगुण/आवश्यकतानुसार पंचायत समिति बाड़मेर एवं सिणधरी के उक्त ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में नियमानुसार/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेगें।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

58. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में वर्तमान में किस-किस पद्धति के कितने-कितने चिकित्सालय कहां-कहां पर कार्यरत हैं और उक्त चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के कब से स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) उक्त चिकित्सालयों में कितने पद चिकित्सकों/नर्स/कम्पाउण्डरों आदि के कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रामगंज जयपुर स्थित डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल में बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत आने वाले ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों के नाम एवं उनमें स्टाफ के स्वीकृत पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-अ पर दर्शाये गये सभी चिकित्सा संस्थान लगभग 25 वर्ष पुरानी है, जिनमें से चौड़ा रास्ता पुरानी बस्ती, रामगंज आदि 50 वर्ष पुरानी है। इसलिए स्वीकृत पदों की स्वीकृति दिनांक दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का एक औषधालय चौकड़ी तोपखाना देश जयपुर में कार्यरत है। जिसमें चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 1-1 पद स्वीकृत है। उक्त औषधालय वर्ष 2006 से स्वीकृत है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक औषधालय तोपखाना देश, जयपुर में संचालित है। जिसमें चिकित्सक का 1 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 2 पद एवं परिचारक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का 1 पद स्वीकृत है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 2 चिकित्सालय संचालित है। जिसमें स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम			
	वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक/ आयुर्वेदिक चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर	कनिष्ठ लिपिक	परिचारक
लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर	07	15	01	06
पुरानी बस्ती, (गणगौरी बाजार) जयपुर	01	01	-	01

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत आने वाली ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया दिया है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत आने वाले होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के औषधालयों में कोई पद रिक्त नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत आने वाले आयुर्वेदिक औषधालय, लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर में नर्स/कम्पाउण्डर के 2 पद दिनांक 01.06.2011 एवं 01.08.2011 से रिक्त है।

(3) वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतः वित्तीय प्रावधान की गणना नहीं करायी गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के नवसृजित ग्रामों हेतु सड़कें

59. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में वर्ष 2001 के बाद नव सृजित राजस्व गांवों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) जिला सीकर में वर्ष 2001 के बाद कितने राजस्व गांवों का गठन हुआ और अब तक सड़क से नहीं जुड़े हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सीकर में सड़क मार्ग से 500 मीटर से कम दूरी के कितने राजस्व ग्राम पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अपने फण्ड से पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत नहीं जुड़ पाये 500 मीटर से कम दूरी के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि वर्ष 2001 के बाद घोषित नये राजस्व गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़ने का प्रावधान नहीं है।

(2) जिला सीकर में वर्ष 2001 के बाद घोषित नये राजस्व गांव जो आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाये है का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट -1 पर प्रस्तुत है।

(3) जिला सीकर में 500 मीटर से कम दूरी के जो राजस्व ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों से नहीं जुड़ पाये है की विधान सभा वार सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। ऐसे ग्रामों को सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के कोटकासिम क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

60. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला अलवर के बीबीरानी से कोटकासिम बोलनी हरियाणा राज्य की सीमा तक कोटकासिम से औद्योगिक क्षेत्र खुशखेडा व खैरथल से हरसौली, बीबीरानी जौडिया भौंकर गेलपुर तक की डामर की सडकों का चौड़ाईकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। अलवर जिले की बीबीरानी-कोटकासिम-बोलनी सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(एम.डी.आर.) के हरियाणा राज्य की सीमा तक 20.00 कि.मी. लम्बाई के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्तरराज्यीय सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत दी गई है। भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कोटकासिम से औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा (12.00 कि.मी.) एवं खैरथल से हरसौली-बीबीरानी-जौडिया-भौकर-गैलपुर (42.50 कि.मी.) तक की डामर सड़कों का चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

ढाणियों एवं खेतों में बसे कृषकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु नीति

61. श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों व खेतों में बसे किसानों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त ग्रामीण क्षेत्रों की ढाणियों व खेतों में बसे किसानों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के मापदण्ड राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्देशित "विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन 2004" में निर्धारित किये गये हैं जिसके संबंधित उपबंधों की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में घरेलू कनेक्शन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार दिए जा रहे हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकृत गांव व ढाणियों व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों एवं ढाणियों को विद्युतीकृत कर विनियामक आयोग द्वारा आदेशित सामान्य दर के अनुसार कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अविद्युतिकृत गैर आबादी क्षेत्र में "स्व वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकृत ढाणियां व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जहां स्वीकृत है, उनमें विद्युतीकरण के साथ सामान्य दर पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

खेतों में बसे किसानों को घरेलू कनेक्शन "स्व वित्त पोषित योजना" के तहत दिए जा रहे हैं।

विद्युतीकृत ग्राम व ढाणियों में बीपीएल परिवारों को घरेलू कनेक्शन नि:शुल्क दिए जा रहे हैं।

(4) अविद्युतीकृत ढाणियों अथवा खेतों में बसें किसानों को "स्व वित्त पोषित योजना" के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

प्रपत्र 'अ'

विद्युतीकृत ग्रामों में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के मापदण्ड

विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन

1. विद्युत आपूर्ति चाहने वाला परिसर का स्वामी या कब्जेदार ऐसी परिसर में विद्युतापूर्ति के लिए संबंधी उपखण्डाधिकारी को आवेदन कर सकता है। आवेदक व निगम बीच ऐसी आपूर्ति हेतु एक अनुबंध भी होगा।
2. नियमित व अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक व निगम बीच ऐसी आपूर्ति हेतु एक अनुबंध भी होगा।
3. आवेदक उसके आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क भी जमा करवायेगा यदि वह निगम से विद्युत लाईन व विद्युत संयंत्र भी लगवाना चाहता है तो उसे भाग 2 के मद की आपूर्ति अनुसार ऐसी आपूर्ति दिए जाने हेतु निगम द्वारा काम में ली जाने वाली ऐसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र के व्यय भी जमा कराने होंगे। जहां आवेदक विद्युत लाइन भी संयंत्र उपलब्ध करवाता है तो वह ऐसे व्यय का केवल 15 प्रतिशत

पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में विद्युत लाइन तथा विद्युत संयंत्र की प्रति जमा करायेगा।

4. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ भाग 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति की राशि भी निम्न के लिए जमा करावएगा :

अ. आपूरित विद्युत तथा

ब. निगम द्वारा लगाए जाने वाले मीटर

5. आवेदन के साथ आवेदक की अधिष्ठापना के बारे में विद्युत निरीक्षक द्वारा विहित किया गया प्रपत्र 'एल' में, एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा।

6. जहां किसी परिसर को विद्युत आपूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति की परिसर सर्विस लाइन खींचने के लिये उपयोग में ली जानी है या उसकी परिसर के ऊपर से होकर गुजरती है अथवा उसकी परिसर में होते हुए भूमिगत सर्विस लाइन बिछानी है तो आवेदक अपने आवेदन के साथ ऐसे व्यक्ति की सहमति संलग्न करेगा।

7. आवेदन का प्रपत्र निगम द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा या इसे निगम की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

8. आवेदन राजस्थान सरकार द्वारा विहित मूल्य के न्यायेत्तर मुद्रांक वर्तमान मूल्य 10/- रु. का किया जाएगा। आवेदन न्यायेत्तर मुद्रांक पर न किए जाने की दशा में, एक न्यायेत्तर मुद्रांक निम्नानुसार विधिवत पृष्ठांकन सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

''यह न्यायेत्तर मुद्रांक श्री/श्रीमती/कु./मै...................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री........................निवासी...................;के नाम............... श्रेणी में विद्युत कनेक्शन के लिए मुद्रांक शुल्क के प्रति संलग्न किया जाता है।''

9. आवेदक आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।

10. यदि आवेदन पत्र किसी भी पहलू से अपूर्ण पाया गया है तो निगम, ऐसी कमी के आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस के अन्दर-अन्दर सूचित करेगा।

प्रपत्र 'अ'

विविध प्रभारों के मापक्रम

आवेदन शुल्क घरेलू कनेक्शन

सिंगल फेज	200/-
एलटी थ्री फेज	500/-

1. विद्युत लाईन/संयंत्र उपलब्ध करवाने तथा वितरण मेन्स एवं/या सर्विस लाइन 500 मीटर तक के विस्तार के लिए व्यय :

अ. आवेदन के साथ जमा करने वाली राशि

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में	700/-
ग्रामीण आबादी क्षेत्र	1500/-

राजसमंद एवं रेलमगरा तहसील में आवासीय एवं कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति

62. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला राजसमंद की तहसील राजसमंद एवं रेलमगरा में आवासीय एवं कृषि के लिए विद्युत आपूर्ति एवं कटौती के लिए समयावधि घोषित की गई है? यदि हां, तो पंचायतवार उसके आपूर्ति का क्या समय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सर्दी के मौसम में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति रात्रि के चौथे प्रहर में करने से सिंचाई में किसानों को होने वाली कठिनाइयों के प्रति निगम के अधिकारी एवं सरकार सजग है? यदि हां, तो इनके निवारण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला राजसमन्द मुख्यालय पर घरेलू कार्य हेतु 21 घण्टे विद्युत आपूर्ति/3 घण्टे विद्युत कटौती की जा रही है। रेलमगरा तहसील मुख्यालय पर घरेलू कार्य हेतु 20 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति एवं 4 घंटे विद्युत कटौती की जा रही है। राजसमन्द तहसील एवं रेलमगरा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायतों में वर्तमान में सायं 6 बजे से प्रात: 7 बजे तक 13 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त दिन में कृषि ब्लॉक समय में 6 घण्टे घरेलू विद्युत सप्लाई भी होती है।

कृषि कार्य के लिए उक्त दोनों तहसीलों की सभी पंचायतों में ब्लाकवार 6 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

पंचायतवार ब्लाकवार विद्युत आपूर्ति का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 6-6 घंटे के 4 ब्लाकवार विद्युत आपूर्ति की जा रही है ब्लाक का साप्ताहिक रूप से क्रम बदला जाता है। जिससे प्रति सप्ताह रात्रि के ब्लॉक को दिन में परिवर्तित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

तहसील राजसमन्द

प्रपत्र-अ

क्र. सं.	ग्राम पंचायत सूची	कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति समय					
		3.11.2011 तक	4.11.2011 से 13.11.11 तक	14.11.11 से 2.10.12 तक	2.1.12 से 12.10.12 तक	13.1.12 से 24.1.12 तक	25.1.12 से आज दिनांक तक
1.	मूण्डोल	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
2.	सांगठकलां	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
3.	भाटोली	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	18 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
4.	धांयला	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
5.	फियावडी	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
6.	पिपलांत्री कलां	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
7.	साकरोदा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
8.	एमडी	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
9.	पिपली आचार्या	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
10.	बोरज	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
11.	फरारा	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
12.	राज्यावास	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
13.	बामन्टूवाडा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक

क्र. सं.	ग्राम पंचायत सूची	कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति समय					
		3.11.2011 तक	4.11.2011 से 13.11.11 तक	14.11.11 से 2.10.12 तक	2.1.12 से 12.1.12 तक	13.1.12 से 24.1.12 तक	25.1.12 से आज दिनांक तक
14	महासतियों की मादडी	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
15	पसून्द	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
16	सुन्दरचा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
17	मोही	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
18	आत्मा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
19	कुंवारिया	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
20	तासोल	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
21	पीपरडा	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
22	भावा	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
23	केलवा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
24	बिनोल	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
25	बडारडा	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
26	भाणा	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
27	वणाई	10 बजे से 14 बजे तक	12 बजे से 18 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक	16 बजे से 22 बजे तक
28	खटामला	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक

राजसमन्द व रेलमगरा तहसील में सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति दिनांक 16.02.2012 तक 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 17.02.2012 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सांय 6 बजे से प्रात: 7 बजे तक 13 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

तहसील रेलमगरा

क्र. सं.	ग्राम पंचायत सूची	कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति समय					
		3.11.2011 तक	4.11.2011 से 13.11.11 तक	14.11.11 से 2.1.12 तक	2.1.12 से 12.1.12 तक	13.1.12 से 24.1.12 तक	25.1.12 से आज दिनांक तक
1	रेलमगरा (उपखण्ड मुख्यालय)	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
2	पिपली अहिरान	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
3	कुण्डिया	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
4	ओडा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
5	धनेरिया	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
6	गोगाथला	10 बजे से 14 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
7	जवासिया	10 बजे से 14 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
8	बामनिया कलां	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
9	सांसेरा	10 बजे से 14 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
10	लापस्या	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
11	पछमता	2 बजे से 6 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
12	पिपली डोडियान	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
13	सकरावास	2 बजे से 6 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
14	जीतावास	2 बजे से 6 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
15	खड बामनिया	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक

क्र. सं.	ग्राम पंचायत सूची	कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति समय					
		3.11.2011 तक	4.11.2011 से 13.11.11 तक	14.11.11 से 2.1.12 तक	2.1.12 से 12.1.12 तक	13.1.12 से 24.1.12 तक	25.1.12 से आज दिनांक तक
16	सादडी	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
17	राजपुरा	2 बजे से 6 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
18	जुणदा	10 बजे से 14 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
19	पनोतिया	10 बजे से 14 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
20	बनेडिया	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
21	गवारडी	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
22	चौकडी	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
23	कोटडी	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
24	सिन्देसरकलां	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
25	मेहन्दुरिया	2 बजे से 6 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक
26	कुरज (5000 से अधिक आबादी)	10 बजे से 14 बजे तक	21 बजे से 3 बजे तक	10 बजे से 16 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
27	गिलूण्ड (5000 से अधिक आबादी)	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
28	चराणा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	4 बजे से 10 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक
29	काबरा	10 बजे से 14 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक	22 बजे से 4 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	20 बजे से 2 बजे तक	6 बजे से 12 बजे तक

राजसमन्द व रेलमगरा तहसील में सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति दिनांक 16.02.2012 तक 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 17.02.2012 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सांय 6 बजे तक 13 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में नियुक्त मुख्य अभियन्ता

63. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनियमितताओं की वजह से जिम्मेदारी वाले पद पर नियुक्ति की रोक के बावजूद श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ थर्मल पावर प्लांट में एक मुख्य अभियंता की महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कर दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुख्य अभियंता ने एक निविदा में घोटाला करते हुए बीकानेर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है तथा सर्विस बुक में रेड मार्क लगाते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें भविष्य में जिम्मेदारी वाले पद पर नहीं लगाया जावे? क्या इसके बावजूद भी उस अधिकारी को सूरतगढ थर्मल में मुख्य पद पर लगा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रामांवाली बाई पास का टेण्डर पूल के माध्यम से ठेका ऊंचे दर में दिया गया है? क्या उक्त टेण्डर के जरिये सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सूरतगढ थर्मल पावर प्लान्ट में वर्तमान में पदस्थापित मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकरण में उन्हें जिम्मेदारी वाले पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिये गये।

(2) जी नहीं। उपरोक्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध किसी टेण्डर में बीकानेर में किसी घोटाले की शिकायत निगम प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है और ना ही उनकी सर्विस बुक में रेड मार्क लगाया गया है।

(3) जी नहीं। अभी तक इस टेण्डर की प्राइज बिड नहीं खोली गई है और ना ही कोई कार्यादेश दिया गया है, तदनुसार सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त टेण्डर निरस्त कर, यह कार्य रिड-कोर (राजस्थान सरकार का उपक्रम) को देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सिरोही जिले में आवासीय परिसरों/सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत लाइनें/ ट्रान्सफार्मर

64. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ओटाराम देवासी)

(1) राज्य में वर्ष 2008 से जनवरी, 2012 तक अव्यवस्थित एवं ढीली लाइनों के कारण तथा सार्वजनिक स्थानों पर जनसुरक्षा की दृष्टि से गलत स्थान पर खड़े ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत पोल में विद्युत प्रवाह होने की कितनी घटनायें हुई एवं उसमें कितने घायल हुए तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सड़क चौराहों, सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा लोगों के आवासीय घरों के ऊपर से निकलने वाली लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत पोलों को हटाने के क्या प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि किसी व्यक्तिगत भूमि में खड़े ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोलों को हटाने में प्रार्थीगण अथवा आवेदनकर्त्ता से राशि वसूली जाती है? क्या सार्वजनिक स्थानों पर खतरा बने ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत पोलों को जनसुरक्षा की दृष्टि से हटाने के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायी है?

(4) क्या जिला सिरोही में बिजली की अव्यवस्थित एवं ढीली लाइनों तथा मुख्य सड़क चौराहों, सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा लोगों के आवासीय घरों के ऊपर से निकलने वाली विद्युत लाइनों, सार्वजनिक स्थानों पर खतरा बने ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत पोलों को जनसुरक्षा की दृष्टि से हटाने के संबंध में स्थानीय ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार को अवगत कराये जाने के उपरान्त भी जनसुरक्षा की दृष्टि से खतरा बने उक्त ट्रांसफार्मरों, विद्युत पोलों तथा लाइनों को सरकार द्वारा नहीं हटाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन जवाबदेह है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2008 से जनवरी, 2012 तक अव्यवस्थित एवं ढीली लाईनों के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने अथवा मृत्यु की घटना नहीं हुई।

(2) भारतीय विद्युत नियम के अनुसार पूर्व स्थापित विद्युत लाईन अथवा सबस्टेशनों को सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सड़क, चौराहों, सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा लोगों के आवासीय घरों के ऊपर से निकलने वाली वर्तमान में स्थापित लाईनों, ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत पोलों को हटाने हेतु अनुमानक के अनुसार आवेदक द्वारा व्यय वहन करने पर लाईन अथवा सबस्टेशन को हटाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल

(ऊर्जा मंत्री)

नियमानुसार विद्युत सुरक्षात्मक दूरी के मापदंड को सुनिश्चित रखते हुए स्थापित किए गए हैं। परन्तु जहां बाद में सार्वजनिक स्थानों में परिवर्तन/ निर्माण अथवा विकास कर सुरक्षात्मक दूरी कम कर दी गई है तो संबंधित संस्था अथवा स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास/सार्वजनिक निर्माण विभाग/शहरी विकास प्राधिकरण/ आवेदक द्वारा शिफ्टिंग की राशि जमा कराने पर इन्हें हटाए जाने का प्रावधान है।

(4) जी नहीं। कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

65. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2010-11 में कुल कितने बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये व कितने शेष हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2007 से 2010 की अवधि में 2630 विद्युत कनेक्शन दिया जाना शेष बताया गया था? यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने कनेक्शन दे दिये गये व कितने कनेक्शन दिया जाना शेष है और शेष कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा रायसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 357 बीपीएल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये गये एंव 2273 बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना शेष था।

(2) जी हां। उक्त लम्बित कनेक्शनों में से जनवरी, 2012 तक 465 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं एवं शेष रहे 2165 कनेक्शनों को स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों का सघन विद्युतीकरण कर, वित्तीय वर्ष 2012-13 तक जारी किया जाना सम्भावित है।

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

66. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला (सीकर) में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु जो उपभोक्ता अपना सामान स्वयं लेकर नहीं गये उनकी कितनी फाइलें वर्तमान में सहायक अभियंता कार्यालय में कब से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अजमेर विद्युत वितरण निगम में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु सामान का परिवहन आवेदक द्वारा नहीं किया जाता बल्कि निगम द्वारा किया जाता है। अतः आवेदकों द्वारा स्वयं सामान परिवहन नहीं करने के कारण विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कोई पत्रावली लम्बित नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

रोहट (पाली) के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

67. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली की तहसील रोहट में कितने पशु चिकित्सालय भवन विहीन हैं एवं कितने पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं तथा किस-किस पशु चिकित्सालय में कौन से पद स्वीकृत हैं और इनमें से कौन-कौन से पद कितने -कितने समय से किन-किन कारणों से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन गांवों में पशु चिकित्सालय भवन बने हुये हैं परन्तु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली की तहसील रोहट का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रोहट राजकीय भवन में संचालित नहीं है, जो कि वर्तमान में किराये के भवन में संचालित है। इस तहसील में वर्तमान में संचालित कुल 3 पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है -

(पशुपालन मंत्री)

संस्था का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद/कारण
प्रथम श्रेणी प.चि. रोहट	वरि.प.चि.अ	1	-
	प.चि.सहायक	1	1 (2009) सेवानिवृति से
	पशुधन सहायक	1	-
	पशुधन परिचर	1	-
	जलधारी	1	-
	गडरिया	1	-
	स्वीपर	1	1 (2007) स्थानान्तरण से
पशु चिकित्सालय वायद	प.चि.अ.	1	1 (2007) स्थानान्तरण से
	पशुधन सहायक	2	-
	पशुधन परिचर	2	-
	स्वीपर	1	1 (2009) स्थानान्तरण से
पशु चिकित्सालय मंडावास	प.चि.अ.	1	-
	पशुधन सहायक	1	-
	पशुधन परिचर	2	1 (2010) स्थानान्तरण से
	स्वीपर	1	1 (2005) स्थानान्तरण से

(2) जी नहीं। पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(3) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालय रहित ग्राम

68. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के विभिन्न गांवों में पशु चिकित्सालय एवं पशु केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड है?

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के अनेक गांवों में निर्धारित मानदण्ड रखते हुए भी उक्त केन्द्र स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो कौन से गांवों में व क्यों? क्या सरकार उक्त स्थानों पर नये केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां,तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश के विभिन्न गांवों में पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के मापदण्ड निम्नानुसार हैं -

<u>नवीन पशु चिकित्सालय खोलने</u> हेतुः-

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/संस्था से 6 किलोमीटर की दूरी।

2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 5000 हो ।

3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता ।

4. 3-4 कमरों का पक्का भवन एवं 200 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता ।

<u>नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने</u> हेतुः-

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी ।

2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 3000 हो ।

3. पक्की सडक, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता ।

4. 3-4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन एवं 200 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता ।

(2) जी नहीं । पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं । दिनांक 01.08.2009 से प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत नहीं है, वहां नजदीक के पशु चिकित्सालय से प्रति माह एक पशु चिकित्सा शिविर एवं पशु पालक गोष्ठी का आयोजन किया जाकर पशु चिकित्सा लाभ एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ पशु पालकों को पहुंचाया जा रहा है।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

69. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में गत तीन वर्षों से कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त केन्द्रों पर कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पिछले तीन वर्षो से 13 पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं, जिनमें स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्था का नाम	कुल स्वीकृत पद	कुल रिक्त पद
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, धौलपुर	8	1
2.	पशु चिकित्सालय, पंचगांव	6	1
3.	पशु चिकित्सालय, तसीमो	5	1
4.	पशु चिकित्सालय, बरेहमोरी	5	0
5.	पशु चिकित्सालय, सखवारा	5	1
6.	पशु चिकित्सालय, खेडा सरानी	6	1
7.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, मोरोली	2	1
8.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, कोलारी	1	0
9.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, मालोनी खुर्द	2	0
10.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, टेहरी	2	0
11.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, भैसेना	1	0
12.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, जाटोली	1	0
13.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, विश्नोदा	1	0
	कुल	**45**	**6**

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पंचायत भवन

70. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितनी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पंचायत भवनों को बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 11 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन क्रमशः अणतपुरा, बैनाडा, भूथल, फालीयावास, गढ़, करणगढ़, खतेहपुरा, कुथाड़ा खुर्द, पालावाला जाटान, मनोहरपुरा, टोडाभाटा क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं) योजना के दिशा-निर्देश वर्ष 2011-12 में पूर्व से ही प्रावधान किया हुआ है। तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

फलौदी विधान सभा क्षेत्र में अनुपयोगी विभागीय कार्यालयों आवासों पर अतिक्रमण

71. **श्री ओम जोशी** (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इन्दिरा गांधी नहर एवं लिफ्ट नहरों के निर्माण पर कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि राजस्व विभाग से कालोनी बनाने हेतु ली गई थी तथा उक्त पर क्या-क्या निर्माण करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्मित कार्यालय, आवासों, गोदामों का वर्तमान में कोई उपयोग हो रहा है? विभिन्न परियोजनायें पूरी हो जाने के बाद रिक्त पड़े ऐसे भवनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कालोनियों में भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये हुए हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कैनाल कालोनी फलौदी हेतु 625 बीघा भूमि फलौदी में, 45 बीघा भूमि कैनाल कालोनी बाप हेतु बाप में एवं 50 बीघा भूमि कैनाल कालोनी कानासर हेतु कानासर में राजस्व विभाग से ली गई

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

है। उक्त भूमियों पर आवासीय कॉलोनी, गैर आवासीय, रेस्ट हाउस, स्टोर सैड, एवं विभिन्न कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया गया है। फलौदी लिफ्ट नहर पर विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों हेतु आवास, लिफ्ट नहर हेतु अवाप्त की गई भूमि पर निर्मित है। (विवरण संलग्न प्रपत्र अ-1 से अ-3)।

(2) जी हां। निर्मित कार्यालय भवनों, गोदामों एवं आवासों का उपयोग हो रहा है। तथापि वर्तमान में रिक्त पड़े भवनों की कालोनी वार सूचना निम्नानुसार है :-

कोलोनी	कार्यालय	आवास	गोदाम	डोरमेंटरी (रेस्ट हाउस)
फलौदी	01	171	16	01
बाप	-	08	-	-
कानासर	01	06	-	01

(विवरण संलग्न प्रपत्र अ-1 से अ-3)

(3) जी नहीं । इन आवासीय कालोनियों में भू-माफियाओं द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ एवं अरनोद तहसील के अग्नि पीड़ितों को मुआवजा राशि

72. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के कच्चे-पक्के मकानों में आग लगने की घटनाओं पर सरकार द्वारा पीड़ितों को मुआवजा राशि दी जाती है? यदि हां, तो इसके क्या नियम/मानदण्ड हैं और कब तय किये गये थे? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009-10 से 2011-12 में जनवरी, 2012 तक जिला प्रतापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में ग्रामीण एवं नगरपालिका क्षेत्र में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई और क्या आग की घटनाओं से जानमाल की क्षति वालों को सहायता मुहैया कराई गई है? तहसीलवार ग्राम पंचायतवार, वर्षवार पीड़ित व्यक्तियों को दी गई सहायता राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के कच्चे/पक्के मकानों में प्राकृतिक अग्निकाण्ड की घटनाओं पर सरकार द्वारा पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं है। पीड़ितों को एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के मानदण्डानुसार तात्कालिक सहायता दी जाती है, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 16.01.2012 को जारी मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में 13 जनवरी, 2012 तक जिला प्रत्तापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में ग्रामीण एवं नगरपालिका क्षेत्र में हुए अग्निकाण्डों एवं पीडितों को सरकार द्वारा तत्समय प्रभावी सीआरएफ मानदण्डानुसार दी गयी सहायता राशि का तहसीलवार, ग्रामवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। तत्समय प्रभावी सीआरएफ मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू जिले के अतिवृष्टि से फसल खराबे का सर्वे

73. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू में खरीफ फसल वर्ष 2011 में मोठ-मूंग की फसल अतिवृष्टि के कारण खत्म हो गई? क्या सरकार ने किसानों को हुये इस नुकसान के लिये कोई सर्वे करवाया है? यदि हां, तो किसानों को हुये इस नुकसान की भरपाई के लिये कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

(2) उक्त जिले में किसानों को कितना नुकसान हुआ तथा तहसीलवार किसानों को कितना भुगतान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में फसल खरीफ सम्वत 2068 में करवाई गई गस्त गिरदावरी रिपोर्ट में चूरू जिले में फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम पाया गया है। फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम होने पर सीआरएफ मानदण्डानुसार सहायता देय नही है। अतः इस हेतु चूरू जिले को राशि का आबंटन नहीं किया गया।

(2) बिन्दु संख्या 01 के उत्तरानुसार।

प्रश्न संख्या-74

(स्थगित)

मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना हेतु स्वीकृत राशि

75. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के तहत पंचायतों में लाभार्थियों को आवास योजना हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत आवासों हेतु पंचायती राज ने बी.पी.एल. परिवारों को आवास निर्माण हेतु पट्टे जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने-कितने पट्टे कहां-कहां व नहीं, तो क्यों एवं उन्हें कब तक पट्टे जारी कर दिये जायेंगे? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासों के निर्माण हेतु जिला परिषदों में लाभार्थियों को चैक उनके खातों में जमा करवा दिये गयें हैं? यदि हां, तो पंचायत समितिवार निर्माण राशि कितनी-कितनी जमा करवाई गई व नहीं, तो क्यों? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितिवार वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

पंचायत समितिवार पट्टों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जिला परिषदों द्वारा लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तान्तरित करवाई गई है। पंचायत समितिवार जमा कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चौहटन विधान सभा क्षेत्र में जन सहभागिता योजना के तहत प्रस्तावित महाविद्यालय

76. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय विहीन तहसील उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री पदमाराम)

(2) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय विहीन तहसील/उपखण्ड में पीपीपी योजना के तहत महाविद्यालय खोलने हेतु मई, 2010 में आवेदन पत्र मांगे गये थे तथा उन आवेदनों पर माह सितम्बर, 2011 में कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त लम्बित आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं कर जन सहभागिता के आधार पर नई विज्ञप्ति जारी की गई है? यदि हां, तो क्या उसमें विधान सभा क्षेत्र चौहटन के लिये भी आवेदन पत्र मांगे गये है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के 18 तहसील मुख्यालय, जहां कोई भी महाविद्यालय नहीं है, वहां पीपीपी मोड (निजी सार्वजनिक सहभागिता) के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। योग्य पाये गये प्रस्तावों को शीघ्र ही स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। पीपीपी योजना में मई 2010 में राजकीय महाविद्यालय विहीन तहसीलों में महाविद्यालय खोलने हेतु आवेदन मांगे गये थे। महाविद्यालय विहीन तहसीलों के लिए दिनांक 21 जून, 2010 तक 535 आवेदन प्राप्त हुए। अक्टूबर 2010 में चयन समिति ने जांच कर किसी भी संस्था को योग्य नहीं पाया गया। 4 मार्च, 2011 को प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में आवेदनों के पुन: परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा आवेदन पत्रों की गहनता से जांच करने पर कोई भी आवेदक संस्था को पात्र नहीं पाया गया।

(3) जी हां। प्राप्त 535 आवेदन पत्रों की समीक्षा के दौरान किसी भी संस्था की पात्रता नहीं होने के कारण दिनांक 19.12.2011 को दुबारा विज्ञप्ति जारी की गई। चौहटन में निजी क्षेत्र में महेश इंस्टीटयूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज निजी महाविद्यालय संचालित होने के कारण चौहटन को 18 महाविद्यालय विहीन तहसीलों में शामिल नहीं किया गया।

राजकीय महिला महाविद्यालय अजमेर हेतु भूमि एवं भवन

77. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में राजकीय महिला कालेज वर्ष 1994-95 से संचालित है? क्या उक्त कालेज राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के छात्र हास्टल में संचालित हो रहा है? यदि हां, तो संकाय अनुसार इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में एकमात्र महिला महाविद्यालय के महत्व को देखते हुए इसके भवन हेतु भूमि आबंटित करने एवं भवन निर्माण करने हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। संकाय अनुसार अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है :-

कक्षा वर्ष	कला संकाय	वाणिज्य संकाय
प्रथम	239	156
द्वितीय	140	149
तृतीय	158	101
योग	**537**	**406**

(2) राजकीय महिला महाविद्यालय अजमेर को सावित्री कन्या अनुदानित महाविद्यालय अजमेर के भवन में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योगों हेतु स्वीकृत ऋण एवं अनुदान

78. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कौन-कौन से लघु उद्योग हेतु कितना-कितना ऋण

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

दिया जाता है एवं किस लघु उद्योग पर कितना-कितना अनुदान देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में सरकार द्वारा किस-किस उद्योग पर कितना-कितना ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लघु उद्योग हेतु ऋण नहीं दिया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नकारात्मक सूची में उल्लेखित उद्योगों को छोड़कर विनिर्माण उद्योगों के लिए रु. 25.00 लाख व सेवा उद्योग के लिए रु. 10.00 लाख तक बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग स्थापना हेतु मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग/सीमावर्ती क्षेत्र) को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) नियमानुसार बैंकों के माध्यम से देय है। योजना का ब्रोशर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में खादी बोर्ड/खादी आयोग द्वारा किसी उद्योग पर कोई ऋण नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत खादी बोर्ड द्वारा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में लाभांवित इकाइयां इस प्रकार हैं :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**नाम उद्यमी**	**ग्राम**	**पंचायत समिति**	**उद्योग**	**परियोजना लागत**	**मार्जिन मनी अनुदान**
1	श्री सतपाल/रामानन्द वर्मा	बर्डोद	बहरोड़	आफसेट मशीन	2.00	0.70
2	श्री अशोक कुमार शिम्भुदयाल	बर्डोद	बहरोड़	चर्म जूता	0.50	0.17
3	श्रीमती राधा देवी आशुतोष विमल	खेडकी	बहरोड़	दन्त मंजन	1.00	0.35
4	श्री घासीराम/भोलाराम	ढूढारियां	बहरोड़	दुग्ध उत्पाद	1.50	0.53

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड में किसी उद्यमी को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

(ब्रोशर विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालयों के क्षतिग्रस्त भवन

79. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा भवनों के निर्माण/मरम्मत बाबत वर्ष 2011-12 में राशि का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जिला टोंक के विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां के और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक औषधालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के प्रस्तावों का राज्य में आंकलन किया है? यदि हां, तो कितने भवन जीर्ण-शीर्ण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में कई भवन गिरकर जनहानि कर सकते हैं? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां के? क्या सरकार भवनों के संबंध में तकनीकी रिपोर्ट अथवा जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा भवनों के निर्माण/ मरम्मत बाबत् वर्ष 2011-12 में केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत मेनस्ट्रमिंग आफ आयुष के तहत रुपये 2196.97 लाख का प्रावधान पी.आई.पी. (कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना) योजनान्तर्गत किया गया है।

(2) जी हां। सरकार जिला टोंक के विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के जीर्ण-शीर्ण निम्न 8 भवनों के निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है-

(आयुर्वेद मंत्री)

क्र.सं.	नाम औषधालय
1	नगर मालपुरा
2	धोला का खेड़ा
3	सोडा
4	सोडा बावड़ी
5	कलमण्डा
6	आवडा
7	लाम्बा हरिसिंह
8	चावण्डिया

(3) जी हां। सरकार ने आयुर्वेदिक औषधालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के प्रस्तावों का राज्य में आंकलन किया है। राज्य में 345 जीर्ण-शीर्ण भवन हैं।

(4) जी नहीं। राज्य में मरम्मत योग्य औषधालय भवनों की सूचना प्राप्त हुई है जिनकी सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है। प्राप्त सूचना का तकनीकी परीक्षण प्रक्रियाधीन है। तकनीकी परीक्षण उपरांत जिला आयुर्वेद अधिकारियों को मरम्मत हेतु अधिकृत किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में कार्यरत राजकीय/निजी चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय

80. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने प्राइवेट एवं राजकीय मेडिकल कालेज कहां पर कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलने के क्या नियम व प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य में स्थित प्राइवेट एवं राजकीय मेडिकल कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानीटरिंग की जांच की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति हेतु कितने आवेदन कब से क्यों लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राइवेट एवं राजकीय मेडिकल कालेज की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(2) विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य में स्थित प्राईवेट एवं राजकीय मेडिकल कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानीटरिंग हेतु प्रत्येक कालेज में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के नोर्म्स के अनुसार चिकित्सा शिक्षा इकाई का गठन किया हुआ है जिसका भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहती है।

(4) आवेदन लम्बित नही है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सिरोही जिले में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित कार्य दिवस

81. **श्रीमती गंगा बेन गरासिया** (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2011-12 में अब तक मनरेगा में कुल कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में वर्ष 2008-09 से 2010-11 में कुल कितने श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 2011-12 में दिनांक 22.02.2012 की एमआईएस की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराये गये रोजगार का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक एमआईएस की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराये गये रोजगार का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

मनरेगा में कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित नियुक्ति

82. **श्री अशोक डोगरा** (बून्दी) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2011 से मनरेगा के कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक मानते हुये छठे वेतन मान अनुसार परिलाभ दिये जा रहे हैं? क्या राजस्थान सरकार भी मनरेगा

(श्री अशोक डोगरा)

कार्मिकों को इस तरह का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मनरेगा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान मूल विभाग से नहीं करके मनरेगा से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2012 तक इनको कितना भुगतान किया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मनरेगा में कार्यरत सरकारी कर्मचारी व संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्य दिवस में अन्तर है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बाबत अब तक किये गये सरकारी प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 4498 दिनांक 04.05.2011 के द्वारा 01.04.2011 से मनरेगा के कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक नहीं माना गया है परन्तु संविदा पदस्थ अमले को छठवां वेतनमान के समकक्ष संविदा पारिश्रमिक दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं (परिशिष्ट 1)।

राज्य में संविदा कार्मिकों को इस तरह का लाभ देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि योजनान्तर्गत अनुबन्धित कार्मिकों का वर्तमान मानदेय उनके द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य के अनुरूप है।

(2) जी हां। प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना से किया जा रहा है। जो कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर मनरेगा योजना का कार्य कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार वेतन का भुगतान मनरेगा योजना मद से किया जाता है। वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2012 तक किये गये भुगतान की जिलेवार सूचना परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिन का कार्य सप्ताह है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम में योजना के अन्तर्गत साप्ताहिक कार्य दिवस 6 होने के कारण संविदा कार्मिकों का कार्य सप्ताह 6 दिवस का रखा गया है।

(4) जी नहीं।

(प्रति व सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 42 का विवरण)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं तत्कालीन पद	क्रय किये गये सामान का विवरण	मात्रा	लागत (रु. में)
1	श्रीमती आरूषी ए. मलिक, जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	कम्प्यूटर प्रिन्टर	210 210	83,31,360/-
2	श्री सुबीर कुमार, जिला कलेक्टर टोंक	कम्प्यूटर प्रिन्टर	160 160	64,34,688/-
3	श्री नवीन जैन, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़	कम्प्यूटर प्रिन्टर	205 200	78,99,975/-
4	श्री जोगाराम, जिला कलेक्टर दौसा	कम्प्यूटर प्रिन्टर पालने	190 190 2184	78,28,760/- 21,57,792/-
5	श्री नीरज के. पवन, जिला कलेक्टर करौली	पोधे	-	51,50,659/-

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में RUIDP के तहत कार्यों व राशि का अकुशल उपयोग

मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के नगरपालिका क्षेत्र में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सीवरेज लाइन डालने एवं जल वितरण योजना के कार्य हेतु राशि रुपये क्रमशः 19 करोड 91 लाख, एवं 28 करोड़ 63 लाख वर्ष 2010 में स्वीकृत हुए थे तथा उक्त कार्य को करने हेतु कार्यादेश दिनांक 20.5.2010 को जारी किया गया तथा उक्त कार्य दिनांक 19/05/2012 तक समाप्त होना है, किन्तु रामसमंद नगरीय क्षेत्र की यह स्थिति है कि जल वितरण हेतु जो पाइप लाइन डाली गई थी उसमें आधा शहर जल वितरण योजना से वंचित रह रहा है। जन स्वास्थ्य अभि. विभाग के अधिकारियों द्वारा शहर का सर्वे फील्ड में जाकर नहीं करने एवं कार्यालय में ही बैठकर प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु भेज दिये गये। जिसका परिणाम यह है कि आर.यू.आई.डी.पी. के करोड़ों रुपये खर्च होने के उपरान्त भी आधा शहर जल वितरण योजना से वंचित रह गया है। वंचित रह जाने से आधे शहर के निवासियों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। शहर में जो सीवरेज लाइन डाली जा रही है वो भी टेंडर में बताये गये मापदण्डों के अनुसार नहीं डाली जा रही है। काम में ली गई सामग्री की गुणवत्ता भी घटिया है। जिसका समय-समय पर वहां के नागरिकों द्वारा सवाल उठाये जा रहे हैं। टेंडर को सी कैटेगरी तथा डी कैटेगरी के ठेकेदारों को सबलेट कर दिया गया जिससे कार्य की गुणवत्ता खराब हुई है। और पूरे शहर की सड़कें खोदी गयी है जिनमें बीटी के कार्य में बहुत ही ढील बरती जा रही है। जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं नगरीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि राजसमंद नगरपालिका क्षेत्र में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा किये जा रहे कार्यों की तुरन्त प्रभाव से जांच करानी चाहिए, और शहर की सड़कों के हालात एवं पूरे शहर में पेयजल योजना को तुरन्त प्रभाव से सुधारी जावें।

किरण माहेश्वरी
(राजसमंद)

जहाजपुर की सड़क एमडीआर-7 के दुर्घटना संभावित हिस्से का सुधार व मध्यवर्ती छूटी सड़क का निर्माण कार्य

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र से निकल रही सडक एमडीआर -7 के त्रिवेणी चौराहे से देवली तक की सड़क को विकसित एवं चौड़ाईकरण का कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. के मार्फत करवाया जा रहा है। इस सड़क को विकसित एवं चौड़ाईकरण की प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व तखमीना प्रस्तुत करते समय तकनीकी कर्मचारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया जिससे इस सड़क के किमी 54.0 से किमी. 56.0 जो कि नागदी बांध की पाल दीवार पर है जिसमें कई Blind Curve होकर डबल “S” नुमा आकृति की सड़क बनी हुई है जिसे सीधा करने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण इस पोर्सन में दुर्घटना होने एवं जानमाल की क्षति की प्रबल संभावना बनी रहेगी। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क के इस पोर्सन को सीधा करने से जहां एक ओर सड़क की लम्बाई लगभग एक कि.मी. कम हो जाने से लागत में कमी आयेगी वहीं उक्त पोर्सन में सरकारी भूमि होने से भूमि अवाप्ति एवं मुआवजा भुगतान की कार्यवाही भी नहीं करनी पड़ेगी।

इसी प्रकार उक्त त्रिवेणी चौराहे से देवली सड़क के कार्य की स्वीकृति में किमी 0.0 से कि.मी. 72.0 तक के विकसित एवं चौड़ाईकरण के लिए कार्यादेश जारी किये गये हैं जिसमें इस सड़क का त्रिवेणी चौराहे से मोरलां चौराहे तक ही निर्माण कार्य किया जावेगा। इस प्रकार मोरलां चौराहे से देवली तक लगभग 2 किमी सड़क का विकास एवं निर्माण नहीं होने से जहाजपुर क्षेत्र की जनता को कृषि उत्पादन को मण्डी तक लाने, अन्य बाजार सम्बन्धी कार्य, विद्यार्थियों को स्कूल व कालेज तक आने-जाने एवं मरीजों को चिकित्सालय तक लाने के लिए सकड़ी एवं अविकसित सड़क होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पडेगा।

उक्त सड़क के डबल ‘‘S” नुमा Blind Curve को सीधा करने एवं मोरलां चौराहे से देवली तक की छूटी हुई सड़क के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रकरण माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाया गया था किन्तु जनहित के उक्त मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि एमडीआर-7 की त्रिवेणी चौराहे से देवली-सड़क को विकसित एवं चौड़ाईकरण के कार्य के दौरान किमी 54.0 से किमी. 56.0 के बीच स्थित डबल "S" नुमा Blind Curve को सीधा करने एवं मोरलां चौराहे से देवली तक के छूटे हुए लगभग दो किमी सड़क निर्माण की स्वीकृति शीघ्र कराने की व्यवस्था करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

बाली में व्यापक पशुपालन के दृष्टिगत अतिरिक्त पशु चिकित्सा केन्द्र खोलना व वर्तमान रिक्तियों की पूर्ति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना के तहत माननीय पशुपालन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पहाड़ी, वन एवं बांध नहरी बाहुल्य के मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली के सभी गांवों में ग्रामीणजनों का मुख्य रोजगार का साधन पशुपालन है, बाली क्षेत्र की देवासी, भील, मीणा व अन्य अनुसूचित जाति के लोग पशुपालन के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं इनके साथ ही प्रत्येक किसान के यहां बडी संख्या में दुधारू पशु पाले जा रहे हैं। बाली क्षेत्र के गांव व ग्राम पंचायत क्षेत्र क्रमशः 1-बड़ौद, 2-दादाई, 3-खेतरली, 4-गौरीया, 5-कुमाटिया एवं इनके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पशुपालन हो रहा है लेकिन पशुओं के इलाज उपचार के नाम पर इन गांवों या इनके आसपास सरकार द्वारा कोई पशु चिकित्सा इकाई नहीं खोली गई है। इस क्षेत्र में पशु चिकित्सा अभाव में आये दिन पालतू दुधारू पशु बीमार होकर मर रहे हैं जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रही है दूसरी ओर महंगे दुधारू पशु खरीदकर लाने वाले पशुपालक कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं। उक्त ग्राम पंचायतों, गांवों एवं इनके आस-पास एक-एक पशुपालक के पास सैंकड़ों भेड़ बकरियां, गाय भैंसे हैं। अतः बड़ौद, दादाई, खेतरली, गौरीया व कुमाटिया में पृथक-पृथक पशु चिकित्सा उपकेन्द इसी बजट सत्र 2012 में खुलवाकर बाली क्षेत्र के पशुपालकों को राहत प्रदान करें। सरकार द्वारा बाली क्षेत्र में पहले से खोले गये पशु चिकित्सालय क्रमशः 1-ढालोप, 2-बीसलपुर, 3-सेवाडी एवं 4-नाणा आदि में चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के स्वीकृत पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं ऐसे हालात में इन चिकित्सालयों क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

होते हुए भी पशुपालकों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। अतः इन पशु चिकित्सालयों में स्वीकृतशुदा प्रत्येक रिक्त पद को भरा जावे।

पुष्पेन्द्र सिंह

(बाली)

बड़ौदा मेव (अलवर) में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय को पुनः खोला जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, जिला अलवर में कस्बा बडौदा मेव में वर्षों तक सहायक कृषि निदेशक कार्यालय कार्यरत रहा, किन्तु बिना किसी वाजिब कारण बताये यह कार्यालय बन्द कर अलवर हैडक्वार्टर पर खोला गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र का किसान बहुत परेशानी में आ गया है। किसानों को अपनी समस्या हेतु भारी किराया भाड़ा खर्च कर अलवर हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। इस संबंध में मैं, यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि कस्बा बड़ौदा मेव में कृषि उपज मंडी की स्थापना भी दो वर्षों से हो गई है। आश्चर्य है कि कस्बा बड़ौदा मेव में कृषि

उपज मंडी कार्यालय तो खोला गया, जिससे किसान अपनी फसल की उपज का बेचान यहां कर सके किन्तु कृषि कार्यालय यहां बंद कर दिया गया। उपज तो सही मायने में तब आएगी जब किसानों को कृषि विभाग से फसल उगाने का सही परामर्श मिल सके। समय-समय पर कृषि के उत्पादन के लिये खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध हो सकें।

किसानों को वास्तव में कितनी दिक्कत आती है, यह व्यवहारिक रूप से सरकार को क्यों समझ में नहीं आती।

मैं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्षेत्र जिस क्षेत्र से लगभग 35-45 पंचायतें जुड़ी हैं। हजारों एकड़ का रकबा इससे जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत कृषि कार्य ही है। यहां कोई छोटा-बड़ा उद्योग नहीं है, कृषि पर आधारित ही व्यापार भी है। अतः सरकार से माननीय मंत्री महोदय कृषि विभाग से मेरा बारंबार विनम्र निवेदन है कि यहां पूर्व की भांति पुनः सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोला जावे, ताकि किसानों की वाजिब एवं व्यवहारिक समस्यायें दूर हो सकें। मैं, यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि अगर यह कार्यालय नहीं खोला गया तो किसान/व्यापारी आन्दोलन करने को मजबूर हो सकता है।

अतः मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि सरकार इसी सत्र में बजट भाषण में कस्बा बड़ौदा मेव में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोलने की पुनः घोषणा करें।

ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)

बयाना, वैर व रूपवास तहसीलों (भरतपुर) के ग्रामों को पेयजल समस्या के निराकरण के लिए चम्बल लिफ्ट योजना से जोड़ा जाना

निवेदन है बयाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल की भारी समस्या है। हैण्डपम्प लगते एवं बिगड़ते रहते हैं जो स्थाई समाधान नहीं है। इस समय चम्बल से लिफ्ट योजना के अनुसार भरतपुर, डीग, कुम्हेर, कामां तक पानी पहुंच रहा है इसी जिले की तहसीलें बयाना एवं वैर भी हैं, जिनके लिए स्थाई समस्या हेतु जब पीने का पानी अन्य तहसीलों के निवासियों को आ सकता है तो बयाना एवं वैर के निवासियों के बारे में विचारणीय कदम होगा। क्योंकि जब ग्रामवासियों को पीने का पानी ही नहीं होगा तो अन्य सुविधाएं उपलब्ध होना सपना मात्र है।

मेरी मांग है कि जो पानी धौलपुर से जिला भरतपुर को अन्य तहसीलों को आयेगा बयाना तहसील को भी शामिल किया जाना न्याय संगत होगा। इससे ग्रामवासियों में सरकार की एक सुहाष्टि का प्रचार ही नहीं सदभावना का संचार होगा। एवं भावी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को शुद्व एवं समुचित पेयजल उपलब्ध रहेगा।

अब मेरी मांग है कि बयाना-रूपवास के प्रत्येक ग्राम को पानी चम्बल लिफ्ट योजना से जोड़कर योजना का विस्तार किया जावे। यह एक पुनीत ही नहीं मानव जन कल्याण योजना का सरकार मूर्तरूप से उदाहरण होगा। मुझे पूरा विश्वास है सरकार अपना मानवीय दृष्टिकोण बदलकर इस पुनीत यज्ञ में अपनी आहुति देकर योजना साकार करेगी।

ग्यारसाराम कोली

(बयाना)

बाड़मेर में पाले से नष्ट फसल का मुआवजा

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश एवं प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था ही कृषि पर आधारित है। किसानों का हित ही हमारी प्रमुखता है। चूंकि हम

ज्यादातर इसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम सभी को भली-भांति जानकारी है कि लगभग 27 जनवरी एवं 09 फरवरी के आसपास में प्रदेश में शीतलहर का दौर था। उसी शीतलहर के दौरान बाड़मेर-जालोर-पाली एवं आसपास के जिले जो जीरा एवं ईसबगोल के प्रमुख उत्पादक स्थानों में तो इतना पाला पड़ा कि किसानों की समस्त फसल ही चौपट हो गई। मेरे द्वारा तत्कालीन क्षेत्र का दौरा भी किया गया था। किसानों की हालत देखने योग्य नहीं थी। एक गरीब किसान जिसने ऋण लेकर जीरा, ईसबगोल एवं अरण्डी जैसी फसल का उत्पादन करने हेतु काश्तकार्य किया हो और ऊपर से पाला पड़कर फसल नष्ट हो जाएं तो किसान में क्या गुजरती है इसको एक किसान या उसका बेटा ही महसूस कर सकता है।

मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले फायदे के भरोसे किसानों को छोड़ देगी तो उनके साथ घोर अन्याय होगा। क्योंकि बीमा कम्पनियों के निर्धारित मौसम केन्द्रों एवं मानदण्डों में इस नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है। क्योंकि उनके निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नुकसान का सही आंकलन होना सम्भव ही नहीं है। मैं यहां राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष एवं आपदा राहत कोष के नियम जिसमें चक्रवात, अकाल, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना जो शर्ते हैं। उनमें शीतलहर या पाला शब्द को सम्मिलित करने हेतु पत्र व्यवहार कर, उसे शामिल करने में केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर हमारी भावनाओं से केन्द्र सरकार को अवगत करायें।

मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बाड़मेर जिले के मेरे क्षेत्र में समदड़ी, पादरू, सिणधरी, सिवाना, रमणिया, खण्डप एवं बायतू, धोरीमन्ना, चौहटन, बालोतरा आदि क्षेत्र के किसानों की फसल चौपट हो चुकी है।

मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान सरकार किसानों के हित में हल्का पटवारियों से जीरा, ईसबगोल एवं अरण्डी की फसल की विशेष गिरदावरी करवाये एवं उस गिरदावरी के आधार पर वास्तविक नुकसान का आंकलन कर किसानों को राहत प्रदान करने हेतु मुआवजा देने का प्रावधान करने हेतु एक पैकेज जारी करे ताकि अन्नदाता किसान को राहत मिल सके। साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष एवं आपदा राहत कोष के नियम जिसमें चक्रवात, अकाल, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना जो शर्ते हैं। उनमें

शीतलहर या पाला शब्द को सम्मिलित करने हेतु पत्र व्यवहार कर, उसे शामिल करने में केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर किसानों को राहत प्रदान करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

रामगंजमण्डी में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि में अव्यवस्था

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 35 ग्रामों में सुचारू रूप से शुद्ध पेयजल, सफाई, रोड लाईट, सड़क आदि की व्याप्त समस्याओं के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करती हूं कि नगर विकास न्यास व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित पूर्ण विकसित कालोनियों-विवेकानन्द नगर, स्वामी विवेकानन्द नगर, विनोबा भावे नगर, गणेश नगर, बालाजी नगर, रंगबाड़ी योजना, रंगबाड़ी कच्ची बस्ती, कृष्णा नगर, वीर सावरकर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, अजय आहूजा नगर, हरिओम नगर, आंवली, रोजड़ी, नया गांव, बंधा, धर्मपुरा, धाकड़खेड़ी, गिरधरपुरा, दसलाना, नोहरा आदि गांवों की दुर्दशा छिपाये नहीं छिप सकती। विकास की बात तो दूर, उक्त ग्रामों में रहने वाली आम जनता को न तो समय पर पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, न चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, सफाई व्यवस्था तो ऐसी है कि नालियां व मोहल्ले सड़ रहे हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही है प्रदूषण भयंकर रूप से व्याप्त हो रहा है, रोड लाइटें काफी समय से बंद पड़ी हैं जिसको सुधारने वाला कोई नहीं है। नगर विकास न्यास और नगर निगम का ध्यान उक्त क्षेत्र की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इस वर्ष भगवान की कृपा से अच्छी वर्षा हुई लेकिन हमारे संसाधनों से अधिकारीगण उस पानी का ठीक तरह से उपयोग करने की योजना नहीं बना पा रहे हैं। इस स्थिति में उक्त क्षेत्र में आने वाले समय में पानी की विकराल समस्या पैदा होने वाली है। अभी हाल ही में पिछले एक माह से विनोबा भावे नगर में स्थित शादी-समारोहों के गार्डनों से नालियों में बहकर आने वाला गंदा पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो रहा है जो कि एक लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकार की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। मैंने कई बार उक्त समस्याओं के संबंध में जिला कलक्टर एवं सचिव, नगर विकास न्यास व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया परन्तु उनके कानों पर

जूं नहीं रेंग रही है, न ही आज तक समस्या का समाधान हो पाया है जिसके चलते जनता ने 27 फरवरी, 2012 को विशाल प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया।

अतएव इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं पुरजोर शब्दों में मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष बजट पैकेज स्वीकृत किया जाये एवं संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध योजना बनाकर लागू करने हेतु आदेशित किया जाये।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

रतनगढ़-सालासर वाया मालासी सड़क मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की आवश्यकता के मद्देनजर बाईपास का निर्माण

बीकानेर संभाग के चूरू जिले में सालासर हनुमानजी का विश्वप्रसिद्ध सिद्धपीठ मन्दिर है। हनुमानजी के दर्शनार्थ हेतु दूर-दूर से लाखों लोग पैदल व गाड़ियों से आते हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने रतनगढ़-सालासर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन रतनगढ़-सालासर वाया मालासी सड़क मार्ग को बाईपास से वंचित रख दिया गया है, जबकि इस मार्ग पर यात्री एवं वाहनों के आवागमन का दबाव बहुत ज्यादा है, सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण मालासी में भैरूजी महाराज का सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में हजारों हजार भक्तजन अपने बच्चों के जात-जडूला के लिये भी आते रहते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिससे मार्ग अवरूद्ध होने के कारण गाड़ियों की लम्बी कतारें लग जाती है व लम्बा जाम सा लग जाता है तथा कई घंटों तक मार्ग का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है।

अतः मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सालासर-रतनगढ़ सड़क मार्ग को मालासी बाईपास बनाकर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा देश के हर कोनों से आने वाले लाखों भक्तजनों को आवागमन में सुविधा प्रदान करावें।

राजकुमार रिणवां

(रतनगढ़)

अलवर शहर में तिजारा रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवर-ब्रिज की शिथिल गति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में तिजारा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण प्रारम्भ हुए ढाई वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु आज दिन तक कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जिसके कारण आमजन को सुविधा होने के बजाय भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते अवरूद्ध हो रहे हैं, आवागमन में भारी परेशानी लोगों को हो रही है। तिजारा फाटक के दूसरी ओर बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर हजारों की तादाद में छात्र-छात्राएं अध्ययन हेतु दैनिक रूप से आते-जाते हैं, पास में ही अनेक आवासीय कालोनियां विकसित हैं जिनके निवासियों को भी रोज अपने शहर स्थित कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। पटरी पार क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधा हेतु भी लम्बा रास्ता पार करके आना पड़ रहा है जिससे मरीजों की रास्ते में ही मौत होने जैसी दुर्घटनाएं तक घटित हो रही हैं। तिजारा फाटक से टेल्को चौक के मध्य दोनों ओर पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण महिलाओं को पानी सिर पर घडों के माध्यम से तिजारा से ले जाना पड़ता है। वर्तमान में फाटक बंद होने के कारण पेयजल से भी क्षेत्रवासी वंचित हो रहे हैं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है। वर्ष 2011 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की संभागीय बैठक में सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त आरओबी को 31 दिसम्बर, 2011 तक हर हालत में पूरा करने हेतु वादा किया गया था किन्तु स्थिति ढाक के तीन पात जैसी बनी हुई है। निर्माण ठेकेदार द्वारा आवासीय कालोनी-कर्मचारी कालोनी के सामने बड़े -बड़े गड्ढे खोदकर पैदल आवागमन को भी अवरूद्ध कर रखा है, निर्माण बेहद लचर गति से चल रहा है जिसकी गति बढाने क लिए अनेक बार क्षेत्रवासियों द्वारा आंदोलन, धरना व प्रदर्शन तक भी किये गये हैं किन्तु सरकार सुप्तप्राय: अवस्था में है। अत: यह स्थिति हम सब के लिए चिंता का विषय है। मेरी

सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि उक्त आरओबी का निर्माण तेज गति से चलाकर शीघ्र पूर्ण कर आवागमन को सुगम बनाया जाये।

बनवारीलाल सिंघल

(अलवर शहर)

जनता जल योजना को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों के मद्देनजर पीएचईडी के पास रखा जाना

मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाह रहा हूं कि जन स्वा अभि. विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी जनता जल योजना को ग्राम पंचायतों के अधीन करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भंयकर संकट खड़ा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना विभाग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत वृहत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टयूबवैल, ओपनवेल एवं हैण्डपंप खोदे गये हैं जिसके कारण ग्रामीण जनता को इससे बड़ी राहत मिली थी लेकिन पिछले दिनों विभाग के आदेशानुसार इस योजना को ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया गया।

महोदय, मैं बाड़मेर जिले की स्थिति के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जहां पर पेयजल की भारी समस्या है ऐसे में जनता जल योजना को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने से ग्राम पंचायतें इसका संचालन नहीं कर पा रही हैं। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश टयूबवैल एवं ओपनवेल बंद पड़े हैं।

महोदय, ग्राम पंचायतें इस कार्य को करने में न तो तकनीकी रूप से सक्षम हैं और न ही आर्थिक रूप से। जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। महोदय, इस योजना को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने के विरोध में जिला परिषद बाड़मेर की पिछले महीने हुई साधारण सभा में सभी ने एकमत से प्रस्ताव पारित भी किया है कि इस योजना को पीएचईडी के पास ही रखा जावे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से श्री मान पीएचईडी मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाये अन्यथा गर्मियों के दिनों में पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

मेड़ता सिटी के चिकित्सालयों में स्थित पदों की पूर्ति व जनाना चिकित्सालय की स्थापना

1. मेड़ता नगर करीब 70,000 की जनंसख्या का क्षेत्र है तथा इसके आसपास रियां बाड़ी, जसनगर, पादूकलां, गोटन, मेड़तारोड, रेण आदि बड़े कस्बे व कई गांव हैं। जिनके निवासीगण को रोगोपचार के लिये मेड़तासिटी में आना पड़ता है। इस प्रकार करीब दो लाख लोगों को मेड़तासिटी में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिये आना पडता है।

2. कि मेड़तासिटी में चिकित्सालय में नेत्र रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग तथा फिजीशियन आदि चिकित्सकों के पद हैं। परन्तु ये पद काफी लम्बे समय से रिक्त हैं। जिससे रोगियों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिये जोधपुर व अजमेर जाना पड़ता है। जिससे रोगियों को आर्थिक नुकसान होता है। इस कारण समय व श्रम का भी सदुपयोग नहीं हो पाता है व समय पर इलाज नहीं होने से रोगियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

3. कि माननीय स्थाई लोक अदालत व जिला न्यायालय मेड़ता में जन हितार्थ याचिका पर चिकित्सा विभाग द्वारा पुराने चिकित्सालय भवन में दो चिकित्सक व दो मेल नर्स की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपने आप को पाबन्द किया जो भी उपलब्ध नहीं होने से जनता में भारी रोष है व नये चिकित्सालय में जाकर स्वास्थ्य लाभ लेने के यातायात व्यय 200 रुपये आम आदमी के बस की बात नहीं है।

4. कि मेड़तासिटी में पुराने चिकित्सालय भवन में जनाना चिकित्सालय की स्थापना कर जनता को राहत प्रदान करावें। महिला चिकित्सा के मामले भी मेड़ता व आसपास के नागरिकों को जोधपुर व अजमेर जाना पड़ता है। जिससे समय पर माता-बहिनों को इलाज नहीं मिलने से उनके शरीर व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होकर मृत्यु जनित रोग फैलने के कारण मृत्यु होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, से निवेदन है कि मेड़तासिटी के चिकित्सालय में लंबे अर्से से रिक्त उपरोक्त वर्णित रोगों के संबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति करवाई जावे व पुराने चिकित्सालय भवन में दो चिकित्सक व जनाना अस्पताल की स्थापना करवाकर लोक कल्याण का पुनीत कार्य करावें। इस संबंध में मेड़तासिटी के नागरिक आपके आभारी रहेंगे।

अतः मेड़तासिटी के चिकित्सालय में लंबे अर्से से रिक्त उपरोक्त

वर्णित रोगों के संबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति व पुराने चिकित्सालय भवन में दो चिकित्सक व जनाना अस्पताल की स्थापना करवाई जावे।

सुखाराम नेतड़िया

(मेड़ता)

नीमकाथाना क्षेत्र में नलकूपों के लम्बित विद्युत कनेक्शनों की स्वीकृति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत वर्षों में जलदाय विभाग द्वारा लगाये गये सिंगल प्वाइंट टयूबवैल जो ज्यादातर एससी एवं एसटी की बस्तियों से संबंधित है, पर विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन जारी करने से उत्पन्न स्थिति की ओर विद्युत मंत्रीजी एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि नीमकाथाना में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े-निर्धन वर्ग की जो बस्तियां सालों-साल से बसी हुई हैं, उनमें जलदाय विभाग द्वारा पिछले दो सालों में राज्य सरकार द्वारा जो ट्यूबवैल लगाये गये हैं, उन पर विद्युत विभाग द्वारा डिमांड नोटिसेज भी जारी कर दिये गये हैं जो कि जलदाय विभाग द्वारा जमा भी कराये जा चुके हैं, परन्तु आज दिन तक उन पर विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने से मेरे क्षेत्र की आम जनता भारी परेशानी में है, क्षेत्र की जनता को आने वाले मार्च-अप्रैल-मई में भयंकर पानी की किल्लत का सामना करने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग द्वारा यदि तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन जारी कर टयूबवैलों से आमजन को पेयजल मुहैया नहीं हुआ, तो मजबूरन जनता को आंदोलनात्मक रूख अपनाना पड़ेगा, कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने की पूरी आशंका है।

मेरी इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं ऊर्जा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग है कि तुरन्त प्रभाव से जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जायें कि वे नीमकाथाना क्षेत्र की आम जनता को राहत प्रदत्त करने हेतु टयूबवैलों के पेण्डिंग विद्युत कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र जारी करें। धन्यवाद।

रमेश खण्डेवाल

(नीमकाथाना)